



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936

No. 520]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

विषय : एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी 8, सी 10, सी 12, सी 14, सी 16, और सी 18 की लंबाई के कार्बन श्रृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी 12, सी 14, सी 12 – सी 16, सी 12 – सी 18, सी 16-18 और सी 14 – सी 16 (सामान्यतः सी 12 – सी 14 के रूप में प्रवर्गीकृत) कार्बन श्रृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं, अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों", जिसमें विशुद्ध सी8 शामिल नहीं है जिन्हें एतद्वारा "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच – अंतिम जांच परिणाम

सा.का.नि. 712 (अ).- 22011/26/2013 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसका सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997, को ध्यान में रखते

(क) प्रक्रिया

1. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई, एक 100 प्रतिशत निर्यातानुमुख इकाई ने एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी 8, सी 10, सी 12, सी 14, सी 16, और सी 18 की लंबाई के कार्बन श्रृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी 12 – सी 14, सी 12 – सी 16, सी 12 – सी 18, सी 16-18 और सी 14 – सी 16 कार्बन श्रृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं (सामान्यतः सी 12 – सी 14 के रूप में प्रवर्गीकृत) अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों", जिसमें विशुद्ध सी8 शामिल नहीं है जिन्हें एतद्वारा "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग करते हुए एक आवेदनपत्र याचिका में यथाप्रदर्शित यह आरोप लगाते हुए मेरे समक्ष दायर किया है कि इस "पीयूसी" के संवर्धित आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित

की जा हैं और/या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न की जा रही है, और उन्होंने भारत में इस "विचाराधीन उत्पाद" के संवर्धित आयातों द्वारा कारित की जा रही बाजार विकृति या बाजार विकृति की चुनौती से घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने की मांग की है।

2. इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी होती हैं, इस "पीयूसी" के आयातों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 13 फरवरी, 2014 के जांच शुरुआत नोटिस, अर्थात् 13 फरवरी, 2014 को जीएसआर 87(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और उसका शुद्धिपत्र दिनांक 19 फरवरी, 2014 को उसी दिन अर्थात् 19 फरवरी, 2014 को ही भारत के राजपत्र असाधारण के जीएसआर 100(ई) के तहत प्रकाशित किया गया।

3. दिनांक 13 फरवरी, 2014 के इस जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति और तदुपरांत दिनांक 19.02.2014 को जारी शुद्धिपत्र की एक प्रति संबद्ध कार्य देखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को नई दिल्ली में स्थित राजदूतावासों और अधोलिखित सूचीबद्धगत हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई :

3.1 निर्यातक

- (क) **एमरी ओलियोकैमिकल्स**, लेवल 5, बिल्डिंग-ई, पिरेम्बा स्क्वेयर, सौजना रिसार्ट, सेक्सन यू2 40150 शाह आलम सेलान्गोर मलेशिया
- (ख) **विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड**, 56 नील रोड, सिंगापुर 08883
- (ग) **पी एंड जी कैमिकल्स** प्राकटर एंड गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशन्स एसए सिंगापुर ब्रांच, 238ए थामसन रोड #20-01/10 नोवेना स्क्वेयर टावर ए, सिंगापुर 307684
- (घ) **सासोल लिमिटेड**, सासोल जर्मनी जी एम बी एच एंक्लमैन्सप्लैट्स 120537 हैम्बर्ग
- (ङ) **के एल के ओलियो** लेवल 8, मेंतारा के एल के, नम्बर 1, जालान पीजेयू 7/6 मुटियारा दामनसारा, 47810 पेटालिंग जाया, सेलानगर दारुल अहसान, मलेशिया
- (च) **मुसिम मास पीटी मुसिम मास जे1 केएल याससुदर्शो केएम7**, 9 तोन्जुंगमुलिया मेडान 20241, उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया
- (छ) **इकोग्रीन ओलियोकैमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड**, 99, बुकित तिमाह रोड #03-01 अल्फा सेंटर, सिंगापुर 229835
- (ज) **एफपीजी ओलियोकैमिकल्स एसडीएन-बीएचडी**, एफपीजी ओलियो कैमिकल्स, एसडीएन बीएचडी (184896-यू) लाट 3831, कौन्दान पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, तान्जुंग गेलांग, पीओ बॉक्स 26, पेजाबट पास बैलाक, 26080 कैन्टन, पेहांग दारुलमाक्मर, मलेशिया
- (झ) **काओ कारपोरेशन**, पिलिपिनास काओ, इंक, एक काओ ग्रुप कंपनी, 7वां तल, टावर वन एवं एक्सचेंज प्लाजा आयाला ट्राइंगल आयाला एवेन्यू, 1226 मकती सिटी, फिलीपीन्स
- (ञ) **थाई ओलियोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड**, 123 सनटावर्स बिल्डिंग ए, 14वां विभावाडी रंगसिट रोड, चामफोन, चाटुचाक बैंकाक 10900 थाईलैंड
- (ट) **टेक गुआन**, टेक गुआन (चीन) लिमिटेड संख्या 1, टेक गुआन रोड, रूगाओ पोर्ट इकानामिक डेवलपमेंट जोन रूगाओ, जियांगसु प्राविन्स, चीन 226532
- (ठ) **आक्सिटेनो** एवेनिडा ब्रिगैडिआइरो लुइस एंटानियो, 1343 बेला विस्टा -सीईपी 01317-910, साओ पाउलो - एसपी - ब्राजील
- (ड) **बीएसएस/कागनिस**, हेन्केलस्ट्रास्सी 6740551, डसेलडार्फ नार्डरहिन - वेस्टफालेन जर्मनी

3.2 भारत में प्रमुख आयातक/ प्रमुख औद्योगिक प्रयोक्ता

- (क) **गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड**, सी 49/2, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पावनी नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400703

- (ख) विश्वाट कैमिकल्स लिमिटेड "विस्वाट" 7 सतसंग काम्प्लेक्स अपर गोविंद नगर, एलएस राहेजा मार्ग, मालाड (पूर्व) मुंबई-400097
- (ग) रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड फीनिक्स हाउस "ए/बी" विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम) मुंबई, 400013
- (घ) इंडियन ग्लायकोल लिमिटेड 2 वी सेक्टर 126, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201304
- (ङ) स्टर्लिंग आक्जिलरीज प्राइवेट लिमिटेड 30/31, मारोल कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमवी रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400059
- (च) मातंगी इंडस्ट्रीज, प्लॉट संख्या 28, फेज 1 निल्सिन इंडस्ट्रीज के पीछे, जीआईडीसी, वात्वा, अहमदाबाद 382445, गुजरात
- (छ) वीनस इथाक्सीलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 109-111 बिचोलिम इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिचोलिम, गोआ - 403529
- (ज) गुजरात कैमिकल्स, 111, जलनिधि काम्प्लेक्स, बहुमाली भवन के पीछे, नानपुरा सूरत-1
- (झ) आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड 71 उद्योग क्षेत्र द्वितीय तल, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई - 400080
- (ञ) कुशा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 101, वरुण अपार्टमेंट दत्तात्रेय रोड, सांताक्रूज (पश्चिम) मुंबई -400054
- (ट) कृष्णा एंटीआक्सीडेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 लोपाज मैनार, मुंबई - 400013

3.3 घरेलू उत्पादक

- (क) वी वी एफ (इंडिया) लिमिटेड (घरेलू उद्योग) 109, सायन (पूर्व), मुंबई - 400022
- (ख) गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड पिरोशनगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली, मुंबई - 400079

3.4 राजदूतावास का नाम और पता

- (क) फिलिपीन्स का राजदूतावास, माननीय (श्री) बेनितो बी. वालेरिआनो राजदूत 50-एन, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021
- (ख) बेल्जियम का राजदूतावास, टी सी जी फाइनैशियल सेंटर 7वां तल, सी 53, जी ब्लाक, बांद्राकुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051/50 एन, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ग) यूएसए का राजदूतावास, यूएस का राजदूतावास, शांतिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (घ) यूके का राजदूतावास, नीति मार्ग, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ङ) यूएई का राजदूतावास, 12 चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 (भारत)
- (च) स्विटजरलैंड का राजदूतावास, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (छ) पोलैंड का राजदूतावास, 50 एम, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ज) सिंगापुर का राजदूतावास ई-6, चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (झ) नीदरलैंड का राजदूतावास, "फोर्ब्स बिल्डिंग" प्रथम तल चरणजीत राय मार्ग मुंबई-400001 /6/50 एच, शांतिपथ कौमी कुमाह मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ञ) इटली का राजदूतावास, 50 ई, चंद्रगुप्त मार्ग, नई दिल्ली-110021
- (ट) फिनलैंड का राजदूतावास ई-3, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ठ) फ्रांस का राजदूतावास, 2/50 ई, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ड) फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का राजदूतावास, पोस्ट बाक्स नम्बर 613, नई दिल्ली-110001
- (ढ) चीन का राजदूतावास, 50डी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

- (ण) **इंडोनेशिया का राजदूतावास**, 9 अल्टामाउंट रोड, कुम्बाला हिल, मुंबई -400026/ 50 ए, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (त) **थाईलैंड का राजदूतावास**, डी-1/3, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
- (थ) **मलेशिया का राजदूतावास**, 50 एम, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

4. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावलियां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे इस जांच शुरुआत नोटिस के 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत करा दें।

5. हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने के लिए निम्नलिखित से अनुरोध प्राप्त हुआ तथा उसे स्वीकार कर लिया गया :

- (i) श्री मोहम्मद राध्दी अब्दुल रज्जाक (निदेशक) ट्रेड पैक्टिसेस सेक्सन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, लेवल-140, ब्लॉक 8, सरकारी कार्यालय काम्प्लेक्स, जालान डुटा 50622 कुआलालम्पुर, मलेशिया ई-मेल : alltps@miti.gov.my
- (ii) मैसर्स मेजरहब ओलियोकैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 10वां सिद्धिविनायक अपार्टमेंट्स, चौथा तल, सोसायटी रोड, जोगेश्वरी पूर्व मुंबई-400060, ई-मेल: majorhubindia@vsnl.net
- (iii) मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (एचयूएल) यूनीलीवर हाउस, बी डी सावंत मार्ग, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400099
- (iv) मैसर्स चान पेक वान, सचिवालय, कैमिकल इंडस्ट्रीज काउंसिल आफ मलेशिया, मलेशिया ओलियोकैमिकल मैनुफैक्चरर्स ग्रुप (एम ओ एम जी) विस्मा एफएमएम, संख्या 13, पेर्सियासन डैगांग, पीजेयू 9, बंदर श्री दमामसारा 52200 कुआलालम्पुर मलेशिया, ई-मेल : pek_wan@FMM.ORG.MY
- (v) मैसर्स पैन ओलियो इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, 309,10,11 आदित्य बनारसी हैरिटेज, माइन्ड स्पेस, आफ लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई 400064, ई-मेल : panoleo@panoleo.com
- (vi) श्री मनोज झा, मैसर्स यूनिडस, ई-मेल : manoj@unidusononline.com
- (vii) भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ब्लाक 50ई, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, ई-मेल : rusintrade@mail.ru
- (viii) मैसर्स पीटी इकोग्रीन ओलियोकैमिकल्स, इंडोनेशिया, पीओ बॉक्स 1010, नागोया प्लाजा, बाताम, आईलैंड, 29432, इंडोनेशिया, ई-मेल : info.batam@ecogreenoleo.com
- (ix) व्यापार एवं आर्थिक प्रभाग, भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल 65, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली -110003 – ई –मेल : chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
- (x) मैसर्स काविकेयर प्राइवेट लिमिटेड, 12, सेन्टोफा रोड, तेयनाम्पेट, चेन्नई-600018
- (xi) विदेश व्यापार महानिदेशालय, जालान, एम 1, रिदवान रायस संख्या 5, जकार्ता 10110
- (xii) मैसर्स रत्नसागर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
- (xiii) मैसर्स इमामी लिमिटेड, 687, आनंदपुर ई एम बाईपास, कोलकाता – 700107 – ई-मेल : sapan.barik@emamigroup.com
- (xiv) मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, 555/1, एनर्जी काम्प्लेक्स, बिल्डिंग ए, 15वां तल, विभावाड़ी रंगसिट रोड, चाटुचाक, बैंकाक, 10900, थाईलैंड

5.1 मैसर्स पीटी मुसिम मास, इंडोनेशिया ने समयवृद्धि का अनुरोध किया जिससे कि वह अपना उत्तर प्रस्तुत कर सके।

5.2 विहित अवधि के अंदर जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु अनुरोध पर रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 6(4) के अनुसार समय विस्तार करने की अनुमति दे दी गई।

5.3 आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादक के संयंत्र का स्थल दौरा करके सत्यापन किया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

5.4 घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त या अधिप्राप्त अगोपनीय सूचना को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त विचारों पर अपनी अभ्युक्तियां प्रस्तुत करने के लिए और उनका निरीक्षण करने के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

5.5 घरेलू उद्योग ने दायर किए गए आवेदन में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के रूप में तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके समर्थन में उन्होंने दिनांक 21.04.2014 का एक पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा उनके द्वारा सामना की जा रही संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी को दर्शाते हुए सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर अपनी अनुसरित परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया है और घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क उदग्रहित नहीं किया जाता है तो उनको ऐसी क्षति कारित होगी जिसके पूरा किया जाना असंभव है।

5.6 अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के घरेलू उद्योग के अनुरोध की अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के साथ जांच की गई और उस पर फिर प्रारंभिक जांच परिणाम में समुचित निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया, जहां प्रथम प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि कुछ ऐसी नाजुक परिस्थितियां मौजूद हैं जिनसे घरेलू उद्योग को हो रही अपूरणीय क्षति से अंतरिम राहत प्रदान कराने के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक है।

5.7 तदनुसार, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 26 मई, 2014 को जारी किए गए और उसी दिन अर्थात् दिन के 26 मई, 2014 को ही सा.का.नि. 357(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए।

5.8 तदुपरांत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 28 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 03/2014-सीशु (एसजी) के तहत संबंधित अधिसूचना जारी करने की तारीख से 200 दिनों से अधिक समय की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई।

5.9 तत्पश्चात्, 26 अगस्त, 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सार्वजनिक सुनवाई के समय घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने मौखिक प्रस्तुतिकरण अभिव्यक्त किए। इस कार्यवाई के दौरान, कुछ पक्षकारों ने जिन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, परंतु वे इस विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता/निर्यातक थे, इस सार्वजनिक सुनवाई में प्रतिभागिता करने और अपने प्रस्तुतिकरण करने का अनुरोध किया। इन सभी को व्यापक जनहित में महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अनुमति दे दी गई। निम्नलिखित पक्षकारों में से केवल क्रम संख्या 2,5 और 6 पर उल्लिखित पक्षकारों ने ही अपने लिखित प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किए जिनपर समुचित स्थानों पर विचार किया गया है। उनके विवरण निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	स्थिति
1	मैसर्स अतुल लिमिटेड, नई दिल्ली	आमष्क/प्रयोक्ता
2	मैसर्स क्रोडा इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आयातक/प्रयोक्ता
3	मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, साहिवाबाद, उत्तर प्रदेश	आयातक/प्रयोक्ता
4	मैसर्स एचपीएल एडिटिव्य लिमिटेड, हरियाणा	आयातक/प्रयोक्ता
5	मैसर्स हिन्दुस्तान पालीएमिड्स फाइबर लिमिटेड	आयातक/प्रयोक्ता
6	मैसर्स इंडियन स्पेशिमलिटी कैमिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन	एसोसिएशन
7	मैसर्स पुष्पसन्स फिब्रोला प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	आयातक/प्रयोक्ता
8	मैसर्स सूफी इंटरप्राइजेज, मुंबई	आयातक/प्रयोक्ता

5.10 सीमाशुल्क प्रशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें।

5.11 एक हितबद्ध द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों का प्रति प्रत्युत्तर, यदि कोई, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया।

5.12 दिनांक 26 अगस्त, 2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों की जांच की गई और समुचित निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया। प्राप्त या अधिप्राप्त सूचना के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

5.13 गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली मुंबई- 400079 ने अपने दिनांक 16/12/2013, 03/01/2014 और 22/01/2014 में भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र का समर्थन किया है। उन्होंने इस विचाराधीन उत्पाद के आयात, उत्पादन, बिक्री, संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग आदि के संबंध में आंकड़े प्रदान करके इस जांच में सहयोग भी किया है, जिन पर विचार किया गया और उन्हें समग्र क्षति विश्लेषण के लिए रिकार्ड में लिया गया।

(ख) जांच शुरूआत के पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरण : घरेलू उद्योग तथा कई हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरूआत पश्चात के अपने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किए हैं, इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में भी हिस्सा लिया और सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुतिकरण भी किए। इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के उद्देश्य से कि जांच शुरूआत के पश्चात और सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्ति प्रवृत्ति के हैं, उनके द्वारा पुनरावृत्ति रूप में उठाए गए मुद्दों पर संक्षिप्तता के उद्देश्य से, या तो जांच शुरूआत पश्चात या सार्वजनिक सुनवाई पश्चात के रूप में समुचित स्थानों पर विचार किया गया।

घरेलू उद्योग (आवेदक) के विचार

1. **घरेलू उद्योग :** मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई, एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई ने दावा किया कि उनका उत्पादन इस "पीयूसी" का देश में होने वाले कुल उत्पादन का 63 प्रतिशत भाग बनता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार वर्तमान याचिका दायर करने का उनका पूरा आधार है। आवेदक के अलावा, इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई द्वारा भी किया जा रहा है, जो इस आवेदनपत्र का समर्थन कर रहे हैं।

2. **अंतर्ग्रस्त उत्पाद :** वसीय अल्कोहल्स अलिफैटिक अल्कोहल होते हैं तथा यह अनुविद्ध एवं अननुविद्ध रूपों में प्राप्त होते हैं। अल्कोहलों को समूहबद्ध किया जा सकता है और इनकी सबसे सामान्य लंबाई सी 12, सी 14 और उनका सम्मिश्रण है। इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन प्राकृतिक वसा एवं तेलों, अधिकांशतः नारियल और पाम गिरी का तेल, का संपरिवर्तन करके मिथायल ईस्टर या वैक्स ईस्टर का रिडक्शन करके किया जाता है। यह प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया के रूप में, वेजिटेबल आयल्स जैसे अपरिष्कृत पाम गिरी का तेल, का उच्च ताप एवं दाब पर विखंडन करके, प्रारंभ की जाती है। वेजिटेबल आयल्स/फैट्स (अखाद्य) मूलतः फैटी एसिड्स का ट्रिग्लायसेराइड होते हैं, जिसे हाइड्रोलायसिस प्रतिक्रिया करके वसीय अम्लों एवं ग्लायसरोल में परिवर्तित किया जाता है जिसे सामान्य भाषा में वसा विखण्डन कहा जाता है। तब इन अपरिष्कृत वसीय अम्लों का उच्च ताप एवं निर्वात में सादा/ विखंडित आसवन किया जाता है, फिर इसका प्रलवणन (ईस्टरीफिकेशन) किया जाता है जो वसीय अम्ल और वसीय अल्कोहल के बीच, इनर्ट वातावरण में, वैक्स ईस्टर बनाने के लिए प्रतिक्रिया का एक परिणाम होता है। फिर विशुद्ध मोम प्रलवण का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है जो फिक्सड बेड कापर कैटालिस्ट की मौजूदगी में घटित होता है और उससे अपरिष्कृत फैटी अल्कोहल बनता है। फिर इसका आसवन एवं परिशुद्धीकरण किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री फ्लेक्स, चूसिका (पैस्टिल्स) और द्रव रूप में की जाती है।

3. आवेदक ने 4 वर्षों की अवधि के लिए आयात एवं क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए हैं। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 (दिसम्बर 2013) तक के तिमाहीवार आंकड़े प्रदान कराए हैं जिनके आधार पर जांच शुरूआत का नोटिस जारी किया गया। तथापि, घरेलू उद्योग ने दिनांक 21.04.2014 और दिनांक 15.05.2014 के पत्र के तहत अतिरिक्त सूचना भी प्रस्तुत की जिसमें जनवरी 14 से अप्रैल 14 तक की अवधि के लिए आयातों एवं अन्य आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित सूचना का उल्लेख था। उसने इसमें अपनी शोचनीय स्थिति का वर्णन किया था और इस विचाराधीन उत्पाद पर तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया था, और यह कहा गया था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो बढ़ते आयातों के कारण उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उसमें सुधार होना मुश्किल हो जाएगा।

4. क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी न होना

4.1 अन्य कोई ऐसे कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। वसीय अल्कोहलों की मांग में पिछले तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। मांग में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग बाजार में हुई इस वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन, बिक्री या लाभ में वृद्धि नहीं कर सका।

4.2 याचिकाकर्ता एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है इसके कारण से इसे डीटीए इकाइयों से प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हो रहा है। कच्चे माल (पी के ओ) जैसे पाम गिरी आयल (जो यथामूल्य 7.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में होता है) पर लगा सीमाशुल्क परिष्कृत उत्पाद पर लागू शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है। चूंकि एक निर्यातोन्मुख इकाई कच्चे माल (पाम गिरी आयल) का आयात शुल्कों का भुगतान किए बिना कर सकती है और अपने परिष्कृत उत्पाद की निकासी 7.725 प्रतिशत की दर, (जो अब 18 फरवरी, 2014 से 3.86 प्रतिशत हो गया है), से शुल्क का भुगतान करके कर सकता है, इसलिए निर्यातोन्मुख इकाई पर लागू निवल शुल्क आयातित सामग्री से वसीय अल्कोहलों का विनिर्माण करने वाली डीटीए यूनिटों द्वारा दिए जा रहे शुल्क की तुलना में बहुत कम होता है। डीटीए इकाइयों को कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है, जिससे उनकी लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। इसलिए, घरेलू इकाई के लिए निवल शुल्क ई ओ यू इकाइयों के शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है।

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में डीटीए और ईओयू इकाइयों को समान स्थान पर रखा गया है। पीकेयू कुल उत्पादन लागत का लगभग 2/3 होती है। चूंकि पाम गिरी आयल भारत में, वाणिज्यिक मात्रा में, उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इस कच्चे माल का आयात किए जाने की जरूरत होती है और यह दोनों प्रकार की इकाइयों को समरूप या समान आयात कीमत पर उपलब्ध होता है। इसकी संपरिवर्तन लागत भी भिन्न नहीं होती है। तथापि, शुल्क ढांचा निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए फायदे मंद है, क्योंकि कच्चे माल पर शुल्क सामान्यतः 100 प्रतिशत होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डीटीए यूनिट 70/-रुपए मूल्य के कच्चे माल का आयात करता है तो उसे 70/-रुपए शुल्क देना पड़ता है, जबकि निर्यातोन्मुख इकाई को यह कच्चा माल छूट लाभ के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान किए बिना प्राप्त होता है। इसी तरह, एक निर्यातोन्मुख इकाई से निकासी किया गया समान उत्पाद जिसपर 7.725 प्रतिशत प्रभारित किया जाता है जो 8/-रुपए से 10/-रुपए की रेंज में होता है। इस प्रकार निर्यातोन्मुख इकाइयों का निवल शुल्क डीटीए इकाइयों के लिए निर्धारित शुल्क से बहुत कम होता है। ईओयू द्वारा डीटीए क्लीयरेंस के लिए लागू शुल्क में और अधिक कमी करके उसे 3.86 प्रतिशत कर दिया गया है।

4.4 खपत की प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं है, जिससे यह सुझाव मिलता हो कि यह क्षति इन्हीं कारकों द्वारा पहुंचाई जा रही है। किसी भी मामले में, यह जरूरी नहीं है कि आयात क्षति का प्रमुख कारक हो, बशर्ते कि इसे इस तरह दिखाया जा सके कि वह क्षति का एक कारक है।

4.5 वर्तमान मामले में, ऐसी कोई अन्य परिस्थितियां या कारक नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा रही हो और कारणात्मकता की जरूरत पूर्णतया पूरी होती है।

5. "घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है"

5.1 वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई जांचों में ईओयू को घरेलू उद्योग के एक अंग के रूप में माना है। जिस स्थिति तक किसी निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई अनुरक्षित रखा जाता है तब तक भारत में विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू रूप से बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेश व्यापार नीति में उक्त उत्पाद की घरेलू निकासी पर (निर्यात के लिए एफओबी मूल्य का 50 प्रतिशत तक) शुल्क की रियायती दर के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य उत्पादों पर अर्जित हकदारी का प्रयोग वसीय अल्कोहलों के लिए निर्यातों के कुल एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक किया जा सकता है। उक्त सीमा से परे, किसी निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा बिक्री समुचित उत्पाद कर का भुगतान करने पर की जा सकती है। अतः, भारत में निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा विनिर्मित उत्पाद की बिक्री करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक उसका एनएफई सकारात्मक है। इस मामले में, विटामिन ए के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच परिणाम के पैराग्राफ 35 का उद्धरण यहां दिया जा रहा है, जिसमें पीरामल हेल्थकेयर (एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया था :

"किसी उद्योग के 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई हेनित था और इसलिए उसके घरेलू उद्योग की पात्र नहीं होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ईओयू सुविधा स्वयं याचिकाकर्ता की "घरेलू उद्योग" के रूप में स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किए गए क्लीयरेंस विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं या वे आपातिक नहीं हैं और उन्हें घरेलू रूप से संदत्त उत्पाद कर विक्रियों के रूप में माना जाता है, न कि आयातों के रूप में। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का भारत में समस्त उत्पादन के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमों के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।"

कोई निर्यातोन्मुख इकाई कोई ऐसी इकाई नहीं होती है जो भारत से बाहर स्थित हो और इसलिए वह घरेलू उद्योग का एक भाग होती है।

5.2 याचिकाकर्ता पुनः यह प्रस्तुत करते हैं कि वीवीएफ समान वस्तु या प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करता है। वीवीएफ द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहलों की आयातित उत्पादों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा होती है और इसलिए वह घरेलू उद्योग की परिभाषा को संतुष्ट करता है।

6. आशियान देशों (ए आई एफ टी ए) के साथ विदेशी व्यापार करार के अनुसार शुल्क में कमी

6.1 भारत ने व्यापार सुगमीकरण के लिए आशियान – भारत मुक्त व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) नामक एक करार किया है जिसके अनुसरण में प्रशुल्क अवरोधों को समयबद्ध ढंग से कम किया जाना/समाप्त किया जाना है। इस संधि प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क प्रारंभ में दिनांक 01 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011 के द्वारा 10 प्रतिशत कम किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 57/2013 के तहत उसका उपशमन कर दिया गया था।

6.2 कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को एआईएफटीए के कारण ही क्षति होती है और यह क्षति आयातों पर उपरोपित नहीं की जानी चाहिए।

6.3 घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एआईएफटीए द्वारा कारित की जा रही क्षति का उपरोपण न करना नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा 2 के अनुसार इस कारण से बांझित नहीं है कि एआईएफटीए "आयातों के अलावा" एक अन्य कारक नहीं है।

6.4 नियमावली के अनुबंध-2 के पैराग्राफ 2 में संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का उपरोपण न करने का प्रावधान है जो निम्नवत है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच, प्रयोजनमूलक साक्ष्यों के आधार पर, संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या उसकी चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी प्रदर्शित न करती हो। जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक साथ-साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों तो इस क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।"

6.5 उपर्युक्त प्रावधान यह अपेक्षा करता है कि घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के अलावा उन अन्य कारकों का अभिज्ञान करना चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है और उनके द्वारा कारित क्षति का उपरोपण आयातों पर नहीं करना चाहिए। विचाराधीन कारक दो प्रकार के हैं :

क. वे कारक जो आयातों में वृद्धि में अपना योगदान देते हों।

ख. वे कारक (संवर्धित आयातों के अलावा) जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हों।

6.6 एआईएफटीए के परिणामस्वरूप शुल्कों में कमी करना उन कई कारकों में से एकमात्र ऐसा कारक है जिसके आयातों में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे ही कुछ अन्य कारकों में शामिल हैं विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, विचाराधीन उत्पाद के लिए वैकल्पिक निर्यात बाजार उपलब्ध न होना, विचाराधीन उत्पाद की निर्यात के देशों में कम मांग, भारत में शुल्क में कमी आदि। यह वे कारक हैं जो आयातों की वृद्धि में योगदान करते हैं जिनके लिए गैर-उपरोपण किए जाने की अपेक्षा नहीं होती है।

6.7 दूसरे प्रकार के कारकों में घरेलू उद्योग द्वारा तकनीकी उन्नयन की कमी, भारत में खपत की प्रणाली में परिवर्तन आपूर्ति की ओर से अवरोध आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। आपूर्ति भारत में ऊपर सूचीबद्ध द्वितीय श्रेणी के कारकों का अर्थात् घरेलू उद्योग को आयातों के अलावा क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों का ही गैर-उपरोपण विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इसलिए शुल्क में कमी के लिए गैर-उपरोपण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

6.8 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि चूंकि एआईएफटीए व्यापार असंतुलन का समाधान करने का एक वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान करता है इसलिए महानिदेशक रक्षोपाय का रक्षोपाय कार्रवाई प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक रूप से गलत और इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। एआईएफटीए के अंतर्गत, उप पक्षकारों के अधिकार एवं प्रतिबद्धता का उल्लेख है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। एआईएफटीए के अनुच्छेद 10(1) में प्रावधान है कि इस संधि के होने के बावजूद भी डब्ल्यूटीओ सदस्य (जिनमें भारत भी शामिल है) रक्षोपायस करार के अंतर्गत अपने अधिकार एवं अपने दायित्वों को प्रतिधारित करेंगे। इस करार का एक उद्घारण नीचे दिया जा रहा है :

"अनुच्छेद 10

रक्षोपाय साधन

प्रत्येक पक्षकार, जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX और डब्ल्यूटीओ करार (रक्षोपाय संबंधी करार) के अनुबंध-1क में रक्षोपाय संबंधी करार और डब्ल्यूटीओ करार (कृषि संबंधी करार) के अनुबंध-1क में कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्रतिधारित करता है। गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX और रक्षोपाय संबंधी करार या कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में किया गया कोई कार्य ढांचागत करार (आशियान -भारत डीएसएम करार) के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र करार के अधीन नहीं होगा।

6.9 यह तथ्य है कि एफटीए के अंतर्गत शामिल देशों से होने वाले आयातों पर शुल्क को दिनांक 01.01.2014 से हटा लिया गया है, इसके परिणामस्वरूप भी अन्य बाजारों से भारत को संबद्ध वस्तु का विपथन हो रहा है और आयातों में इसके उद्रेक के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क का तत्काल उद्ग्रहण करना आवश्यक है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में यूरोपियन काउंसिल ने कृषिपय स्टील उत्पादों के आयातों पर अनंतिम साधन अधिरोपित किया है। इस संदर्भ में इस निर्धारण के पैराग्राफ 51 से 57 का उल्लेख नीचे किया जाता है :

"(51) इस आयोग ने यूएस बाजार से विपथित की जा रही वस्तु की भारी मात्रा के संभावित गंतव्य का प्रारंभिक आकलन किया है। यह नोट किया जाता है कि अन्य बाजारों (विशेष रूप से जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका) की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की संभावना नहीं है कि इन बाजारों को भारी मात्रा में विपथन किया जा सके या विपथन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तृतीय देशों के उत्पादकों को अपनी घरेलू बाजारों में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वे अब यूएस बाजार के लिए पहले से निर्धारित वस्तुओं को समाहित करने में अक्षम हैं। कम्युनिटी बाजार की उन्मुक्तता पर ध्यान देते हुए, विदेशी उत्पादकों को यूएस बाजार से अपवर्जित वस्तु के लिए एक उपयुक्त स्थान हो सकता है। इन हालातों में आयोग यह निष्कर्ष निकालता है कि यूएस बाजार से अपवर्जित निर्यातों का पर्याप्त भाग कम्युनिटी को विपक्षित कर दिया गया है या विपक्षित कर दिया जाएगा।

(52) अतः, यह प्रत्याशा की जा सकती है कि यूएस बाजार में आयात प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद के कम्युनिटी में होने वाले आयातों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। विश्लेषण यह दर्शाता है कि लगभग 15 मिलियन टन स्टील उत्पाद (लगभग 4.1 बिलियन डालर मूल्य के), जो वर्ष 2000 में इस उत्पाद के कम्युनिटी द्वारा किए गए कुल आयातों के बराबर हैं, यूएस साधनों के अंतर्गत कवर हैं और इस जोखिम को कम्युनिटी की बाजारों की ओर विपथित किया जा रहा है।

(53) यूएस द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2002 को घोषित यूएस साधनों द्वारा समुदाय के उत्पादकों की स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई है क्योंकि इन साधनों ने कम्युनिटी के उत्पादकों को अपने प्रक्षेपण संशोधित कर अधोगामी करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे उनके अर्जन (निर्यात और घरेलू बिक्री से होने वाला) में कमी आ गई है तथा उनकी लाभप्रदायकता को और अधिक क्षति पहुंची है। यह कम्युनिटी उद्योग के बीच वर्तमान पुनर्गठन के लिए समझौताकारी है। यह इस उद्योग के लिए विगत में किए गए पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण प्रयासों को कम कर रहा है।

(54) चूंकि कम्युनिटी उत्पादकों के प्रक्षेपण अधोगामी संशोधित हुए हैं, इसलिए लागत में कमी करने के उद्देश्य से इन उत्पादन सुविधाओं को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद होने से बचना मुश्किल है। इस तालाबंदी न केवल समान उत्पादों का उत्पादन प्रभावित होगा बल्कि समान सुविधाओं का प्रयोग करके अन्य उत्पाद का उत्पाद भी प्रभावित होगा। उद्योग के आकलनों के अनुसार इसका सामाजिक प्रभाव यह हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में 20,000 से अधिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। इसका ऋणात्मक प्रभाव उन क्रियाकलापों पर भी पड़ सकता है जो इस साधन से प्रभावित कम्युनिटी के सदस्यों पर निर्भर हैं।

(55) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित 15 उत्पादों की घरेलू खपत स्थिर बनी हुई है या उसमें कमी आ रही है और यूएस साधनों की घोषणा से पहले जिन दरों पर आयात में वृद्धि हो रही थी, घरेलू उत्पादकों की स्थिति कमजोर हो रही है।

(56) यूएस द्वारा अपनाए गए साधन से आयातों में भारी वृद्धि से कम्प्यूनिटी के उत्पादकों को अपने लाभ और विक्रियों का प्रक्षेपण अधोगामी करना पड़ा है। यह संशोधित प्रक्षेपण कम्प्यूनिटी उत्पादकों से अपनी लागत में कमी करने और प्रत्याशित घाटे से बचने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग करते हैं जिसमें उत्पादन सुविधाओं को समाप्त करना, कर्मचारियों की छंटनी करना आदि शामिल है। ऐसी कार्रवाई करके कम्प्यूनिटी उत्पादकों को कारित की जाने वाली क्षति अपूरणीय होगी। यदि इनसे बचा जाना है तो अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक होगा।

(57) इसलिए, आयोग यह विचार किया है कि एक ऐसी नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने में किया गया कोई विलंब से ऐसी क्षति पहुंच सकती जिसकी भरपाई होना मुश्किल हों। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बिना किसी विलंब के अनंतिम रक्षोपाय साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ग) हितबद्ध पक्षकार

ग.1 रूसी परिसंघ

चूंकि उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 और 29051700 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का रूसी परिसंघ से भारत को आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख तथा डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए रूसी परिसंघ को जांचाधीन देशों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए।

ग.2 फिलीपीन्स केएओ इंक

चूंकि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख तथा डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए इसका रक्षोपाय शुल्क से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए जबकि चोटी के तीन निर्यातकों (इंडोनेशिया मलेशिया और थाईलैंड) से आयातों का हिस्सा 98 प्रतिशत से अधिक है।

ग.3 इंडिया ग्लायकोल लिमिटेड

- (i) भारत में केवल दो ही उत्पादक हैं मैसर्स वीवीएफ और गोदरेज़ लारिल अल्कोहल, जिसमें प्रथम उत्पादक की 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है। चूंकि उनके पास भारी निर्यात दायित्व है, इसलिए मांग तथा गैर प्रतिस्पर्धी कीमतों की तुलना में उनकी घरेलू विक्रियां सीमित ही हैं साथ ही उनकी प्रदाय अवधि भी दीर्घ है। वे अपनी एकाधिकारवादी स्थिति में समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।
- (ii) आशियान देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करार के अनुसार आयात शुल्क में कमी करने पर जोर दिया गया है।
- (iii) वर्ष 2013-14 में उत्पादन और मांग में वृद्धि हुई तथा लाभप्रदता में सुधार हुआ। जब जांच पूरी न हो जाए और क्षति का सुनिश्चयन न हो जाए तब तक कोई भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

ग.4 एमरी ओलियोकैमिकल्स मलेशिया

एक आवेदक की इंडोनेशिया में विनिर्माण इकाई है और उसे निर्यात लाभ प्राप्त हो रहा है तथा वह भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए मध्यवर्ती फीडस्टाक का प्रयोग कर रहा है। मलेशिया के उत्पादकों को यह लाभ प्राप्त नहीं है।

ग.5 आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- (i) इंडोनेशिया और मलेशिया को अंतर्निहित लागत लाभ प्राप्त है और वे इस विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी स्थान है जबकि आवेदक प्राथमिकतः निर्यात बाजारों के लिए एक निर्यातोन्मुख इकाई है क्योंकि उनकी विनिर्माण लागत घरेलू बाजार में उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना देती है।
- (ii) यदि शुल्क अधिरोपित कर दिया गया तो अधोगामी उद्योग तहस-नहस हो जाएगा क्योंकि एसएलएस और एसएलईएस का आयात आशियान एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क पर किया जाता है। किसी भी प्रकार के शुल्क से

भारतीय उद्योग के हित को नुकसान होगा क्योंकि आधोगामी उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा और मूल्यवर्धन अन्य देशों को अंतरित हो जाएगा।

ग.6 विश्वात कैमिकल्स लिमिटेड

स्थानीय अधिप्रापण भरोसेमंद नहीं है और उसकी कीमत आयातों की तुलना में बहुत अधिक है, जबकि आवेदक की प्राथमिकता निर्यात है।

ग.7 काविन केयर लिमिटेड

- (i) हम एसएलईएस और एसएलएस का प्रयोग करके शैम्पू बनाते हैं जिसके लिए वसीय अल्कोहलों की जरूरत पड़ती है जिनका आयात मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है जिसे प्राकृतिक एवं तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं। एसएलईएस और एसएलएस दोनों पर भारत-आशियन एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क है।
- (ii) पाम गिरी का तेल और इसके अधोगामी उत्पादों की विशिष्ट बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से यह उत्पाद महंगा हो जाएगा और कम कीमत वाले शैम्पू शेसे की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी जिससे भारी जनसंख्या को अपने बाल स्वस्थ रखने में नुकसान होगा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग प्रभावित होगा।

ग.8 मेजरहब ओलियोकैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

- (i) आवेदक यह छुपा रहे हैं कि वे भी सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, वसीय अम्लों और सी18.1 (ओलिक एसिड) की बिक्री करते हैं और वे इसका गलत प्रतिनिधित्व करते हैं कि इसका उत्पादन करना और सी8, सी10 अल्कोहलों का बिक्री करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है।
- (ii) वित्तीय क्षति से संबंधित आवेदक के अभिकथन का प्रतिनिधित्व गलत है, चूंकि वसीय अम्लो – सी16, सी18, सी1618 की बिक्री में आवेदक के हिस्से में भारी गिरावट आई है (जो वसीय अल्कोहलों की तुलना में उनका प्रमुख व्यवसाय है) और वे यूरोप में इस वस्तु का स्वयं पाटन कर रहे हैं और जब वहां पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिया गया तो उन्होंने अपना रुख भारत की ओर कर लिया।
- (iii) उन्होंने इस तथ्य का विलोपन किया है कि गोदरेज़ उद्योग सी1214 अल्कोहल का आयातक है।
- (iv) वर्ष 2013-14 में आयात में कमी होने के लिए आवेदक द्वारा दिया गया कारण कि मलेशिया और इंडोनेशिया में तालाबंदी से ऐसा हुआ, एक गलत सूचना है क्योंकि ओलियो उद्योग में कैटालिस्ट का परिवर्तन करने के लिए नियमित बंदी की जाती है।
- (v) अधिकांश मलेशियाई और इंडोनेशियाई उत्पादकों का कच्चे माल सीपीकेओ और सीपीओ के लिए खुद का तेल संयंत्र है परंतु यह सुविधा वीवीएफ और गोदरेज दोनों के ही पास नहीं है।
- (vi) भर्ती में वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 तक 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसलिए रोजगार में क्षति होने का उनका दावा निराधार है।
- (vii) सी16, सी1618 और सी18 अल्कोहलों में आवेदक का हिस्सा घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों में बढ़ा है।

ग.9 मैसर्स पीटी मुसिम मास

- (i) आवेदक ने बेशी एवं अवांछित गोपनीयता का दावा किया है जिसने पक्षकार को आवेदक के दावे और भरोसा की गई सामग्री को तर्कसंगत रूप से समझने से वंचित कर दिया।
- (ii) घरेलू उत्पादक किसी ऐसे एसएफए का उत्पादन नहीं करते हैं जिसकी लंबाई सी8 और सी10 हो और जो उनका सम्मिश्रण हो और इन वस्तुओं के आयात से आवेदक को क्षति नहीं हो सकती है। इस विचाराधीन उत्पाद को सही-सही परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे एसएफए के प्रकारों को पृथक किया जा सके।
- (iii) आवेदक का यह दावा सिद्ध नहीं होता है कि आयातों में अचानक वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि आयातों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 (वार्षिकीकृत) की अवधि के दौरान और खासकर 2013-14 में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।
- (iv) आवेदक ने वर्ष 2013-14 के आंकड़ों की अनदेखी कर दी और उन्होंने प्रत्येक तिमाही का विश्लेषण विगत वर्ष की तिमाही से करना प्रारंभ कर दिया।
- (v) आवेदक का यह दावा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में संयंत्र की तालाबंदी दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 की पहली और दूसरी तिमाही में आयातों में कमी है, विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि उत्पादन फिर से प्रारंभ हो जाने के पश्चात वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में उत्तरवर्ती उद्रेक नहीं हुआ।

- (vi) इस विचाराधीन उत्पाद का चयन जानबूझकर एसएफए के आयातों पर कम प्रकाश डालने के लिए किया गया क्योंकि आधार वर्ष 2010-11 (जैसा कि आवेदक ने प्रस्ताव किया है) के साथ आयातों की प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और यदि आधार वर्ष 2011-12 लिया जाए तो बिल्कुल भिन्न तस्वीर उपस्थित होगी।
- (vii) आवेदक का क्षति का दावा स्थापित नहीं होता है क्योंकि इसकी क्षमता और इसके उत्पादन में वर्ष 2013-14 में भारी सुधार हुआ।
- (viii) आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट इसकी ईओयू स्थिति तथा निर्यात उन्मुखी होने के कारण इस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो सकता है।
- (ix) रक्षोपाय शुल्क से आवेदक को इंडोनेशिया और मलेशिया के एसएफए के उत्पादकों की तुलना में कोई लाभ नहीं पहुंचेगा क्योंकि मुख्य कच्चे माल का उत्पादन वहां स्वयं किया जाता है।

ग.10 फेटी अल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड, विल्सर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, केएल – कियांग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी एवं गैलेक्सी सरफैक्टेन्ड्स

- (i) याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने केवल सी12, सी14, सी16, सी18 और उनके सम्मिश्रणों का ही उत्पादन एवं बिक्री की है, न कि सी8 और सी10 कार्बनों की। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्बन श्रृंखला लंबाई और संयोजनों, जिनका आयात भारत में नहीं किया जा रहा है या जिनका जांच की अवधि के दौरान कदाचित ही प्रयोग किया गया वे हैं सी810 और सी14। अतः इन उत्पादों की परिभाषा में इस ग्रेड को शामिल करना गलत होगा।
- (ii) वर्तमान विधिक एवं वाणिज्यिक स्थिति में वीवीएफ घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया है और उसे क्षति हो रही है। वीवीएफ कच्चे माल के आयात पर निर्भर है जो इंडोनेशिया और मलेशिया में निर्यात करके अर्धवर्धित है, जबकि वीवीएफ जब घरेलू बाजार में वसीय अवकोहलों की बिक्री करता है, तो प्रयोक्ताओं को सीमा शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो भारत-आशियान करर के अंतर्गत इन देशों से वसीय अल्कोहल के आयात के मामले में अनुप्रयोज्य नहीं है।
- (iii) पिछले वर्ष की तुलना में, आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई और केवल आयातों तथा विचाराधीन उत्पाद पर विचार करते समय प्राधिकारी को सभी उत्पाद ग्रेडों/कार्बन श्रृंखला की लंबाइयों की अलग से जांच करनी होती है।
- (iv) वास्तव में अधिकांश ग्रेडों के आयात में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई और जांच की अवधि (दिसम्बर, 2013-14 तक) के दौरान वे सबसे कम स्तर पर थे।
- (v) याचिकाकर्ता और अन्य उत्पादक गोरदेज़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईओयू) दोनों ही का प्राथमिक उद्देश्य भारत की संबद्ध वस्तु का निर्यात करना है।
- (vi) आयातों में बढ़ोतरी होने का एक बड़ा कारण आशियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की भारत की पहल है और उन्हें शुल्क की रियायती पर प्रदान करना है।
- (vii) याचिकाकर्ता डीटीए क्लीयरेंस केवल उच्च दर पर ही प्राप्त कर सकता है न कि आशियान एफटीए के अंतर्गत भारत की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क की अधिमानी दर पर। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण इस अंतर को समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा लिया गया एक नीति निर्णय है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

ग.11 पीटी इकोग्रीन

- (i) एनओआई और शिकायत में उपयुक्त ढंग से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ये संवर्धित आयात अभिनव, अचानक, तेजी से एवं महत्वपूर्ण स्थिति में घटित हुए।
- (ii) शिकायतकर्ता निर्यातोन्मुखी इकाई स्कीम के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है और भारतीय बाजार में घरेलू बिक्री मात्रा उत्पादन की कुल मात्रा के एक तिहाई तक सीमित है और यह भारतीय बाजार की घरेलू मांग को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर सकती है।
- (iii) भारत में वसीय अल्कोहल के दो उत्पादक हैं नामशः शिकायतकर्ता और गोदरेज, उसका भी भारत में घरेलू उत्पाद के भारी भाग पर अधिकार है और इस प्रकार दोनों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
- (iv) गोदरेज शिकायतकर्ता का एक भाग नहीं है और शिकायत में प्रस्तुत किया गया इसका समग्र निष्पादन सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है।

ग.12 रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड (साल्वे ग्रुप)

भारत इथायलीन आक्साइड की समुचित कीमत निर्धारण और लौरिल अल्कोहल की उपलब्धता के कारण इस समय इथाक्सीलेशन हब है और विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क समस्त मूल्यवर्धन को समाप्त कर देगा जिससे रोजगार एवं राजस्व में घाटा होगा।

ग.13. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

- (i) आयातों की मात्रा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से संकेंद्रित है और उससे वैश्विक रक्षोपाय साधन वांछित नहीं है। आवेदनकर्ता को व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी ढांचागत करार के अंतर्गत वस्तु व्यापार करार के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों पर विचार करना चाहिए।
- (ii) इस तथ्य का स्पष्टतः कोई कारण नहीं है कि कुछ कार्बन श्रृंखलाएं जिनका उत्पादन नहीं किया जा रहा है उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित क्यों कर दिया जाना चाहिए। आवेदनपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक सी8 और सी10 लंबाई के वसीय अल्कोहल और उनके सम्मिश्रणों का आयात नहीं करता है।
- (iii) अनपेक्षित विकास के पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की दी गई है और आवेदन में उसकी मौजूदगी ही नहीं है।
- (iv) आवेदक के प्रचालन कम निर्यात निष्पादन और निर्यात बाजार में न्यूनतम प्रापण तथा उच्च वित्त लागत के कारण प्रभावित हो सकते हैं और क्षति, यदि कोई हो, स्वतः पहुंचाई गई है और वह संवर्धित आयातों पर आरोप्य नहीं है।
- (v) संबद्ध वस्तु का आशियान सीईसीए के अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से भारत को प्रशुल्क मुफ्त आयात किया जा सकता है। इस क्षति का कारण आधारभूत रूप से व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा है और इसे संबद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (vi) आवेदक ने समायोजन योजना का प्रकटन करने के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता के दावे का अनुचित लाभ प्राप्त किया है।
- (vii) रक्षोपाय शुल्क का कोई अधिरोपण जनहित के विपरीत होगा क्योंकि उपभोक्ता उद्योग के हितों पर सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

घ. घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी जांच शुरूआत पश्चात प्रस्तुतिकरणों का उत्तर दिया है और उसके शुरूआती प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 ("अधिनियम") की धारा 8ख के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा रक्षोपाय करार से संगत नहीं है। उनका यह तर्क सही नहीं है क्योंकि चूंकि वाक्यांश "घरेलू उत्पादन" का आशय भारत में उत्पादन से होता है न कि "भारत में खपत" के लिए निर्धारित उत्पादन से। यह अनुरोध अनुचित है कि स्थायी जरूरत की जांच केवल घरेलू उत्पादन के संदर्भ में की जानी चाहिए। उत्पादन के स्तर पर यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या किसी वस्तु की खपत भारत में की जाएगी या अन्यत्र। किसी भी हाल में भारतीय उत्पादकों का कुल उत्पादन, उनके निर्यात को घटकर, भी यह प्रदर्शित करता है कि याचिकाकर्ता का इस जांच के प्रयोजनार्थ आधार है।

"घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई होने और इसलिए घरेलू उद्योग के रूप में उसके अपात्र होने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातोन्मुख इकाई की सुविधा याचिकाकर्ता के "घरेलू उद्योग" के रूप में दर्जे की विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किया गया क्लीयरेंस विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के लिए प्रतिबंधित अथवा आपातिक नहीं है और उसे उत्पाद कर संदत्त घरेलू बिक्रियों के रूप में माना जाता है न कि आयातों के रूप में। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।"

घ.2 कोई निर्यातोन्मुख इकाई, भारत के बाहर स्थित इकाई नहीं होती है और इसलिए यह घरेलू उद्योग का ही भाग होती है।

घ.3 कास्को ब्लासम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क आयुक्त के मामले में, जिसे वर्ष 2004 (164) ईएलटी 423 (ट्रि दिल्ली) में रिपोर्ट किया गया, माननीय अधिकरण ने यह उल्लेख किया कि किसी ईओयू द्वारा निकासी की गई वस्तु को घरेलू वस्तु के रूप में माना जाता है। इसका संगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

"5. यह सुस्थापित 12000 (120) ईएलटी 8001 है कि किसी निर्यातोन्मुखी इकाई में उत्पादित वस्तु को आयातित वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और उसे सीमाशुल्क के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी वस्तु के संबंध में संदेय शुल्क केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत की धारा 28 के अंतर्गत किए गए प्रतिवादी आदेश में की गई शुल्क की मांग संधारणीय नहीं है। तदनुसार हम इस प्रतिवादी आदेश पर ध्यान न देते हुए वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि राजस्व प्राधिकारी आयातित इनपुटों, यदि कोई हो, जिनका उपयोग प्रश्नाधीन कट-फ्लावर्स का उत्पादन करने में किया जाता है, पर शुल्क की मांग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।"

घ.4 याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन में हिस्सा 60 प्रतिशत है और इसलिए यह "घरेलू उद्योग" बनने के योग्य है।

घ.5 याचिकाकर्ता एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है, इसलिए यह डीटीए इकाइयों की तुलना में प्रतिस्पर्धी लाभ का उपयोग करता है। कच्चे माल (पीकेओ) पर सीमाशुल्क जैसे पाम गिरी का तेल (जो यथामूल्य 7.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में होता है) परिष्कृत वस्तुओं पर लागू शुल्क से कहीं अधिक होती है। चूंकि कोई निर्यातोन्मुख इकाई इस कच्चे माल (पीकेओ) का आयात शुल्क का भुगतान किए बिना कर सकता है और अपने परिष्कृत उत्पादन की निकासी 7.725 प्रतिशत की दर से (जिसे अब दिनांक 18 फरवरी, 2014 से 3.86 प्रतिशत कर दिया गया है) शुल्क का भुगतान करके कर सकता है। इसलिए ईओयू लागू निवल शुल्क आयातित सामग्री से वसीय अल्कोहल विनिर्मित करने वाली इकाइयों से बहुत कम होती है। डीटीए इकाइयों को कच्चे माल पर सीमाशुल्क वहन करना होता है जिससे उनकी लागत पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। अतः घरेलू यूनिट का निवल शुल्क ईओयू इकाई के निवल शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है।

घ.6 यह दावा सही नहीं है कि आयातों की अधिकता और लाभप्रदायकता के बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण भ्रामक है क्योंकि यह इंडेक्स संख्याओं पर आधारित है। पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित की गई क्षति के बीच परस्पर संबंध है। यह आयात, वर्ष 2012-13 और 2013-14 में सर्वाधिक हो रहे थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभप्रदायकता, निवेश पर अर्जन, घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की स्थिति पर्याप्त बदतर हो गई जबकि उन दिनों आयात उच्चतर स्थिति में थे।

घ.7 यह क्षति ऐसे "घरेलू उद्योग" को कारित की जानी चाहिए जो समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का आयात करता हो। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहल आयातित वस्तु के तुलनीय है और वे आयातित वस्तु से वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से अंतर्निमेय हैं।

घ.8 इस उत्पाद में उन ग्रेडों/प्रकारों को कवर किया जाता है जो उनके तकनीकी गुणधर्मों, रासायनिक संघटनों और अन्य आधारभूत विशिष्टताओं के रूप में समान होते हैं। इन सभी शीर्षकों के उत्पादनों का समान उपयोग होता है। इसलिए यह उत्पाद समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं। मामूली से सतही संभावित अंतर के बावजूद, इन उत्पादों के समरूप आधारभूत भौतिक गुणधर्म होते हैं और इनके समरूप अंतिम प्रयोग भी होते हैं। इनकी बिक्री समान या समरूप बिक्री सरणियों से की जाती है। यह उत्पाद मुख्यतः कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक आठ अंकीय स्तर के एक शीर्षक पर या एक प्रकार पर, विवक्ति में, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा क्योंकि आयातगण अन्य प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का आयात करना प्रारंभ कर देंगे। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित उत्पाद पर रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में समुचित ढंग से विचार किया गया है।

घ.9 विचाराधीन उत्पाद में एक एकल कच्चे माल से व्युत्पन्न ग्रेड/प्रकार शामिल हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी एकल सम्मिश्रण/कट को विविक्ति में नहीं लिया जा सकता है इसलिए सी8 से सी 18 तक की कार्वन श्रृंखलाओं के संपूर्ण सेट को इस उत्पाद की एकल श्रेणी के रूप में माना जाएगा। इनके अनुप्रयोग मौटे तौर पर एक समान हैं, यह कि इनका प्रयोग डिटर्जेंट और निजी देखभाल उद्योग में किया जाता है। वास्तव में सी12, सी14 और सी16 सी18 को इथोक्सीलेट में संपरिवर्तित किया जा सकता है और उनका प्रयोग डिटर्जेंट अनुप्रयोगों में सर्फैक्टेंट के रूप में किया जाता है। सी12 सी18, जो सी12 सी14 तथा सी16 सी18 का सम्मिश्रण होता है का प्रयोग भी समान अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। सी 14 पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सी12 सी14 सम्मिश्रण का एक भाग होता है।

घ.10 यह विचार करना भी संगत होगा कि वसीय अल्कोहलों का प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट और निजी देखभाल उत्पादों में 10 प्रतिशत से भी कम होता है। विभिन्न सम्मिश्रणों में वाणिज्यिक/ तकनीकी अंतरनिमेयता होती है। अन्तिम उत्पाद का प्रमुख गुणधर्म वसीय अल्कोहलों से प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि यह अन्य सामग्री के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है।

घ.11 याचिकाकर्ता तलोजी इकाई में लगी प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इस प्रक्रिया द्वारा वाणिज्यिक रूप से नारियल अल्कोहल के रूप में ज्ञात उत्पाद, जो सी8 से सी 18 का सम्मिश्रण है, का उत्पादन किया जा सकता है। प्रभाजन आसवन की प्रक्रिया द्वारा सी8 से सी 18 के किसी प्रभाजन को किया जा सकता है।

घ.12 याचिकाकर्ता ने सी10 की बिक्री उत्पाद कर शुल्कों का भुगतान करके की है।

ड. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरण : (उन हितवद्ध पक्षकारों के बारे में, जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया, पुनरावृत्ति से बचाने के लिए जांच शुरूआत के पश्चात किए गए प्रस्तुतियों में शामिल किए गए बिन्दुओं के अलावा संगत बिन्दुओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है)।

ड.1 काविन केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 5 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत निम्नलिखित लिखित प्रस्तुतिकरण किया गया :

(क) एसएलईएस के लिए प्रमुख कच्चा माल बसीय अल्कोहल (सी12-14) है शैम्पो फार्मुलेशनों का प्रमुख संघटक होता है। बसीय अल्कोहलों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण 50 पैसे वाले शैम्पो की श्रेणी अव्यवहार्य बना देती है जिसके कारण भारतीय बहुसंख्य बाजार स्वस्थ केयर वाश को कम कर देगी।

(ख) यह घरेलू कंपनियों को सहयोग देने की वर्तमान सरकार की वचबद्धता के विपरीत होगा।

ड.2 इंडोनेशिया की सरकार द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

(क) अभिनव माह के आंकड़े आयातों में आकस्मिक तीव्र, अथवा भारी वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, वृद्धि की दर में अप्रैल, 2014 में कमी आ गई। जांच की अवधि भी यह विश्लेषण करने के लिए बहुत कम है।

(ख) महानिदेशक रक्षोपाय शुरूआत में इस बात से सहमत हो गए कि एफटीए के अंतर्गत प्रशुल्क में कमी एक पूर्वाभाषी विकास था। किसी अनपेक्षित विकास की स्थापना बाद में यह कहकर नहीं की जा सकती है कि आयातों में असाधारण गति और अप्रत्याशित उद्रेक प्रत्याशित नहीं था।

(ग) गंभीर क्षति का मानक बहुत अधिक उच्च एवं श्रम साध्य है। चूंकि (i) संवर्धित आयात नहीं हुए हैं (ii) वीवीएफ के निष्पादन की जांच निर्यात निष्पादन के आधार पर करनी है और (iii) वीवीएफ की घरेलू बिक्रियां और अन्य भारतीय एफओएच उत्पादकों की बिक्रियां संगत रूप से स्थिर थी, इसलिए गंभीर क्षति को पूरा करने वाला मानक पूरा नहीं होता है।

(घ) क्षति के संकेतकों और आयात प्रवृत्ति के बीच जांच का समानांतर मूवमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में कारणात्मक संबंधों का विवशकारी विश्लेषण द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

(ङ) एक निर्यातोन्मुख इकाई होने के कारण वीवीएफ की घरेलू बिक्रियां पूर्णतया इसके निर्यात निष्पादन पर आधारित हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि शुरूआत में निर्यात मात्रा घरेलू बिक्रियों की तुलना में बहुत अधिक थी; जिसमें बाद में भारी गिरावट आ गई जिससे वीवीएफ का समग्र निष्पादन प्रभावित हुआ। तथापि, यह एक स्वतः अनुप्राणित क्षति थी और यह एफओएच के आयातों से असंगत थी क्योंकि वीवीएफ ने घरेलू बिक्रियों के बजाय निर्यात पर अधिक बल दिया।

(च) रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग अच्छी तरह से व्यापारीकृत वस्तु पर किया जाता है और करार में क्रियान्वयन के अधिक उच्चतर मानदंडों की अपेक्षा की जाती है। रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग केवल असाधारण प्रकृति की आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। वर्तमान जांच में ऐसी कोई असाधारण प्रकृति नहीं देखी जाती है।

ड.3 मैसर्स कुसा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

यह लुब्रिकेंट/सर्फैक्टेंट एडिटिव का विनिर्माता है और बसीय अल्कोहल का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करता है।

(क) इन एडिटिव्स का भारत-आशिया विदेशी व्यापार करार के कारण दक्षिणपूर्व एशियाई देशों से शुल्क मुक्त आयात किया जा रहा है। इस शुल्क के कारण एक विलोमित शुल्क ढांचा सृजित हो जाएगा।

(ख) घरेलू उद्योग (वीवीएफ और गोदरेज) ने कभी भी भारतीय बाजार पर प्रकाश नहीं डाला। कुसा अपने आरएम की खरीद गोदरेज से तब तक करता रहा जब तक उन्होंने उसका विनिर्माण रोक देने का निर्णय नहीं कर लिया और उसके बाद फिर उसने वीवीएफ से खरीद करना प्रारंभ किया जो उसकी मासिक मात्रा की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ थे, इस कारण उन्हें वैकल्पिक आयात आपूर्तिकर्ता को ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(ग) रोजगार और निवेश जोखिम पर है।

- (घ) एक बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी अनुप्रवाही उद्योग को अब गैर-प्रतिस्पर्धी होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रक्षोपाय शुल्क अनुप्रवाही उत्पादों का आयात करने को अधिमानता देगा और हमारे निर्यातों को भी क्षति पहुंचेगी। यह वर्तमान सकार की स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की नीति के विपरीत है।

ड.4 मैसर्स पीटी मुसिम मास द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) प्राधिकारी जांच की अवधि अर्थात् वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक संपूर्ण कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित पैरामीटरों की प्रवृत्तियों की जांच करने में असफल रहे हैं। इसकी जांच केवल 5 माह की अवधि के लिए की गई है जिससे रक्षोपाय संबंधी करार और भारतीय रक्षोपाय नियमावली का उल्लंघन होता है क्योंकि चुनिंदा जांच विधिक रूप अनुमेय नहीं है और इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि संवर्धित आयात गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं।
- (ख) आयातों में वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक नहीं है आयातों में यह वृद्धि डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के साथ पठित गाट 1994 के अनुच्छेद XIX :1 (क) और भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ग) के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख (1) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप आयात सिद्ध नहीं होता है।
- (ग) संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर जांच की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, इसलिए आयातों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और वर्तमान जांच के परिणामस्वरूप रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण विधिक रूप से अननुमेय होगा।

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616
प्रवृत्ति	100	172	257	290
पिछले वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि	--	72%	50%	13%

- (घ) प्राधिकारी ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति उठानी पड़ रही है या गंभीर क्षति की चुनौती का सामना कर रहा है।
- (ङ) घरेलू उद्योग की बिक्री, जांच की अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग और मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में अपरिगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।
- (च) घरेलू उद्योग की स्थिति में भारी समग्र परिक्षपयण का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और इसलिए इस मामले में डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(क) और अनुच्छेद 4.2(क) और सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(6)(ग) तथा भारतीय रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के पैराग्राफ 1 के आशय के अंतर्गत "गंभीर क्षति" की उच्चतम सीमा सिद्ध नहीं होती है।
- (छ) गंभीर क्षति की चुनौती का दावा किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं होता है और वर्ष 2013-14 में आयातों में केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि अप्रैल, 2014 में आयातों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई।
- (ज) संवर्धित आयातों और कथित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध सिद्ध नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातोंमुखी पर अधिक बल देने घरेलू बाजार में समान की बिक्री करने के लिए घरेलू उद्योग पर अधिरोपित प्रतिबंध और घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में कमी जैसे कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तरदायी बताया गया है।
- (झ) संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि आशियान भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) के अंतर्गत भारत द्वारा प्रदान कराई गई प्रशुल्क रियायतों के कारण हुई है। भारत द्वारा दी गई ये रियायतें एफटीए के अंतर्गत की गई ठोस प्रतिबद्धताएं हैं और उसे "अनपेक्षित विकास" नहीं कहा जा सकता है।
- (ञ) समायोजन योजना चिंता का विषय है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को अपना पुनर्संठन करने में क्षति सहन करनी पड़ेगी क्योंकि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चे माल का उत्पादन मलेशिया और इंडोनेशिया में किया जाता है।

- (ट) रक्षोपाय शुल्क जनहित में नहीं है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं है क्योंकि उसका अनुप्रवाही उद्योगों और प्रयोगों पर प्रभाव पड़ेगा और संबद्ध वस्तु की मात्रा में संभावित गिरावट आएगी क्योंकि विदेश व्यापार नीति द्वारा घरेलू उद्योग पर अधिरोपित प्रतिबंधों के कारण वह केवल घरेलू बाजार में ही बिक्री कर सकता है।

ड.5 मैसर्स पीटी एवरग्रीन ओलियो कैमिकल्स, इंडोनेशिया इस दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण अधूरी जांच पर आधारित था क्योंकि महानिदेशक रक्षोपाय ने प्रारंभिक निर्धारण में दो नई जांच अवधियों अर्थात् दिसम्बर, 2013 – अप्रैल, 2014 और वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही से वर्ष 2014-15 की तृतीय तिमाही का वार्षिकीकृत आधार पर स्थापित करके केवल संवेदनशील परिस्थितियों की ही जांच की है और उन्होंने रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5 में अपेक्षित अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।
- (ख) ऐसे किसी संवर्धित आयात का साक्ष्य नहीं दिया गया है जो अभिन्न, अचानक, तीव्र एवं बहुत अधिक हो। (अर्जेन्टीना आयात फुटवीयर डब्ल्यूटी/डीएस121/आर)।
- (ग) आयात एवं अनपेक्षित विकास के बीच गाट 1994 के अनुच्छेद XIX :1(क) के अनुसार कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफलता। प्रशुल्कों कमी स्पष्टतः एक अनपेक्षित विकास है क्योंकि यह सरकारों के बीच वार्ताओं पर आधारित है।
- (घ) गंभीर क्षति का कोई साक्ष्य नहीं। आयात में अप्रैल, 2014 में 16 प्रतिशत की कमी आई, याचिकाकर्ता ने निर्यातोन्मुख इकाई के अंतर्गत प्रचालन किया जिसके लिए इसकी बिक्री में निर्यात पर बल दिया गया और इसकी घरेलू बिक्री की मात्रा पूर्णतया इसके निर्यात निष्पादन पर आधारित है और निर्यात बिक्री मात्रा घरेलू बिक्री मात्रा से बहुत अधिक थी। याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां, क्षमता, क्षमता उपभोग, उत्पादन, लाभ एवं हानि, बाजार हिस्सा की प्रयोजन मूलक ढंग से जांच भारत में एफओएच के आयातों के बजाय याचिकाकर्ता के निर्यात निष्पादन के आधार पर की जा सकती है।
- (ङ) आयात एवं याचिकाकर्ता के निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंधी नहीं।
- (च) गैर-श्रेयकरण कारक विश्लेषण के संबंध में कोई उपयुक्त एवं तर्कसंगत विश्लेषण नहीं दिया गया। आयातों का याचिकाकर्ता के निष्पादन के साथ कोई सह-संबंध नहीं है क्योंकि यह पूर्णतया निर्यात बिक्री के निष्पादन पर निर्भर है।

ड.6 मैसर्स र्होडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड – साल्वे ग्रुप द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) लारिल अल्कोहल्स पर 20 प्रतिशत के प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क से उद्योग के लिए प्रतिविलोमत शुल्क ढांचा प्रारंभ होगा और तद्वारा उत्पन्न अवकलज वाणिज्यिक रूप से घरेलू बाजार में सस्ते आयातों की तुलना में अव्यवहारों हो जाएंगे।
- (ख) प्रस्तावित शुल्क से हथाक्सीलेट्स और अवकलजों के आयात में उद्रेक आएगा तथा मूल्यवर्धन भारत से बाहर चला जाएगा। इससे रोजगार में क्षति होगी और भारत सरकार को राजीव का नुकसान होगा।
- (ग) उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारत में संयंत्र में आरईएनआर 200 करोड़ रुपए की निवेश योजना की समीक्षा की जाएगी क्योंकि प्रस्तावित शुल्क से निवेश अनावश्यक हो जाएगा। भारत में होने वाला भावी निवेश दक्षिण एशिया में अन्य साल्वे निकायों को अंतरित हो जाएगा।
- (घ) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान वीवीएफ के अधिवक्ताओं का यह तर्क पूर्णतया गलत है कि दक्षिण एशिया में इथाक्सीलेशन के लिए कोई क्षमता नहीं है क्योंकि उसके लिए सिंगापुर में शेल एंड साल्वे की भारी क्षमता है जिसके मार्च, 2015 तक मुख्य धारा में आने की संभावना है।

ड.7 मैसर्स स्टर्लिंग आक्जीलरीज प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

- (क) हमारे उद्योग के लिए प्रतिलोभित शुल्क ढांचा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी जाएगी क्योंकि जिन वस्तुओं का हम विनिर्माण करते हैं उनका आयात करना अंतिम प्रयोक्ता के लिए अधिक आकर्षक हो जाएगा।

- (ख) वीवीएफ एवं गोदरेज ने भारतीय बाजार पर कभी बल नहीं दिया। वीवीएफ के साथ व्यवसाय करा असंभव था क्योंकि उनकी कीमतें उच्च थीं और उनका मुख्य बल हमेशा निर्यातों पर रहा और उन्होंने घरेलू क्रेताओं की हमेशा अन्देखी की।
- (ग) रोजगार एवं निवेश जोखिम में है।
- (घ) वीवीएफ द्वारा दिए गए आंकड़ों में फेरबदल किया गया क्योंकि वे अपने माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने में सफल रहे जबकि घरेलू ग्राहकों को हमेशा उनकी उच्चतर कीमत निर्धारण नीति से समझौता करना पड़ा, इसलिए उनके अनुबद्ध वसीय अल्कोकलों का इथाक्सीलेट्स, सल्फोनेडस आदि की घरेलू आपूर्तियों के लिए प्रयोग करना अर्थक्षम नहीं रहा।
- (ङ) दक्षिण पूर्व एशिया में इथाक्सीलेट्स की बहुत क्षमता है जो रक्षोपाय शुल्क का क्रियान्वयन करने के साथ ही भारत आना प्रारंभ हो जाएगा, इससे हमारे उद्योग पर प्रतिलोभित शुल्क ढांचा सृजित होगा।

ड.8 मैसर्स विश्वाट कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण से प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होता है जिससे घरेलू विनिर्माण की तुलना में आयात को सुलभता प्राप्त होती है और यह कार्रवाई विनिर्माण का संवर्धन करने के सरकार के उल्लिखित आशय के विपरीत है क्योंकि मौजूद निवेश के समक्ष काफी चुनौतियां हैं।
- (ख) वीवीएफ एवं गोदरेज ने कभी भी भारतीय बाजार पर फोकस नहीं किया। गोदरेज फैटी अल्कोहल 1214 काफी पहले से ही भारतीय बाजार में आपूर्ति करना बंद कर दिया था। वे सीटों स्टियरायल अल्कोहल 1618 केवल तभी पेश करते हैं जब उनके पास उसका बेशी स्टॉक होता है। वीवीएफ एलए 1214 और सीटो स्टियरायल की पेशकाश तभी करता है जब उनका निर्यात नहीं होता है। इस शुल्क का अधिरोपण केवल एक उद्यमी को अनुचित लाभ पहुंचाता है जो दूसरे उद्यमी की बाजार में पैर फैलाने के लिए 20 प्रतिशत लाभ का प्रयोग करता है।
- (ग) रोजगार और निवेश खतरे में है।
- (घ) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण ने अनुप्रवाही उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनने के लिए मजबूर कर दिया और इसने एक ऐसे विनिर्माण उद्यम, जिसे सरकार संवर्धन कर रही है, की कीमत पर व्यापारिक माहौल सृजित किया है।
- (ङ) वीवीएफ के अधिवक्ता द्वारा गलत सूचना प्रस्तुतिकरण क्योंकि एसएलएस, एसएलईएस और इथाक्सीलेट्स निर्यात दक्षिण एशियाई देशों से भारत को होना पहले से ही प्रारंभ हो गई।

ड.9 मैसर्स यूनीडस द्वारा दिनांक 95 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

यूनीडस सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल्स (एसएफए) और एसएफए से बने परिष्कृत उत्पाद की पेशकश करता है जिसका विभिन्न उद्योगों में अंतिम प्रयोग किया जाता है। इनमें से अधिकांश अंतिम उत्पादों पर 0 से 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है जबकि एसएफए मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत शून्य शुल्क दर पर उपलब्ध होता है।

- (क) 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करते हुए दिनांक 28 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 03/2014-सीमाशुल्क (एसजी) से एक नया प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होगा जिससे इथाक्सीलेट्स और सल्फोनेट्स के दक्षिण पूर्व एशिया और मध्यपूर्व से आयात में वृद्धि होगी।
- (ख) इस ट्रेकोनियन रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर में 2 निर्यातोन्मुख इकाइयों की कीमत पर कई कुशलतापूर्वक कर भुगतान करने वाले घरेलू उद्योग नष्ट हो जाएंगे।
- (ग) इससे निम्नलिखित परिणाम भी निकलेगा :
 - (i) मूल्य वर्धित विशेषज्ञता रसायन विनिर्माण का भारत से बाहर अंतरण
 - (ii) उच्च दक्षता प्राप्त मानव शक्ति रसायनिक और इंजीनियरों के रोजगार को क्षति
 - (iii) चूंकि हम आधारभूत एसएफए के बजाय उच्चतर मूल्यवर्धित उत्पाद का आयात करेंगे इससे हमें विदेशी विनिर्माण का घाटा होगा
 - (iv) एमएमजीसी – जैसे शैम्पो, टूथपेस्ट, फेशवाश आदि के मास मार्केटपर मुद्रास्फीति जैसा प्रभाव
 - (v) भारत में विशेषज्ञता रसायनों में भावी निवेश में भारी कमी।
- (घ) यह शुल्क वर्तमान सरकार की अभिकथित नीति "मेक इन इंडिया" को काफी हद तक नष्ट कर देगा।

ड.10 मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड, मैसर्स विल्लमर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, मैसर्स के एल केपांग ओलियोमास एसडीएन पीएचडी और मैसर्स गैलेकसी सर्फैक्टेंट्स द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) जांच शुरुआत अधिसूचना में यह सूचना दी गई वर्ष 2010-11 की अवधि के आंकड़ों का जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में माना जाएगा। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम दिसम्बर, 2013 से लेकर अप्रैल 2014 तक के आंकड़ों पर आधारित है।
- (ख) महानिदेशक रक्षोपाय ने जांच शुरुआत के लिए चुनी गई जांच अवधि की अनदेखी की है और "संवेदनशील परिस्थितियों" की जांच करने के लिए नई अवधि को अपनाया है जो सही नहीं है।
- (ग) न तो भारतीय रक्षोपाय विधि और न ही रक्षोपाय संबंधी करार में अनंतिम निर्धारण करने के लिए पृथक आंकड़ों पर विचार करने, संवेदनशील परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए पृथक आंकड़ों पर विचार करने का प्रावधान है। जांच की अवधि के लिए ही आंकड़ों एवं सूचना की जांच की जानी चाहिए। संवेदनशील परिस्थितियों के नाम पर पूरी तरह से नए आंकड़ों को नहीं अपनाया जा सकता है।
- (घ) जांच के लिए चुनी गई समस्त अवधि असामान्य है क्योंकि आयात दिसम्बर, 2013/मध्य जनवरी, 2014 में असामान्य रूप से कम होंगे और तत्पश्चात असामान्य रूप से उच्चतर हो जाएंगे।
- (ङ.) अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की घोषणा करने के लिए संवेदनशील परिस्थितियां अपर्याप्त हैं।
- (च) यह दर्शाने के लिए स्पष्ट साक्ष्य की जरूरत है कि संवर्धित आयातों ने गंभीर क्षति कारित की गई है/गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 के अनुसार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए पूर्ववर्ती स्थितियों का निर्धारण करना अनिवार्य है। तथापि, महानिदेशक, रक्षोपाय ने प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 17.3 में गंभीर क्षति की मौजूदगी की जांच करने के बजाय केवल यह जांच की है कि क्या संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। वर्तमान मामले में विधि में यथा-अपेक्षित प्रारंभिक निर्धारण हुआ ही नहीं है।
- (छ) तिमाही से तिमाही का विश्लेषण गलत है। वस्तु की कीमत को कच्चे माल सीपीओ की कीमत से सीधे जोड़ दिया गया है और उसमें कई घटाव/बढ़ाव के परिणामस्वरूप वस्तु की कीमतों में घट/बढ़ होगी। इसलिए तिमाही से तिमाही विश्लेषण करना तर्कसंगत नहीं है।
- (ज) प्रारंभिक जांच परिणाम एक तर्कसंगत आदेश नहीं है क्योंकि यह प्रतिवादियों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देने में असफल रहा है और उस तर्क को प्रकट करने में असफल रहा है जिससे निर्धारण किया गया है।
- (झ) महानिदेशक रक्षोपाय अनपेक्षित विकास और प्रतिबद्धताओं के प्रभाव का सही आशय समझने में असमर्थ रहे हैं और उस विकास के संबंध में कोई परिणाम नहीं है जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई है।
- (ञ) गाट 1994 के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत "डब्ल्यूटीओ के एक दायित्व के रूप में प्रशुल्क में कमी के कारण आयातों में वृद्धि" की जांच नहीं की गई है। भारत ने वस्तु पर 7.5 प्रतिशत प्रशुल्क में एकपक्षीय रूप से कमी की है और कमी गाट के अंतर्गत बाध्यताओं के कारण नहीं की गई है। यह एक नीति अपेक्षा थी यदि आयातों में वृद्धि स्वतः स्फूर्त नीतिगत पहल के कारण हुई है तो रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (ट) घरेलू उद्योग की डीटीए में आपूर्ति करने की हकदारी एवं क्षमता की जांच नहीं की गई है।
- (ठ) आवेदक घरेलू उत्पादक "घरेलू उद्योग" का हिस्सा नहीं बन सकता है क्योंकि यह एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है।
- (ड) महानिदेशक रक्षोपाय ने इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि क्या आवेदक घरेलू उत्पाद अपनी वस्तु की डीटीए में बिक्री करके और एनएफई अर्जित करके मांग को पूरा कर सकता है। याचिकाकर्ता की डीटीए हकदारी मूल्य वर्धन पर निर्भर है। यदि घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री की जाती तो सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं होता।
- (ढ) यह नहीं दर्शाया गया है कि भारतीय बाजार को कितनी गंभीर क्षति हुई है क्योंकि आवेदक उत्पादक एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है और कच्चे माल का आयात पुनः निर्यात करने के लिए किया जाता है न कि डीटीए में बिक्री करने के लिए। आवेदक उत्पादक भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है।
- (ण) कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। ईयू ने वीवीएफ पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया, उसके परिणामस्वरूप वीवीएफ को घाटा एवं क्षति हुई।
- (त) वीवीएफ ईओयू स्टेट्स के कारण प्रतिस्पर्धी नहीं है। वीवीएफ के पास डीटीए में बिक्री के कारण बहुत सीमित क्षमता है और उसे डीटीए में बिक्रियों पर गैर-उत्पाद कर योग्य सीमाशुल्क का अतिरिक्त बोझ सहन करना पड़ा है। चूंकि सीमाशुल्क में छूट नहीं दी जा सकती है, इसलिए डीटीए में अतिरिक्त लागत बनती है।
- (थ) वीवीएफ को विनिमय लाभ/घाटा सहन करना पड़ा है।
- (द) चूंकि कोई व्यवहार्य समायोजन योजना नहीं है, इसलिए शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।

- (ध) वसीय अम्ल के भिन्न लंबाई की कार्बन श्रृंखला अपने में भिन्न उत्पाद हैं और उनकी जांच अलग-अलग की जानी चाहिए थी। जहां बहुत उत्पाद प्रकारों को एक उत्पाद प्रकार में शामिल कर दिया जाता है वहां सही विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक उत्पाद प्रकार का पृथक् विश्लेषण किया जाए।
- (न) वीवीएफ ने उच्चतर क्षमता उपयोग का दावा किया है कि महानिदेशक रक्षोपाय ने उसे एक-चौथाई तक कम कर दिया है।
- (प) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना एसएलईएस/एसएलएस उत्पादकों तथा अनुप्रवाही उपभोक्ता उद्योग के लिए हानिकारक होगा।
- (फ) वीवीएफ ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जबकि उन्होंने उसके लिए उन्होंने कोई औचित्य नहीं दिया है। अन्य हितवद्ध पक्षकारों की सूचना पर भरोसा करके दिए गए अधिसूचना में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया है।

ड.11 मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :-

- (क) वसीय अम्ल और ग्लिसरीन सह-उत्पाद होने के कारण आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। वसील अम्लों के प्रापण की लागत और वसीय अम्लों की अंतरण लागत को उच्चतर लागत और गैर क्षतिकारी कीमत के लिए अधिक नहीं बताना चाहिए। लागत का निर्धारण और घरेलू एवं निर्यात विक्रियों के लिए लगाई गई पूंजी को स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया जाना चाहिए।
- (ख) घरेलू उत्पादन पर विचार केवल मानद निर्यातों को कम करके ही किया जाना चाहिए जिससे बढ़े हुए एवं अशुद्ध आंकड़ों (जैसे कि वे इस समय हैं) से बचा जा सके।
- (ग) क्षति विश्लेषण वार्षिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किए बिना किया गया है और इस प्रकार यह परम्परा के विपरीत एवं स्वेच्छाचारी है। आयातों में वृद्धि, जैसी कि वार्षिक आंकड़ों से दर्शायी गई है, न तो आकस्मिक है, न ही इतनी संवेदनशील कि उसके लिए तत्काल शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित था।
- (घ) प्रशुल्क में कमी करने की प्रकल्पना पहले ही कर ली गई थी और उसे अनपेक्षित विकास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश की क्षमता में वृद्धि गाट के अंतर्गत भारत के कर्तव्यों का प्रभाव नहीं है और यह आयातों के लिए अनपेक्षित विकास के रूप में असंगत है।
- (ङ.) वीवीएफ ने दावा किया है कि समायोजन योजना में उत्पादन लागत के रूप में कोई भी लाभ व्युत्पन्न नहीं हैं। केवल स्वीकार किए गए सेट-आप्स इंडोनेशियाई अनुषंगी से जुड़े हैं, जो सकारात्मक समायोजन की संकल्पना के विरुद्ध है। समायोजन योजना, वहां तक यह विदेशी क्षेत्राधिकार (इंडोनेशिया) की निर्यात नीति से प्रासंगिक है, संधारणीय नहीं है।
- (च) शुल्क में इस कीम का कोई लाभ वसीय अम्लों के उपभोक्ताओं/अंतिम प्रयोक्ताओं को नहीं हुआ। एक उपभोक्ता के लिए किसी निर्यातोन्मुख इकाई से खरीद करना डीटीए इकाई से खरीद करने की तुलना में अधिक महंगा है।

विवरण (आईएनआर)	निर्यातोन्मुख इकाई	डीटीए
कच्चा माल	100	100
संपरिवर्तन लागत	50	50
लाभ	15	15
सीवीडी/उत्पाद कर	10	10*
कीमत	175	175
सीमा शुल्क	3.5%	शून्य
घरेलू बिक्री कीमत	181.12	175

*बिक्री कीमत पर आधारित होने के लिए परिकल्पित

- (छ) ईयू द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से वीवीएफ के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा है जिसका घरेलू बाजार में इस उत्पाद की उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ा है। यदि निर्यातोन्मुख इकाई और डीटीए बाजार में बिक्री प्रापण समान रहता तो यह अस्वीकार किया जा सकता था कि वीवीएफ को हुई क्षति प्राथमिकता डीटीए बिक्रियों से हुई है।
- (ज) वीवीएफ द्वारा प्रदर्शित की गई लागत और बिक्री बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही प्रयोक्ताओं के लाभ में कमी आएगी जिससे उसकी कीमत में वृद्धि होगी और उसे उपभोक्ताओं वे वसूला जाएगा।
- (झ) यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो भारत में अवकलज उत्पादों का विनिर्माण करना अर्थक्षम नहीं होगा, क्योंकि उनका भारत में आयात बिना किसी सीमाशुल्क के किया जा सकता है।
- (ञ) वैकल्पिक रूप से, आयातों में उद्रेक का प्रतिरोध करने के लिए आशियान सीईसीए के अंतर्गत उपलब्ध विशिष्ट रक्षोपाय उपचार की सिफारिश करनी चाहिए।

ड.12. मैसर्स मेजरहब ओलियोकैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 04.09.2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) मेजरहब ने गोदरेज को तस्वीर के पीछे रखने की कभी सिफारिश नहीं की; वास्तव में उन्होंने सूचना प्रदाता से अनुरोध किया कि वह गोदरेज से प्रश्न करें। यह सत्यापित कैसे होगा कि किसी नोटिस में जहां गोदरेज इंडस्ट्रीज को आयातक के रूप में नहीं माना गया है वहां इस तथ्य का सत्यापन क्या है कि आयात के आंकड़ों में फेरबदल नहीं की गई है। नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने या तो गोदरेज को छुपा दिया है या वह बड़ी शीतिर टीम है।
- (ख) आवेदक ने वसीय अल्कोहलों का आयातों को अनुबिद्ध एवं अननुबिद्ध अल्कोहल के रूप में उप-विभाजन किया है। इसके पीछे कारण उनकी व्यापार की प्रकृति है।
- (ग) मेजरहब एक व्यापारी है। विधि में या इतिहास के अंकों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जहां यह कहा गया हो तो रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के कारण व्यापारी को नुकसान नहीं होगा, परंतु वास्तव में सच्चाई यह कि उन्हें कारित क्षति की कारण उन्हें वैकल्पिक व्यवसाय की तलाश करनी पड़ेगी। हमने महानिदेशक रक्षोपाय को फैक्टरी कामगारों की संख्या में कमी होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- (घ) वित्त मंत्री ने अपने बजट में इस प्रकार के रक्षोपाय शुल्क के पक्षपातपूर्ण उदग्रहण के उदाहरण दिए हैं। जहां साबुन और ओलियो रसायनों के लिए कच्चे माल पर लेवी को कम करके शून्य प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं यदि गैलेक्सी के लिए लेवी में वृद्धि की जाती है तो यह (बड़े उद्योगों में कच्चे माल के संबंध में भी) अनुचित नहीं होगा (जहां बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों की तुलना में अधिमानी दर्जा दिया गया है।

ड.13. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) शुल्क का अधिरोपण करने से गोदरेज को लाभ होगा जो वसीय अल्कोहल के दो घरेलू विनिर्माताओं में से एक विनिर्माता है और जिसे एसएलएस और एसएसईएस के अन्य विनिर्माओं की तुलना में अधिक लाभ होगा।
- (ख) आरती उद्योग की प्रमुख बिक्री घरेलू बाजार में होती है और उनकी अतिजीविता खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उन्हें भारी क्षमता वाला अपना संयंत्र केवली छोटी सी निर्यात बाजार के सहारे चलाना आर्थिक रूप से क्षतिकर हो जाएगा।
- (ग) इसका निवेश और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ड. 14 मैसर्स मातंगी इंडस्ट्रीज द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) उनके उत्पाद वसीय अल्कोहलों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उत्पादों का विभिन्न मुक्त व्यापार करार लागू होने के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। प्रतिलोमित शुल्क ढांचे के कारण, उन्हें कच्चे माल का आयात करने के लिए भारी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे।
- (ख) घरेलू उद्योगों (वीवीएफ और गोदरेज) ने कभी भी भारतीय बाजार पर फोकस नहीं किया।
- (ग) रोजगार और निवेश खतरे में है।
- (घ) अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अनुप्रवाही उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रक्षोपाय शुल्क आयात प्रतिस्थापितियों को अधिमानता प्रदान करेगा और वर्तमान सरकार की स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की नीति के विरुद्ध है।

ड.15 घरेलू उद्योग (मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा अपने दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

क. शुल्क का उदग्रहण करने के लिए पूर्वापेक्षाएं पूरी होती हैं

गाट 1994 के अंतर्गत रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आधारभूत अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :

- (i) इन उत्पादों का आयात, घरेलू उत्पादन के संगत या समग्र रूप में संवर्धित मात्रा में किया जा रहा हो।
- (ii) यह आयात ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किए जाते हों कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो या उनसे गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।
- (iii) समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग की मौजूदगी।

म्युनिसिपल विधि के अंतर्गत अधिनियम की धारा 8ख (1) में इस निर्धारण के आधार पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है कि इस उत्पाद का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने यह निर्धारण होना चाहिए कि :

- याचिकाकर्ता का "समान वस्तु" के "घरेलू उद्योग" के रूप में आधार हो।
- आयातों में उद्रेक हो
- इन संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा क्षति कारित न की जा रही हो।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि याचिकाकर्ता शुल्क का दीर्घ अवधि के लिए अधिरोपण करने के आवेदन के साथ एक समायोजन योजना भी प्रदान करेगा। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामलों में उपर्युक्त सभी अपेक्षाओं को पूर्णतया पूरा किया गया है और याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि निर्णायक शुल्क का उदग्रहण करने के लिए निर्धारण किया जाए।

ख. घरेलू उद्योग – याचिकाकर्ता का "समान वस्तु के घरेलू उद्योग" के रूप में आधार

समान वस्तु को रक्षोपाय नियमावली के नियम 2 के उप-नियम (ड.) के अंतर्गत "एक वस्तु जो जांच के अधीन वस्तु से सभी तरह से समान या समरूप हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। आयातित एवं स्वदेशी रूप से उत्पादित उत्पाद के बीच पूर्णतया वाणिज्यिक एवं तकनीकी अंतर्निमेयता है। आयातित उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के बीच आधारभूत समानताएं निम्नलिखित हैं :

- (i) सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, या सी18 की लंबाई के कार्बन चैनयुक्त अनुबिद्ध वसीय अल्कोहलों और उनके ब्लेंडों के बीच साझा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म हैं।
- (ii) दोनों ही उच्च दाब एवं उच्च ताप हाइड्रोजनीकरण पर उत्पन्न होते हैं अर्थात् विनिर्माण प्रक्रिया और प्रयोग की गई तकनीक समान है।
- (iii) उनका प्रयोग प्राथमिकतः सर्फेक्टेन्ट्स का विनिर्माण करने, व्यक्तिगत मामलों के लिए, होमकेयर, वस्त्र अनुषंगी अनुप्रयोगों के लिए अर्थात् उनके कार्य एवं प्रकार्य समान हैं।
- (iv) एकल अनुबिद्ध वसीय अल्कोहल या समान/समरूप कार्बन चैन लंबाई के ब्लेंडों अर्थात् उनके उत्पाद विनिर्देशन समान हैं।
- (v) उनकी बिक्री साझा प्रयोक्ताओं और डीलरों को की जाती है अर्थात् उनके लिए समान बाजार हैं।
- (vi) शीर्ष 2905.17 या 3823.70 के अंतर्गत कवर होते हैं अर्थात् उनका एचएसएन वर्गीकरण समान है।

अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान नियमावली के अंतर्गत आयातित वस्तु के "समान वस्तु" है। याचिकाकर्ता भारत में "समान वस्तु" के कुल उत्पादन के बड़े हिस्से (लगभग 65 प्रतिशत) का उत्पादक है। यह एक सुस्थापित स्थिति है कि "बड़े अनुपात" या "बड़े हिस्से" का आशय अधिकता से नहीं है कि बल्कि केवल एक भारी या महत्वपूर्ण हिस्से से है। इस संदर्भ में लुब्रीजाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2005 (187) ईएलटी 402 के अंतर्गत की गई थी, दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है। घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 65 प्रतिशत है और इसलिए वह घरेलू उद्योग के रूप में योग्य है।

ग. आयातों में उद्रेक

ग. i. वसीय अल्कोहलों का आयात पहले से ही बहुत अधिक है और उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। आयातों का विवरण निम्नलिखित है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616	79957
प्रवृत्ति	100	172	257	290	403

*अप्रैल-जून, 2014 पर आधारित

ग. ii. आयातों में यह वृद्धि भारी दर पर जारी रही। वर्ष 2010-11 (आधार वर्ष) की तुलना में वर्ष 2013-14 में आयातों की प्रमात्रा में तीन गुना वृद्धि हुई है। आयातों में मांग के संगत रूप में और समग्र रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, मात्रा एवं दर दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। आयातों में समग्र वृद्धि के अलावा घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संगत रूप में भी भारी वृद्धि हुई है।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616	79957
वीवीएफ का उत्पादन	68605	49585	67837	93297	60746
उत्पादन के % के रूप में आयात	29%	69%	75%	62%	132%
प्रवृत्ति	100	238	259	214	455

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

अतः यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संगत रूप में आयातों में वर्ष 2010-11 में 29 प्रतिशत से वृद्धि होकर वर्ष 2013-14 में यह आयात 62 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2014-15 के आंकड़े आयातों में उत्पादन के संगत रूप में 29 प्रतिशत से और अधिक वृद्धि होकर 132 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू उत्पादन अर्थात् निर्यात घटाकर उत्पादन के संबंध में आयातों का विश्लेषण दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक एवं वास्तविक है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात**	60%	118%	226%	247%	610%
प्रवृत्ति	100	197	377	412	1020

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

** (निर्यात घटाकर उत्पादन)

ग.iii. यूएस स्टील रक्षोपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह धारित किया है कि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत "संबंधित आयातों" की अपेक्षा है कि "वृद्धि हो रहे आयातों की। अतः आयातों में जांच की अवधि की समाप्ति तक अथवा निर्धारण के तत्काल पूर्ववर्ती अवधि तक आयातों में हो रही वृद्धि की अपेक्षा नहीं है। परंतु शर्त यह है कि जांच के अधीन उत्पाद का "आयात" जांच की अवधि की समाप्ति पर इतनी अधिक मात्रा में किया जा रहा हो जिससे कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित की जा रही हो। अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं। इस रिपोर्ट का संगत पैरा नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :

"7.207. हमें अपने विचार के लिए अनुच्छेद 2.1 में समर्थन मिला जाता है जिसमें प्रावधान है कि, "ऐसे उत्पाद का इतनी अधिक संबंधित मात्रा में आयात किया जा रहा हो। इस करार में विशेषण "संबंधित" का प्रयोग किया गया है न कि "बढ़ रहे" का। शब्द "संबंधित" का प्रयोग हमें यह संकेत देता है कि इस तथ्य का निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है कि आयातों में इस समय तक वृद्धि हो रही है। बल्कि आयातों में अभिनव विगत में "वृद्धि" हुई हो परंतु उनमें अनिवार्यतः, यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती समय तक वृद्धि हो रही हो बशर्ते कि जांचाधीन उत्पाद का "आयात" जांच की अवधि की समाप्ति पर इतनी अधिक संबंधित मात्रा में हो रहा हो कि उससे अनुच्छेद 2.1 की जरूरत पूरी हो रही हो।

ग. iv. डब्ल्यूटीओ पैनल को पदबंध "संबंधित आयातों" पर यूएस व्हीट ग्लूटेन के संबंध में अपनी पैनल रिपोर्ट में विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त निर्णय का एक उद्धरण निम्नलिखित है :

"1.1. यूएसआईटीसी ने यह प्रेक्षण किया कि आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई (3) और यह पाया कि "वस्तुतः समस्त" वृद्धि वर्ष 1996 और 1997 में हुई। (4) यूएसआईटीसी ने उत्पाद का आयात से अनुपात के संबंध में भी आंकड़ों का उल्लेख किया है जो वर्ष 1993 में 100.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994 में 88.2 प्रतिशत दर्शाता है और यह दर्शाता है कि इसमें वृद्धि होकर यह प्रतिशत 1995 में 89.7 प्रतिशत, 1996 में 139 प्रतिशत और 1997 में 145.4 प्रतिशत था।

1.2 यद्यपि यह आंकड़े घरेलू उत्पादन में समग्र एवं संगत, दोनों रूपों में – जांच की प्रारंभिक अवधि में आयात में गिरावट दर्शाते हैं, परंतु इसके पश्चात वे जांच की अवधि की समाप्ति पर इनमें तीव्र एवं भारी वृद्धि दर्शाते हैं। हम इन आयातों में प्रदर्शित की गई वृद्धि को, यूएसआईटीसी के समक्ष उपस्थित आंकड़ों – में घरेलू उत्पादन के समग्र एवं संगत रूप दोनों में ----- अभिनव, अचानक तीव्र एवं भारी वृद्धि के रूप में मानते हैं।

ग. v. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि 5 वर्षों की अवधि में 38 प्रतिशत की वृद्धि को "संबंधित आयातों" के रूप में माना जाता है। इस मामले में आयातों में वर्ष 2014-15 में 403 प्रतिशत वृद्धि हुई है विगत तीन वर्षों में आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संगत रूप में आयातों में इस वृद्धि में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में मामूली सी गिरावट आई है परंतु यह तब भी बहुत उच्च स्तर पर बना रहा। इसके अतिरिक्त, यह गिरावट आयातों में किसी कमी के कारण नहीं आई थी बल्कि निर्यात विक्रियों में सुधार के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से आई थी।

घ. घरेलू उद्योग को कारित गंभीर क्षति

गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को संगत माना गया है।

घ. i. आयातों में समग्र एवं संगत रूप से वृद्धि की मात्रा एवं दर

आयातों में संपूर्ण अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि उनमें आधार वर्ष की तुलना में 291 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयातों में घरेलू उत्पादन (निर्यात को घटाकर) के संबंध में भी निरंतर वृद्धि हुई है अर्थात् वे 60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 247 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2014-15 में आयातों में वर्ष 2010-11 की तुलना में घरेलू उत्पादन के संबंध में और अधिक वृद्धि हुई तथा आयात बढ़कर 610 प्रतिशत हो गए। आयातों में वृद्धि की यह मात्रा एवं दर, समग्र एवं संगत रूप में, बहुत अधिक है।

घ. ii. घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा

मांग या खपत में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत हो गया और यह वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-11 में बाजार का घरेलू उद्योग एवं आयातों में समान रूप से वितरण था और बाजार में भारतीय उद्योग का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। वर्ष 2011-12 में आयातों में भारी उद्रेक आया और आयातों ने बाजार के 60 प्रतिशत से अधिक पर कब्जा कर लिया। जैसा कि उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है आयातों से वर्ष 2011-12 से निरंतर वृद्धि हो रही है और अब उनका 80 प्रतिशत से अधिक बाजार पर बाजार हिस्सा है। कुल मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री और आयातों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	घरेलू उद्योग की बिक्री	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कुल मांग	बाजार हिस्सा	
					घरेलू उद्योग	आयात
2010-11	19843	17080	8242	45165	38%	44%
2011-12	34142	15285	6677	56104	27%	61%
2012-13	51055	12891	7573	71519	18%	71%
2013-14	57616	14777	8728	81123	18%	71%
2014-15*	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

दूसरी ओर घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई यह वर्ष 2010-11 में 38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 10 प्रतिशत हो गया।

घ. iii. बिक्री के स्तर में परिवर्तन

याचिकाकर्ता की घरेलू उद्योग की प्रवृत्ति निम्नलिखित है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात**	17080	15285	12891	14777	10376
प्रवृत्ति	100	89	75	87	61

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक, खपत के समग्र एवं संगत, दोनों रूपों में निरंतर गिरावट आई है। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में बिक्री में मामूली सा सुधार हुआ परंतु यह वर्ष 2010-11 के स्तर से अभी भी भारी मात्रा में कम बना रहा। बिक्री में इस गिरावट को बाजार हिस्से नाटकीय ढंग से आई गिरावट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जो 38 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई, जबकि आयातों का हिस्सा 44 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत आधार पर) में सर्वाधिक कमी आई। विगत तीन तिमाहियों का विश्लेषण से घरेलू बिक्री में गिरावट की यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है :

	तीसरी तिमाही, 2013-14	चौथी तिमाही, 2013-14	पहली तिमाही, 2014-15
घरेलू बिक्री (एमटी)	3557	2965	2594
प्रवृत्ति	100	83	73

घ. iv. घरेलू उत्पादन

बढ़ती बाजार में इस भारी संवर्धनात्मक मांग को आयातों द्वारा पूरा किया गया है। घरेलू उद्योग को घरेलू मांग में वृद्धि होने से कोई फायदा नहीं हुआ और इसके घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट आई है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
घरेलू उद्योग का उत्पादन (निर्यात को घटाकर)	33319	28974	22560	23303	13065
प्रवृत्ति	100	87	68	70	39

घ. v. उत्पादकता

उत्पादकता में कोई खास अंतर नहीं आया है।

घ. vi. क्षमता उपयोग

क. घरेलू उत्पादन (निर्यात को घटाकर उत्पादन) के लिए क्षमता उपयोग में भी भारी गिरावट आई है।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
क्षमता उपयोग %	28%	24%	19%	19%	11%
प्रवृत्ति	100	86	68	68	39

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ख. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 28 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2013-14 में 19 प्रतिशत रह गया और वर्ष 2014-15 में इसमें और अधिक कमी हुई तथा यह 11 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, निर्यातों को ध्यान में रखते हुए समग्र क्षमता उपयोग में 2013-14 में मामूली सा सुधार हुआ, परंतु इसमें वर्ष 2014-15 में पुनः गिरावट की प्रवृत्ति आ गई।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
क्षमता उपयोग %	57%	41%	56%	78%	51%
प्रवृत्ति	100	72	99	136	89

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ग. इसके अतिरिक्त, विगत तीन तिमाहियों का विश्लेषण भी क्षमता उपयोग में गिरावट को प्रदर्शित करता है

	तीसरी तिमाही, 2013-14	चौथी तिमाही, 2013-14	पहली तिमाही, 2014- 15
क्षमता उपयोग (घरेलू) (%)	19%	15%	11%
प्रवृत्ति	100	79	58
क्षमता उपयोग (कुल) (%)	84%	64%	51%
प्रवृत्ति	100	76	61

घ. vii. लाभ एवं हानि

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में पूरी तरह से समाप्त हो गई। लाभप्रदायकता निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ/हानि	100	-266	-2796	-2232

वर्ष 2011-12 से घरेलू उद्योग की स्थिति में तेजी से गिरावट आ रही है, और बाजार के आकार में वृद्धि होने के बावजूद यह अपनी लागत को वसूल पाने में भी सक्षम नहीं था। समान वस्तु का उत्पादन पूरी तरह से अलाभकर हो गया क्योंकि घरेलू उद्योग को निरंतर भारी घाटा हो रहा था।

घ. viii. रोजगार

यूनिट में रोजगार वर्ष 2010-11 में *** था और वर्ष 2014-15 में *** था। यह वृद्धि कमोवेश रूप से स्पिलिटिंग प्लांट, वसीय अम्ल फ्रैक्सनेशन प्लांट, ग्लिसरीन प्लांट में विस्तार होने और ग्राही विद्युत संयंत्र का प्रतिष्ठापन होने से हुआ है, जिसके लाभ अब प्रारंभ होना शुरू हो गए हैं।

ड. क्षति की चुनौती आसन्न है

सभी संगत पैरामीटर घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यदि शुल्क का अधिरोपण अविलंब नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग जीवित रहने में सक्षम नहीं हो पाएगा। गंभीर क्षति कारित की गई है, जैसाकि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक गिरावट आसन्न है। इस समय आयात उच्च स्तर पर हैं और उनमें वृद्धि हो रही है। यूएस लैम्ब के डब्ल्यूटीओ पैनल में यह धारित किया गया कि "अत्यधिक" उच्च स्तर पर, दीर्घ समयावधि के लिए, और अधिक वृद्धि के बिल, आयातों को गंभीर क्षति की चुनौती माना जाएगा। वसीय अल्कोहलों का

वर्ष 2011-12 से भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में निरंतर गिरावट हो रही है और उसे भारी घाटा हो रहा है। याचिकाकर्ता की अतिजीविता भी खतरे में है, क्योंकि गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है।

च. i. घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गंभीर क्षति के बीच स्पष्ट संबंध है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में आयात उच्चतम सीमा पर थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी, लाभप्रदायकता, निवेश पर अर्जन, घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है जबकि आयात अपनी उच्च सीमा पर थे कतिपय स्रोतों से वसीय अल्कोहलों के आयातों पर शुल्क को दिनांक 01.01.2014 से हटा लिया गया है। इस कमी को प्रत्याशा में तीसरी तिमाही में आयातों में गिरावट आई। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों को अपने पक्ष में रखने में समर्थ रहा। सीमाशुल्क हटा लिए जाने के पश्चात वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में आयातों में भारी वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की स्थिति में और भी अधिक गिरावट आ गई। वर्ष 2010 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही तथा वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के बीच तुलना निम्नलिखित को अभिव्यक्त करती है :

	तीसरी तिमाही 13-14	चौथी तिमाही 13-14	पहली तिमाही 14-15
आयात (एमटी)	13161	18176	19989
प्रवृत्ति	100	138	152
वीपीएफ के उत्पादन के संबंध में आयात (%)	52%	94%	132%
प्रवृत्ति	100	181	254
आयातों का बाजार हिस्सा	70%	76%	80%
प्रवृत्ति	100	109	114
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	19%	12%	10%
प्रवृत्ति	100	63	53

च. ii उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पिछली अवधि की तुलना में अंतिम तिमाही में भारी गिरावट आई है। तीसरी तिमाही में मामूली से सुधार के प्रभाव को वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही और वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आयातों में जनवरी-जून वर्ष 2014-15 में भारी वृद्धि हुई है।

च. iii. इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को आयातों से भारी कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अंतिम तिमाही में भारी कमी आई है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर क्षति कारित की गई है और गंभीर क्षति की और अधिक चुनौती आसन्न है। आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी सिद्ध हो जाता है।

छ. क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों का अभाव

छ. i. घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने वाले अन्य कोई कारक नहीं है। वसीय अल्कोहलों की मांग में विगत तीन वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। मांग में लगभग 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई फिर भी घरेलू उद्योग बाजार में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन, बिक्री या लाभ में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा।

छ. ii. याचिकाकर्ता एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है, इसके कारण इसे डीटीए इकाइयों की तुलना में एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। कच्चे माल (पीकेओ) जैसे पाम गिरी का तेल (जो यथामूल्य 7.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में है) पर सीमाशुल्क परिष्कृत उत्पादों पर लागू शुल्क की तुलना में बहुत अधिक है। चूंकि एक निर्यातोन्मुख इकाई कच्चे माल (पीकेओ) का आयात, शुल्कों का भुगतान किए बिना कर सकती है, और 7.725 प्रतिशत की दर से (जो अब 18 फरवरी, 2014 से 3.86 प्रतिशत हो गया है) शुल्क का भुगतान करके अपने परिष्कृत उत्पाद को क्लीयर कर सकती है, इसलिए निर्यातोन्मुख इकाई पर लागू निवल शुल्क आयातित सामग्री से वसीय अल्कोहलों का विनिर्माण करने वाली डीटीए इकाइयों द्वारा सहन किए जा रहे शुल्क की तुलना में बहुत कम है। निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए शुल्क का ढांचा फायदेमंद है क्योंकि कच्चे माल पर सामान्यतः लगभग 100 प्रतिशत शुल्क होता है। उदाहरण के लिए कोई डीटीए इकाई जो 70/-रुपए मूल्य के कच्चे माल का आयात कर रही है, उसे 70/-रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा जबकि निर्यातोन्मुख इकाई को शुल्क छूट के अंतर्गत बिना किसी शुल्क के भुगतान के कच्चा माल प्राप्त होगा। निर्यातोन्मुख इकाई से क्लीयर समान वस्तु पर 7.725 प्रतिशत शुल्क

प्रभारणीय होगा जो 8/-रुपए से 10/-रुपए की रेंज में होगा। इस प्रकार निर्यातोन्मुख इकाई पर निवल शुल्क डीटीए इकाई पर निवल शुल्क की तुलना में बहुत कम होगा।

छ. iii यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में डीटीए और निर्यातोन्मुख इकाई दोनों को समान दर्जा दिया गया है। पीकेओ कुल उत्पादन लागत का लगभग 2/3 हिस्सा बनता है। खपत की प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे यह सुझाव मिल सके कि इन कारकों द्वारा क्षति कारित की जा रही है। इस मामले में अन्य कोई ऐसी परिस्थितियां या कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को एक साथ ही क्षति कारित हो रही हो और कारणात्मकता की जरूरत को पूर्णतया पूरा किया गया है।

ज. अनपेक्षित परिस्थितियां

ज. i. वैश्विक क्षमताओं में अनपेक्षित विकास – वैश्विक मांग से कहीं अधिक

याचिकाकर्ता यह विश्वास करता है कि वर्ष 2011 से इस संबद्ध वस्तु के लिए वैज्ञानिक क्षमता में 151 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। क्षमता में उक्त वृद्धि में से लगभग 75 प्रतिशत क्षमता विस्तार बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे विल्मर, इकोग्रीन, केएल के पांग मुसी मास आदि द्वारा किया गया है, वे कंपनियां प्रतिभागी निर्यातक हैं जो वर्तमान जांच में शुल्क के उदग्रहण का विरोध कर रही है।

अनुमानित वैश्विक क्षमता

देश	वर्ष 2011 से पहले (एमटी)	वर्ष 2011 के पश्चात (एमटी)
इंडोनेशिया	3,24,000	9,98,000
मलेशिया	4,90,000	5,90,000
फिलीपीन्स	1,80,000	2,80,000
वैश्विक क्षमता	22,70,000	34,27,000

निर्यातक	वर्तमान अनुमानित क्षमता
सासोल/विल्यर जेवी चीन	60,000
विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडोनेशिया	1,50,000
विल्यर हन्ट्समैन जेवी नीदरलैंड्स	1,50,000
इकोग्रीन ओलियो कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	4,04,000
मुसी मास इंडोनेशिया	2,80,000
केएल केपांग ओलियोमास, एसडीएन बीएचडी मलेशिया	2,80,000
थाई ओलियो कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	1,30,000
चीन सान्जयांग फाइन कैमिकल्स चीन	1,30,000
लिआओयांग हैक्सिंग शेनयानंग, चीन	2,20,000
जोड़	18,04,000

ज. ii. इतनी विशाल क्षमता स्थापित कर लेने से बाजार में संबद्ध वस्तु की अधिक आपूर्ति होने होने लगी। केवल दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ही वैश्विक क्षमता के लगभग 60 प्रतिशत क्षमता की स्थापना हुई जबकि इसकी मांग कुल वैश्विक मांग का 7 प्रतिशत से भी कम है। इसके कारण बाजार में भारी जमाखोरी होने लगी।

ज. iii. वसीय अल्कोहल की वैश्विक आपूर्ति में तीव्र एवं आकस्मिक वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजारों की तलाश हुई और मौजूदा तथा भावी बाजारों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। इस संवर्धनात्मक क्षमता का प्रमुख लक्ष्य चीन और भारत में बढ़ती बाजारें थी। विकसित देश में वैश्विक मांग कमावेश से रूप से सैचुरेटेड है और वहां पहले से ही स्थानीय उद्यमी हैं जिनकी इन बाजारों में प्रबल उपस्थिति है। इसके विपरीत चीन और भारत

में आर्थिक विकास तथा शैम्पू एवं डिटरजेंट आदि जैसे उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई है। इसक साथ-साथ इन देशों में आबादी में भी वृद्धि हुई है। चीन के मामले में, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों चीन में अपनी यूनिटें स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिससे कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान कराए जा रहे विभिन्न लाभों का फायदा उठा सकें। तथापि, भारत के बारे में प्रमुख कार्यनपीति भारी मात्रा में अपने उत्पाद का निर्यात करना है जिससे कि भारतीय बाजार आयातित माल से पट जाए और भारतीय उत्पादक जैसे याचिकाकर्ता भारतीय बाजार से बाहर हो जाएं।

iv. विभिन्न बाजारों में मांग परिदृश्य निम्नलिखित है :

- **अमेरिका** : अमेरिका की बाजार में बढ़ती मांग नहीं है और यह पहले से ही पटी पड़ी है। प्राकृतिक अल्कोहलों को सिंथेटिक अल्कोहलों से जो कम कीमत पर शेल गैस की उपलब्धता के कारण सस्ते हैं प्रपाती प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।
- **यूरोप, आस्ट्रेलिया और रूस** : यह बाजारें भी पटी पड़ी हैं जहां मांग में नगण्य वृद्धि है। स्थानीय उत्पाद जैसे विल्यर, शेल बीएसएसएफ आदि स्थानीय मांग को पहले से ही पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ईयू ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से वसीय अल्कोहलों क आयात पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर रखा है।
- **अफ्रीका** : यह बाजार बहुत छोटी है जिसके अधिकांश भाग की दक्षिण अफ्रीका में पूर्ति की जाती है।
- **मध्यपूर्व** : स्थानीय उत्पादकों की क्षमता 83000 एमटी (सऊदी कयान) है जो स्थानीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है।
उपर्युक्त कारणों से प्रमुख फोकस भारत पर ही है।

झ. जनहित

झ. i. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दक्षिण पूर्व एशिया में सृजित बेशी क्षमताओं के कारण संपूर्ण विश्व में इस संबद्ध वस्तु की भारी आपूर्ति है। ऐसे परिदृश्य में इन निर्यातकों ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने और घरेलू उद्योग को समाप्त कर देने के लिए आक्रामक कार्नीति अपनाई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग पहले से ही भारी घाटे में चल रहा है। आयातों में उद्रेक का प्रशमन करने के लिए तब तक निर्णायक शुल्क का उदग्रहण नहीं किया जाता है तब तक घरेलू उत्पादकों के बंदी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के अभाव में विदेशी निर्यातक अपनी आपूर्ति प्रतिबंधित कर सकते हैं और अपनी कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं के दीर्घ हित में नहीं होगा।

झ. ii. अल्प अवधि में भी, शुल्क के उदग्रहण का अंतिम उत्पादों जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटरजेंट आदि की उपभोक्ता कीमतों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। शैम्पू पर शुल्क के प्रभाव का परिकलन अधोलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

शैम्पू (शैसे) 6 एमटल	
	रुपए
कीमत	1
लागत	0.6
भार द्वारा प्रयुक्त 15%* एसएलईएस 1257 डालर एमटी की दर से	0.068
एसएलएस में वसीय अल्कोहलों की मौजूदगी 50%*	0.034
20% शुल्क का प्रभाव	0.0068
कीमत का %	0.68%
कीमत का % से कम या एक पैसा कम	

*उद्योग मानदंडों पर आधारित

**एसएलईएस के एक मालीक्यूल में वसीय अल्कोहल का 1 मालीक्यूल होता है। एसएलईएस का मोलीक्यूलर भार 384 (एसएलईएस रहोडिया देखें) और सी 1214 का औसत मालीक्यूलर भार 190-197 (वीवीएफसी 12-14 एमएसडीएस देखें) चूंकि दो मालीक्यूलर भार का अनुपात (अर्थात 194/384) 0.5 है, इसलिए एसएलईएस में वसीय अल्कोहल अंतर्वस्तु लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है।

झ. iii. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वसीय अल्कोहल पर 20 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव शैम्पू की कीमत पर, जब इसकी बिक्री सैशे में की जाती है तो, 1 प्रतिशत से भी कम अर्थात नगण्य होगा।

ज. प्रतिभागिता का अधिकार प्रतिबंधित है

ज. i. याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि केवल पंजीकृत "हितबद्ध पक्षकारों के ही लिखित प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी नोट किया जाए कि जिन्होंने यद्यपि अपना पंजीकरण तो करा लिया है परंतु नियम 6(4) के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित प्रश्नावली दायर नहीं की है। प्रत्येक निर्यातक आयात और एसोसिएशन, जो प्रतिभागिता करना चाहता है, उसे माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय को इस बात से संतुष्ट कर देना चाहिए कि वे संबद्ध वस्तु के हितबद्ध पक्षकार हैं। नियमावली के नियम 6(4) में यह अपेक्षा की जाती है कि निर्यातगण विहित प्रपत्र में 30 दिनों के अंदर सूचना प्रस्तुत कर दें। वर्तमान मामले में अधिकांश निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। प्रश्नावली में निर्यातक से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि यह साध्यांकित हो सके कि वे "संबद्ध वस्तु के निर्यातक" हैं। किसी प्रत्युत्तर के अभाव में निर्यातक के रूप में उनका दावा सिद्ध नहीं होता है। यदि इन पक्षकारों को प्रतिभागिता करने की अनुमति दे दी जाती है और उनके प्रस्तुतिकरण रिकार्ड में ले लिए जाते हैं उससे नियम 6(4) निरर्थक हो जाएगा। इसी तरह अधिकांश आयातकों ने अपनी आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इस प्रकार उन्होंने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य या सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि उन्होंने संगत अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसलिए, आयातक के रूप में उनका दावा भी साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट नहीं है और इसलिए उन्हें भी इस कार्रवाई में प्रतिभागिता करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ज. ii. नियम में यथापरिभाषित "हितबद्ध पक्षकार" में वे "व्यापार या बिजनेस एसोसिएशन शामिल होती हैं जिनके अधिकांश सदस्य उक्त वस्तु के उत्पादक निर्यातक या आयातक होते हैं।" किसी रक्षोपाय की कार्रवाई में प्रतिभागिता करने के लिए किसी एसोसिएशन को अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है अर्थात् उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके अधिकांश सदस्य उत्पादक निर्यातक या आयातक हैं। आईएससीएमए यह दर्शाने से असफल रहा है कि इसके अधिकांश सदस्य संबद्ध वस्तु में लेनदेन करते हैं। इस तथ्य के मद्देनजर कि गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी एसोसिएशन के कुछ सदस्य शुल्क का उद्ग्रहण किए जाने का समर्थन कर रहे हैं। तथापि इनके पदाधिकारियों के विचारों को एसोसिएशन के विचार नहीं माना जा सकता है। एसोसिएशन एक शासकीय स्थिति प्राप्त कर सकती है और जीबीएम/मत का आयोजन करने के पश्चात ही वह यह निश्चित कर सकती है कि उनकी एसोसिएशन के अधिकांश सदस्यों के विचार क्या हैं।

ड. अत्यधिक गोपनीयता

(क) अपीलीय निकाय ईसी – फासेनर्स (चीन) में उल्लेख किया है कि :

"543. अनुच्छेद 6.5.1 यह मानता है कि "आपवादिक परिस्थितियों" में हो सकता है कि गोपनीय सूचना को सार रूप में प्रस्तुत करना असंभव हो। इन आपवादिक परिस्थितियों में कोई पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि वह गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, ऐसा होते हुए भी उस पक्षकार को "यह कारण बताना आवश्यक होगा कि उसका सारांशीकरण संभव क्यों नहीं है।" अनुच्छेद 6.51 किसी पक्षकार को गोपनीय रूप में प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने के कर्तव्य से तभी छूट करता है जब ऐसा करना "संभव न हो"। किसी पक्षकार को केवल यह दावा करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि उसका सारांश बोझिल या महंगा होगा। किसी सूचना को सारांश रूप में प्रस्तुत करना वहां संभव नहीं होगा जहां उस सूचना को प्रस्तुत करने का कोई वैकल्पिक तरीका विकसित नहीं किया जा सकता है और उससे या तो संवेदनशील सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता या उससे गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना के सार की तर्कसंगत समझ प्राप्त होने के पर्याप्त स्तर को विस्तार से नहीं बताया जा सकता है।"

(ख). वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को न तो कोई सारांश और न ही उन कारणों का विवरण प्रदान कराया गया है जिनके कारण सारांशीकरण संभव नहीं है। यह देखा जा सकता है कि याचिका के गुणवत्ता संबंधी सभी आंकड़ों का जांच शुरूआत अधिसूचना में तथा अंतिम जांच परिणाम में प्रकटन कर दिया गया है। किसी आयातक/निर्यातक के लिए गोपनीयता के भिन्न मानदंड को अपना न्यायोचित नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि पक्षकारों से सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करने को कहा जाए, और ऐसा न करने पर ऐसे पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों को नामंजूर कर दिया जाए।

ड. 16. मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समर्थक) – दिनांक 05 सितम्बर, 2014 का प्रस्तुतिकरण

- (क) गोदरेज आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि के कारण चिन्तित हैं और वह भी 3 या 4 वर्षों के समयान्तराल में, जो वर्ष 2010-11 में 20,000 एमटी से कम था, बढ़कर 2013-14 में 57600 एमटी हो गया।
- (ख) यद्यपि इस उत्पाद की मांग में भारत में निरंतर वृद्धि हुई है तथापि आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 70 प्रतिशत हो गया।

- (ग) भारतीय बाजार में आयातों की बाढ़ आने से भारतीय उत्पादकों की लाभप्रदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसलिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क तत्काल अधिरोपित करना अपेक्षित है।

च. जिन पक्षकारों को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी गई थी (अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अलावा) सार्वजनिक सुनवाई पश्चात उनके विचार जिन्होंने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण किए थे।

च.1 मैसर्स हिन्दुस्तान पोलीएमिड्स एवं फाइबर्स लिमिटेड (एचपीएफएल) द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के

तहत किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) यह जांच गौण स्रोत आईबीआईएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रारंभ की गई और यह अपवाद करने के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए जिनके आयाता आंकड़े और प्रशुल्क शीर्षों को जान-बूझकर वर्तमान जांच परिणाम के दायरे से बाहर रखा गया है।
- (ख) यह जांच त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बिना किसी समुचित विश्लेषण और तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना परिभाषित किया गया है। सी8 अल्कोहल को जांच के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- (ग) तकनीकी प्रतिस्थापनीयता का अभाव है। भैतिक गुणवधर्मों में अंतर है। सी8 और सी10 द्रव रूप में मिलते हैं और सी8 का द्रावांक -16.5 सी^० और सी10 का द्रावांक 5-70 सेल्सियस है। इसके विपरीत सी18 ठोस है और उसका द्रावांक 56-60^० सेल्सियस है।
- (घ) सी8 भी वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। सी8 और अन्य शुद्ध रसायनों की कीमतों में भारी अंतर है। इसलिए वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के प्रश्न को पूरी तरह नकारा दिया गया है।
- (ङ) घरेलू उद्योग सी8 और सी10 का उत्पादन नहीं करता है और उनका उत्पादन करने का कोई इरादा भी नहीं है। इसलिए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए सी8 और सी10 उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

च.2 भारतीय स्पेशियलिटी कैमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सरकार के उस विचार के विपरीत है कि लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। रक्षोपाय शुल्क अनुप्रवाही सर्फैक्टेंट उद्योग के लिए एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित करता है और इसके परिणामस्वरूप, नीति द्वारा, घरेलू विनिर्माण के बजाय आयातों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- (ख) यह शुल्क अधिरोपित करके हम उन कार्यकुशल उत्पादकों को हतोत्साहित कर रहे हैं जिन्होंने प्रतिस्पर्धात्मकता सृजित करने के लिए कठिन परिश्रम किया है।

च. मैसर्स क्रोडा इंडिया द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) शुल्क का अधिरोपण करने से भारत के भारत विनिर्माण को महत्व मिलेगा, जिससे रोजगार कम होगा, इससे उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव पड़ेगा, भारत में भावी निवेश में कमी आएगी और उद्योग एसएफए के स्थान पर पर्यावरण के लिए नुकसानदायक फीड स्टॉक जैसे अल्कायम फिनाल्स का संवर्धित प्रयोग पुनः शुरू कर सकते हैं।
- (ख) एसएफए के कई ग्रेड जरूरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं होते हैं। दो घरेलू उद्योग उत्पादकों ने भारत पर कभी भी फोकस नहीं किया और वे हमेशा निर्यात करने के लिए तत्पर रहे और उनके अधिकांश भाग का निर्यात उन देशों को किया गया था जहां कोई शुल्क संरक्षण नहीं था और जहां ये विनिर्माता सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके और ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए आसान होगा।
- (ग) भारी अनुप्रवाही उद्योग भारत में अंतिम उपभोक्ता की सेवा करने के लिए लागत प्रभावी विकल्प की तलाश कर रहा है। संवर्धित लागत से कई उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी और उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
- (घ) रोजगार और निवेश के अवसर समाप्त हो चुके हैं। इथाक्सीलेट्स का विनिर्माण अल्कायल फिनाल (जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है) से किया जाता है परंतु जागरूक प्रयासों से परिस्थितिकी रूप से अनुकूल इथाक्सीलेट्स एसएफए पर आधारित होता है और उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उसका विकास किया गया और यदि रक्षोपाय शुल्क का अनुरक्षण किया जाता है तो एसएफए की लागत में भारी वृद्धि होगी।

ख. प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण – हितबद्ध पक्षकार

ख.1. इंडोनेशिया की सरकार, दिनांक 12.09.2014 के पत्र के तहत, प्रस्तुत किए गए विचार निम्नलिखित हैं :

- (क) संवर्धित आयातों का कोई साक्ष्य नहीं है। अत्यधिक अभिनव पांच माह के आंकड़े कोई भी अभिनव, आकस्मिक, तीव्र एवं भारी वृद्धि प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, वृद्धि की दर संगत रूप से कम रही और इसमें कमी होकर यह अप्रैल, 2014 में 16 प्रतिशत हो गई। प्रयुक्त जांचावधि बहुत कम है जिससे समुचित जांच किए जाने की अनुमति नहीं मिलती है।
- (ख) प्राधिकारीगण आयात एवं अनपेक्षित विकास के बीच संबंध स्थापित करने में असफल रहे हैं। गंभीर क्षति या भारी समग्र परिक्षण का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि संवर्धित आयात हुए ही नहीं हैं, इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई के अंतर्गत कार्य करता है; इसलिए उसकी बिक्री, क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, बाजारा हिस्सा की जांच याचिकाकर्ता के निर्यात निष्पादन के आधार पर की जानी चाहिए। आयातों एवं याचिकाकर्ता के कार्यनिष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया है।
- (ग) महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में अन्य कारकों का गैर-उपारोपण विश्लेषण नहीं किया गया है जैसा कि करार के अनुच्छेद 6.2(ख) में अधिदेशित है।
- (घ) निर्यातोन्मुख इकाई के अंतर्गत याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री मात्रा पूरी तरह से निर्यात निष्पादन पर निर्भर है अर्थात् अधिक निर्यात अधिक घरेलू बिक्रियां। इसलिए घरेलू बिक्रियां असंगत है।

ख.2. मैसर्स पीटी मुसिम मास द्वारा 18 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए प्रस्तुतिकरण

- (क) आयातों में समग्र एवं संगत वृद्धि स्थापित नहीं की गई है। संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर जांच की अवधि के दौरान, गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं, इसलिए आयातों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और आयातों में वृद्धि इतनी अधिक अभिनव, अचानक, तीव्र एवं भारी नहीं है जिससे गंभीर क्षति कारित हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।
- (ख) घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति भाग गंभीर क्षति की चुनौती स्थापित नहीं की गई है।
- (ग) रोजगार, उत्पादन, उत्पादकता और मालसूची जैसे प्रमुख क्षति पैरामीटर जांच की अवधि की अवधि उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं।
- (घ) याचिकाकर्ता ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में यह प्रस्तुत किया है कि रोजगार में भारी वृद्धि "स्पिलिटिंग संयंत्र, वसीय अम्ल, फ्रैक्शनल प्लांट, ग्लिसरीन प्लांट और ग्राही विद्युत संयंत्र की प्रतिष्ठापन" को उपरोप्य है। यह स्पष्ट नहीं है कि बहुत से विनिर्माण संयंत्रों का विस्तार क्यों किया जाना चाहिए, कि जब याचिकाकर्ता को कथित रूप से क्षति हो रही है।
- (ङ) संवर्धित आयातों और कथित गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया है। यह क्षति आयातों के अलावा अन्य कारकों जैसे घरेलू उद्योग का निर्यातोन्मुख फोकस, घरेलू बाजार में बिक्री करने पर घरेलू उद्योग पर अधिरोपित प्रतिबंध, और घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में अवरोध आदि से कारित की गई है।
- (च) खमता में वैश्विक वृद्धि को, दक्षिण पूर्व एशिया के निर्यातकों की क्षमता में वृद्धि के विपरीत आयातों में वृद्धि की गिरती हुई दर के आलोक में अनपेक्षित विकास नहीं माना जा सकता और इसलिए आयातों में वृद्धि तथा दक्षिण पूर्व एशिया के निर्यातकों की क्षमताओं में वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (छ) याचिकाकर्ता का यह प्रस्तुतिकरण गलत है कि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और रूस में बाजार अनुबिद्ध हैं। हमने दक्षिण पूर्व एशिया से संयुक्त राज्य को संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का संकलन यह सिद्ध करने के लिए किया है कि क्या आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार संयुक्त राज्य की बाजार में अनुबिद्धता है। विशेष तौर पर, अधोलिखित आंकड़े इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर से वर्ष 2010 से वर्ष 2013 की अवधि के लिए एचएस कोड 392370 के अंतर्गत वर्गीकृत वसीय अल्कोहल की आयात मात्रा प्रदान करते हैं।

देश	2010 (किलोग्राम)	2011 (किलोग्राम)	2012 (किलोग्राम)	2013 (किलोग्राम)
इंडोनेशिया	3,53,57,553	3,04,62,364	3,35,52,695	3,95,05,317
मलेशिया	3,52,55,606	4,07,38,116	4,20,26,903	4,78,50,859
सिंगापुर	2,64,580	2,76,712	2,95,032	24,05,731

ज. सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के निर्यातों में वर्ष 2012 की तुला में वर्ष 2013 में 715 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह स्पष्टतः दर्शाता है कि यूएस बाजार अननुबिद्ध नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा निराधार है।

झ. आवेदक ने अपने शुरूआती आवेदनपत्र में समायोजन योजना का विवरण प्रदान नहीं किया है और वह घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए योजनाबद्ध किसी सकारात्मक समायोजन योजना का समाधान नहीं किया है जैसाकि भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2)(ख) के अंतर्गत अपेक्षित है।

छ.3. मैसर्स कुसा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) शुल्क का अधिरोपण सरफैक्टेंट्स/लुब्रीकेंट्स एडिटिव उद्योग के लिए प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित करेगा।
- (ख) घरेलू उद्योग (वीवीएफ और गोदरेज) ने कभी भी भारतीय बाजार में फोकस नहीं किया। कुशा ने अपने कच्चे माल की खरीद गोदरेज से तब तक ही जब तक उसने अपना विनिर्माण बंद करने का निश्चय नहीं कर लिया और फिर उसने अपने कच्चे माल की खरीद वीवीएफ से की जो उसकी जरूरत की मासिक मात्रा को पूरा करने में अक्षम रहा, इसलिए उसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश करनी पड़ी जो अब विकल्प के रूप में समाप्त हो गया है।
- (ग) रोजगार और निवेश खतरे में है।
- (घ) एक बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी अनुप्रवाही उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रक्षोपाय शुल्क से अनुप्रवाही उत्पाद के आयात को अधिमानता मिलेगी और हमारे निर्यात को भी क्षति पहुंचेगी। यह मौजूदा सरकार की स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की नीति के विरुद्ध है।

छ.4. मैसर्स गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स लिमिटेड, केएल-किपांग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी, मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड और मैसर्स विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- क रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की पूर्वापेक्षाएं वीवीएफ द्वारा सूचीबद्ध केवल तीन शर्तों तक ही सीमित नहीं हैं परंतु उनमें निम्नलिखित भी शामिल है :
- (i) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि आयातों में वृद्धि भारत द्वारा गाट, 1995 (गाट का अनुच्छेद XIX.1 (क) के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के कारण हुई है।
- (ii) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि आयातों में वृद्धि ऐसे विकास के कारण हुई है जिसकी डब्ल्यूटीओ कार के समय अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। (गाट का अनुच्छेद XIX.1 (क))।
- (iii) आवेदक घरेलू उत्पादक का आवेदन के साथ आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों या दोनों का उल्लेख होना चाहिए [नियम 5(2)(ख)]।
- (iv) प्राधिकारी को योजना की मौजूदगी से संतुष्ट होना चाहिए जिससे आयात प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन सुलभ होगा [नियम 11(2)]।
- (v) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि यह उपाय जनहित में है।

ख. यदि एक दिन का भी शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो नियम 11(2) के साथ पठित नियम 5(2) (ख) के अनुरूप सकारात्मक समायोजन योजना प्रदान कराई जानी चाहिए।

ग. एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई होने पर याचिकाकर्ता के पास वर्तमान जांच में "घरेलू उद्योग" के रूप में अपेक्षित आधार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दुस्तान ग्रेनाइट बनाम भारत संघ [2007(12) एससीसी (178)]।

निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने के प्रयोजन से की जाती है जबकि घरेलू उद्योग प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री सामान्य नियम के तौर पर केवल आपवादिक रूप में की जाती है।

- घ. याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका का गोदरेज ने समर्थन किया है परंतु रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत "समर्थक" की कोई संकल्पना नहीं है। (डीजीएस ने हाट रोलड क्वायल्स/शीट्स और स्ट्रिप्स में धारित किया है)। इसके अतिरिक्त वीवीएफ एक निर्यातोन्मुख इकाई है और यह घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए पात्र नहीं है और घरेलू बाजार में क्षति का निर्धारण करने के लिए इसके आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- च. याचिकाकर्ता ने सभी कार्बन चैन लंबाई को एक रूप के तौर पर माना है और आयातों में उद्रेक दिखाने के लिए उनको मिला दिया है परंतु सभी प्रकार की वसीय अल्कोहल श्रृंखलाओं को एकत्र करके एक एकल श्रृंखला के रूप में मानकर आयातों की प्रवृत्ति और उनके प्रभाव की जांच करना सही नहीं है।
- छ. वसीय अल्कोहल के आयात का बड़ा भाग घरेलू बाजार में प्रयोग नहीं किया जाता है परंतु उसका प्रयोग उससे विनिर्मित परिष्कृत वस्तु के लिए किया जाता है और उसका देश के बाहर निर्यात किया जाता है याचिकाकर्ता द्वारा यथाप्रदत्त मांग सही नहीं है।
- ज. महानिदेशक रक्षोपाय यह देखने के लिए पूरी तरह से जांच कर सकते हैं कि क्या क्षति प्रदर्शित करने वाले आर्थिक पैरामीटर असंबद्ध वस्तु से संबंधित है और उन्हें शामिल कर लिया गया है।
- झ. घरेलू बाजार को क्षति, जबकि निर्यात बाजार में वृद्धि हो रही हो, को क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के साथ-साथ लाभप्रदायकता में गिरावट उचित प्रतीत नहीं होती है।
- ञ. संबद्ध वस्तु के आयातों तथा याचिकाकर्ता के कार्यनिष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध खो गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता का निष्पादन सीधे-सीधे निम्नलिखित कारकों से जुड़ा हुआ है :
 - (i) संबद्ध वस्तु के वीवीएफ द्वारा किए गए निर्यातों पर ईयू ने पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। वर्ष 2011, जब से पाटनरोधी शुल्क प्रभावी हुआ, तब से याचिकाकर्ता को भी क्षति होने लगी और उसे पहली बार नुकसान हुआ।
 - (ii) निर्यातोन्मुख इकाई का दर्जा होने के कारण वीवीएफ प्रतिस्पर्धी नहीं रहा चूंकि किसी निर्यातोन्मुख इकाई पर डीटीए को निकासी पर उदग्रहित उत्पाद कर सीमाशुल्क के समान होता है और आधारभूत सीमाशुल्क सेनैटैबल नहीं होता है, परिणामतः, कोई निर्यातोन्मुख इकाई जो डीटीए में बिक्री करना चाहती है, उसे अतिरिक्त लात वहन नहीं पड़ती है।
 - (iii) आशियान भारत मुक्त वपार करार का प्रभाव :
आयातों में वृद्धि होने का एक सबसे बड़ा कारण भारतीय सरकार की व्यापार वृद्धि करने की अपनी निजी पहल है।
 - (iv) आभ्यन्तरिक कारक
याचिकाकर्ता के वित्तीय विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खपत में कमी होने, शहरी क्षेत्रों का मंथर क्षति से विकास होने, कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने, मुद्रास्फीति, न्यूनतर जीडीपी वृद्धि, नीतिगत विवरणों उच्च ब्याज दर और उच्चतर घाटे कारण क्षति सहन करनी पड़ी है।
- ट. इस क्षति को याचिकाकर्ता की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर क्षमता बाजारों का अध्ययन करने, और प्रतिस्पर्धा तथा समक्षता निर्माण पर उपरोपित किया जा सकता है।
- ठ. अनपेक्षित परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए अन्य क्षेत्राधिकार में বেশी क्षमता होने का कोई महत्व नहीं है।
- ड. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से एसएलएस/एसएलईएस के संबंध में प्रतिलोमित शुल्क ढांचा तैयार होगा।
- ढ. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। उन्होंने अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों में उन आंकड़ों का भी प्रकटन नहीं किया है जिनका प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले ही प्रकटन कर दिया गया है।

छ.5. मैसर्स गैलेक्सी सरफेक्टेन्ड्स लिमिटेड (पृथक प्रस्तुतिकरण) द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण

घरेलू उद्योग के लिए यूरोप क संवेदनशील बाजार है विषय पर किया गया प्रस्तुतिकरण।

- (क) घरेलू उद्योग का यह खंडन तथ्यात्मक रूप गलत है कि यूरोप एक बहुत बड़ी बाजार नहीं है।
- (ख) यूरोप में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करते समय यूरोप घरेलू उद्योग के लिए सबे बड़ी निर्यात बाजार था। चूंकि घरेलू उद्योग के साथ में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य उद्योगियों पर भी न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क लगा था, उदाहरणार्थ इकोग्रिन पर 0% प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क है, परंतु यह शुल्क ग्राहकों से वसूल कर पाना संभव नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग में घाटे की प्रवृत्ति बन जाएगी।

- (ग) इसके परिणामस्वरूप, यूरोप, जिसका वर्ष 2012-13 में भारी हिस्सा था, पर ही निरंतर आश्रित रहने से केवल क्षति में वृद्धि ही होगी जो उनके वित्तीय अभिकथन के समरूप है।
- (घ) वसीय अल्कोहल का भारत से निर्यात (मुख्यतः यूरोप को) को घरेलू बाजार की कीमत पर सब्सिडाइज किया जा रहा था, जिसके कारण भी आयातों में वृद्धि हुई।
- (ङ) पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव इस प्रवृत्ति में स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के व्यवसाय में यूरोप के हिस्से में क्रमिक रूप से प्रतिवर्ष कमी आई है।
- (च) विधि के अनुसार, कोई भारतीय निर्यात को सब्सिडाइज करके या पाटनरोधी शुल्क से क्षति को कम करके क्षति के लिए रक्षोपाय शुल्क की मांग नहीं कर सकती है।

जल आधारित उत्पादों का परिवहन करने की अक्षमता के कारण आयातों में वृद्धि न होने के संबंध में प्रस्तुतिकरण (गैलेक्सी सरफेक्टेन्ट्स लिमिटेड)।

- (क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए बिन्दु सही नहीं है और पास-पड़ोस के क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है जहां से परिष्कृत वस्तु शून्य/न्यून शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है और इसकी हमारी खुद की खरीद द्वारा परिपुष्टि हुई है।
- (ख) वसीय अल्कोहल आधारित सभी उत्पाद जल आधारित नहीं होते हैं जैसे इथाक्सीलेट्स एवं अल्कोहल सल्फेट्स जल मुक्त उत्पाद हैं जिससे घरेलू उद्योग की मौजूदा अशुद्ध तथा प्रस्तुत करने की प्रणाली की पुनः संपुष्टि होती है।
- (ग) यदि कोई भारतीय कंपनी भारी मात्रा में विश्व के कोने-कोने में निर्यात कर रही है और इसकी प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है तो इस मुद्दे की कोई वैधता नहीं है कि अनुबिद्ध वसीय अल्कोहलों से बने उत्पाद जल आधारित हैं और इसलिए उनका लंबी दूरी तक परिवहन नहीं किया जा सकता है।
- (घ) आयात मात्रा, जिसे तीव्र रूप से प्रतिस्पर्धी अनुप्रवाही सरफेक्टेन्ट्स उद्योग द्वारा दबा के रखा गया है, ने जांच के प्रारंभ के पश्चात की अवधि ने उद्वेक होना प्रारंभ कर दिया जिसे महानिदेशक रक्षोपाय को नोट करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रोजगार, निवेश और अनुप्रवाही सरफेक्टेन्ट उद्योग के आर्थिक पद चिन्हों पर विचार करते हुए सचेतक विकास है।
- (ङ) उपर्युक्त सभी बिन्दु इस तथ्य को पर्याप्त रूप से सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग प्राधिकारियों को निवेशित शुल्क ढांचे के संबंध में गुमराह कर रहा है और सब्सिडाइजिंग निर्यातों से होने वाली क्षति से संरक्षण प्राप्त करने के लिए गलत सूचना का प्रयोग कर रहा है।
- (च) वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारतीय विनिर्माण उद्योग का प्रयोग एक ऐसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उपकल्पना की जांच का प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसका विनिर्माण अप्रतिस्पर्धी के रूप में स्वीकार किया गया है और जिसके आंकड़े त्रुटिपूर्ण एवं प्रत्युत्तर गलत है।

छ.6 मैसर्स विश्वाट कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) वसीय अल्कोहल का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्चा माल मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में उत्पादित किया जाता है। अतः भारतीय विनिर्मातागण कमी भी प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आधारभूत तेल का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार आयात के बिना वे प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे और उन्हें अपनी यूनिटें बंद करनी पड़ेगी।
- (ख) वीवीएफ यह दावा करता है कि वसीय अल्कोहल के संवर्धित आयातों ने घरेलू विनिर्माताओं को नष्ट कर दिया है परंतु घरेलू विनिर्माताओं में से एक, गोदेरेज इंडस्ट्रीज, ठीक-ठाक कार्य कर रही है और वह लगातार लाभ अर्जित कर रही है।
- (ग) वीवीएफ के पास कुछ वसीय उत्पादों जैसे सी8 और सी10 की जरूरत को पूरा करने की क्षमता नहीं है, फिर भी वे उसे रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत कवर करना चाहता हैं।
- (घ) वीवीएफ यह दावा करता है वर्ष 2012-14 के दौरान वसीय कल्होकलों का उच्च आयात के कारण उनकी लाभप्रदता, बाजार हिस्सा, निवेश पर प्रतिलाभ बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, परंतु वास्तविक कारण है उनके द्वारा कवर किया गया आधारभूत कच्चा माल बहुत उच्च कीमत पर था और कीमत के अंतर्राष्ट्रीय रूप से अचानक गिरावट से उनकी बिक्री प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा के उतार-चढ़ाव ने उनकी कच्चे माल की लागत भी प्रभावित हुई है।

- (ड) वीपीएफ द्वारा कैमिकल्स वीकली में दिए गए साक्षात्कार के अनुसार इंडोनेशियाई निवेश नया नहीं है परंतु बहुत पुराना है परंतु इसे स्थिति में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था या इसे भावी समायोजन योजना के एक भाग के रूप में नहीं दिखाया गया। यह तथ्य कि यह पहले से ही 60 प्रतिशत प्रचालनात्मक है और इसका भारत को पहले से ही निर्यात किया जा रहा है, इसका आशय यह है कि यह एक नया समायोजन नहीं है जैसा कि याचिका में संकेत दिया गया है। इंडोनेशियाई निवेश कर की वचत करने वाला नहीं था तो समायोजन योजना पत्र में इसके कारण कर में वचत क्योंकि दिखलाई गई है।

छ.7. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

इस शुल्क का अधिरोपण भारत में मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण को हतोत्साहित करेगा क्योंकि इससे इन उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात प्रोत्साहित होंगे, निवेश हतोत्साहित होगा, रोजगार में क्षति होगी, वसीय अल्कोहल के विनिर्माताओं में से एक को अनुचित लाभ होगा क्योंकि वे भी अनुप्रवाही उत्पादों के विनिर्माता हो सकते हैं और इसका उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव पड़ेगा।

छ.8 मैसर्स पीटी एवरग्रीन ओलियोकैमिकल्स, इंडोनेशिया द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

- (क) प्रारंभिक निर्धारण अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए अपेक्षित कारकों के अधूरे विश्लेषण पर आधारित था। महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा प्रारंभिक निर्धारण के लिए की गई जांच में वह संवर्धित आयात, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती, एफओएच के आयातों तथा दावाकृत क्षति के बीच करणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कोई अनपेक्षित विकास सही एवं समुचित रूप से न तो स्थापित किया गया और न ही उसका उपयुक्त एवं तर्कसंगत गैर-उपारोपण किया गया।
- (ख) अनपेक्षित विकास और आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता के कैमिकल वीकली को दिनांक 9 सितम्बर, 2014 को दिए गए साक्षात्कार के आधार पर, याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि भारत और चीन की बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया में निवेश किया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में किए गए दावे और याचिकाकर्ताओं के सीईओ द्वारा व्यक्त किए गए तथ्यों के बीच समग्र विसंगतियां मौजूद हैं। याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि क्षमता में विस्तार एक अनपेक्षित विकास कैसे है। क्षमता में विस्तार करने की योजना बनाई गई थी और इसे कई चरणों में तैयार किया गया था जिससे कि यह स्पष्ट रूप से पूर्वदृष्ट हो जाए।
- (ग) याचिकाकर्ता ने अप्रैल-जून, 2014-15 की प्रथम तिमाही (वार्षिकीकृत) के आंकड़े जोड़कर अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में अपने आंकड़ों का नवीकरण करने का प्रयास किया जिसे स्पष्टतः सहन की जा रही गंभीर क्षति को दर्शाने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया कि उसके घरेलू उत्पादन को उसकी घरेलू बिक्री के साथ सगीकृत किया जा सकता है परंतु घरेलू क्षमता उपयोग के संबंध में स्थिति अधिक संभ्रमकारी है। इस तरह के संभ्रमकारी विश्लेषण से प्रयोजनात्मक परिणाम नहीं निकल सकता है क्योंकि इसे कृत्रिम रूप से गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती को दर्शाने के लिए इरादतन डिजाइन किया गया है।
- (घ) याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को नकारने का प्रयास किया कि इसका समग्र निष्पादन पूर्णतया इसके निर्यात निष्पादन पर निर्भर है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसको दिया गया ईओयू स्टेट्स का घरेलू बिक्रियों सहित इसके समग्र निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याचिकाकर्ता को अपनी निर्यात बिक्री में भारी गिरावट सहन करनी पड़ी (मासिक और तिमाही विश्लेषण के आधार पर)। याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री मात्रा उसके निर्यात मात्रा की तुलना में महत्वहीन थी। सहन की गई क्षति अत्यधिक अल्प निर्यात निष्पादन पर उपरोपित की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने इस संवेदनशील कारक का कोई विश्लेषण नहीं किया परंतु उसने आंकड़ों का कोई एकल विश्लेषण किए बिना ही यह दावा किया है कि उसके ईओयू दर्जे का उसके घरेलू निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है, परंतु उसका यह दावा गलत है। याचिकाकर्ता के सीईओ ने अपने साक्षात्कार में यह संपुष्ट किया कि याचिकाकर्ता उच्चतर आयात प्रशुल्क के कारण चीन की बाजार में भी अपनी पहुंच नहीं बना सका। ऐसा इसलिए है कि भारत ने अभी तक चीन के साथ अपना मुक्त व्यापार करार नहीं किया है तब कि उसने दक्षिण एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ यह करार किया है जिसके द्वारा आशियान ढांचे के अंतर्गत उनका चीन के साथ एफटीए पहले से ही है।

छ.9. मैसर्स एचयूएल द्वारा अपने दिनांक 19.09.2014 के पत्र के तहत किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

(क) शुल्क का उदग्रहण करने के लिए पूर्वापेक्षाओं को पूरा कर लिया गया

रक्षोपाय जांच के लिए अनिवार्य आवश्यकता को रक्षोपाय संबंधी करार ("रक्षोपाय करार") के अनुच्छेद 2 की भाषा तक की सीमित नहीं किया जा सकता है। रक्षोपाय साधनों की उत्पत्ति डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत गाट 1994 के अनुच्छेद XIX में है जिसमें आवेदक द्वारा गिनाए गए कारकों अर्थात् अनपेक्षित विकास के अलावा अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएं भी हैं। याचिकाकर्ता की समायोजन योजना विदेशी क्षेत्राधिकार की नीतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह आवेदक के पक्ष में नहीं है बल्कि यह इंडोनेशिया स्थित इसकी अनुषंगी के पक्ष में है।

(ख) घरेलू उद्योग

आवेदक द्वारा परिकलित "घरेलू उत्पादन" भी मिथ्या है क्योंकि यह सभी निर्यात बिक्रियों का अपवर्जन करने के पश्चात शेष बची उत्पादन मात्रा है। यद्यपि आवेदक का वर्तमान जांच में कुछ आधार है परंतु क्षति के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का दायरा इस विचाराधीन उत्पाद के एक अन्य बड़े उत्पादक अर्थात् गोदरेज का अपवर्जन करता है।

(ग) आयातों में उद्रेक

यद्यपि आयातों में वृद्धि हुई है, आवेदक का ईओयू स्टेट्स स्पष्टतः यह संकेत करता है कि आवेदक की प्राथमिकता निर्यात बिक्रियां हैं। जांच की शुरुआत के पश्चात की अवधि स्वयं जांच द्वारा प्रभावित रही है, तद्वारा इस अवधि पर आयातों में उद्रेक का विश्लेषण करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) घरेलू उद्योग को कारित गंभीर क्षति

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया क्षति विश्लेषण आकस्मिक रूप से विचार की भिन्न अवधियों पर भरोसा करता है। मात्रा से संबंधित सभी पैरामीटर आवेदक के ईओयू स्टेट्स और निर्यात बिक्रियों पर इसके सतत बल द्वारा प्रभावित कर रहे। भारत द्वारा किए गए निर्यातों की कीमत भारत में किए गए आयातों की तुलना में कम है, जो कथित रूप से गंभीर क्षति कारित कर रहा है।

(ङ.) क्षति की चुनौती

यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक क्षति की चुनौती के संबंध में किए गए अपने दावे को बरकरार रखने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

(च) आयातों एवं घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने आवेदक को स्पष्टतः क्षति पहुंचाई है, ये हैं आवेदक की ईओयू स्थिति, आवेदक का घटता-बढ़ता निर्यात निष्पादन

(छ) अनपेक्षित विकास

यह एक तथ्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया के पास पाम गिरी के तेल का मुख्य कच्चा माल भारी मात्रा में संसाधन होने के कारण ओलियो रसायनों का वैश्विक हब है।

(ज) जनहित

लागत एवं शुल्कों के कीमत प्रभाव पर आवेदक का विश्लेषण त्रुटिपूर्ण और अथार्थ है।

(झ) प्रतिभागिता का प्रतिबंधित अधिकार

एचयूएल के पास सुनवाई तथा सभी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है और माननीय महानिदेशक रक्षोपाय एचयूएल द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों को रिकार्ड में लेने के लिए बाध्य है।

(ञ) गोपनीयता

यदि महानिदेशक रक्षोपाय निर्यातकों/आयातकों को मात्रा संबंधी आंकड़ों का प्रकटन करने का निदेश देते हैं तो यह उपयुक्त होगा कि वह आवेदक को भी यह अनुदेश दें कि वह संगत सूचना का प्रकटन करे।

(ट) समायोजन योजना

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समायोजन योजना पहले से ही सुस्थापित है – इंडोनेशिया का संयंत्र से ही 60 प्रतिशत प्रचालनात्मक है और उसके सभी निर्यात भारत को किए गए हैं। यह वीवीएफ के प्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में किए गए दावे के बिल्कुल विपरीत है कि इंडोनेशिया से केवल 1.7 प्रतिशत आयात किए जाते हैं।

छ.10. घरेलू उद्योग (मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण

(क) अनपेक्षित विकास

विधि के अंतर्गत अनपेक्षित विकास की जांच करना अपेक्षित नहीं है :

- (i) अनपेक्षित परिस्थितियों के संबंध में भारतीय विधि के अंतर्गत किए गए प्रावधान मानते हैं कि उसका निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है। ऐसी म्युनिसिपल विधि के अभाव में जहां आयातों को अनपेक्षित परिस्थितियों का परिणाम दर्शाना अपेक्षित हो, ऐसी किसी अपेक्षा को विधि के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता है। यह एक सुस्थापित

स्थिति है कि विभिन्न संधियों के जरिए अधिनियमित अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्वचन में केवल सहायक हो सकती है। इसलिए ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि आयातों में वृद्धि अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण हो। इस संदर्भ में **ग्रामोफोन बनाम बहादुर पांडेय 1984 (2) एससीसी 535 (एससी)** में रिपोर्टित, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है जिसमें उसने निम्नलिखित अधिवचन किया था : "राष्ट्रों का सौजन्य हो या न हो, विवाद की स्थिति म्युनिसिपल विधि ही प्रचलित होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को संसद मना करती है तो राष्ट्रीय न्यायालय हां नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि को पृष्ठांकित कर सकते हैं परंतु यदि उनका राष्ट्रीय विधि के साथ विवाद होता है तो वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रीय राज्य का अंग होने न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का अंग होने के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रीय विधि को लागू करेंगे।"

- (ii) अधिकांश अधिकारिता में यह विचार ग्रहण किया जाता है कि रक्षोपाय संबंधी करार सर्वाधिक अभिनव विधायन होने के कारण गाट करार के अंतर्गत बाध्यताओं के दायरे को निगमित करता है और स्पष्ट करता है।

अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण आयातों में उद्रेक

- (i) इस तथ्य की पूर्वावधारणा के बिना कि भारतीय विधायन के अंतर्गत "अनपेक्षित विकास" के संबंध में निर्धारण करने की कोई अपेक्षा नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में यह उद्रेक निम्नलिखित अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण आया है।
- (ii) यह तथ्य कि मुक्त बाजार करार के अंतर्गत शुल्क में क्रमिक रूप से कमी की जा रही है, प्राधिकारी के संज्ञान में था, परंतु क्षमताओं में भारी वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि पूर्वापेक्षित नहीं थी।
- (iii) इंडोनेशिया एवं अन्यो के द्वारा निर्यात का उदग्रहण जिसके कारण बाजार संवितरण हुआ। भारत द्वारा उरुग्वे दौर के अंतर्गत बाध्यताओं में प्रविष्ट होते समय भारत को इसकी पूर्वापेक्षा नहीं थी।
- (iv) एफटीए के अंतर्गत आने वाले देशों में भारी उत्पादन क्षमताएं सृजित होगी जो वैश्विक मांग के अनुरूप नहीं होगा।

देश	वर्ष 2011 से पहले (एमटी)	वर्ष 2011 के बाद (एमटी)
इंडोनेशिया	3,24,000	9,98,000
मलेशिया	4,90,000	5,90,000
फिलीपीन्स	1,80,000	2,80,000
वैश्विक क्षमता	22,70,000	34,27,000

स्रोत : ओलियालाइन

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वैश्विक क्षमता में वर्ष 2011 से 22,70,000 एमटी से वृद्धि होकर यह 34,27,000 एमटी हो गई है।

- (v) यूरोपियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना, जो संबद्ध वस्तु की प्रमुख बाजार थी।
- (vi) प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों द्वारा प्रधान कच्चे माल पर उच्च निर्यात कर की वसूली।

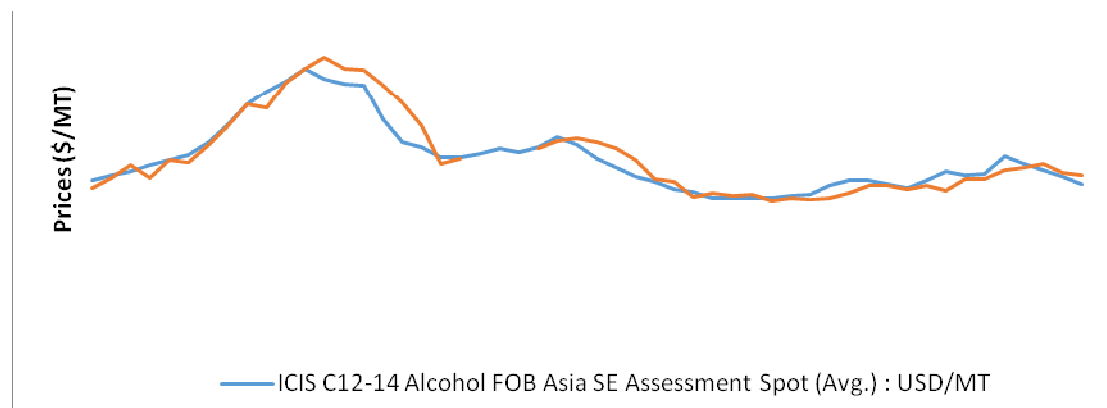
(ख) आयातों में वृद्धि की ऋणात्मक दर नहीं है :

यह निष्कर्ष कि आयातों में वृद्धि की दर संगत रूप से कम थी और वर्ष 2014 में इसमें 16 प्रतिशत तक गिरावट आई, गलत है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि रक्षोपाय संबंधी करार तथा म्युनिसिपल विधि में यह अपेक्षा की जाती है कि संबद्ध वस्तु का आयात इतनी अधिक "संवर्धित मात्रा" में किया जाए जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो। इसमें यूएस-स्टील रक्षोपाय तथा यूएस व्हीट ग्लुटेन में डब्ल्यूटीओ पैनेल के निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

(ग) क्षति निर्यात निष्पादन के कारण कारित नहीं हुई है

- (i) वार्षिक आधार पर निर्यात जो वर्ष 2010-11 में 35286 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 69994 एमटी हो गया। क्षति अवधि के दौरान निर्यातों में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण नहीं हुई है।

- (ii) घरेलू उद्योग की आयात कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच तुलना की मांग की गई है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्यात कीमत एवं आयात कीमत के बीच तुलना समान स्तर पर अर्थात् एफओबी स्तर पर सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकती है।
- वीवीएफ निर्यात कीमत मोटे तौर पर बाजार प्रवृत्ति का ही अनुपालन करती है जैसाकि निम्नलिखित ग्राफ से देखा जा सकता है :



आईसीएससी 12-14 अल्कोहल एफओबी एशिया एसई आकलन स्थल (औसत) : यूएस डॉलर/एमटी

ग्राफ 1

उपर्युक्त सूचना स्पष्टतः प्रदर्शित करती है कि क्षति निर्यातों के कारण नहीं हुई।

- किसी भी हाल में क्षति निर्धारण निर्यात मात्रा पर विचार किए बिना किया गया। बिक्री घरेलू उत्पादन, लाभप्रदता आदि पर विचार केवल घरेलू बिक्रियों के लिए किया गया है न कि निर्यातों के लिए। इससे क्षति विश्लेषण से निर्यातों के प्रभाव का गैर उत्तरदायित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है।
- ऐसी कोई अन्य परिस्थितियां या कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो तथा कारणात्मक की जरूरत पूर्णतया पूरी हो रही है।
- यद्यपि घरेलू उद्योग का हित निर्यात बाजार में है, तथापि क्षति प्रस्तुतिकरण घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित सूचना के आधार पर किए गए हैं। इसलिए सहन की गई क्षति के लिए निर्यात निष्पादन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- यह उल्लेख किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग ईओयू स्कीम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षति अवधि के दौरान स्थानीय बाजार में उच्चतर मात्रा की बिक्री करने का पात्र था।

(घ) शुल्क उदग्रहण करने के परिणामस्वरूप शैम्पू के उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव

- कुछ पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि शुल्क का शैम्पू तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पर विपरीत प्रभाव होगा। इससे पहले यह दर्शाने के लिए परिकलन प्रदान कराए गए हैं कि शुल्क का प्रभाव कीमतों का केवल 0.68 प्रतिशत होगा।
- यद्यपि वसीय अल्कोहलों पर शुल्क में क्रमिक रूप से प्रति वर्ष गिरावट (15 प्रतिशत से 0 प्रतिशत तक) गिरावट आ रही है परंतु प्रशुल्क परिवर्तनों के कारण उपभोक्ता ने कीमत में किसी कमी को लुप्त नहीं उठाया है। वसीय अल्कोहल की कीमतों में भिन्नता भी रही है परंतु भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमत में कोई कमी नहीं आई।
- वैकल्पिक रूप से वसीय अल्कोहलों, एसएलएस/एसएलईएस की मात्रा को उच्च स्तर की लाभप्रदता बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे फ्रैक्शन द्वारा निश्चित रूप से कमी की जा सकती है।

ड. इथाक्सीलेट्स और एसएलएस, एसएलईएस के उत्पादकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं

- यह तर्क कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से एसएलएस/एसएलईएस के लिए एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होगा उचित प्रतीत नहीं होता है और यदि ऐसा होता भी है तो विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं जिनको पीड़ित उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- अनुप्रवाही उत्पादों के आयात में उद्रेक की संभावना निम्नलिखित कारणों से बिल्कुल भी संभावित नहीं है :

- एफटीए देशों में इन अनुप्रवाही उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए कोई बेशी क्षमता नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में इथायलीन आक्साइड की कम उपलब्धता और मौजदा क्षमताओं का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी ग्राही खपत के लिए संविदा पर उपयोग किया जा रहा है।
- इतिवृत्तात्मक रूप से वसीय अल्कोहल तथा एसएलएस/एसएलईएस के बीच शुल्क में 10 प्रतिशत का अंतर रहा है, विगत में एसएलएस/एसएलईएस का उच्च परिवहन लागत के कारण नगण्य आयात हुआ है।
- एसएलईएस स्लरी रूप में होता है और इस घोल में जल संघटक 50 प्रतिशत – 70 प्रतिशत तक होता है इसलिए इस परिवहन बहुत मंहगा है।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 में एसएलएस/एसएलईएस का कुल आयात 604 एमटी था जब कि उसी अवधि के दौरान लगभग 57000 एमटी वसीय अल्कोहलों का आयात हुआ।
- विभिन्न स्रोतों से वसीय अल्कोहलों का आयात करने पर ईयू द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है। इन शुल्कों के बावजूद एसएलएस/ एसएलईएस/ इथाक्सीलेट्स के आयातों में ईयू में कोई वृद्धि नहीं हुई जैसाकि ईयू के लिए अनुप्रवाही उत्पादों के आयात आंकड़ों से स्पष्ट है।

वर्ष	चोटी के देश	एफटीए देश	अन्य	कुल	% टॉप	% एफटीए
2010	95998	2193	12337	110528	87%	2%
2011	89380	1978	13252	104610	85%	2%
2012	97205	2632	14076	113913	85%	2%
2013	104740	1532	18612	124884	84%	1%

स्रोत : ईयू की शासकीय वेबसाइट

- ईयू को एसएलएस, एसएलईएस और इथाक्सीलेट्स के 80 प्रतिशत से अधिक निर्यात स्विटजरलैंड, नार्वे , यूएसए, भारत, जापान और तुर्की (जिन्हें चोटी के देश कहा गया है) से किया गया है, जिनको एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क नहीं मिला है।
- हम निम्नलिखित मुद्दों पर विगत में किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।
 - एसएलईएस की कच्चे माल अंतर्वस्तु का आधे से अधिक संघटक वसीय अल्कोहल होता है।
 - शैम्पू, टूथपेस्ट आदि का उत्पादन करने में एसएलएस/एसएलईएस का प्रयोग किया जाता है।
 - एसएलएस/एसएलईएस की मात्रा, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पादों में किया जा सकता है, पर विधिक और परामर्शी प्रतिबंध होते हैं।
 - टूथपेस्ट में सामान्यतः 2 प्रतिशत से कम एसएलएस होता है, जबकि शैम्पू में 15 प्रतिशत से कम एसएलएस होता है।

टूथपेस्ट की कीमत/लागत पर शुल्क का प्रभाव

टूथपेस्ट की कीमत (150 ग्राम)	70 रुपए
टूथपेस्ट की लागत – लाभ, डीलर मार्जिन, थोक बिक्रेता का मार्जिन, विज्ञापन लागत को छोड़कर	40 रुपए
टूथपेस्ट में वजन के आधार पर अधिकतम 2 प्रतिशत एसएलएस का प्रयोग किया जाता है। एचयूएल द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार 2360 यूएस डालर प्रति एमटी की दर से 3 ग्राम एसएलएस (पैरा 34)	0.42 रुपए
एसएलएस में वसीय अल्कोहल संघटक 60 प्रतिशत है।	0.25 रुपए
फैटी अल्कोहल पर 20 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव	0.05 रुपए

70/-रुपए की कीमत वाले टूथपेस्ट पर शुल्क का निवल प्रभाव 5 पैसे का है अर्थात 0.07 प्रतिशत है जो 1 प्रतिशत भी नहीं है।

च. अवधि का चयन उपयुक्त नहीं है

- (i) रक्षोपाय संबंधी करार का एक साधारण पाठन से यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 2 से 7 की अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत निर्णायक शुल्क के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है, न कि अनंतिम शुल्क के लिए। इसलिए अनंतिम उदग्रहण के लिए केवल एक प्रारंभिक निर्धारण किया जाना अपेक्षित होता है कि संवर्धित आयातों द्वारा गंभीर क्षति कारित की गई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी गई है।
- (ii) यह नोट करने योग्य है कि वाक्यांश "प्रारंभिक निर्धारण" का प्रयोग रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4 में प्रयुक्त "निर्धारण" के स्थान पर अनुच्छेद 6 में किया गया है।
- (iii) संवेदनशीलता के पहलू की जांच अत्यधिक अभिनव समय के संबंध में की जानी चाहिए। जांच शुरूआत अधिसूचना में वर्ष 2013-14 को जांच की अवधि के एक भाग के रूप में माना गया। चूंकि उस समय वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे इसलिए वार्षिकीकृत आंकड़ों पर विचार किया गया। अनंतिम जांच परिणाम में वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया गया जिससे आयतों में उद्रेक प्रदर्शित होता है।
- (iv) यह दावा तथ्यात्मक रूप से असत्य है कि संपूर्ण क्षति अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है, जैसाकि जांच परिणाम के पैराग्राफ 17.4 से स्पष्ट है। संवेदनशीलता के पहलू की जांच करने के लिए केवल तिमाही विश्लेषण ही किया गया।

छ. घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति कारित नहीं हुई

- (i) गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना संगत माना गया :
 - संवर्धित आयातों की समग्र एवं संगत रूप से मात्रा एवं दर
 - आयातों द्वारा अधिग्रहित घरेलू बाजार का हिस्सा
 - बिक्री के स्तर में परिवर्तन
 - उत्पादन
 - उत्पादकता
 - क्षमता उपयोग
 - लाभ/हानि
 - रोजगार
- (ii) सभी संगत पैरामीटरों ने भारी गिरावट प्रदर्शित की जो 2014-15 में भी जारी रही (तिमाही 1, 2014-15 के आंकड़ों पर आधारित)।

ज. क्षति की चुनौती आसन्न है

सभी संगत पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है। उपर्युक्त के मद्देनजर जब तक शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तब तक घरेलू उद्योग जीवित रहने में सक्षम नहीं होगी। गंभीर क्षति कारित की गई है जैसाकि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक गिरावट आना असंभव है।

झ. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा उपयुक्त है

- (i) यह तर्क दिया गया है कि भारतीय उत्पाद अनब्लेंडेड उत्पादों अर्थात् सी8, सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 का न तो विनिर्माण कर रहे हैं और न ही बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रस्तुत करते हैं कि सी8 का विनिर्माण और बिक्री गोरदेज इंडस्ट्रीज द्वारा एचपीएफएल सहित कई ग्राहकों को की जाती है। मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर के साथ बीजक की प्रतियां संलग्न हैं।
- (ii) जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है इसके पास सी8 का विनिर्माण करने की क्षमता है और वह इसे भारतीय ग्राहकों को देने की इच्छुक है बशर्ते कि इसकी मांग हो।
- (iii) यह भी तर्क दिया गया है कि वीवीएफ द्वारा शुद्ध कट्स की बिक्री नहीं की जाती है और यह कि ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड उत्पादों के बीच भारी कीमत अंतर है। यह सही नहीं है कि क्योंकि ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड उत्पादों की कीमत में बाजार में इसकी मांग और आपूर्ति के आधार पर अंतर आ जाता है।
- (iv) इसके अतिरिक्त प्योर कट अल्कोहलों का ब्लेंडेड उत्पाद का उत्पादन करने के लिए मिश्रण एक साधारण भौतिक ब्लेंडिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसे सिंगल फेज ब्लेंडिंग कहा जाता है।

ब. हितबद्ध पक्षकार-वार टिप्पणियां

- (i) **इंडोनेशिया की सरकार :** घरेलू उद्योग को कारित की गई गंभीर क्षति भारत में खपत की तुलना में घरेलू बिक्री में तीव्र गिरावट से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है और उसे भारी घाटा उठाना पड़ रहा है।

- (ii) **पीटी मुसिम मास** : क्षति अपेक्षाओं को जांच सूची के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसाकि कि इस निर्यातक द्वारा माना जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि बाजार हिस्से में आई गिरावट ईओयू स्कीम के अंतर्गत प्रतिबंधों के कारण आई है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जब तक सकारात्मक एनएफई बना रहता है तब तक डीटीए में वस्तु की बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

समायोजन योजना उचित है।

याचिकाकर्ता ने वर्ष वार प्रक्षेपित बचत को दर्शाते हुए एक विस्तृत समायोजन योजना प्रस्तुत की है। समायोजन योजना की शर्तों के अनुसार घरेलू उद्योग इंडोनेशिया में एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। योजना के अनुसार याचिकाकर्ता इंडोनेशिया तथा अन्य सरकारों द्वारा अधिरोपित भारी निर्यात कर से बचने तथा बेहतर संभारतंत्र लाभ प्राप्त करने, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमतों पर बेहतर ढंग से चर्चा करने और छोटे-छोटे संयंत्रों से पीकेओ प्राप्त करने के विकल्प का लाभ उठाने के लिए आंशिक रूप से प्रसंस्कृत उत्पाद का आयात करेगा। कच्चे माल की लागत में कमी के परिणामस्वरूप भारत में वसीय अल्कोहलों की समग्र उत्पादन लागत में गिरावट आएगी। उस ढंग को दर्शाते हुए जिससे यह बचत प्राप्त की जाएगी एक विस्तृत परिकलन शीट याचिका के अनुबंध-च के रूप में प्रदान कराई गई है।

- (iii) **कुसा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड** : वसीय अल्कोहलों के उन आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं जिनका आयात निर्यात उत्पादों में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह आशंका कि निवेश या रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, गलत है।
- (iv) **क्रोडा इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** : क्रोडा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग कुछ ग्रेडों की बिक्री नहीं करता है। तथापि पत्र में किसी भी ग्रेड विशेषीकृत नहीं किया गया है। क्रोडा ने भारत और विदेश दोनों ही जगहों पर निम्नलिखित ग्रेडों की आपूर्ति के लिए आर्डर्स प्लेस किए हैं जिनकी आपूर्ति हमारे द्वारा कर दी गई है।
- (v) **स्टर्लिंग आक्सीलरीज** : यह तर्क कि वे अनुप्रवाही उद्योग जीवित नहीं बचेंगे जो एंटी आक्सीडेंट्स का विनिर्माण करने में लगे हैं, सही नहीं है और एंटी आक्सीडेंट्स के लिए प्रतिवर्ष केवल 200 एमटी वसीय अल्कोहलों की बिक्री की जाती है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इस उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ेगा।
- (vi) **केएल - केपांग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी/विल्यर/थाई फैटी/गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स** : घरेलू उद्योग एक निर्यातोन्मुख इकाई है जैसाकि विक्रय इस्पात लिमिटेड मामले में तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई विभिन्न जांच परिणामों में धारित किया गया है। हिन्दुस्तान ग्रेवाइट मामले में निर्णय याचिकाकर्ता के इस दावे की और अधिक संपुष्टि की गई है कि वस्तु की डीटीए में बिक्री करने पर वर्ष 2004 में भी कोई प्रतिबंध नहीं था। यह मुद्रा पूर्णतया गैर-न्यायोचित है कि क्षति विनियम नियंत्रण घाटे कारण हुई है। यद्यपि फारेक्स नीति बनी हुई है तथापि, वस्तु की फैक्टरी में वास्तविक प्राप्ति और होजिंग अथवा फैक्टरी से माल की बिक्री के बीच समायान्तराल के कारण फारेक्स लाभ/हानि होगी। याचिकाकर्ता की एक फारेक्स प्रबंधन नीति है। यद्यपि फारेक्स नीति बनी हुई है तथापि, वस्तु की फैक्टरी में वास्तविक प्राप्ति और होजिंग अथवा फैक्टरी से माल की बिक्री के बीच समायान्तराल के कारण फारेक्स लाभ/हानि होगी। वित्तीय विवरण में राजस्व की मान्रूता उस तारीख को होती है जब सिस्टम में वाणिज्यिक बीजक तैयार किया जाता है और उसी तरह सिस्टम में कच्चे माल की लागत भी वस्तु की प्राप्ति की तारीख को तैयार की जाती है। उस फारेक्स दर में, जिस पर राजस्व के साथ-साथ कच्चे माल की लागत की पहचान की जाती है, अंतर होजिंग तारीख बनाम राजस्व/कच्चे माल की लागत पहचान तारीख के बीच समायान्तराल के कारण हो सकता है। आधारभूत रूप से वित्तीय विवरण में दर्शाया गया प्रभाव कच्चे माल की लागत और राजस्व का एक भाग है परंतु उन्हें लेखाकरण मानकों के अनुसार अन्य व्ययों के भाग के रूप में दर्शाया गया है। यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान उच्च विनिमय दर उतार-चढ़ाव था और रुपए में प्रपाती अवमूल्यन हुआ जिसके कारण कारपोरेशन जगत को भारी विदेशी मुद्रा घाटा हुआ। यह उतार-चढ़ाव कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारके के कारण आया जिसमें यूरोजोन संकट भी शामिल है और रुपए के अवमूल्यन से जो डालर की तुलना में 56.40 था। याचिकाकर्ता की क्षतियां उद्योग की प्रवृत्ति की तुलना में बहुत कम है।
- (vii) **मेजर हब** : यह स्पष्ट नहीं है कि केवल गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स के लिए ही शुल्क की मांग करने का आधार क्या है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क आयातक पर ध्यान दिए बिना है।
- (viii) **काविन केयर** : इस शुल्क का शैम्पू पर प्रभाव नगण्य होगा। चूंकि शैम्पू की लागत पर इसका प्रभाव नगण्य है इसलिए काविनकेयर की लाभप्रदता पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (ix) **यूनीडस** : अनुप्रवाही उत्पादकों पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अंतिम प्रयोक्ता भारत के अंदर से क्रय करेंगे, न कि आयात करेंगे, यदि वे "भारत में निर्मित पृष्ठांकन करते हैं। जहां तक भारत को वैश्विक विनिर्माण हब स्थापित करने का संबंध है – यह स्पष्ट किया जाता है कि उन वसीय अल्कोहलों पर शुल्क लागू नहीं होगा जिनका प्रयोग निर्यात उत्पादों के लिए किया जाता है।
- (x) **साल्वे** : पर्सनल केयर और होमकेयर उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए दक्षिणपूर्व एशिया एक बड़ा हब है। इथाक्सीलेट का अधिकांश उत्पादन शैम्पू तथा अन्य उत्पादों के क्षेत्रीय उत्पादकों तक संकुचित है। इन परिस्थितियों में भारत को निर्यात करने के लिए बेशी क्षमता उपलब्ध नहीं है।
- (xi) **विश्वाट कैमिकल्स** : दक्षिण पूर्व एशिया से इथाक्सीलेट्स तथा अन्य अनुप्रवाही उत्पादों के आयातों में उद्रेक होने की संभावना कम ही है क्योंकि इस क्षेत्र में बेशी क्षमता थोड़ी है।
- (xii) **ओमनी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड** : यह तर्क न्यायोचित नहीं है कि अनुप्रवाही उत्पादों के भारी निर्यात साबिक से होंगे। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है अधिक भाड़ा और तकनीकी कारणों से अनुप्रवाही उत्पादों का आयात संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, साबिक को एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क का लाभ भी प्राप्त नहीं है और इसके आयातों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
- (xiii) **पीटी इकोग्रिन** : भारत में खपत की तुलना में घरेलू बिक्री में भारी गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। लाभप्रदायकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा आयातों के बीच सीधा संबंध है।
- (xiv) **हुल** : सह उत्पादों, ग्लिसरीन और वसीय अल्कोहल के लिए व्यय के आबंटन के संबंध में एक संदेह व्यक्त किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे प्रमुख उत्पाद वसीय अल्कोहल है तथा ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का वसीय अल्कोहलों के साथ प्रासंगिक रूप से विनिर्माण किया जाता है। जहां तक समायोजन योजना का संबंध है याचिकाकर्ता इंडोनेशिया स्थित अपने संयंत्र के माध्यम से निर्यात कर बचाने तथा अन्य संभारतंत्रीय लाभ एवं कीमत लाभ प्राप्त करने में सफल रहेगा।
- (xv) **हिन्दुस्तान पालीएमिड्स एंड फाइबर्स लिमिटेड (एचपीएफएल)** : याचिका में उल्लिखित अध्याय शीर्षक केवल संकेतात्मक प्रकृति का है और यह किसी भी रूप में इस उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- (xvi) **मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 29.09.2014 के पत्र के तहत पुनः** यह स्पष्ट किया है कि कुछ पक्षकारों का उनके प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों में दिया गया यह तर्क कि यूएस बाजार स्थिर नहीं है और सिंगापुर से आयातों 715 प्रतिशत वृद्धि हुई है, सही नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि सिंगापुर से आयातों में विशेष रूप से वृद्धि हुई परंतु यूएस में वसीय अल्कोहलों के सभी स्रोतों से आयात में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने यूएस आईटीसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथा उपलब्ध संबद्ध वस्तु के वर्षवार आयात आंकड़ों संलग्न किए हैं।

छ.11 मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समर्थक) द्वारा अपने दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत किया गया प्रस्तुतिकरण

- (क) पीटी मुसिम मास ने अपनी प्रस्तुतिकरण के पैरा 3.9.2 में यह उल्लेख किया है कि जीआईएल की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2013-14 और वर्ष 2012-13 में क्रमशः 7 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 की बिक्री यात्रा की तुलना आधार वर्ष 2010-11 से किया जाना अपेक्षित है। आधार वर्ष की तुलना में बिक्री में वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में बिक्री की लागत पर मार्जिन बनाए रखा गया है जबकि वर्ष 2012-13 और 2013-14 में उपभोक्ता का मार्जिन बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
- (ख) हम मैसर्स विश्वाट लिमिटेड द्वारा उनके प्रस्तुतिकरण के पैरा 2 में लगाए गए आरोप का खंडन करते हैं कि हमने उनको संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने से मना कर दिया। हम विश्वाट को सीटो स्टियरिल अल्कोहल की लगातार आपूर्ति करते हुए हैं, जब कि उनकी ओर से मांग की गई।
- (ग) विश्वाट और आरती के लिखित प्रस्तुतिकरणों में यथाआरोपित जीआईएल को कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता है। रक्षोपाय शुल्क से घरेलू उद्योग की तथा अन्य उत्पादों की आकस्मिकता वर्धित आयातों द्वारा कारित क्षति से रक्षा किया जाना अपेक्षित होता है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने से घरेलू उद्योग तथा अन्य उद्योग जैसे जीआईएल वसीय अल्कोहल क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे क्योंकि तब उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे।
- (घ) जीआईएल के पास टोलिंग व्यवस्था के अंतर्गत इथाक्सीलेशन और इथाक्सीलेट्स की इनहाउस उपलब्धता नहीं है। अतः घरेलू इथाक्सीलेट्स को प्रभावित करने का प्रश्न नहीं उठता है। जीआईएल की सल्फोनेशन क्षमता भी सीमित है (उद्योग क्षमता का 15 प्रतिशत - 20 प्रतिशत और यह बाजार में अग्रणी उद्यमों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए यह तर्क गलत है कि जीआईएल एसएलईएस/एसएलएस उद्योग को विपरीत ढंग से प्रभावित करेगा।

- (ड) हुल द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 58 में यह उल्लेख किया गया है कि जीआईएल की 50 प्रतिशत क्षमता ईओयू के रूप में पंजीकृत है, परंतु यह सही नहीं है। जीआईएल की घरेलू क्षमता इसकी कुल क्षमता की लगभग 70 प्रतिशत है। इसलिए घरेलू बाजार की जरूरत को जीआईएल द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी ईओयू इकाई द्वारा डीटीए को की गई बिक्रियों पर ईओयू स्कीम में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (च) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान क्रोडा द्वारा उल्लेख किया गया कि भारतीय उत्पादक सी1618 की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम यह प्रस्तुत करते हैं कि हमने क्रोडा को नियमित आपूर्ति की है और नमूना दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
- (छ) हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में सी8 और सी10 वसीय अल्कोहलों की आपूर्ति भी की है। हम यह प्रस्तुत करते हैं कि सी8 वसीय अल्कोहल की जीआईएल द्वारा एचपीएफएल सहित कई ग्राहकों को बिक्री की गई है (नमूना बीजक संलग्न)।
- (ज) इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय उत्पादक अन्ब्लेडेड उत्पादों अर्थात् सी8, सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 की न तो विनिर्माण करते हैं और न ही उसकी बिक्री करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड उत्पादों के बीच भारी कीमत अंतर है। यह इस कारण से सही नहीं है कि ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड उत्पादों की कीमत में बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति के आधार पर अंतर आ जाता है। यदि अन्ब्लेडेड ग्रेड्स का अपवर्जन कर दिया जाता है तो आयात प्योर कट्स का आयात करके और फिजिकल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से ब्लेंडस का उत्पाद करके शुल्क अवबंचना कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि सी16 और सी18 की बिक्री करेगा। आयातक उनका उसी अनुपात में ब्लेंड तैयार करेंगे। इस समय चूंकि सी 16 और सी18 उपलब्ध है, सी 16 और सी8 के लिए मांग कम है और इसलिए इन उत्पादों की कीमत अधिक है। हम पुनः यह प्रस्तुत करते हैं कि प्योर कट्स की फिजिकल ब्लेंडिंग हमारी फैक्टरी के जरूरत पड़ने पर अक्सर की जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया नहीं है और इसे आयातक/ग्राहक द्वारा आसानी से किया जा सकता है।
- (झ) यह उल्लिखित और इस प्रक्रिया से संगत किसी अन्य पहलू के लिए जीआईएल एतद्वारा, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों को ही यथासंभव सीमा तक स्वीकार करता है।

ज. अन्य पक्षकारों द्वारा प्रत्युक्तियां

ज.1 मैसर्स हिन्दुस्तान पोलीएमिड्स एवं फाइबर्स लिमिटेड (एचपीएफएल) द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2 के पत्र के तहत किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (क) साक्ष्य की पर्याप्तता एवं उपयुक्तता के संबंध में शुल्क का उदग्रहण किए जाने की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है।
- (ख) महानिदेशक को उन्हीं सिद्धांतों को अनुपालन करना चाहिए जो निदेशालय द्वारा अन्य जांचों में किए गए हैं; यदि कोई विपथन किया गया है तो इस विपथन के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए खासकर घरेलू उद्योग के आधार, विचाराधीन उत्पाद, आयात आंकड़ों का स्रोत और क्षति विश्लेषण के संबंध में।
- (ग) आवेदक उद्योग ने हमारे इस दावे का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है कि वे न तो सी8 का उत्पादन कर रहे हैं और न ही ऐसा करने का उनका इरादा है। प्योर कट्स ब्लेंडस से तुलनीय नहीं है।
- (घ) घरेलू उद्योग को क्षति सी8 के आयातों द्वारा कारित की जा सकती है क्योंकि आवेदक उद्योग सी8 का उत्पादन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त सी8 और सी10 का उत्पादन करना उनके लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं है क्योंकि इन उत्पादों पर शुल्क की सिफारिश करने का कोई औचित्य भी नहीं है।
- (ड) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना न केवल विधायी रूप से गलत है बल्कि यह अंतिम प्रयोक्ता में हितों के भी विपरीत है।
- (च) महानिदेशक द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक प्रस्तुतिकरण किए जाने और लिखित प्रस्तुतिकरण करने और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार की तरह प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति दिए जाते ही गैर-पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में अधिकारों एवं स्टेट्स का मुद्दा समाप्त हो जाता है। "हितबद्ध पक्षकारों" को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देना अपेक्षित नहीं है। नियम 6(6) के अंतर्गत केवल विधिक प्रावधान यह है कि मौखिक सूचना पर तब विचार किया जाना चाहिए जब इसका लिखित प्रस्तुतिकरण किया गया हो।

झ. शुद्ध सी8 ग्रेड के संबंध में जांच

- (क) मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 19.09.2014 के लिखित प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण की जांच के दौरान यह नोटिस किया गया है कि वे सी8 सिंगल कट का विनिर्माण और उसकी बिक्री कर रहे हैं और उसका उन्होंने समर्थन किया है,

उन्होंने बीजकों की संगत प्रतियां भी संलग्न की है। यह नोटिस किया गया कि शुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल के वास्तविक उत्पादन का तथ्य रिकार्ड में इससे पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार या किसी अन्य पक्षकार ने इससे पहले यह मुद्दा उठाया था। इसलिए, निदेशालय को उपलब्ध कराए गए इस नए साक्ष्य का प्रत्युत्तर देने का हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) ने दिनांक 24.09.2014 को इस साक्ष्य का सभी हितबद्ध पक्षकारों (अन्य पक्षकारों सहित) को इस निदेश के साथ परिचालित करने का आदेश दिया कि वे अपने प्रत्युत्तर दिनांक 29.09.2014 तक प्रस्तुत कर दें। इसका परिचालन घरेलू उद्योग तथा समर्थकर्ता मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज को भी किया गया था।

(ख) यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग तथा समर्थनकर्ता मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने दिनांक 25.09.2014 को पत्रों के तहत अपने विचार व्यक्त किए कि उन्हें शुद्ध सी8 का इस जांच के दायरे में अपवर्जन कर दिए जाने में कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि इस ग्रेड के लिए भारतीय बाजार बहुत सूक्ष्म है। चूंकि घरेलू उद्योग और उसके समर्थक दोनों ने ही साफ तौर पर विशुद्ध सी8 का विचाराराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी इसलिए विचाराधीन उत्पाद को संशोधित/ परिशोधित कर दिया गया। इसलिए, समर्थक के दिनांक 19.09.2014 के प्रस्तुतिकरण पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों की प्रत्युक्तियों की कोई संगतता नहीं रह जाती है तथापि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर अकादमिक प्रयोजन से निम्नलिखित चर्चा की जा रही है।

ज. मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज द्वारा दिनांक 19.09.2014 के पत्र के तहत प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचार

ज.1. मैसर्स टीपी मुसिम दिनांक 29.09.2014

- (क) विलगीकरण करके घरेलू बिक्रियों का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि क्या जीआईएल के निष्पादन पर आयातों का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक विश्लेषण करना चाहिए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, खासकर, संबंधित उत्पाद के आयातों में समग्र एवं संगत रूप से वृद्धि की दर एवं मात्रा, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग के हिस्से पर किया गया कब्जा, बिक्री उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ, हानि एवं रोजगार के स्तर में परिवर्तन आदि।
- (ख) आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में घरेलू बिक्री में गिरावट केवल 2 प्रतिशत से कम है।
- (ग) जीआईएल का यह दावा है गलत है कि उसकी बिक्रियों में वृद्धि लाभप्रदता की कीमत पर हुई है। जीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट यह इंगित करती है कि वसीय अल्कोहल प्रभाग ने इसके रसायन प्रभाग के व्यवसाय में काफी टर्नओवर किया है।
- (घ) इसके अतिरिक्त, जीआईएल ने अपने प्रस्तुतिकरण के पैरा 6 में यह उल्लेख किया है कि "किसी ईओयू स्कीम में कोई प्रतिबंध नहीं है।" यह सही नहीं है। जीआईएल डीटीए में अपने सामान की बिक्री सकारात्मक एनएफई पूरा करने पर ही कर सकता है।
- (ङ) चूंकि वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड एक 100 प्रतिशत ईओयू है और जीआईएल भी समर्पित ईओयू है इसलिए यदि दोनों कंपनियों की निर्यात बिक्री में गिरावट आती है तो उसका संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। भारत में उत्पादित वसीय अल्कोहल में कमी होने से भारत में संबद्ध वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए ईओयू द्वारा संबद्ध वस्तु की डीटीए में बिक्री करने का प्रतिबंध है और इसका संबद्ध वस्तु के घरेलू प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।

ज.2. मैसर्स हुल दिनांक 29.09.2014

- (क) सुनवाई पश्चात प्रस्तुतिकरणों में गोदरेज की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, महानिदेशक रक्षोपाय इतने विलंबित स्तर पर प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
- (ख) महानिदेशक रक्षोपाय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि "प्रचालन मार्जिन" (जैसा कि गोदरेज ने अपने प्रस्तुतिकरण में उल्लेख किया है) का आशय क्या है। इस डाटा के किसी स्रोत अथवा उसकी विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।
- (ग) हुल के प्रस्तुतिकरण के पैरा 4 में किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएलईएस/एसएलएस उद्योग पर केवल गोदरेज का ही प्रभाव नहीं है बल्कि अनुप्रवाही उद्योग के लिए यह प्राथमिक चुनौती बना रहता है।
- (घ) जहां तक गोदरेज द्वारा पैरा 6 में किए गए उल्लेख का संबंध है यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि गोदरेज के दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो गोदरेज के लिए डीटीए क्षमता में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत का विस्तार गोदरेज की कुल क्षमता में केवल 77 प्रतिशत का (आधार के रूप में कुल क्षमता) विस्तार होगा जो नगण्य है।

- (ङ) गोदरेज का डीटीए उत्पादन वीवीएफ में "घरेलू उत्पादन" से अधिक है। इसलिए गोदरेज का घरेलू उत्पादन में वीवीएफ से अधिक हिस्सा है।
- (च) गोदरेज ने अपने प्रस्तुतिकरण के पैरा 2 और 7 में यह कहा है कि वह सी1618 ब्लेंड का उत्पादन करता है तथा उसने क्रोडा को उसकी नियमित आपूर्ति की है। तथापि, चूंकि गोदरेज घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है इसलिए गोदरेज की ब्लेंड की व्यापारी बाजार में बिक्री को देखना सही नहीं है।
- (छ) इस प्रस्तुतिकरण के पैरा 9 में कहा गया है कि वसीय अल्कोहलों के अनब्लेंडेड उत्पादों की कीमत ब्लेंडेड उत्पादों की तुलना में अधिक होती है और यह अंतर 20 प्रतिशत से अधिक होता है- जिसकी "प्रवंचना" करने का प्रयास करना आयातक का, गोदरेज के अनुसार, कर्तव्य है।

ज.3. मैसर्स पीटी इकोग्रिन दिनांक 29.09.2014

- (क) जीआईएल की वार्षिक बिक्री के आंकड़े केवल सकारात्मक प्रवृत्ति ही दर्शाते हैं। यह दर्शाते हैं कि जीआईएल की घरेलू बिक्रियां स्थिर थीं। उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और आयातों की प्रवृत्ति का एफओएच के आयातों का घरेलू निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि वर्ष 2011-12 में इसकी बिक्री घट गई थी, जबकि भारत को आयातों की मात्रा वर्ष 2012-13 और 2013-14 की तुलना में कम थी।
- (ख) रक्षोपाय जांच में यह एक सामान्य परम्परा है कि उद्योग के संकेतकों की जांच में केवल आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि की संपूर्ण अवधि की प्रवृत्तियों की जांच की जाए। महानिदेशक रक्षोपाय के प्रारंभिक जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि जीआईएल की घरेलू बिक्रियों की दर में मासिक और तिमाही विश्लेषण के आधार पर सकारात्मक वृद्धि हुई है।
- (ग) कारणात्मक संबंध में कई संवेदनशील कारक हैं जैसे याचिकाकर्ता की ईओयू के रूप में स्थिति, भारत आशियाना एफटीए के अंतर्गत एफओएच पर आयात शुल्क समाप्त करना, एफओएच के आयातों पर ईयू द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने से याचिकाकर्ता का अल्प निर्यात निष्पादन, उच्चतर प्रशुल्क के कारण चीन को निर्यात करने में अक्षमता, जैसे गोदरेज अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों में उल्लेख करने में पूर्णतया असफल रहा।
- (घ) जीआईएल ने अनपेक्षित विकास, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती, कारणात्मक संबंध तथा गैर-एट्रीब्यूशन कारक की अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में कही भी जांच नहीं की है, इसके अभाव में जीआईएल याचिकाकर्ता को समर्थन देने में असफल रहा है।

ज.4. मैसर्स यूनीडस दिनांक 29.09.2014

- (क) यह समझ में नहीं आता है कि जीआईएल नया मद्दा कैसे उठा सकता है और इस स्तर पर दस्तोवज कैसे प्रस्तुत कर सकता है। यह लाभ अन्य हितवद्ध पक्षकारों को भी दिया जाना चाहिए।
- (ख) मैसर्स वीवीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्युक्ति भी परिचालित की जानी चाहिए।
- (ग) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्तागण अनुप्रवाही उत्पादों का आयात कर रहे हैं और आवेदक तथा अन्य स्थानीय उत्पादकों दोनों को ही आशियान देशों में सल्फोनेटर्स तथा इथाक्सीलेटर्स के बड़े व्यापारियों के हाथों अपना व्यवसाय खो रहे हैं क्योंकि एफटीए के अंतर्गत 0-6 प्रतिशत पर परिष्कृत उत्पाद का आयात करने की अनुमति है।

ज.5. मैसर्स विश्वाट, दिनांक 29.09.2014 की ई-मेल

- (क) हमारे प्रस्तुतिकरण के प्रत्युत्तर में गोदरेज ने अपने सीटों स्टियराइल अल्कोहल टीए1618 की हमें दी गई आपूर्ति का विवरण दिया है। तथापि उन्होंने वसीय अल्कोहल 1214 की हमें आपूर्ति के संबंध में कुछ नहीं कहा। हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने वसीय अल्कोहल 1214 का उल्लेख किया है न कि सीटो स्टियराइल अल्कोहल का।
- (ख) प्रत्युक्ति स्तर पर नए प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (ग) घरेलू उद्योग ने कई बार ग्राहकों के उद्धरण पर प्रदायगी नहीं की या ग्राहकों की अनुसूची के अनुरूप बिक्री नहीं की।
- (घ) गोदरेज सीटों स्टियराइल का बीजक दिया है जबकि उत्कृष्ट बाजार सी1214 की है।
- (ङ) गोदरेज ग्राहकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इथाक्सीलेशन संयंत्र होने के बावजूद गोदरेज और वीवीएफ की टोलिंग पर आसान पहुंच थी।

ख.6. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिनांक 29.09.2014

- (क) प्रत्युक्ति के भाग के रूप में नए प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं करने चाहिए।
- (ख) गोदरेज ने लारियल अल्कोहल की आपूर्ति पर कमीबल नहीं दिया।
- (ग) गोदरेज के अनुप्रवाही उत्पादों के विनिर्माण में अनुचित लाभ होगा और वह बाजार को बनाने, बिगाड़ने, विकृत करने में अपना योगदान दे सकता है।

ट. मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 19.09.2014 के प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**ट.1 मैसर्स एचपीएफएल दिनांक 29.09.2014**

- (क) हमें दिनांक 26.08.2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिखित प्रस्तुतिकरण प्रदान नहीं किए गए, उनके ई-मेल कतिपय हितबद्ध पक्षकारों को ही किए गए।
- (ख) उक्त पक्षकार ने डीजी से नए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विशेष अनुमति मांगने के किसी आधार पर परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है, यह पहले रिकार्ड का भाग नहीं था परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका संज्ञान जांच के इतने विलंबित स्तर पर लिया गया।
- (ग) इस बात का कोई संकेत नहीं है कि माननीय डीजी ने जांच के इतने विलंबित स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति दी भी या नहीं।
- (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रक्षोपाय विधि में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में विचार किए जाने का प्रस्ताव है या नहीं क्योंकि वह जांच शुरूआत अधिसूचना में या प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग का भाग नहीं था। यदि डीजी अब गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में विचारने का प्रस्ताव करते हैं तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विधिक वैधता पर विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। खासकर तब जब कि उक्त पक्षकार समान वस्तु का आयातक है और वह आयातों में कथित वृद्धि में अपना योगदान देता है।
- (ङ) जहां तक गोदरेज द्वारा प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण में किए गए उल्लेख और साक्ष्य का संबंध है, हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकृष्ट करते हैं :
 - (i) बीजक की प्रतियां वैध नहीं हैं।
 - (ii) अधिकांश संवेदनशील जानकारी जैसे बीजक की तारीख गोपनीय रखी गई है।
 - (iii) अपने क्लायंट एचपीएफएल की ओर से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गोदरेज ने भी वर्ष 2011 के बाद सी8 की आपूर्ति नहीं की है। उन्होंने बार-बार यह उल्लेख किया है कि सी8 के व्यवसाय में उनकी कोई रुचि नहीं है। इसके अतिरिक्त, गोदरेज या घरेलू उद्योग किसी ने भी सी8 का क्रय करने के हमारे प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही उन्होंने डीजी कोई विशिष्ट आश्वासन दिया है कि वे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सी8 की आपूर्ति करते हैं।
 - (iv) यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि गोदरेज ने सी8 और सी10 का उत्पादन करने से संबंधित उत्पादन सूचना को भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर में गोपनीय रखा है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।
 - (v) गोदरेज का यह दावा पूर्णतया गलत है कि सी8 तथा उनके ब्लेंड्स की कीमतों में कोई अंतर नहीं है।

इन दोनों उत्पादकों के लिए रिकार्ड में ऐसी कोई समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम अपनी टिप्पणियां कर सकें।

ट.2 मैसर्स क्रोडा दिनांक 29.09.2014 के पत्र के तहत

- (क) हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्युक्ति के बिन्दु 7 में हमारे दिनांक 26.08.2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का गलत अभिकथन किया गया है। हमने इस बैठक में यह उल्लेख किया था कि एक घरेलू उत्पादक वीवीएफ पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्बोनायल मूल्य विनिर्देशनों की हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सी18 उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर सकता, वहीं दूसरा घरेलू उत्पादक गोदरेज को भी वर्ष 2013-14 के दौरान हमारी डिलीवरी तारीखों पर हमारे विनिर्देशनों को पूरा करने वाली मात्रा की आपूर्ति करने में असफल रहा है।
- (ख) सी12-14 की गोदरेज के पास उपलब्धता एवं उसकी आपूर्ति के संबंध में जैसा कि 2011 के मध्य से हमारे द्वारा तथा इसके अन्य उपभोक्ताओं द्वारा हाईलाइट किया गया है – गोदरेज के प्रतिनिधि ने हमें मौखिक रूप से बताया कि वे सी12-14 की बिक्री बाह्य ग्राहकों को नहीं करते हैं और इसका प्रयोग के इन-हाउस खपत के

लिए ही किया जाता है। हम उनसे अप्रैल, 2014 तथा जुलाई-अगस्त, 2014 में ही मिले थे। तथापि उन्होंने उसकी संपुष्टि लिखित रूप में कभी नहीं की।

ठ. महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जांच एवं जांच परिणाम

1. मैंने इस मामले के रिकॉर्डों, घरेलू उद्योग, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर अधोलिखित समाधान कर दिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच घरेलू विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत समालोचनात्मक परिस्थितियों की मौजूदगी के संदर्भ में की गई। रक्षोपाय करार के प्रावधानों और डब्लू टी ओ निकायों के निर्णयों के प्रावधानों का समुचित स्थानों पर उल्लेख किया गया/उन पर चर्चा की गई। तदनुसार ही अपने जांच परिणाम दिए गए हैं। यह, अनन्तिम जांच परिणाम जो घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों/आवेदन पत्रों, हितबद्ध पक्षकारों के जांच शुरूआत पश्चात प्रत्युत्तरों तथा अन्य आंकड़ा के आधार पर किया गया है।
2. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का वर्णन करती है। धारा 8ख की उप-धारा (1) में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है जिसका भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा रहा हो जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती हो या जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
3. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले तरीकों एवं सिद्धांतों का प्रावधान है। यह नियम सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के अंतर्गत बनाए गए हैं। मुझे इन नियमों के अंतर्गत विधि के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
4. मैं उपपादित करता हूँ कि हितबद्ध पक्षकारों में से एक हितबद्ध पक्षकार ने आशियान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के मद्देनजर इस रक्षोपाय आवेदन पर कार्रवाई करने में इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया और यह धारित किया है कि चूंकि अधिकांश आयात आशियान राष्ट्रों में उद्धवित हुए हैं और वाणिज्य विभाग जो इन एफ टी ए में वार्ताकारी रहा है, ही राहत प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए। इस मुद्दे का अनन्तिम आधार पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते समय अच्छी तरह से समाधान कर दिया गया था। तथापि, मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस मामले में जांच करने के लिए महानिदेशक किस तरह जिम्मेदार है।
5. इस संबंध में, मैंने उक्त द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार का गंभीरता से अध्ययन किया। इस संधि से एक उद्धरण देना पर्याप्त होगा।

अनुच्छेद 10

रक्षोपाय साधन

1. प्रत्येक पक्षकार जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है उसे गाट 1994 के अनुच्छेद XIX, डब्लू टी ओ करार के अनुबंध 1 क में उल्लिखित (रक्षोपाय करार) और डब्लू टी ओ करार (कृषि संबंधी करार) के अनुबंध 1 क में कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपने अधिकार एवं दायित्व प्रतिधारित करता है। गाट 1994 के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार या कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई ढांचागत करार के अंतर्गत (आशियान भारत डी एस एम करार) विवाद निपटान तंत्र करार के अधीन नहीं होगा।

1.1 उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत कि इस मामले में राहत प्रदान करने के लिए रक्षोपाय निदेशालय एक उपयुक्त मंच नहीं है। यह प्रेक्षण किया जाता है कि विभिन्न करारों में व्यापार असंतुलन का समाधान करने के लिए वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान किया गया है जिससे कि व्यापार असंतुलन दूर हो सके, रक्षोपाय महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के तत्वाधान में कार्य कर रहे के, अंतर्गत अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में आशियान मुक्त व्यापार करार में स्वयं यह प्रावधान किया गया है कि इस संधि के होते हुए भी डब्लू टी ओ सदस्य (भारत सहित) रक्षोपाय करार के अंतर्गत आने वाले अपने सभी अधिकार एवं दायित्वों का प्रतिधारण करेंगे।

1.2 इसके अतिरिक्त सामान्य रक्षोपाय साधन का अधिरोपण बिना किसी भेदभाव के विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, निर्यात के देश पर विचार किए बिना, न्यूनतम के प्रावधान को छोड़कर और उसके अलावा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (1) के परन्तुक के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने वर्तमान मामले में सामान्य रक्षोपाय साधनों के अंतर्गत राहत प्राप्त करने का आश्रय लिया है जो मौजूदा विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतया

न्यायोचित है। इसलिए, प्रचुर मात्रा में यह स्पष्ट है कि इस कार्यालय को आवेदक के वर्तमान मामले में रक्षोपाय आवेदन पर कार्रवाई करने का प्राधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है और तदनुसार मैं यह जांच परिणाम रिकॉर्ड करने की कार्रवाई करता हूँ।

6. यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना द्वारा रिकार्ड किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान इस जांच परिणाम उपयुक्त स्थानों पर एवं अधोलिखित समाधान कर दिया गया :

7. घरेलू उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए साक्षात्कार का कई हितबद्ध पक्षकारों में उल्लेख किया है, जहां उसने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग की विगत 10 वर्षों में भारी उन्नति हुई है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 29.09.2014 का एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कैमिकल वीकली को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कैमिकल वीकली के साथ एक पत्राचार का भी उल्लेख किया है जिसमें एक स्पष्टीकरण अगले संस्करण में प्रकाशित किया जाता है। चूंकि यह जांच परिणाम घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सत्यापित सूचना पर आधारित है, साक्षात्कार पर कोई भरोसा व्यक्त नहीं किया गया।

8. जांचाधीन उत्पाद का दायरा : विचाराधीन उत्पाद 'सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, या सी18 लम्बाई के कार्बन चैन युक्त एकल, मिश्रण और अमिश्रण सहित (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं), जिनमें एकल सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 (जिन्हें सामान्यतः सी12-सी14 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) सैचुरेटेड वसीय अल्कोहल शामिल हैं' **परंतु विशुद्ध सी8 का अपवर्जन करते हुए जिन्हें एतद पश्चात 'पी यू सी' (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है।** आयात किया जा रहा यह विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 23237090 और 29051700 के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सैंकतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग मुख्यतः सर्फैक्टेंट्स, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, भेषजों और कृषि संबंधी अंतिम अनुप्रयोगों, चर्म, वस्त्र, फर, पल्प, कागज, पेट्रोलियम उत्पाद कैमिकल रबड़ उत्पादों के श्रेष्ठ रसायनों लिए किया जाता है, रबड़ उत्पादों, प्लास्टिक और फेब्रिकेट किए गए धातु उत्पाद जिसमें खनन अपतटीय प्रचालन निर्माण कार्य साल्वेंट के रूम में और डीग्रीजिंग उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद की बिक्री खुदरा स्तर पर नहीं की जाती है और यह केवल औद्योगिक प्रयोगों के लिए ही होता है।

9. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद के दायरे को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न शाखा श्रृंखला के संमिश्रित/वसीय अल्कोहल भिन्न मर्दें हैं। यह विधि की अपेक्षा है कि ऐसे घरेलू उद्योग को क्षति होनी चाहिए जो समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करते हों। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहल आयातित वस्तु के तुलनीय है और वे वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से आयातित वस्तु के अंतर्निमेय हैं। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद में उन ग्रेडों/प्रकारों को शामिल किया गया है जो तकनीकी गुणधर्मों, रासायनिक संघटन और अन्य संबंधित आधारभूत पहलुओं के रूप में समान हों। इन सभी शीर्षकों के उत्पादों का प्रयोग समान होता है। इसलिए यह सभी उत्पाद समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं। छोटे-छोटे संभव आभासी अंतरों के बावजूद, इन सभी उत्पादों का समान भौतिक गुणधर्म होता है और उनके समान प्रयोग होते हैं। उनका विपणन बिक्री समान या समरूप बिक्री सरणियों के जरिए की जाती है।

10. घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में एक कच्चे माल से व्युत्पन्न सभी ग्रेडों/प्रकारों तथा कार्बन चैन सी8 से सी18 के संपूर्ण सेट को एकल श्रेणी के उत्पाद के रूप में देखे जाने की जरूरत है। इन सभी का अनुप्रयोग मोटे तौर पर सामान्य होता है अर्थात् इनका प्रयोग डिटर्जेंट और निजी देखभाल उद्योग में किया जाता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार सी12 सी14 और सी16 सी18 दोनों को इथैक्सीलेट्स में संपरिवर्तित किया जा सकता है और डिटर्जेंट अनुप्रयोगों में उनका प्रयोग सर्फैक्टेंट के रूप में होता है। सी12 सी18 जो कि सी12 सी14 और सी16 सी 18 का संमिश्रण है, का प्रयोग भी उन्हीं अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। सी14 पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सी12 सी14 के संमिश्रण का एक भाग है। इसके अतिरिक्त, यह विचार करना संगत होगा कि साबुन, डिटर्जेंट, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में वसीय अल्कोहलों की मात्रा 10 प्रतिशत से भी कम होती है। विभिन्न संमिश्रणों की वाणिज्यिक एवं तकनीकी अंतरनिमेयता होती है। अंतिम प्रयोग उत्पाद का आवश्यक गुणधर्म वसीय अल्कोहल से प्राप्त नहीं होता है बल्कि यह अन्य सामग्री, जो प्रमुख होती है और/या भारी मात्रा में अंतिम उत्पाद में मौजूद होती है, से प्राप्त होता है। इन उत्पादों के बीच कीमत के संबंध में प्रतिस्पर्धा होती है। यह रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि याचिकाकर्ता तलोजा यूनिट में लुर्गी प्रक्रिया का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया द्वारा एक उत्पाद जिसे वाणिज्यिक रूप से कोकोनट अल्कोहल के रूप में जाना जाता है और जो सी8 से सी18 का संमिश्रण होता है, का उत्पादन किया जाता है। प्रभाजन आसवन प्रक्रिया द्वारा किसी प्रभाजन-सी8

से सी18 को लिया जा सकता है। इसलिए चूंकि यह मदे अंतर निमेय हैं और समरूप विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा समरूप कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इस मामले में विचाराधीन उत्पादकों सही परिभाषित किया गया है।

11. एक हितबद्ध पक्षकार (जो पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार नहीं है) मैं हिन्दुस्तान पालीएमिड्स एंड फाइबर्स लिमिटेड (एचएफपीएल) का यह तर्क है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान सी8 और सी10 वसीय अल्कोहल का विनिर्माण नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने सी8 और सी10 का विनिर्माण नहीं किया है इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के उनके वर्णन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में है, मैं यह पाता हूँ कि घरेलू उद्योग ने ऐसे साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उन्होंने सी10 का उत्पादन उत्पाद कर का भुगतान करके किया है। जहां तक सी8 का संबंध है, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उनके पास सी8 का विनिर्माण करने की क्षमता है परन्तु चूंकि इस उत्पाद की भारत में मांग कम है, इसलिए उन्होंने इस ग्रेड की बिक्री नहीं की है। तथापि, उन्होंने सी8 वसीय अल्कोहलों का विनिर्माण करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है और न ही कोई विवाद किया है। एक अन्य भारतीय उत्पादक अर्थात् मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए इस रक्षोपाय आवेदन पत्र का समर्थन करता है, ने यह दर्शाने के लिए बीजक प्रस्तुत किए हैं कि उसने क्षति अवधि के दौरान शुद्ध सी8 का उत्पादन और उसकी बिक्री की है।

12. इस संबंध में यह नोट करना उचित है कि घरेलू उद्योग द्वारा सी8 वसीय अल्कोहल को इस विचाराधीन उत्पाद में उसका विनिर्माण करने की उनकी क्षमता के कारण शामिल किया है, जिसका किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। तथापि, यह भी एक तथ्य है कि जब घरेलू उद्योग वास्तव में उक्त उत्पाद का विनिर्माण नहीं कर रहा है तो उसकी आयातित समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि विशुद्ध सी8 का भारत में आयातों होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग के प्रयोग के लिए घरेलू रूप से उत्पादित सी8 वसीय अल्कोहल उपलब्ध नहीं है, जैसाकि पक्षकार द्वारा उल्लेख किया गया है। तदनुसार, यह उपपादित किया जाता है कि घरेलू उद्योग के घरेलू आंकड़ों में कहीं भी आयातित विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल का जिक्र कहीं नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल को ब्लेंड्स के साथ शामिल करने का उद्देश्य ब्लेंड्स (सी8 तथा अन्य सहित) के बजाय वसीय अल्कोहलों का आयात करके संभावित परिवर्चना को रोकने और बाजार में बिक्री के लिए वांछित जरूरत के अनुसार मिश्रण करने का इरादा था। मैं यह भी नोट करता हूँ कि घरेलू उद्योग द्वारा शुरुआत में दी गई सूचना में सी8 के आयात की सूचना शामिल थी परन्तु सी8 से संबंधित प्रशुल्क शीर्ष 29051690 को शामिल नहीं किया गया था।

13. मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विशुद्ध सी8 का उत्पादन करने और उसकी बिक्री के बीजक के संबंध में दिनांक 19.09.2014 के प्रत्युक्ति पत्र के तहत प्रस्तुत सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों तथा अन्य पक्षकारों को टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स वीवीएफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने-अपने दिनांक 25.09.2014 के पत्रों के तहत यह उल्लेख किया है कि समर्थनकर्ता उद्योग द्वारा बहुत अल्प मात्रा में विनिर्माण पर विचार करते हुए उन्हें इस ग्रेड के लिए बहुत कम भारतीय बाजार होने के कारण जांचाधीन उत्पाद के दायरे से विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल का अपवर्जन कर दिए जाने पर कोई ऐतराज नहीं है। समर्थनकर्ता उद्योग ने विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल के उत्पादन, बिक्री आदि से संबंधित विवरण भी प्रदान किया है जो निम्नलिखित है :

14. विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल का अपवर्जन करने के पश्चात कुल उत्पादन और बिक्री की विवरण निम्नलिखित है।

एमटी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 पहली तिमाही
अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	118582	96344	112613	143232	28319
विशुद्ध सी8 का समर्थनकर्ता द्वारा उत्पादन (अपवर्जित)	208	37	31	0	0
वास्तविक अखिल भारतीय उत्पादन	118374	96307	112582	143232	28319
भारतीय उत्पादकों की कुल बिक्री	8242	6677	7573	8728	2485
समर्थनकर्ता की विशुद्ध सी8 की बिक्री (अपवर्जित)	33	26	31	15	0
भारतीय उत्पादकों की कुल वास्तविक बिक्री	8209	6651	7542	8713	2485

मैं यह उपपादित करता हूँ कि समर्थनकर्ता उत्पादक ने भी विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहलों की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और बिक्री नहीं की है। समर्थनकर्ता द्वारा विशुद्ध सी8 ग्रेड वसीय अल्कोहल का अपवर्जन करने की पेशकश पर इसलिए उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग एवं समर्थनकर्ता द्वारा तथा एक अन्य पक्षकार मैसर्स एचपीएफएल द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल का अपवर्जन करने का विचार स्वीकार्य प्रतीत होता है।

15. उपर्युक्त के मद्देनजर मैं वर्तमान जांच के दायरे से विचाराधीन उत्पाद की परिधि से विशुद्ध सी8 वसीय अल्कोहल का अपवर्जन करने के लिए सहमत हूँ। उपर्युक्त कारणों से विचाराधीन उत्पाद में इस सीमा तक संशोधन/परिवर्तन किया जाता है और संशोधित/परिवर्तित विचाराधीन उत्पाद "सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, या सी18 लम्बाई के कार्बन चैन युक्त एकल, मिश्रण और अमिश्रण सहित (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं), जिनमें एकल सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 (जिन्हें सामान्यतः सी12-सी14 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) सैचुरेटेड वसीय अल्कोहल शामिल हैं' परंतु विशुद्ध सी8 का अपवर्जन करते हुए जिन्हें एतद पश्चात 'पी यू सी' (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है।

16. **घरेलू उद्योग** : सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के खंड (6) (ख) में उल्लेख है कि :

(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय उन उत्पादकों से होता है

क. जो भारत में समग्र रूप से समान वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादकों, या

ख. जिनका भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामूहिक रूप से उत्पादन भारत में उस घरेलू उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो।

यह आवेदन पत्र मैसर्स वी वी एफ (भारत) लिमिटेड मुम्बई, एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई, द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदक कुल भारतीय उत्पादन के 65 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है। मामले के रिकार्ड के अनुसार एक अन्य उत्पादक मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("जीआईएल") भी इसका उत्पादन करता है।

17. मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने दिनांक 22 जवरी, 2014 के पत्र के तहत, मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया है और वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक के लिए अपने उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। यह उपपादित किया जाता है कि रक्षोपाय जांच में समर्थनकर्ता जैसी कोई संकल्पना नहीं है। इसलिए उन्हें इस जांच में घरेलू उद्योग नहीं माना गया है। तथापि, इस मुद्दे से संगत होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को क्षति विश्लेषण के लिए रिकार्ड में ले लिया गया है। भारत में इस उत्पाद के कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा पिछले चार वर्षों में 51 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच रहा है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

अवधि	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	अन्यों का उत्पादन (एमटी)	कुल भारतीय उत्पादन (एमटी)	भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा
2010-11	686 68605	49769	118118374	58%
2011-12	49549585	46722	962 96307	51%
2012-13	67867837	44745	112 112582	60%
2013-14	93293297	49935	142143232	65%

18. चूंकि आवेदक का भारत में समान उत्पाद के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है इसलिए विधिक रूप से वह घरेलू उद्योग है।

19. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि वह एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है। इस संदर्भ में उनके द्वारा ग्रेनाइट बनाम भारत संघ [2007(12) एससीसी (178)] में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है जिसमें यह अधिवचन किया गया कि ईओयू का गठन अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने के उद्देश्य से किया जाता है जबकि घरेलू टैरिफ एरिया में बिक्री करना इस सामान्य नियम का केवल अपवाद हो सकता है। शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुद्दा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख का निर्वचन करने से संबंधित नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय में न्यायालय ने यह धारित किया कि ईओयू द्वारा डीटीए में वस्तु की बिक्री किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि, डीटीए की बिक्री एक अपवादों में यह प्रतिपादित करता हूँ कि घरेलू उद्योग द्वारा यह अपवाद जांच की अवधि कराया जा रहा है। डीटीए में बिक्री किया जाना भी कुल घरेलू भाग एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए घरेलू उद्योग में डीपी रक्षोपाय से अपने संरक्षण की भाग की है।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के सेफ्ट्रियाक्जोन डाइसोडियम हेमीहेप्टाहाइड्रेट-स्टराइल, चीन जन.गण. (दिनांक 2 जुलाई, 2008 का अंतिम जांच-परिणाम) निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह कहा गया है कि ईओयू को घरेलू

उद्योग का एक भाग नहीं माना जा सकता है। इस मामले के तथ्यों में मैं यह उपपादित करता हूँ कि ईओयू को घरेलू उद्योग से अपवर्जित किया गया है क्योंकि उसने भारी मात्रा में आयात किया था और उसको हुई क्षति स्वतः अनुप्राणित प्रतीत होती है। अधिनियम की धारा 9क (पाटनरोधी जांच से संबंधित) के अंतर्गत वे उत्पादक जो आयातक हैं या उनका आयातकों या निर्यातकों से कोई संबंध है उन्हें "घरेलू उद्योग" के दायरे से अपवर्जित किया जा सकता है। रक्षोपाय प्रावधान में अंतर्गत ऐसा कोई अपवर्जन नहीं है और इस मामले में पक्षकार का यह मामला है कि याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का आयातक है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने विटामिन ए मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी (पाटनरोधी) के जांच परिणाम के पैरा इस पर भरोसा किया है जिसमें पीरामल हैल्थकेयर (100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) को घरेलू उद्योग माना है :

"घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई होने के संबंध में और इसलिए वह घरेलू उद्योग होने के लिए अपात्र हो, यह नोट किया जाता है ईओयू सुविधा रूप में "घरेलू उद्योग" के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। वास्तव में, यह नोट किया जाता है याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में की गई क्लियरेंसेस विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर कोई प्रतिबंध या आकस्मिकता नहीं है और उन्हें उत्पाद कर संदत्त घरेलू विक्रियों के रूप में माना जाता है न कि आयात के रूप में। अतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादनों के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।"

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुनः यह तर्क दिया गया है कि ईओयू द्वारा की जाने वाली घरेलू विक्रियों की प्रमात्रा पर प्रतिबंध है। मैं विदेश व्यापार नीति से यह उपपादित करता हूँ कि ईओयू द्वारा डीटीए विक्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि सकारात्मक एनएफई अनुरक्षित किया जाए। मुझे इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि निर्यातोन्मुख इकाई भी भारत में समान वस्तु की उत्पादक है।

22. विक्रम इस्पात बनाम केंद्रीय उत्पाद कर आयुक्त वर्ष 2000 (120) ईएलटी 800 ट्रि डेल (एल बी) में रिपोर्टित मामले में माननीय अधिकरण ने यह अधिवचन किया है कि ईओयू द्वारा की गई घरेलू विक्रियों को आयात के रूप में नहीं माना जाता है और उन्हें विनिर्मित संबद्ध वस्तु के केंद्रीय उत्पाद करके अध्यधीन निकासी के रूप में माना जाता है। कास्को ब्लासमस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क आयुक्त, वर्ष 2004 (164) ईएलटी 423 (ट्रि डेल) में रिपोर्टित, मामले में माननीय अधिकरण ने पुनः उल्लेख किया है कि ईओयू द्वारा घरेलू रूप से क्लियर की गई वस्तु को घरेलू वस्तु के रूप में माना जाए। संगत पैरा नीचे उद्धृत किया जाता है।

23. उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं उपपादित करता हूँ कि याचिकाकर्ता भारत में एक उत्पादक है और उसका समान वस्तु के उत्पादन में भारी हिस्सा है और यह अधिवचन किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6) (ख) के अंतर्गत यथापेक्षित एवं यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और वह घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।

24. सूचना का स्रोत

इस "विचाराधीन उत्पाद" का आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 और 29051700 के अंतर्गत किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 और अप्रैल-जून, 2014 की अवधि के लिए (खेपवार) आईबीआईएस मुंबई से प्राप्त किए गए हैं। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में दिसम्बर, 2013 तक के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उनका घरेलू उद्योग के केंद्रीय उत्पाद रिकार्डों के आधार पर निदेशालय द्वारा सत्यापन किया गया और क्षति विश्लेषण के विचारार्थ आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। 1 जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू आंकड़ों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वे विधिवत साक्ष्यांकित हैं और उनका इस कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया और उन पर अनंतिम जांच परिणाम जारी करते समय विचार किया गया है।

25. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि तथा वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के लिए क्षति पैरामीटरों से संबंधित सूचना घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्राधिकृत रूप से प्रस्तुत की गई जिसे सत्यापन के उपरांत क्षति विश्लेषण के लिए (उत्पाद कर रिकार्ड के अनुसार, आवश्यक समझी गई सीमा तक) विचार किया गया। लागत आंकड़े और क्षति मार्जिन का परिकलन याचिका द्वारा प्रदान कराया गया है, जो स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित है।

26. जांच की अवधि (पी ओ आई) :

न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975, में न ही सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997, विशेषरूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि या रक्षोपाय जांच के विचारार्थ न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार जांच की अवधि का चयन करने के लिए कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं है। तथापि, जांच की अवधि से संबंधित विस्तृत विवरण कोरिया के विरुद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में पैनल ने विस्तार से वर्णन किया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि आयातक देश के

जांचकर्ता प्राधिकारी को "जांच की अवधि की दीर्घता" और इसके "भंग" होने का निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।

"हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भंग की अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अवधि और इसके भंग होने की अवधि जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अवधि पांच वर्ष और छह माह थी, यह अवधि अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेंटीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अवधि के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अवधि की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अवधि की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अवधि पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अवधि की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अवधि का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है : प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अवधि की लंबाई बताई गई हो; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि, संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)¹

पैनल ने उसी यूएस लाइन पाइप मामले में यह निर्धारित किया कि :

"किसी रक्षोपाय जांच में संवर्धित आयात प्रवृत्ति की जांच करने के लिए जांच की अवधि वहीं होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच के लिए है। यह स्थिति किसी पाटनरोधी या प्रतिवहनकारी शुल्क की जांच के विपरीत है जहां पाटन या सब्सिडीकरण की ध्वनि किसी वास्तविक क्षति जांच करने के लिए सामान्यतः माफी कम पड़ जाती है। हमारा विचार है कि इस अंतर के पीछे के कारणों में से एक कारण यह है कि अर्जेंटीना फुटवीयर मामले में अपीलीय निकाय द्वारा यह पाया गया कि "यह निर्धारण कि क्या आयातों का "इतनी अधिक मात्रा में होने" की जरूरत पूरी हो जाती है यह केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण द्वारा पूरी नहीं होती है। "अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जहां संवर्धित आयातों का निर्धारण करने का मामला आता है वहां "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की जांच करना अपेक्षित होता है। आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों की प्रवृत्ति के मूल्यांकन के साथ केवल एक निश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्षति निर्धारण के लिए संगत अवधि के संबंध में जो विचार अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त किए गए हैं वहीं विचार संवर्धित आयातों का निर्धारण करने पर भी लागू होंगे (पैरा 7.209)²

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो रक्षोपाय संबंधी म्युनिसिपल विधि और न ही रक्षोपाय संबंधी करार या गाट के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। तथापि, संदर्भ की भावना के अनुरूप ऐसा प्रतीत होता है कि संगत जांच अवधि पर्याप्त लंबी हो जिससे संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह केवल अत्यधिक अभिनव विगत में ही समाप्त नहीं होनी चाहिए बल्कि जांच की अवधि अभिनव विगत हो।

28. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन की गई अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लंबी हो कि संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और सीजनल अंतर के प्रभाव को निष्क्रिय बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरूआत के नोटिस में दिसम्बर, 2013 तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिकीकृत आधार पर विचार किया गया है। अनंतिम जांच परिणाम में अप्रैल, 2014 तक के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है, इसके साथ ही अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के विचारार्थ उसी अवधि के लिए घरेलू आंकड़ों की संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी की जांच करने के लिए मासिक एवं तिमाही आधार पर जांच की गई है। अब इन आंकड़ों को जून, 2014 तक अद्यतन कर दिया गया है। इसलिए, इन तथ्यों और ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोतों पर विचार करते हुए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (जिसे एतदपश्चात् पीओआई कहा गया है) के रूप में वर्ष 2010-11 से 2013-14, वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही सहित, की अवधि के लिए आंकड़ों को अपनाना उचित माना गया है।

¹ डब्ल्यूटी/डीएस 202/आरडीटी दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइप लाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

² डब्ल्यूटी/डीएस 202/आर दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइप लाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

29. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 के आंकड़े अपनाकर डीजी ने जांच की अवधि में परिवर्तन कर दिया है और उनको सुनने का अवसर दिए बिना ही अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की है। यह प्रस्तुतिकरण निराधार है और विधि की समुचित समझ के बिना है। "जांच की अवधि" कोई पारिभाषित विधिक अभिव्यक्ति नहीं है जैसाकि पाटनरोधी विधि में हुआ है। रक्षोपाय विधि में जांच की अवधि में डीजी के विवेक से चयनित संदर्भ अवधि का उल्लेख है जिसे वह आयातों में वृद्धि तथा ऐसी चयनित अवधि के समय गंभीर क्षति का मापन करने के लिए करते हैं। यद्यपि व्यापार नोटिस में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रावधान है परंतु डीजी द्वारा चयन की गई अवधि तीन वर्षों से अधिक या कम भी हो सकती है। दुर्भाग्यवश हितबद्ध पक्षकारों ने अवधि का चयन करने के लिए विधि की गलत समझ बना ली (जिसे सामान्य भाषा में जांच की अवधि कहा जाता है)। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां चयनित अवधि बहुत कम हो सकती है जैसे तीन माह, परंतु मेरे विचार से डीजी को विधि के अंतर्गत इस अवधि का चयन करने का पूर्णाधिकार प्राप्त है, यदि आयातों में वृद्धि या क्षति में ऐसा चाहा जाता है। उदाहरण के लिए वैश्विक मंदी की स्थिति में आयातों में अधिक तीव्र गति से अचानक वृद्धि हो सकती है और ऐसी स्थिति में डीजी संरक्षण के लिए आवेदन पर ऐसी स्थिति में भी विचार कर सकते हैं जब क्षति इतने कम समय में ही कारित क्यों न हुई हो। म्युनिसिपल रक्षोपाय विधि का उद्देश्य घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के दुष्टपरिणामों से बचना है और इस संरक्षण की अभिवृद्धि अवधि की दीर्घता पर निर्भर नहीं हो सकती है। यही कारण है कि म्युनिसिपल विधि में अवधि की दीर्घकता का निर्धारण नहीं किया गया है और उसे डीजी के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

30. घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत संगत आंकड़ें प्रस्तुत करने तथा उसके पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरण करने पर डीजी ने जांच की अवधि/संदर्भ अवधि जून, 2014 के अंत तक बढ़ा दी। इसलिए संवेदनशील परिस्थितियों में संवर्धित आयातों के कारण क्षति विश्लेषण के लिए अपनाए गए जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक की अवधि के लिए आंकड़े जांच की अवधि के लिए हैं न कि जांच की अवधि के परे के लिए जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने जून, 2014 की समाप्ति तक के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इसलिए उन्हें अपना प्रस्तुतिकरण करने और प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया गया।

31. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक की अवधि को अपनाने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया क्योंकि यह अवधि वह अवधि नहीं थी जिसका चयन जांच शुरूआत नोटिस में किया गया था और इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। मेरा विचार है कि इस अवधि की जांच केवल इस विचार से की गई थी कि क्या संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं और यह कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा संवेदनशील बताई गई इस अवधि में गंभीर क्षति कारित की गई है या नहीं। यह घरेलू उद्योग के इस दावे के कारण अनिवार्य था कि एफटीए के अंतर्गत आशियान देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर दिनांक 01.01.2014 से शून्य शुल्क प्रभावी होने के कारण आयातों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। किसी भी देश में इस विचाराधीन उत्पाद की संवर्धिता मात्रा में केवल इस कारण से बाढ़ सी आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि एफटीए के अंतर्गत आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। यदि इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो घरेलू उद्योग नष्ट हो जाएगा और यह एक देश के औद्योगिक आधार तथा देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है क्योंकि इससे अंतिम प्रयोक्ता उद्योग आयातों पर निर्भर हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया जाए तो इन आयातों के अंतर्प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अनंतिम आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चयनित अवधि अर्थात् 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान गंभीर क्षति के पहलू की जांच प्रारंभिक जांच परिणाम जांच शुरूआत नोटिस के रूप में जारी करते समय वार्षिक आधार पर की गई है और प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया गया था कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की गई है। इसका स्पष्टीकरण इस नोटिस के पैरा 17.3 में कर दिया गया है।

32. इस मुख्य मुद्दे का कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है, का मेरे द्वारा प्रारंभिक आधार पर विधिवत समाधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विधि के किसी ऐसे प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है कि जिसका डीजी द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय उल्लंघन किया गया है।

33. इसके अतिरिक्त, अनंतिम आधार पर शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम नियम 9 के निबंधनों के अनुरूप जारी किए गए हैं। म्युनिसिपल रक्षोपाय विधि में प्रारंभिक आधार पर सिफारिश करने से पहले हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई या कोई अन्य अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह जांच शुरूआत का नोटिस, जो प्रारंभिक जांच परिणाम भी है जारी करने से पहले हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने का प्रावधान विधि में नहीं है। तथापि, म्युनिसिपल विधि में नियम 6 के निबंधनों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकारों को यह अवसर प्रदान करने का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि वे अपने मामले को जांच शुरूआत का नोटिस जारी करने के बाद, परंतु अंतिम जांच परिणाम जारी होने

से पहले जांच की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में स्पष्ट करें। यह वह मामला नहीं है जहां अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले और अवसर नहीं दिया गया था। मेरे विचार से इस विषय पर सांविधिक ढांचा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की जरूरत को, जहां कहीं विधि रूप से आवश्यक हुआ पूरी तरह से पूरा किया गया है।

34. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक के घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़ों का अंतरिम शुल्क की सिफारिश करने से पहले पूरी तरह जांच कर ली गई है। इस संबंध में मेरा विचार है कि आंकड़ों का सत्यापन करना एक विधिक अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह उल्लेख नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े गलत हैं।

35. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि डीजी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में केवल संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी का ही उल्लेख किया है परंतु उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति या गंभारी क्षति की चुनौती का निर्धारण नहीं किया है। मैं पाता हूं कि यह प्रस्तुतिकरण सही नहीं है। मैंने सभी संगत कारकों का विश्लेषण किया है जिनको प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 20 से 33 में निगमित किया गया है और गंभीर क्षति से संबंधित निष्कर्ष पैरा 34 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त गंभीर क्षति एवं संवर्धित आयातों के बीच कारणात्मक संबंधों का उल्लेख प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 35 में किया गया है।

36. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय बोर्ड और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के पश्चात केंद्रीय सरकार के समक्ष ऐसे ही प्रस्तुतिकरण किए हैं। तथापि, बोर्ड ने डीजी की सिफारिशों पर ही अपनी सम्मति प्रस्तुत की है और केंद्रीय सरकार ने भी डीजी के जांच परिणामों को ही माना है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई इन प्रस्तुतिकरणों के बावजूद भी अनंतिम शुल्क अधिरोपित किया है।

37. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 7 में और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 में कतिपय सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रावधान है। नियम में यह प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का वास्तविक आधार पर प्रकटन करना अपेक्षित नहीं होता है जो कंपनी की गोपनीय सूचना है और जिसका प्रकटन करना उक्त पक्षकार के व्यवसाय हित की पूर्वावधारणा को गंभीर क्षति पहुंचाएगा, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और जिसे याचिकाकर्ता ने कभी विगत में सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया है।

38. घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदक का अगोपनीय पाठ प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय और जांच की कार्यवाही के दौरान गोपनीय की मांग करने के लिए कारणों का प्रस्तुतिकरण भी किया है जिसकी समय-समय पर जांच की गई तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया, गोपनीयता प्रदान की गई। इसलिए गोपनीयता का अनुरोध, जहां कहीं इसका दावा किया गया, आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि जिस सूचना पर भरोसा किया गया है वह उन्हें प्रदान कराई गई है और घरेलू उद्योग को भारी गोपनीयता प्रदान की गई है। यह प्रस्तुतिकरण निराधार है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की जांच उनके दावे की गोपनीयता के संबंध में की गई और मेरे विचार से जहां न्यायोचित पाया गया उन्हें गोपनीयता प्रदान की गई। यह निर्विवाद है कि अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कराया गया है।

39. संवर्धित आयात :

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उल्लेख है और उसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

“(1) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, इस बात से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि उससे गंभीर क्षति हुई है अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है तो यह उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी”।

40. नियमों में रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए आयातों के वृद्धि एक आधारभूत पूर्वापेक्षा के रूप में अधिदेशित है। इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात "इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में" हुआ है और रक्षोपाय शुल्क के प्रयोजनार्थ, नियमों में आयातों में घरेलू उत्पाद के संगत एवं समग्र रूप से वृद्धि का विश्लेषण अपेक्षित है।

41. इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 में 'संवर्धित मात्रा' को निम्नवत परिभाषित किया गया है:

"(ग)" "संवर्धित मात्रा" में आयातों में वृद्धि शामिल होती है चाहे वह वृद्धि घरेलू उत्पादन के संबंध में हुई हो या संगत रूप से हुई हो।

42. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में, पैनल के वितपरीत, अर्जेन्टीना फुटबियर (ईसी)³ में अपीलीय निकाय ने अधिवचन किया कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक हो कि उससे क्षति कारित हो सके या क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके। वहां से लिया गया संगत उद्धरण निम्नलिखित है :

"131. 'यह निर्धारण कि क्या आयातों में 'इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि की जरूरत पूरी होती है या नहीं' केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए साधारण रूप से यह प्रदर्शित करना ही पर्याप्त नहीं होता है कि इस उत्पाद के आयात इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अथवा पांच वर्ष पहले हुए की तुलना में अधिक हुए हैं। पुनः, और यह दोहराया गया सा प्रतीत होता है कि केवल आयातों की कोई संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी। आयातों में वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हुई हो कि उससे रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए अपेक्षित घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने की जरूरत पूरी होती हो और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) दोनों की भाषा यह अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और बहुत अधिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में हुई हो जिससे कि गंभीर क्षतिकारित की गई हो या गंभीर क्षतिकी चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

गंभीर क्षति

यूएस-व्हीट ग्लुटेन⁴, में पैनल ने पदबंध" इतनी संवर्धित मात्रा में" का निर्वचन निम्नवत किया है।

8.31 गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) और रक्षोपाय करार ("एसए") के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल वृद्धि का उल्लेख नहीं है। बल्कि उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में वृद्धि की गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रकृतिके संबंध में विशिष्ट जरूरतों का उल्लेख है। गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा की जाती है कि किसी संबंधित सदस्य के भू-भाग में किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में (घरेलू उत्पादन के समग्र एवं संगत रूप में) की जाती है जिससे गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतः आयातों में केवल वृद्धि होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि हम अर्जेन्टीना-फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक हुई हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

43. विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त विधि और डब्ल्यूटीओ न्याय प्रणाली को ध्यान में रखकर किया गया है।

44. विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त मूल्यांकनों के आलोक में किया गया। विचाराधीन उत्पाद के भारत में आयातों ने समग्र रूप में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित की है। आयातों में समग्र रूप में यह वृद्धि पर्याप्त एकाएक हुई है जिससे घरेलू उद्योग के गंभीर क्षति हुई। इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक समग्र रूप के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

क) आयातों में समग्र रूप से वृद्धि

45. भारत में वसीय अल्कोहलों का आयात कई देशों से और प्राथमिकतः इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से किया जाता है। आयातों ने समग्र रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या उसके लिए गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 (वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत) के दौरान वसीय अल्कोहलों के आयातों की प्रमात्रा निम्नलिखित है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	2014-15*
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616	19989	79957
प्रवृत्ति	100	172	257	290	101	403

* अप्रैल-जून, 2014 पर आधारित

³ अर्जेन्टीना – फुटबियर (ईसी) अपीलीय बाडी रिपोर्ट डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999

⁴ यूएस-व्हीट ग्लुटेन संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्ल्यूटी/डीएस/166/आर 31 जुलाई, 2000

46. तालिका में दिए गए उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयातों में समग्र रूप से उद्रेक आया। आयात जो वर्ष 2010-11 में 19843 एमटी थे बढ़कर वर्ष 2013-14 में 57616 एमटी हो गए। यह 190 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में आयातों में अचानक उद्रेक आया। यह उद्रेक लगभग 72 प्रतिशत था। यह आयात जांच की अवधि के दौरान भी बढ़ते रहे। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों का विश्लेषण वर्ष 2010-11 की तुलना में आयातों में 303 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

ख) उत्पादन के संबंध में आयात

47. भारत में जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात वर्ष 2010-11 में 17 प्रतिशत थे वहीं बढ़कर वर्ष 2013-14 में 40 प्रतिशत हो गए, जो एक भारी उद्रेक है। घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में उत्पादन भारी वृद्धि हुई। यह वर्ष 2010-11 में 29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 62 प्रतिशत हो गए।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 14-15	2014-15*
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616	19989	79957
बीबीएफ उत्पादन	68605	49585	67837	93297	15187	60746
कुल भारतीय उत्पादन	118374	96307	112582	143232	28319	113278
घरेलू उद्योग के उत्पादन के % के रूप में आयात	29%	69%	75%	62%	132%	132%
भारतीय उत्पादन के % के रूप में आयात	17%	35%	45%	40%	71%	71%
प्रवृत्ति	100	238	259	214		455
बीबीएफ का घरेलू उत्पादन**	33319	28974	22560	23303	3266	13065
घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात	60%	118%	226%	247%	612%	612%

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

**बीबीएफ का उत्पादन, निर्यात घटाकर

48. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आयातों में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन एवं खपत के संगत रूप में तथा समग्र रूप से, दोनों रूपों से, उद्रेक हुआ है। आयातों में समग्र और संगत दोनों रूपों में वृद्धि काफी पर्याप्त है जो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के आशय से अंतर्गत "संवर्धित आयात" है।

49. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(ग) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"गंभीर क्षति" से आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग का समग्र ह्रास हुआ हो"; और "गंभीर क्षति की चुनौती" से आशय गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।"

50. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा 6(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है "गंभीर क्षति की चुनौती" से आशय गंभीर क्षति को स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है

51. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"यह निर्धारण करने में कि क्या संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है तो महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिभाषात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, इनमें

संवर्धित वस्तु के आयातों में संगत एवं समग्र रूप से तीव्र की दर एवं राशि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे की हिस्सेदारी, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता क्षमता आयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार शामिल है।

52. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) में यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों की जांच की जानी चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। इस तरह का कोई भी मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों के लिए किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के तथा संबंधित उद्योग की परिस्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यतः यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जिससे घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" प्रदर्शित होती हो और इसलिए गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालना न्यायोचित होगा। इसी तरह दूसरे मामले में, हो सकता है कि कतिपय कारकों में गिरावट न आ रही हो परंतु ऐसे होते हुए भी समग्र परिदृश्य घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" प्रदर्शित कर रहा हो।

53. अतः सभी सूचीबद्ध कारकों और कतिपय अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन किया जाए जिसका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

54. अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में "गंभीर क्षति" की परिभाषा तथा अनुच्छेद 4.2(क) में "सभी संगत कारकों" को मूल्यांकन करने की जरूरत के बीच संबंध पर चर्चा की है :

"केवल तभी, जब किसी घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षण" हुआ है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2(क) तकनीकी रूप से यह अपेक्षा करता है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह कि अन्य सभी संगत कारकों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए, परंतु यह प्रावधान इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टतः इस तरह का मूल्यांकन, किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर तथा संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यतः यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जो यह प्रदर्शित करे कि उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षण" हुआ है, और इसलिए गंभीर क्षति की जांच में न्यायोचित ठहरा सकती है। दूसरे मामले में कतिपय कारकों में, हो सकता है कि गिरावट न हो रही हो परंतु, ऐसा होते हुए भी, उद्योग की समग्र स्थिति "भारी समग्र अवक्षयण" को प्रदर्शित करती हो। अतः इस तथ्य की तकनीकी जांच करने के अलावा कि क्या सक्षम प्राधिकारियों ने किसी विशिष्ट मामले में सभी सूची कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, हमारा विश्वास है कि पैनल "गंभीर क्षति" का निर्धारण करने की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(क) में उल्लिखित "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे।

55. यूएस - व्हीट ग्लेटन संबंधी पैनल ने, अपीलीय निकाय द्वारा समर्थित निष्कर्ष में, वाक्यांश "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे।"

"इस तथ्य का निर्धारण कि ऐसे "भारी समग्र परिक्षण" की स्थिति की अवस्थिति का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का, उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है।

हम यह विचार नहीं करते हैं कि किसी उद्योग के लिए भारी समग्र परिक्षण की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि जांच किए गए प्रत्येक एकल कारक में ऋणात्मक प्रवृत्ति हो। बल्कि, ऐसा प्रवृत्तियों की संपूर्णता में और उनकी अन्योन्यक्रिया में होना चाहिए। जिस पर गंभीर क्षति का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अतः कई कारकों में इस तरह के अपटर्न अनिवार्यतः गंभीर क्षति के निर्धारण को प्रतिवारित नहीं करेंगे। यह जांचकर्ता प्राधिकारियों पर निर्भर है कि वे उनके समक्ष उपस्थित साक्ष्य का आकलन एवं उसका मूल्यांकन को और इस तथ्य का एक तर्कसंगत एवं युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दें कि तथ्यों से उनके निर्धारण का समर्थन कैसे होता है।"

56. तदनुसार, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करने के लिए उन सभी कारकों पर, जिनका नियमावली में उल्लेख है तथा उन अन्य कारकों पर, जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत हैं, विचार किया गया। किसी एकल कारक पर निक्षेपण के रूप में विचार नहीं किया गया। संगत व्यवसाय चक्र और परिस्थितियों जो प्रभावित उद्योग से संगत हैं, के संदर्भ के अंतर्गत सभी संगत कारकों पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग, हितवद्ध पक्षकार, समर्थनकारी घरेलू उत्पादकों और विरोधकर्ता हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया गया है।

गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन, उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, निम्नवत किया गया है :

क. बाजार हिस्सा : घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में आयातों की तुलना में भारी गिरावट आई है। आवेदकों का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 में 38 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2011-12 में 27 प्रतिशत रह गया। आवेदक के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में और अधिक गिरावट आई तथा बाजार हिस्सा 18 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014-15 (वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के आधार पर) के लिए वार्षिकीकृत आंकड़ों का विश्लेषण बाजार हिस्से में 10 प्रतिशत की और अधिक गिरावट प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 80 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	घरेलू उद्योग की बिक्री	अन्यों की बिक्री	कुल मांग	बाजार हिस्सा	
					घरेलू उद्योग	आयात
2010-11	19843	17080	8209	45132	38%	44%
2011-12	34142	15285	6651	56078	27%	61%
2012-13	51055	12891	7542	71488	18%	71%
2013-14	57616	14777	8704	81097	18%	71%
पहली तिमाही 2014-15	19989	2594	2485	25068	10%	80%
2014-15	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ख. उत्पाद : इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में, मुख्यतः निर्यातकों के कारण, वृद्धि हुई है। यह घरेलू उत्पादन (अर्थात् निर्यात को घटाकर उत्पादन) की प्रवृत्ति से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें गिरावट की प्रवृत्ति आई है।

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	वार्षिकीकृत 2014-15*
उत्पादन						पहली तिमाही 14-15 पर आधारित
उत्पादन (घरेलू उद्योग) एमटी	68605	49585	67837	93297	15187	60746
प्रवृत्ति	100	72	99	136		89
निर्यात को घटाकर उत्पादन	33319	28974	22560	23303	3266	13065
प्रवृत्ति	100	87	68	70		39

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

घरेलू उत्पादन आधार वर्ष में 33319 था। यह घटकर वर्ष 2013-14 में 23303 तथा वर्ष 2014-15 में 13065 रह गया।

क. क्षमता उपयोग

अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 120000 एमटी थी। निर्यात बाजार में बिक्री के कारण इसकी समग्र क्षमता उपयोग में सुधार हुआ। यदि विचार से निर्यात बिक्रियों को हटा दिया जाए, क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 28 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2013-14 में 19 प्रतिशत और वर्ष 2014-15 में 11 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014-15 में भी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	2014-15 (वार्षिकीकृत)*
क्षमता उपयोग प्रतिशत (उत्पादन)	57%	41%	57%	78%	51%	51%
प्रवृत्ति	100	72	100	137	89	89
क्षमता उपयोग प्रतिशत (निर्यात को छोड़कर उत्पादन)	28%	24%	19%	19%	11%	11%
प्रवृत्ति	100	86	68	68	39	39

ख. बिक्री के स्तर में परिवर्तन

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में, समग्र रूप से और खपत के संगत रूप से निरंतर गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में मामूली सा सुधार हुआ है, परंतु यह बिक्री वर्ष 2010-11 की तुलना में कम थी। बिक्री में इस गिरावट को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तीव्र गिरावट, 38 प्रतिशत से कम होकर 10 प्रतिशत के संदर्भ में देखा जा सकता है जबकि आयातों का हिस्सा 44 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	2014-15*
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	17080	15285	12891	14777	2594	10376
प्रवृत्ति	100	89	75	87		61

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ग. रोजगार

अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि रोजगार के स्तर में कोई भारी अंतर नहीं आया। हर हाल में रोजगार का स्तर अल्पकाल में बहुधा अस्थिर ही बना रहा।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
रोजगार	100	109	119	124	122

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

घ. उत्पादकता

उत्पादकता का स्तर क्षमता उपयोग के अनुरूप ही बना रहा।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
उत्पादकता प्रतिदिन	100	72	99	136	89

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ड. लाभ एवं हानि

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2010-11 में तीव्र गिरावट आई। घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में लाभप्रद बिक्रियां करने में अक्षम रहा।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ/हानि	100	-266	-2796	-2232

घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ग्राहकों को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ी और घाटे पर अपनी बिक्रियां करनी पड़ी। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण भारी घाटा हो रहा है।

57. गंभीर क्षति अथवा उसकी चुनौती उत्पन्न करने वाले अन्य कारक

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध के पैरा (2) में यह निर्धारित है कि उप-पैरा (1) में किया गया निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच से, उद्देश्यपरक साक्ष्यों के आधार पर, यह प्रदर्शित न होता हो कि संबंधित वस्तु के संबंधित आयातों तथा गंभीर क्षति या उसकी चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है और जब साथ ही संबंधित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उत्पाद को "गंभीर क्षति" कारित कर रहे हों तो ऐसी "गंभीर क्षति" के लिए संबंधित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

इस कारण, संभावित अन्य कारकों जिन्हें घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है की जांच की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कारक संगत है :

क. उत्पाद के लिए मांग

जब समग्र मांग में वृद्धि होती है तब यह उम्मीद की जाती है कि उसके अनुरूप ही घरेलू उद्योग की बिक्री में भी बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होगी। तथापि, इस मामले में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में प्रपाती गिरावट आई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई मांग को कमोवेश ढंग से आयातों द्वारा पूरा किया गया।

क. मांग के संबंध में आयात

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद की खपत या मांग का निर्धारण भारत में विभिन्न देशों से उत्पाद के आयातों, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री के रूप में किया जाता है। समायावधि के दौरान मांग/खपत में परिवर्तनों की तुलना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के भारत को होने वाले आयातों में देश में इस उत्पाद की मांग और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है, विभिन्न स्रोतों से आयातों तथा घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्तियों से की जाती है। निम्नलिखित तालिका में यह नोटिस किया जाता है कि मांग के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत थे बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत हो गए, जो काफी महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 में भी वही प्रवृत्ति जारी रही जब मांग के संबंध में आयात बढ़कर 80 प्रतिशत हो गए।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	घरेलू उद्योग की बिक्री	अन्य की बिक्री	कुल मांग	बाजार हिस्सा	
					घरेलू उद्योग	आयात
2010-11	19843	17080	8209	45132	38%	44%
2011-12	34142	15285	6651	56078	27%	61%
2012-13	51055	12891	7542	71488	18%	71%
2013-14	57616	14777	8704	81097	18%	71%
पहली तिमाही 2014-15	19989	2594	2485	25068	10%	80%
2014-15*	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*अप्रैल-जून, 2014 के आंकड़ों पर आधारित

ख. मालसूची

उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए घरेलू उद्योग भारी मालसूची बनाए रखने की स्थिति में नहीं है। प्रदर्शित मालसूची मुख्यतः निर्यात के दौरान उत्पाद के भंडारण के कारण हुई है। इसलिए मालसूची का स्तर समुचित ढंग से घरेलू उद्योग की स्थिति को परावर्तित नहीं करता है।

ग. खपत की प्रणाली में परिवर्तन

घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि भारतीय बाजार के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के इस दावे के विरोध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण इसे स्वीकार कर लिया गया।

घ. घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनकी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया

रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनकी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान कर रही हों।

ड. निर्यात निष्पाद

घरेलू उद्योग के निर्यातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में आयात वर्ष 2010-11 की तुलना में बहुत अधिक थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्षति निर्यातों के कारण नहीं हुई है। किसी भी दशा में, गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए केवल घरेलू बाजार से संबंधित सूचना पर ही विचार किया गया है। कई पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को इसके निर्यात निष्पादन के कारण क्षति हुई है। मुझे इस तर्क में ज्यादा बल प्रतीत नहीं होता है। घरेलू उद्योग के निर्यातों में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई जिसे अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की सुसुप्त क्षमता भी है, स्वदेशी उत्पाद की मांग होने पर उससे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, खासकर तब जबकि डीटीए में बिक्री की अनुमति हो।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	2014-15
निर्यात	35286	20611	45277	69994	11920	47680
प्रवृत्ति	100	58	128	198		135

च. कीमत अधोरदन : निग्रहण/अवमंदन

यह संप्रेक्षण किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों की उतराई कीमत (क) वर्ष 2011-12 के सिवाय घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) बिक्री लागत से बहुत कम है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपने माल की बिक्री, बिक्री लागत से कम मूल्य पर करनी पड़ रही है। आयातों से प्रतिस्पर्धा करने और अपने ग्राहक बनाए रखने के प्रयास में घरेलू उद्योग अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पाया। वर्ष 2012-13 में इसकी बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कीमत अधोरदन के परिणामस्वरूप कीमत निग्रहण हो रहा है। घरेलू उद्योग को संपूर्ण अवधि के दौरान वित्तीय घाटा सहन करना पड़ा है। आयातों के उतराई मूल्य की तुलना में बिक्री लागत और बिक्री कीमत का अंतर निम्नलिखित है :

	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयात की लागत	रुपए/एमटी	103024	132784	114082	96610	114493
	प्रवृत्ति (अनुक्रमित)	100	129	111	94	111
बिक्री लागत	रुपए/एमटी (अनुक्रमित)	100	141	122	104	
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी (अनुक्रमित)	100	138	101	94	116

छ. प्रौद्योगिकी में विकास

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने खंडन नहीं किया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास इस मामले में क्षति कारित करने वाला कारक नहीं है।

58. इसलिए आयातों में उद्रेक के अलावा अन्य ऐसा कोई कारक नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की हो।

59. गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष

क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई। आयातों में भारी उद्रेक के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के गंभीर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के अधिकांश पैरामीटरों में पतन के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन आयातों के विपरीत हो गया।

ख. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, घरेलू उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग तथा लाभप्रदता में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अभिव्यक्त होती है। अतः, उन सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन "भारी समग्र परिक्षण" दर्शाता है कि अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के कारण गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है।

60. गंभीर क्षति की चुनौती

भारत में वसीय अल्कोहल का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को आयातों में उद्रेक तथा भारत में आ रही आयात मात्रा की मौजूदा प्रवृत्ति के कारण गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। आयात की मात्रा पहले से ही बहुत अधिक थी, फिर भी यह निरंतर बढ़ना जारी रही। आयातों के बाजार हिस्से में भी इस संपूर्ण अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमता पर विचार करते हुए यह संभव है कि आयातों में वृद्धि होना जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी। आयातों में और अधिक वृद्धि की संभावना से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। इस तथ्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में लाभप्रद बिक्रियां करने में असमर्थ है, मेरा विचार है कि रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण के अभाव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

61. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक (रक्षोपाय) का यह दायित्व है कि वह "इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करें।" इसके अतिरिक्त, अनुबंध के पैरा 2 में यह अपेक्षा की जाती है कि कथित संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित किया जाए। नियम 8 के अनुबंध के पैरा 2 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच में उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित न हो जाए कि संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध है। परंतु साथ ही जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों तो उस क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।"

62. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है।

"अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकास, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए विचारा है, संवर्धित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरान्त कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।⁵

⁵ कोरिया पर पैनल रिपोर्ट – डेयरी, पैरा 7.89-7.90

63. उपर्युक्त के अनुसार पैरामीटरों का व्यापक अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती संवर्धित आयातों के द्वारा कारित की गई है। कारणात्मक का निर्धारण करने के लिए उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इस मामले में इस संबंध में निम्नलिखित संगत है :

- (i) आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ-साथ भारत में खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में भारी कमी हुई।
- (ii) जिस अवधि में आयातों में उद्रेक हुआ उसी अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी कमी आई।
- (iii) यद्यपि जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है परंतु बढ़ती हुई इस मांग को आयातों द्वारा पूरा किया गया और घरेलू उद्योग इस बढ़ती मांग से लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं था।

64. मैं यह उपपादित करता हूँ कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति की चुनौती के परिणामस्वरूप आयातों में और अधिक वृद्धि की संभावना है।

65. समायोजन योजना

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2) में यह अपेक्षा की जाती है कि "आयात प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे या किए जाने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों या दोनों" के संबंध में एक अभिकथन प्रस्तुतिकरण अपेक्षित है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब गंभीर क्षति को रोकने या उसका समाधान ढूंढने के लिए और समायोजन सुलभीकरण के लिए आवश्यक हो।

66. निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयावधि प्रदान करना है जिससे कि वह आयातों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुनर्संरचना कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(4) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) किसी संभव विस्तार साधन का निषेध करना है यदि घरेलू उत्पादकों समायोजन करने का कोई साध्य न हो।

67. घरेलू उद्योग ने एक विस्तृत समायोजन योजना प्रस्तुत की है जिसमें उसने वर्षवार प्रक्षेपित बचत का प्रदर्शन किया है। समायोजन योजना के अनुसार घरेलू उद्योग इंडोनेशिया में एक नया संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। मैं पाता हूँ कि इंडोनेशिया स्थित वह संयंत्र दिसम्बर, 2013 में प्रचालनात्मक हो गया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि इंडोनेशिया स्थित उनकी इकाई टायल उत्पादन होना है और उनके कच्चे माल की जरूरत के लगभग 2 प्रतिशत की पूर्ति अब तक इसी यूनिट से की गई थी।

68. योजना के अनुसार याचिकाकर्ता इंडोनेशिया द्वारा लगाए गए भारी निर्यात कर से बचने के लिए इंडोनेशिया स्थित अपनी इकाई में विनिर्मित आंशिक रूप से प्रसंस्कृत उत्पाद (एसपीकेओ) का आयात करेगा। मैं पाता हूँ कि इससे इस विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत कम होगी और इससे घरेलू उद्योग को भारी लाभ होगा। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि इंडोनेशिया स्थित उनकी यूनिट से वसीय अल्कोहल के आयातों वे वसीय अल्कोहलों की उत्पादन लागत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसलिए समायोजन योजना को भी उसी अनुसार समझना चाहिए। इस संबंध में मैं पाता हूँ कि घरेलू उद्योग अपनी योजना में पुनर्वास योजना का उल्लेख किया है जो आयातों के संबंध में और इंडोनेशिया स्थित उनकी इकाई से वसीय अल्कोहल की दुलाई पर बचत का विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अपनी दिनांक 18.09.2014 की प्रत्युक्ति के पैरा 2.6 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि कच्चे माल की लागत में कमी होने के परिणामस्वरूप भारत में वसीय अल्कोहल की समग्र उत्पादन लागत में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि तलोजा स्थिति निष्क्रिय स्पिलिटिंग क्षमता पर आई निर्धारित लागत को अन्य व्यवसाय जैसे स्थानीय आयल्स का या अन्य सामग्री का विखंडन करके उसकी क्षमता का उपयोग करके चरणबद्ध रूप से निष्क्रिय किया जाएगा।

69. मैं पाता हूँ कि उनकी उपर्युक्त योजना व्यवहार्य है और इससे यह संभावना है कि संवर्धित आयातों की चुनौती का सामना करने के लिए वे प्रतिस्पर्धी होंगे।

डीटीए में आपूर्ति करने की घरेलू उद्योग की क्षमता

70. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग एक 100 प्रतिशत ईओयू है और इसलिए वह अपने निर्यात दायित्व पर अधिक बल देने के कारण हो सकता है कि वह विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम न हो। मैं हितबद्ध पक्षकारों के इस विचार से सहमत हूँ कि घरेलू उद्योग, जब तक वे निर्यातों के जरिए सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री डीटीए में नहीं कर सकते हैं। तथ्य, मैं यह पाता हूँ कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान भी इस विचाराधीन उत्पाद का निरंतर निर्यात करके इस विचाराधीन उत्पाद की डीटीए में पर्याप्त मात्रा में क्लीयर करने की पात्रता प्राप्त की है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों में वर्ष 2013-14 में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे डीटीए में इस विचाराधीन उत्पाद की अच्छी मात्रा में

बिक्री करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई संदेह किया गया हो। घरेलू उद्योग की विनिर्माण क्षमता संदेह से परे है। मैं पाता हूँ कि उपर्युक्त तर्क विश्वसनीय नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग डीटीए में शुल्क की रियायती दर पर किसी भी मात्रा की बिक्री कर सकता है बशर्ते कि वह उस वस्तु का निर्यात करके सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी पाता हूँ कि पूर्ण शुल्क का भुगतान करके घरेलू बाजार में बिक्री करने पर घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, एक बार घरेलू बाजार की मांग घरेलू उद्योग के अनुसार हो जाने पर घरेलू उद्योग इस स्थिति में आ जाएगा कि वह डीटीए की मांग को पूरा करने के लिए भरपूर उत्पादन कर सके। मैं पाता हूँ कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से जब आयात महंगे हो जाएंगे तो घरेलू बाजार का अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। इससे घरेलू उद्योग अपनी विनिर्माण क्षमता का पूरा उपयोग कर पाएगा। इस समय घरेलू उद्योग सस्ते आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण भी किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्ति से समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि उनका फोकस तो मुख्यतः आयातों पर है। तथापि, मैं यह पाता हूँ कि इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है।

संरक्षण की अवधि

71. समायोजन योजना के संबंध में मैं पाता हूँ कि समायोजन योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह यह है कि इंडोनेशिया स्थित वसीय अम्लों का उत्पादन करने वाले संयंत्र दिसम्बर, 2013 में ही प्रचालनात्मक हो गया है, हालांकि इस संयंत्र का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा। इसलिए, घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनने तथा संवर्धित आयातों की चुनौती से समायोजन करने के लिए तीन वर्षों के संरक्षण की जरूरत नहीं है जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है। मेरे विचार से समायोजन के प्रयोजनार्थ अवधि को कम किया जा सकता है।

वैकल्पिक उपचार

72. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत राहत की मांग करनी चाहिए थी क्योंकि संवर्धित आयात आशियान देशों से ही हो रहे हैं। इस संबंध में मैं पाता हूँ कि यह घरेलू उद्योग का विशेषाधिकार है कि वह सामान्य रक्षोपाय के अंतर्गत या एफटीए विशिष्ट रक्षोपाय विधि के अंतर्गत संरक्षण की मांग करे। चूंकि यह आवेदन सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अधीन किया गया है इसलिए मुझे इसकी जांच तदनुसार ही करनी है। मेरे पास घरेलू उद्योग को यह निदेश देने का अधिकार नहीं है कि वह एफटीए के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियमों से संरक्षण की मांग करे।

73. अनपेक्षित विकास :

यह नोट किया गया है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर कोई ऐसा अभिव्यक्त दायित्व/ अपेक्षा नहीं है कि वे अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय विधि में ऐसी कोई क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करने के लिए अनुकरण किया जाना चाहिए अथवा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में क्रियाविधि के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए या ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसका अनुपालन अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय किया जाना चाहिए। तथापि, गाट के अनुच्छेद—XIX के साथ पठित रक्षोपाय करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को यह अधिकार देता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अनपेक्षित विकास की जांच की जानी चाहिए। यह निदेशालय इस जांच में अनपेक्षित विकास के मुद्दे की लगातार जांच करता आ रहा है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण माना गया कि उन अनपेक्षित विकास अथवा परिस्थितियों की जांच की जाए जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में मैं पाता हूँ कि गाट, 1994 के अनुच्छेद—XIX में प्रावधान किया गया है कि गंभीर क्षति अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

गाट 1994 के अनुच्छेद- XIX में निम्नलिखित उल्लेख है :

1. (क) यदि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रशुल्क रियायतों सहित सौंपे गए किसी दायित्व के प्रभावीस्वरूप उस संविदाकारी पक्षकार के भूभाग से किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे उस भूभाग के समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो संविदाकारी पक्षकार ऐसे उत्पाद के संबंध में ऐसी सीमा तक अथवा ऐसे समय तक के लिए जो उस क्षति से बचने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रतिबद्धता को समग्र रूप से या उसके किसी भाग को समाप्त करने अथवा रियायत को वापस लेने या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

74. अर्जेन्टीना फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध "अनपेक्षित विकास" का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि

अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो अनपेक्षित न हो या किसी सदस्य द्वारा कोई दायित्व लिए जाने के समय प्रत्याशित न हो।

75. आवेदक ने आयातों में उद्रेक के लिए कई कारणों का उल्लेख किया है जो उनकी समझ में इस मामले में अनपेक्षित विकास हैं, उनका विवरण संक्षेप में निम्नलिखित है :

क. वैश्विक क्षमताओं में वैश्विक मांग की तुलना में अत्यधिक अनपेक्षित वृद्धि

इस समय वैश्विक क्षमता वर्ष 2011 से पूर्व की क्षमता से 151 प्रतिशत अधिक है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की वैश्विक क्षमता में ओलियो लाइन, एक प्रकाशन में उपलब्ध विवरण के आधार पर वृद्धि हुई जो निम्नलिखित है :

अनुमानित वैश्विक क्षमता

देश	वर्ष 2011 से पहले (एमटी)	वर्ष 2011 के बाद (एमटी)
इंडोनेशिया	3,24,000	9,98,000
मलेशिया	4,90,000	5,90,000
फिलीपीन्स	1,80,000	2,80,000
वैश्विक क्षमता	22,70,000	34,27,000

यह तर्क दिया जाता है भारी क्षमता की स्थापना की संबद्ध वस्तु की संपूर्ण विश्व में भारी आपूर्ति की गई है। प्रतिभागिता करने वाले किसी भी निर्यातक या सरकार ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनी प्रत्युक्ति/प्रति प्रस्तुतिकरण या तत्पश्चात प्रस्तुत आंकड़ों की विशुद्धता की कोई चुनौती नहीं दी है। मैं उपपादित करता हूं कि घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण में भारी दम है।

ख. वैश्विक मांग आपूर्ति अंतराल

दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इन क्षमताओं की नजर भारत जैसी उभरती बाजार पर है, जो स्पष्टतः अनपेक्षित है।

ग. यूरोपियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण

पुनः यह देखा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध एक पाटनरोधी जांच का आयोजन किया और वर्ष इस माल के विभिन्न स्रोतों पर वर्ष 2011 में निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया। इस शुल्क के कारण निर्यातकों की नजर भारतीय बाजार पर पड़ी जो अनपेक्षित थी।

घ. प्रमुख कच्चे माल पर निर्यात कर

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कच्ची पाम गिरी का तेल पर, जो संबद्ध वस्तु का प्रमुख कच्चा माल है, निर्यात शुल्क अधिरोपित किया गया है जो उरुग्वे दौर के समय अनपेक्षित था।

76. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए मैं यह संप्रेक्षण करता हूं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बेशी क्षमता, भारी मांग - आपूर्ति अंतर तथा वसीय अल्कोहल के निर्यातों पर यूरोपियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के कारण वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के उत्पादक भारत जैसी आपातकालीन बाजारों की तलाश में हैं, जहां आबादी ज्यादा हो ओर डिटरजेन्ट, पर्सनल केयर उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही हो।

77. इसलिए, मैं यह अधिवचन करता हूं कि यूरोपियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से वसीय अल्कोहल के आयातों में वृद्धि के साथ-साथ इस उत्पाद की बेशी क्षमताओं के कारण इस उत्पाद की मांग आपूर्ति में अंतर एक अनपेक्षित विकास है जिसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की गई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी गई।

जनहित

78. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :

"कोई सदस्य, उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गाट 1994 के अनुच्छेद-X के अनुसरण में सार्वजनिक किए गए तथा विगत में सुस्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके जांच के पश्चात, रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के युक्तियुक्त सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई या अन्य समुचित साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य एवं विचार व्यक्त कर सकते हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने या अपने विचार व्यक्त करने का अवसर शामिल हो कि रक्षोपाय शुल्क का

अनुपयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिसमें अपने जांच परिणाम और विधि एवं तथ्यों के सभी संगत मुद्दों पर निकाले गए अपने तर्कयुक्त निष्कर्ष शामिल होंगे।

79. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का प्रयोक्ता उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे उनको भारी घाटा होगा। घरेलू उद्योग ने अपना आकलन, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रदान किया है कि शुल्क का अधिरोपण करने से प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् शैम्पू, टूथपेस्ट, अन्य होम केयर एवं पर्सनल केयर उत्पादों के उत्पादकों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का अनुप्रवाह उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है जो यह दावा करता है कि रक्षोपाय शुल्क के कारण उनकी कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यदि इसे पूरी तरह से प्रासंगिक अंतिम उत्पाद (यह कल्पना करते हुए कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत में 20 प्रतिशत वृद्धि कर देगा) पर लागू किया जाता है तो इसका प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

शैम्पू (शैसे) 6 एमटल	
	रुपए
कीमत	1
लागत	0.6
भार द्वारा प्रयुक्त 15%* एसएलईएस 1257 डालर एमटी की दर से	0.068
एसएलएस में वसीय अल्कोहलों की मौजूदगी 50%*	0.034
20% शुल्क का प्रभाव	0.0068
कीमत का %	0.68%
कीमत का % से कम या एक पैसा कम	

*उद्योग मानदंडों पर आधारित

**एसएलईएस के एक मालीक्यूल में वसीय अल्कोहल का 1 मालीक्यूल होता है। एसएलईएस का मोलीक्यूलर भार 384 (एसएलईएस रहोडिया देखें) और सी 1214 का औसत मालीक्यूलर भार 190-197 (वीवीएफसी 12-14 एमएसडीएस देखें) चूंकि दो मालीक्यूलर भार का अनुपात (अर्थात् 194/384) 0.5 है, इसलिए एसएलईएस में वसीय अल्कोहल अंतर्वस्तु लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है।

क. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे हालात में, हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा है कि शुल्क का उदग्रहण करने से उपभोक्ता पर भारी प्रभाव पड़ेगा, साक्ष्यांकित नहीं है।

ख. इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी आंकड़ों द्वारा साक्ष्यांकित नहीं है कि इस शुल्क का अधिरोपण करने से एसएलएस/एसएलईएस उद्योग के लिए एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होगा, जिसके परिणामस्वरूप एसएलएस/एसएलईएस के आयातों में वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एसएलएस/एसएलईएस पर शुल्क ऐतिहासिक रूप से वसीय अल्कोहल पर लगे शुल्क से कम रहा है। तथापि, इन वस्तुओं का कभी भी भारी मात्रा में आयात नहीं किया गया। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से ईयू में अनुप्रवाही उद्योग के आयातों में वृद्धि नहीं हुई है। यह तर्क दिया गया है कि बड़े-बड़े निर्यातक राष्ट्रों के पास बेशी एसएलएस/एसएलईएस क्षमता नहीं है और इसलिए यह आशंका भी उपपादित नहीं होती है कि एसएलएस/एसएलईएस के आयातों में वृद्धि हो जाएगी। आयातकों ने यह तर्क दिया है कि एसएलएस/एसएलईएस के आयात बढ़ने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि इन मदों का जल आधारित परिवहन संभव है। तथापि, रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि शुल्क से अनुप्रवाही उत्पादों के आयात में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि स्थानीय उत्पादक उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। हर हाल में, मैं सहमत हूँ कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योग के लिए एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा तब तक के लिए खड़ा हो जाएगा जब तक यह शुल्क समाप्त नहीं हो जाता है। परंतु यदि संरक्षात्मक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएगा जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। घरेलू उद्योग की रक्षा करना सरकार की नीति का एक भाग भी है। इसलिए यह तर्क घरेलू उद्योग की रक्षा नामंजूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

80. धारा 8ख का अधिनियमन आयातों के उद्रेक के कारण गंभीर क्षति सहन कर रहे घरेलू उत्पादकों की संरक्षा करने के लिए किया गया है। विधि में इन उत्पादकों को संरक्षण दिए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि वे आयातों से कारगर ढंग से निपटने के लिए अपने व्यवसाय को समायोजित कर सकें। यह सीमित अवधि के लिए एक अस्थायी साधन है। जब तक घरेलू

उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तब तक उन्हें क्षति होती रहेगी और यह भी हो सकता है कि उन्हें अपना उत्पादन बंद कर देने के लिए भी मजबूर होना पड़े। इस परिदृश्य में प्रयोक्ता के पास इस उत्पाद का स्थानीय आपूर्तिकर्ता शेष नहीं बचेगा। यह जनहित में नहीं होगा और न ही इससे अंतिम उपभोक्ता या मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

81. घरेलू उद्योग के उपर्युक्त दावे का इस जांच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। इस मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर किसी विरोधकर्ता प्रस्तुतिकरण/प्रत्युक्ति के अभाव में, घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए के अनुसार यह प्रतीत होता है कि रक्षोपाय शुल्क का संबद्ध उत्पाद के प्रयोक्ताओं के विभिन्न सेगमेंटों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो उसका प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

82. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा और इससे अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

83. विकासशील राष्ट्र

विकासशील राष्ट्रों से आयात के प्रतिशत की भी जांच की गई है। चूंकि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद का, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से उदभूत आयात पर सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के परंतुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

84. निष्कर्ष

उपर्युक्त जांच एवं किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि :

- (क) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) वसीय अल्कोहल के आयात में संपूर्ण जांच अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू उत्पादन के संबंध में तथा संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। आयातों में यह उद्रेक कुल मांग के संबंध में भी बहुत अधिक है।
- (ख) जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि घरेलू उद्योग को सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों अर्थात् बाजार हिस्सा, बिक्री, लाभप्रदता, जिसमें आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 तक तथा वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के प्रभाती गिरावट आई है, के आधार पर समग्र निष्पादन पर विचार करते हुए गंभीर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग बढ़ते घाटे के रूप में तथा देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि होने के बावजूद बिक्री में गिरावट के रूप में कारित गंभीर क्षति प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है। इससे घरेलू उद्योग की स्थिति में भारी समग्र परिक्षण कारित हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान गिरावट आई है जबकि उसी अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इससे बढ़ते आयातों तथा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कारित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।
- (ग) घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में सफल रहा है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उद्रेक के लिए बाजार में हुआ विकास अनपेक्षित है।
- (घ) घरेलू उद्योग यह दर्शाने में भी सक्षम रहा है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा क्योंकि इस रक्षोपाय शुल्क का अंतिम उपयोक्ताओं/उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव नाममात्र का ही पड़ेगा। यह भी उपपादित किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्रवाई के दौरान इस पहलू का खंडन या विरोध नहीं किया है।

सिफारिशें :

- (क) उपर्युक्त जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, और सी18 की लंबाई के कार्बन श्रृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी12, सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 (सामान्यतः सी12-सी14 के रूप में प्रवर्गीकृत) कार्बन श्रृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं, अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों", जिसमें विशुद्ध सी8 शामिल नहीं है जिन्हें एतदपश्चात् "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, के भारत में संवर्धित आयातों ने इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 के निबंधनों के अनुसार इस "विचाराधीन उत्पाद" के आयातों पर दो वर्ष छह माह की अवधि के

लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा। इस अवधि की गणना दिनांक 28.08.2014 को अधिसूचना संख्या 3/2014-सी.शु. (एसजी) के तहत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण की तारीख से की जाएगी। घरेलू उत्पादकों द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद की, लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिलाभ की अनुमति देने के पश्चात, औसत लागत पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग के हितों की संरक्षा करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित माने गए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 और 29051700 (एचएस कोड केवल संकेतात्मक है और उत्पाद विवरण हर हाल में लागू होगा) निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए के अनुसार करने की एतद्वारा सिफारिश की जाती है।

अवधि	रक्षोपाय शुल्क की दर
पहले वर्ष	20% यथामूल्य
दूसरे वर्ष	18% यथामूल्य
उत्तरवर्ती छह माह	12% यथामूल्य

- (ख) मैं दिनांक 26 मई, 2014 के सा.का.नि.357(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में की गई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश और वित्त मंत्रालय की दिनांक 28 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 03/2014 सीयूएस (एसजी) के तहत अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की एतद्वारा संपुष्टि करता हूं। अंतिम निर्धारण के निबंधनों के अनुरूप दिनांक 26/5/2014 को प्रारंभिक जांच परिणाम में विशुद्ध सी8 की कार्बन श्रृंखला लंबाई युक्त अनुबिद्ध वसीय अल्कोहलों" पर अधिरोपित अनंतिम रक्षोपाय शुल्क वापस लिए जाने की सिफारिश की जाती है और यदि संग्रहित किया गया तो, उसका वह प्रतिदाय विधि के निबंधनों के अनुरूप किया जाएगा।
- (ग) चूंकि मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक तथा सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होते हैं इसलिए मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों में उद्धवित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

[एफ.सं. डी-22011/26/2013/पीटी]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2014

(Central Board of Excise and Customs)

Subject:-Safeguard investigation concerning imports of “ Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) ” excluding pure C8 hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration) into India – Final findings.

G.S.R. 712 (E).— D- 22011/26/2013 having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

(A) Procedure

1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Custom (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as “Safeguard Rules”] by M/s. VVF (India) Limited, Mumbai, 100%

Export Oriented Unit seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8, C10, C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) **excluding pure C8” hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration)** into India, as shown in the petition alleging that increased imports of "PUC" was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producer and to protect the domestic producer against market disruption and threat of market disruption caused by the increased imports of "PUC" into India.

2. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of “PUC” into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 13th February, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R.87 (E) on the same day i.e. 13th February, 2014 and the corrigendum of the same dated 19th February, 2014 was also published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R.100 (E) on the same day i.e. 19th February, 2014.

3. A Copy of the Notice of Initiation dated 13th February, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry and subsequently, the copy of corrigendum dated 19-02-14 were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, related embassies in New Delhi and known interested parties listed below:

3.1 EXPORTERS

- a) **Emery Oleochemicals**, Level 5, Building E, Peremba Square, Saujana Resort, Section U2 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- b) **Wilmar International Limited**, 56 Neil Road Singapore 08883.
- c) **P&G Chemicals**. Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch, 238A Thomson Road #20-01/10, Novena Square Tower A, Singapore 307684.
- d) **Sasol Limited**. Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 120537 Hamburg.
- e) **KLK Oleo**. Level 8, Menara KLK, No.1, Jalan PJU 7/6 Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
- f) **Musim Mas**. PT Musim Mas Jl KL Yos Sudarso KM 7,8 Tanjung Mulia - Medan 20241 North Sumatra - Indonesia.
- g) **Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd**. 99 Bukit Timah Road # 03-01 Alfa Centre, Singapore - 229835
- h) **FPG Oleochemicals Sdn Bhd**, FPG Oleochemicals Sdn. Bhd. (184896-U) Lot 3831 Kuantan Port Industrial Area, Tanjung Gelang, PO Box 26, Pejabat Pos Balok, 26080 Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA.
- i) **Kao Corporation**, Pilipinas Kao, Inc. A Kao Group Company 7th Floor Tower One & Exchange Plaza Ayala Triangle, Ayala Avenue, 1226 Makati City, Philippines.
- j) **Thai Oleochemicals Co. Ltd.** 123 Suntowers Building A, 14th, Vibhavadi - Rangsit Road, Chomphon Chatuchak Bangkok 10900 Thailand.
- k) **Teck Guan**. Teck Guan (China) Ltd. No. 1 Tecf Guan Road, Rugao Port Economic Development Zone Rugao, Jinagsu Province, China, 226532.
- l) **Oxiteno**. Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 1343 - Bela Vista - CEP 01317-910, São Paulo - SP, Brazil.
- m) **BASF/Cognis**. Henkelstrasse 6740551 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany.

3.2 MAJOR IMPORTERS / INDUSTRIAL USERS IN INDIA

- a) **Galaxy Surfactants Limited**. C-49/2, TTC Industrial Area, Pawne, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703.
- b) **Viswaat Chemicals Limited**. “Viswaat”, 7 Satsang Complex, Upper Govind Nagar, L.S. Raheja Marg, Malad (East), Mumbai - 400 097.
- c) **Rhodia Speciality Chemicals India Ltd**. Phoenix House “A/B” Wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai, 400013.
- d) **Indian Glycols Limited**. 2B, Sector-126, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, 201304.
- e) **Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd.** 30/31, Marol Co-op. Ind. Est., M.V. Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059.
- f) **Matangi Industries**. Plot No. 28, Phase -1, Behind Nilsin Industries, GIDC, Vatva, Ahmedabad - 382 445, Gujarat.
- g) **Venus Ethoxylates Pvt. Ltd.** Plot Nos. 109-111, Bicholim Industrial Estate, Bicholim, Goa - 403529.

- h) **Gujarat Chemicals.** 111, Jalnidhi Complex, Opp. Bahumali Bldg., Nanpura, Surat -1.
- i) **Aarti Industries Limited.** 71, UdyogKshetra, 2nd Floor, MulundGoregaon Link road, Mulund (W), Mumbai 400080.
- j) **Kusa Chemicals Pvt Ltd.** 101, Varun Apartment, Dattatraya Road, Santacruz (West) Mumbai- 400054
- k) **Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.** 1 Lopes Manor, Mumbai 400103.

3.3. Domestic Producers

- a) **VVF (INDIA) Limited, (Domestic Industry), 109, Sion (East), Mumbai-400022.**
- b) **Godrej Industries Ltd.** Piroshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai- 400079.

3.4. NAME OF EMBASSY AND ADDRESS

- a) **Philippines Embassy,** H.E. (Mr.) Benito B. Valeriano Ambassador, 50-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi: 110021.
- b) **Belgium Embassy,** TCG Financial Centre, 7th floor, C-53, G-Block, BandraKurla Complex, Bandra (E) - Mumbai 400051. / 50-N, Shanti Path, Chanakypuri, New Delhi-110021.
- c) **USA Embassy,** U.S. Embassy, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021.
- d) **UK Embassy,** Niti Marg, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi- 110021.
- e) **UAE Embassy,** 12, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 (INDIA)
- f) **Switzerland Embassy,** Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
- g) **Poland Embassy,** 50-M, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021.
- h) **Singapore Embassy,** E-6, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021.
- i) **Netherlands Embassy,** "Forbes Building" 1st floor, Charanjit Rai Marg, Mumbai 400001. / 6/50 F, Shanti Path, Kwame Nkrumah Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
- j) **Italy Embassy,** 50 E, Chandragupta Marg, New Delhi – 110021 (India)
- k) **Finland Embassy,** E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021.
- l) **France Embassy,** 2/50-E, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110 021
- m) **Embassy of the Federal Republic of Germany,** P.O. Box 613, New Delhi 110001
- n) **China Embassy,** 50-D, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021, India
- o) **Indonesia Embassy,** 9, Altamount Road, Cumballa Hill, Mumbai – 400 026, / 50-A, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
- p) **Thailand Embassy,** D-1/3 VasantVihar, New Delhi 110057.
- q) **Malaysia Embassy,** 50-M, Satya Marg Chanakyapuri, New Delhi 110 021.

4. Questionnaires were sent to the known exporters of other countries, known importers/users in India and other interested parties as per the information available with request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.

5. Request to consider as interested parties was received and accepted as under:

- i. Mr. Mohd Radhi Abdul Razak (Director), Trade Practices Section, Ministry of International Trade and Industry, Level-14, Block-8, Government offices complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail- alltps@miti.gov.my
- ii. M/s Majorhub Oleochemicals P Ltd., 10th, Siddhivinayak Appt, 4th floor, Society Road, Jogeshwari East, Mumbai-400060. E-mail- majorhubindia@vsnl.net
- iii. M/s Hindustan Unilever Limited (HUL) , Unilever House, BD Sawant Marg, Chakala, Andheri East, Mumbai-400099
- iv. Ms Chan Pek Wan, Secretariat, Chemical Industries Council of Malaysia, Malaysian Oleochemical Manufacturers group (MOMG) Wisma FMM, No. 13, Persiasan Dagang, PJU 9, Bandar Shri Damamsara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail- pek_wan@FMM.ORG.MY
- v. M/s Pan Oleo Enterprise Pvt. Ltd, 309, 10, 11, Aditya Banarasi Heritage, Mind space off Link road, Malad West, Mumbai-400064. E-mail- panoleo@panoleo.com
- vi. Mr Manoj Jha, M/s Unidus, E-mail- manoj@unidusonline.com
- vii. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India, Block-50E, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021. E-mail- rusintrade@mail.ru
- viii. M/s PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia, Po Box-1010 Nagoya Plaza, Batam Island 29432, Indonesia. E-mail- info.batam@ecogreenoleo.com
- ix. Trade & Economic Section, Delegation of the European Union of India, 65, Golf links, New Delhi-110003. E-mail- chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
- x. M/s Cavinkare Private Limited, 12, Cenotaph road, Teynampet, Chennai-600018.
- xi. Directorate General of Foreign Trade, Jalan, M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110.
- xii. M/s Ratnasagar Herbs Pvt. Ltd.
- xiii. M/s Emami Limited, 687, Anandapur e.m. bypass Kolkata-700107. E-mail- sapan.barik@emamigroup.com

- xiv. M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. 555/1, Energy Complex, Building A, 15th floor, Vibhavadi- Rangsit road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

- 5.1** Request for an extension of time to submit their reply was made by M/s PT Musim Mas, Indonesia.
- 5.2** After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, request for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules' 1997 were allowed.
- 5.3** The information presented by the applicant in their application was verified by on-site visit to the plant of the domestic producer. The non-confidential version of verification report is kept in the public file.
- 5.4** The non-confidential information received or acquired from the interested parties including domestic industry were kept in public file for inspection and filing further comments on the views of one interested party by the other interested parties.
- 5.5** The Domestic Industry has made a request for immediate interim relief by way of a provisional safeguard duty in their safeguard application filed. In support of the same, they also submitted a letter dated 21-04-14 whereby details of their precarious condition based on listed economic parameters showing existence of critical circumstances being faced by them were enumerated and the domestic industry also prayed that in case provisional safeguard duty is not levied, they would face irreparable damage, difficult to repair.
- 5.6** The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined, along with the views expressed by the interested parties, which were then taken into account in making appropriate determination in the Preliminary Findings, where it was prima facie found that there exist critical circumstances which warranted imposition of provisional safeguard duty in order to provide interim relief to the domestic industry from suffering irreparable damage, which could have been difficult to repair.
- 5.7** Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 26th May, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R.357(E) on the same day i.e. 26th May, 2014.
- 5.8** Provisional safeguard duty was subsequently imposed vide Ministry of Finance, Department of Revenue Notification No. 03/2014-Cus (SG) dated 28th August, 2014 imposing Safeguard duty @20% for a period not exceeding 200 days from the date of issue of the Notification concerned.
- 5.9** Thereafter, a public hearing was held on 26th August, 2014. The interested parties, along with the Domestic Industry made oral submissions at the time of Public hearing. During the course, some parties, who were not registered as interested parties, but were the user/exporter of the PUC, requested to participate in public hearing and to make submissions. All were allowed by the DG (SG) in the larger public interest. Out of the following parties, only S.No. 2, 5 and 6 submitted their written submissions which has been considered at appropriate places. Their details are as under:

Sl. No.	Name of the party	Status
1	M/s Atul Ltd, New Delhi	Importer/user
2	M/s Croda India Company Pvt. Ltd, Navi Mumbai.	Importer/user
3	M/s Dabur India Ltd. Sahibabad, U.P.	Importer/user
4	M/s HPL Additives Ltd. Haryana	Importer/user
5	M/s Hindustan Polyamides Fibres Limited	Importer/user
6	M/s Indian Speciality Chemicals Manufactures Association	Association
7	M/s Pushpsons Fibrol Pvt. Ltd. New Delhi	Importer/user
8	M/s Soofi Enterprises, Mumbai.	Importer/User

- 5.10** In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.
- 5.11** Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
- 5.12** All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public hearing

held on 26th August, 2014 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file.

5.13 Godrej Industries Ltd. Piroshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai- 400079 vide their letter dated 16/12/2013, 03/01/2014 and 22/01/2014 gave their support to the Domestic Industry in filing an application for safeguard measures against increased imports of “PUC” into India. They also co-operated in the investigation by providing data regarding Imports, production, sales, installed capacity and Capacity utilization etc. of the “PUC” which was considered and taken on record for overall injury analysis.

(B) **Post-Initiation Submissions:** The Domestic Industry and several Interested parties have submitted their post-initiation submissions as well as they have also participated in the Public Hearing and made post-hearing submissions as well. In order to prevent discussion on issues that are repetitive in their post initiation and post hearing written submissions, the issues raised by them in repetitive manner has been considered once, either post initiation or post hearing, for the sake of brevity, at appropriate places.

Views of Domestic Industry (Applicant):

1. Domestic Industry: M/S VVF (India) Limited, Mumbai, 100% Export Oriented Unit, claimed that his production account for 63% of the total production of ‘PUC’ in the country & represent a major proportion of the Indian production of ‘PUC’ in the country and thus have the standing to file the present petition. Apart from the applicant, the subject goods are being produced by M/s Godrej Industries Ltd. Mumbai in this case, who is supporting this safeguard application.

2. Product Involved: Fatty Alcohols are an aliphatic alcohols and occur in saturated and unsaturated forms. The alcohols can be grouped and most common lengths are C12, C14 and blends thereof. The ‘PUC’ are produced by the reduction of methyl ester or wax ester, through the conversion of natural fats and oils, mostly coconut and palm kernel oil. The process starts with splitting of vegetable oils, such as Crude Palm Kernel Oil, at high temperature and pressure, as a continuous process. The vegetable oils/fats (non-edible) are basically triglycerides of fatty acids which get converted to fatty acids and glycerol by the hydrolysis reaction commonly known as fat splitting. The crude fatty acids are then subjected to plain/ fractional distillation, at a high temperature and vacuum, followed by esterification resulting from a reaction between fatty acid and fatty alcohol in an inert atmosphere to make wax- ester. Pure wax- ester is then subjected for hydrogenation which takes place in the presence of fixed bed copper catalyst, resulting in crude fatty alcohol. This is then distilled and purified. ‘PUC’ are sold in the form of flakes, pastilles and liquids.

3. The import and injury related data for 4 year period has been filed by the applicant. The petitioner has provided the quarter wise information for the year 2010-11 to 2013-14 (till Dec.’13) based on which the Notice of Initiation was issued. However, the DI has filed their additional information vide letter dated 21-04-2014 and dated 15-05-2014 containing information about imports and other economic parameters for the period Jan’ 14 till Apr’ 14, emphasizing their critical situation and with a prayer to impose immediate provisional safeguard duty on the PUC, failing which they would suffer in wake of rising imports so much so that, it would be difficult to repair.

4. Absence of other factors causing injury

4.1. There are no other factors causing injury to the domestic industry. The demand for fatty alcohols has been increasing consistently over the last three years. There is about an 80% increase in demand, yet the domestic industry has not been able to increase its production, sales or profits commensurate to this growth in the market.

4.2. The petitioner is a 100% EOU, due to which it enjoys a competitive advantage over DTA Units. The customs duty on the raw materials (PKO), such as palm kernel oil, (which is in the range of 7.5% to 100% ad valorem) is far in excess of the duty applicable to finished goods. Since an EOU can import the raw material (PKO) without payment of duties, and clear its finished products on, payment of duty @7.725% (which has now become 3.86% w.e.f 18th Feb, 2014), the net duty applicable to EOU’s is much less than that borne by DTA units manufacturing fatty alcohols from imported materials. The DTA units would have to bear customs duty on raw materials which would substantially increase their costs. The net duty incidence of a domestic unit is, therefore, much higher than in the case of an EOU unit.

4.3. It is submitted that the DTA and EOU units in India are similarly placed. The PKO constitutes about 2/3 of the total cost of production. As PKO is not available in India, in commercial quantities, the raw material is required to be imported and is available to both types of units at same or similar import prices. The conversion costs would also not be different. The duty structure is however, advantageous for EOU units, since the duty on raw material is generally 100%. For instance, a DTA unit importing the raw material valued at Rs. 70, would have to pay duty of Rs. 70, whereas the EOU would be able to obtain the raw material without duties under exemption. The like article, cleared from an EOU would be chargeable to duty at 7.725%, which would be in the range of Rs. 8 to Rs. 10. Thus the net duty incidence on the EOU is significantly lower than for DTA units. The duties applicable for DTA clearances by EOU have been further reduced to 3.86%

4.4. There are also no changes in the pattern of consumption, to suggest that injury is being caused by such factors. In any case, it is not necessary that the imports should be the sole cause for injury, provided it can be shown that, it is one of the factors causing injury.

4.5. In the present case, there are no other circumstances or factors which are causing injury to the domestic industry at the same time and the requirements of causation are fully met.

5. 100% EOU is “domestic industry”

5.1. The Designated Authority in the Ministry of Commerce has been considering EOU's as forming part of domestic industry in a number of investigations. There are no restrictions on the sale of domestically manufactured goods in India, as long as a positive NFE is maintained by the EOU unit. The Foreign Trade Policy provides for concessional rate of duty on domestic clearances (upto 50% of the FOB value of exports) of that product. Additionally, entitlement earned on other products can be used for fatty alcohols upto 90% of total FOB value of exports. Beyond the aforesaid limits, sales can be made by the EOU on payment of appropriate duties of excise. There is hence, no restriction on the sale of goods manufactured by an EOU in India as long as there is positive NFE. In this context, paragraph 34 of the findings of the Designated Authority in the case of Vitamin A, is reproduced below wherein Piramal Healthcare (100% EOU) was considered to be a domestic industry:

“With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as “domestic industry”. In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic

sales and not as imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules”.

An export oriented unit, is not a unit located outside India and hence forms part of domestic industry.

5.2. The petitioner further submit that VVF is a producer of the like article or directly competitive article. The fatty alcohols produced by VVF are in direct competition with the imported products and hence it satisfies the definition of domestic industry.

6. Duty reduction as per Foreign Trade Agreement with the ASEAN Countries (AIFTA)

6. 1. India has entered into an Agreement for facilitation of trade ASEAN- India Free Trade Agreement (AIFTA), pursuant to which tariff barriers are to be reduced/removed in a time bound manner. Consequent to the treaty obligations, the duties on the PUC were initially reduced to 10% by Notification No. 46/2011 –Cus dated June 01, 2011 and thereafter eliminated by Notification No. 57/2013 dated December 31, 2013.

6. 2. It has been contended by some of the interested parties that the injury to the domestic industry arises on account of AIFTA and such injury should not be attributed to the imports.

6. 3. The domestic industry has claimed that non attribution of injury caused by the AIFTA, is not warranted in terms of Para 2 of Annexure -2 to the Rules, for the reason that the AIFTA is not a factor “other than the imports”.

6. 4. Para 2 of Annexure 2 to the Rules provides for non attribution of injury caused to the domestic industry by factors other than increased imports. Para 2 reads as under:

“The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigations demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports”.

6. 5. The aforesaid provision requires that factors causing injury to the domestic industry, other than the increased imports should be identified and their injury should not be attributed to the imports. The factors under consideration are of two types:

- A. Factors that contribute to the increase in imports and
- B. Factors that cause injury to the DI, (other than increased imports).

6. 6. The reduction in duties consequent to the AIFTA is merely one of the many factors which has resulted in the surge in imports. Other such factors include enhancement of production capacity by foreign producers, non availability of alternate export markets for the PUC, small demand in the country of export of PUC, reduction in duties in India, etc. These are factors which contribute to the increase in imports, for which non attribution is not required to be done.

6.7. The second type of factors include lack of technological up gradation by the domestic industry, changes in pattern of consumption in India, supply side constraints etc. Non attribution analysis is required to be done only for the second category of factors listed above, that is factors other than the imports, causing injury to the domestic industry. Non attribution is, therefore, not required for the reduction in duties.

6.8. It has further been claimed by the interested parties that since AIFTA provides alternate mechanism to address trade imbalances, therefore, the DG safeguards does not have the jurisdiction to initiate safeguard proceedings. This submission is factually incorrect and not acceptable. Under the AIFTA, the rights and obligations of the parties, who are WTO members, have been retained. Article 10 (1) of the AIFTA, provides that notwithstanding the treaty, the WTO Members (including India) shall retain their rights and obligations under the Agreement on Safeguards. An extract from the Agreement is given below:

“ARTICLE 10

Safeguard Measures

Each Party, which is a WTO Member, retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Safeguards) and Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Agriculture). Any action taken pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement (ASEAN-India DSM Agreement).”

6.9. The fact that the duties on imports from the countries under the FTA has been removed with effect from 01.01.2014 is also resulting in the diversion of goods from other markets to India, and an immediate levy of provisional duty is necessary to offset the effect of the surge in imports. In similar circumstances, European Council has imposed provisional measures, against imports of certain steel products. In this context, paragraphs 51 to 57 of the determination are reproduced below:

“(51) The Commission has made a preliminary assessment of the possible destination of the huge volume of goods diverted from the US market. It notes that, given the weakness of other markets (notably Japan, South East Asia and South America), it is very unlikely that a significant quantity has been, or will be, diverted to such markets. Furthermore, producers in third countries suffer a difficult situation in their domestic markets, which are unable to absorb goods previously destined for the US market. Given the openness of the Community market, it may constitute the only opportunity for foreign producers to find an outlet for goods excluded from the US market. In these circumstances, the Commission concludes that a substantial proportion of the exports excluded from the US market have been, and will be, diverted to the Community.

(52) Therefore, it can be anticipated that the application of import restrictions to the US market will result in a significant further increase in imports of the products concerned into the Community. Analysis indicates that around 15 million tonnes of steel products (worth around \$4,1 billion), equivalent to total Community imports of the products concerned in 2000, are covered by the US measures and risk being diverted to the Community market.

(53) The situation of the Community producers has been significantly worsened by the US measures announced on 5 March 2002 because these measures have forced the Community producers to revise their projections downwards to reflect further reductions in earnings (from both domestic sales and exports), and further damage to profitability. This is compromising current reorganisation within the Community industry. It is also undermining earlier restructuring and modernization within the industry.

(54) Because the Community producers' projections have been revised downwards, in order to cut costs, temporary or permanent closure of production facilities will be difficult to avoid. These closures may affect production not only of the like products, but also of other products produced using the same facilities. The social impact, according to industry estimates, could be the disappearance of a further 20000 jobs in the next few years. The negative impact could also extend to those activities which are dependent on the Community producers affected by the measure.

(55) Bearing in mind that domestic consumption of the 15 products concerned is stagnant or declining and the rate at which imports were growing prior to the announcement of US measures, the situation of the Community producers was weak.

(56) The considerable increase in the growth of imports which the US measures promise has forced the Community producers to revise sales and profits projections downwards. These revised projections demand immediate measures by Community producers to reduce costs and stem anticipated losses, including closing production facilities and laying off employees. The damage caused to the Community producers by taking such action would be difficult to repair. If such action is to be avoided, provisional safeguard measures must quickly be taken.

(57) Therefore, the Commission considers that there exists a critical situation in which any delay in the adoption of provisional safeguard measures would cause damage which would be difficult to repair. It therefore concludes that provisional safeguard measures should be adopted without delay”.

(C) Interested parties:

C.1. Russian Federation

As imports of goods falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 from Russian Federation into India do not exceed 3 percent as per Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 and Article 9 of WTO Safeguards Agreement, Russian Federation should be excluded from the list of countries under investigation.

C.2. Pilipinas Kao, Inc.

As per Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 and Article 9 of WTO Safeguards Agreement, Philippines be excluded from any Safeguard duty as its import share is less than 3 % during the POI while top three exporters (Indonesia, Malaysia and Thailand) has more than 98% share in imports.

C.3. India Glycols limited

- i. In India only M/s VVF and Godrej manufactures Lauryl Alcohol with former having 63% share and is a 100% EOU unit. Imposed with export obligation they are left with limited domestic sales compared to demand and uncompetitive prices coupled with long delivery period .They are trying to leverage their monopolistic situation.
- ii. As per the FTAs signed with the ASEAN countries import duty reduction is emphasized.
- iii. Production and demand increased in 2013-14 along with improvement in profitability. No Safeguard duty should be imposed until investigation completed and injury ascertained.

C.4. Emery Oleochemicals Malaysia

One applicant has manufacturing unit in Indonesia with export duty advantage and uses intermediate feedstock for PUC production in India. Malaysian producers don't enjoy such benefit.

C.5. Aarti Industries Limited.

- i. Indonesia & Malaysia have inherent cost advantage and are competitive locations for PUC while the Applicants have EOUs primarily for export market as their manufacturing cost make them in competitive in domestic market.
- ii. Downstream industry would be killed if duty imposed as SLS and SLES are imported at zero duty under the ASEAN FTA. Any duty will harm the larger interests of Indian industry as downstream products will become non-competitive and value addition shift to other countries.

C.6. Viswaat Chemicals Limited.

Local procurement are non dependable and high priced as compared to the imports while applicants priority is exports.

C.7. Cavin Care Private Limited

- i. We manufacture shampoos using SLES & SLS which in turn need Fatty Alcohols predominantly imported from Indonesia & Malaysia which enjoy natural and comparative advantage. Both SLES/SLS and PUC enjoy NIL duty under India-ASEAN FTA.
- ii. Owing to peculiar market conditions of Palm Kernel Oil and its downstream products Safeguard duty on PUC will make SLES costlier and affect the supply chains of low cost shampoo sachets leading to denial of hygiene hair wash to masses and harm Indian Cosmetic industry.

C.8. Majorhub Oleochemicals P. Ltd.

- i. Applicants are hiding that they also sell C8, C10, C12, C14, C16, C18 fatty acids and C18.1 (Oleic Acid) and misrepresenting it is not commercially viable to produce and sell C8 and C10 alcohols.
- ii. Applicants statement of financial injury is misrepresented as there is considerable decline in the applicants share sales of Fatty Acids-C16, C18, C1618 (their core business as against Fatty alcohols) and themselves dumping the goods in Europe and when ADD was imposed, they turned to the Indian customers.
- iii. They omitted the fact that Godrej Industries is importer of C1214 alcohol.
- iv. Applicant's reason for decreased imports in 2013-14 as plant shut down in Malaysia and Indonesia is a misinformation as shut down in oleo industry is regular for change of catalyst.

- v. Most of the Malaysian and Indonesian producers have their own oil plantation for raw material CPKO and CPO which both VVF & Godrej don't have.
- vi. Recruitment jumped by 20% from F.Y 10-11 to 13-14 and thus their claim of loss of employment is baseless.
- vii. Applicants share increased in C16, C1618 and C18 Alcohols in both domestic and export markets.

C.9. M/s P.T.Musim Mas

- i. Applicant has claimed excessive and unwarranted confidentiality which prevented the party to reasonably understand Applicant's claims and the material relied.
- ii. Domestic producers do not produce SFA with carbon lengths C8 and C10 and blends thereof them and the import of such goods cannot cause injury to the applicants. .PUC should be correctly defined to exclude the types of SFA.
- iii. The Applicant's claims of a sudden surge in imports is not established as imports show a declining trend over the period 2011-12, to 2013-14 (annualized) especially in 2013-14;
- iv. The Applicant ignored the data for 2013-14 and resorted to analyzing each quarter against the same quarter in the previous year.
- v. The Applicant's claim that plant shutdowns in Malaysia and Indonesia slowed imports for the Q1 and Q2 of 2013-14 is not credible as there was no subsequent surge in Q3 of 2013-14 on resumption of production;
- vi. The POI was chosen deliberately to paint imports of SFA in a poor light as the import trends with base year 2010-11 (as proposed by the Applicant) paints a very different picture from the trends shown if the base year was 2011-12; and
- vii. The Applicant's injury claim not established as its production and capacity utilization improved significantly in 2013-14.
- viii. Decline in the Applicant's market share could be due to the restrictions imposed by virtue of its EOU status and the export orientation.
- ix. Safeguard duty will not assist Applicant due to inherent disadvantages compared to Indonesian and Malaysian SFA producers as the main raw material is produced there.

C.10. Thai Fatty Alcohols Co.Ltd, Thailand,Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore,KL-Kepong Oleomas SDN BHD & Galaxy Surfactants.

- i. Petitioner admitted that it has only manufactured and sold C12, C14, C16, C18 and blends thereof and not C8 and C10 carbon. Further, certain Carbon Chain lengths and combinations, which are not being imported into India at all or have been very sporadic during the POI, namely C810 and C14. Thus, it will be incorrect to include such grades in the product definition.
- ii. In present legal and commercial situation, VVF is not competitive in domestic market and is suffering injury. VVF is dependent on import for its raw material which is subject to export tax in Indonesia & Malaysia while when VVF sells Fatty Alcohol in the domestic market; the users have to pay excise duty equal to the customs duty which is not applicable in case of import of fatty alcohol from these countries under India-ASEAN Agreement.
- iii. Compared to previous year, there is no increase in imports, let alone surge in imports and while considering the product under consideration, the Authority has to examine all the product grades/Carbon Chain Lengths separately.
- iv. Imports of most of the grades have in fact fallen significantly during the injury period and were at their lowest during the Period of Investigation (2013-14-upto December).
- v. Both Petitioner as well as the other producer – Godrej Industries Ltd is (EOU), whose primary objective is to export the subject goods out of India.
- vi. A biggest reason for rise in imports is due to India's initiative to boost trade with ASEAN countries and according them concessional rates of duties.
- vii. Petitioner can make DTA clearance only at a higher rate and not the preferential rate of customs duty in terms of India ASEAN FTA. Imposition of safeguard duty cannot correct this difference since it's a policy decision taken by Government of India and Petitioner has no control over this.

C.11. PT. Ecogreen

- i. NOI and the Complaint do not properly explain whether such increased import occurred is recent, sudden, sharp and significant situation.

- ii. Complainant is operating under the Export Oriented Unit Scheme and domestic sales volume to the Indian market is limited to one-third of the total volume of production and cannot cover the demand in the domestic market of India sufficiently.
- iii. There are two producers of fatty alcohol existing in India namely the Complainant and Godrej who also holds significant portion of the domestic production in India and thus should lead to the fierce competition between the two.
- iv. Godrej is not part of the complainant and its overall performance presented in the Complaint show a positive trend.

C.12. Rhodia Specialty Chemicals India Limited (Solvay Group)

India is currently ethoxylation hub due to fair pricing of Ethylene oxide and availability of Lauryl alcohol and Safeguard duty on PUC will drive away all value addition from India leading to loss of employment and revenue.

C.13. Hindustan Unilever Ltd.

- i. The volume of imports is concentrated from Indonesia, Malaysia and Thailand and does not warrant a Global Safeguard measure. The Applicant ought to look for remedy available under Article 10 of Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation.
- ii. There is clearly no reason as to why some of the carbons chains not being produced should be excluded from the product scope as It is clearly stated in the application that the applicant does not produce Fatty Alcohol of Length C8 and C10 along with blends thereof.
- iii. The aspect of unforeseen developments has been completely ignored and absent in the Application.
- iv. The operations of Applicant might be affected because of poor export performance and lower realisations in the export market and high finance costs and in the injury, if any is self inflicted and is not attributable to increased imports.
- v. The subject goods are importable tariff-free in India from countries like Indonesia, Malaysia and Thailand under the ASEAN CECA. Therefore the cause of injury is basically inverted duty structure and cannot be attributed to increased imports of subject goods.
- vi. Applicant has clearly taken undue advantage of claiming excessive confidentiality on disclosing the adjustment plan.
- vii. Any imposition of safeguard duty would be contrary to public interest, as the interests of the consuming industry clear impact the tax revenues earned by the Government.

D. The DI responded to the Post-Initiation submissions of the aforementioned Interested Parties on the issues, re-iterating their initial submissions as below:

D.1. It has been contended by the interested parties, that the definition of domestic industry under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 ("Act") is inconsistent with the Agreement on Safeguards. This contention is not correct, as the term *domestic production* implies production in India, and not production destined for *consumption in India*. The request that the standing requirement, be examined with reference to the domestic production alone is misplaced. At the stage of production, it is not known whether an article would be consumed in India, or elsewhere. The interpretation suggested by the parties is therefore untenable. In any case, the total production of Indian producers, less their exports, also reflects that the petitioner has standing for the purposes of investigation.

"With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as "domestic industry". In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic sales and not as imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules".

D.2 An export oriented unit, is not a unit located outside India and hence forms part of domestic industry.

D.3 In the case of Cosco Blossoms Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Customs reported at 2004 (164) ELT 423 (Tri Del), the Hon'ble Tribunal reiterated that goods cleared by an EOU domestically are treated as domestic goods. The relevant paragraph is excerpted below:

"5. It is well settled 12000 (120) E.L.T. 8001 that goods produced in an EOU cannot be treated as imported goods and subjected to customs duty. The duty payable in respect of such goods is the duty of excise under Section 3 of the Central Excise Act, 1944. Therefore, the duty demand made in the impugned order under Section 28 of the Customs Act

is not sustainable. Accordingly, we set aside the impugned order and allow the present appeal. However, we make it clear that revenue authorities will be at liberty to demand duty on the imported inputs, if any, used in the production of the cut-flowers in question”

D.4 The petitioner’s share of domestic production is 60% and therefore, qualifies as “domestic industry”.

D.5 The petitioner is a 100% EOU, due to which it enjoys a competitive advantage over DTA Units. The customs duty on the raw materials (PKO), such as palm kernel oil, (which is in the range of 7.5% to 100% ad valorem) is far in excess of the duty applicable to finished goods. Since an EOU can import the raw material (PKO) without payment of duties, and clear its finished products on, payment of duty @7.725% (which has now become 3.86% w.e.f 18th Feb 2014), the net duty applicable to EOU’s is much less than that borne by DTA units manufacturing fatty alcohols from imported materials. The DTA units would have to bear customs duty on raw materials which would substantially increase their costs. The net duty incidence of a domestic unit is, therefore, much higher than in the case of an EOU unit.

D.6 The claim that there is no nexus in any excess between the imports and profitability is not correct. The graphical representation is misleading as it is based on indexed numbers. It is further submitted that there is a direct nexus between the imports and serious injury caused to domestic industry. The imports were at their highest in 2012-13, and 2013-2014. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period, when the imports were at high levels.

D.7 Injury must be caused to the “domestic industry” which produces the like or directly competitive products. The fatty alcohols produced by the petitioner are comparable to the imported goods, and are commercially and technically interchangeable with the imported article.

D.8 The product covers grades/types which are same as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The products of all these headings find similar uses. Therefore these products are like and directly competing products. Despite possible minor superficial differences, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses. These are sold via similar or identical sales channel. These products compete mainly on price. Imposition of safeguard duty on one heading at eight digit level or one type, in isolation, will not serve any purpose as importers will start importing other directly competing products. Thus, it is submitted that in view of the above, for the purposes of safeguard investigation, the product mentioned in the initiation notification has been appropriately considered as the ‘product under consideration’.

D.9 The product under consideration includes grades/types derived out a single raw material. However, having regard to the fact that no single blend/cut can be taken in isolation, the entire set of carbon chains C8 to C18 needs to be looked at as a single category of product. The applications are broadly common, that is in the detergent and personal care industry. In fact, both C12 C14 and C16 C18 can be converted to ethoxylates and used as surfactants in detergent applications. C12 C18, which is a blend of C12 C14 and C16 C18 can also be used for similar applications. C14 must also be considered as it is a part of the blend C12 C14.

D.10 It may be relevant to consider, that the fatty alcohols constitute less than 10% of the soaps, detergents, personal care products. The different blends have commercial and technical interchangeability. The essential character of end use product, is not acquired from the fatty alcohol, but by use of other materials.

D.11 The petitioner is using the lurgi process at its Taloja unit. By this process, a product commercially known as coconut alcohols which is a blend of C8 to C18 can be produced. By a process of fractional distillation, any of the fractions – C8 to C18 can be taken out.

D.12 The petitioner has sold C10 on payment of duties of excise.

E. Post-Public Hearing Written Submissions: (relevant points are being mentioned here apart from the points covered in post-initiation submissions to avoid repetitions in respect of Interested parties who attended public hearing and submitted their post-hearing submissions):

E.1. Written Submission by Cavin Kare Private Limited vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. Fatty alcohol (C12 -14) is the key raw material for SLES which is the main constituent of shampoo formulation. The imposition of safeguard duty for Fatty alcohols makes 50 paisa shampoo category unviable, leading to denial of hygiene hair wash to Indian mass market.
- b. It would be against the present government commitment to support the domestic companies.

E.2. Written Submission by Government of Indonesia vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. The data for recent months show no sudden, sharp or significant increase in imports. Moreover, the rate of increase has dropped in April, 2014. The period of investigation is also too short to make an analysis.

- b. The DG Safeguards initially agreed that reduction of tariff under FTA was a foreseen development. Unforeseen development cannot be established by stating later on that the extraordinary pace and unanticipated surge in imports was not expected.
- c. The standard of serious injury has to be very high and exacting. Since (i) there are no increased imports (ii) performance of VVF has to be examined on export performance and (iii) VVF's domestic sales and other Indian FOH producers were relatively stable, the criteria fulfilling serious injury cannot be met.
- d. There is no parallel movement examination between the injury indicators and import trend. In such a case the existence of a causal link needs to be established by a compelling analysis.
- e. Being an EOU, the volume of domestic sales of VVF is totally dependent on its export performance. Data shows that initially export volumes were much higher than domestic sales; which later dropped considerably affecting the whole performance of VVF. However, this was a self-inflicted injury and was irrelevant to import of FOH, since VVF focused on export instead of domestic sales.
- f. Safeguard investigation is applied to fairly traded goods and the Agreement requires much higher standards in implementation. Safeguard measures are applied only in emergency situations of extraordinary nature. No such extraordinary nature is viewed in the present investigation.

E.3 Written Submission by M/s Kusa Chemicals Pvt. Ltd. vide letter dated 2nd September 2014 as follows:

It is a manufacturer of Lubricant/Surfactant Additives, and uses fatty alcohols as a raw material.

- a. These additives are being imported duty free from South East Asian Countries due to INDIA-ASEAN FTA. On account of this duty, an inverted duty structure will be created.
- b. Domestic industry (VVF & Godrej) never focused on Indian market. Kusa was buying their RM's from Godrej until they decided to stop manufacturing and then form VVF who were unable to fulfil the monthly quantity requirement, hence forcing them to find alternative import suppliers.
- c. Employment and Investment at risk.
- d. A very competitive Downstream Industry is now being forced to become uncompetitive. The Safeguard duty will give preference to import of downstream products and our export will also get hurt. This is at odds with the current government policy of encouraging local manufacturing.

E.4. Written Submission by M/s. PT Musim Mas vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. The Authority failed to examine trends in injury related parameters of the domestic industry over the entire course of the period of investigation from 2010-11 until 2013-14. It was examined over a period of only 5 months which is in violation of the Agreement on Safeguards and the Indian Safeguard Rules as such a selective examination is legally impermissible and does not establish that increased imports are causing serious injury.
- b. The increase in imports is not recent, sudden, sharp and significant, an increase in imports in terms of Article XIX:1(a) of GATT 1994 read with Article 2.1 of the WTO Safeguards Agreement as well as Section 8B(1) of the CTA read with Rule 2(c) of the Indian Safeguard Rules has not been established.
- c. The rate of increase of imports of the subject goods exhibits a declining trend over the course of the POI, therefore no increase in imports has occurred and any imposition of safeguard duty as an outcome of the present investigation is therefore legally impermissible.

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616
Trend	100	172	257	290
Increase in imports relative to previous year	--	72%	50%	13%

- d. The Authority has not established that the domestic industry is suffering serious injury or is facing a threat of injury.
- e. An upward trend is shown in the performance of the domestic industry in relation to sales of the domestic industry, employment, production, productivity, capacity utilization and inventory over the course of the period of investigation.
- f. No evidence exists of a significant overall impairment in the position of the domestic industry and therefore the threshold of "serious injury" has not been established in the present case within the meaning of Article 4.1(a) and Article 4.2(a) of the WTO Safeguards Agreement as well as Section 8B(6)(c) of the CTA and paragraph 1 of the Annexure of the Indian Safeguards Rules.
- g. The claim of threat of serious injury has not been substantiated with any evidence and the imports in 2013-14 increased by merely 13% and in fact declined by 15% in April, 2014.

- h. A causal link was not established between the increased imports and the alleged serious injury has wrongly been attributed to the increase in imports for the injury caused by factors such as export oriented focus of the domestic industry, the restrictions imposed on the domestic industry on sale of goods in the domestic market and bottlenecks in the domestic industry's production processes.
- i. Increase in imports of the subject goods occurred due to the grant of tariff concessions by India under the ASEAN India FTA (AIFTA). Such concessions by India are a concrete commitment undertaken under FTA and cannot be considered an "unforeseen development".
- j. Adjustment plan raises concerns. The imposition of a safeguard duty will not assist the domestic industry to restructure and the domestic industry will still suffer from comparative disadvantages as the main raw material for manufacture of the subject goods is produced in Malaysia and Indonesia.
- k. Safeguard duty is not in public interest. The imposition of a safeguard duty is not in public interest as there will be an impact to downstream uses and industries and a potential decrease in the quantity of the subject goods that the domestic industry can sell on the domestic market because of the restrictions imposed on them by the Foreign Trade Policy.

E.5 Written Submission by M/s PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. The imposition of provisional safeguard measure was based on incomplete investigation as the DG SG only examined the critical circumstances by establishing two different new period of investigations namely December 2013 to April 2014 and first quarter of 2013 -2014 to third quarter of 2014 -2015 on annualized basis in the preliminary determination and did not comply with the requirement of Article 6 of the WTO Agreement on Safeguards.
- b. No evidence of increased import which is recent, sudden, sharp and significant (Argentina Import Footwear WT/DS121/R).
- c. Failure to establish the link between import and unforeseen development as per Article XIX: 1(a) of the GATT 1994. The reduction in tariff is clearly a foreseen development as it is based on the negotiation between the Governments.
- d. No evidence of serious injury. Import dropped by 16% in April 2014, the petitioner operated under EOU for which its sales focus on export and its volume of domestic sales is totally dependent on its export performance and export sales volume was much significantly larger than its domestic sales. The petitioner's domestic sales, capacity, capacity utilization, production, profit and loss and market share can only be objectively examined on the basis of petitioner's export performance, instead of import of FOH into India.
- e. No causal relationship between import and performance of the Petitioner.
- f. No adequate and reasoned analysis on non-attribution factors analysis. Import has no correlation with the performance of the Petitioner as it totally depends on its performance of export sales.

E.6. Written Submission by M/s. Rhodia Specialty Chemicals India Ltd. - Solvay group vide letter dated 4th September, 2014 as follows:

- a. The proposed safeguard duty of 20% on Lauryl Alcohols would lead to inverted duty structure for the industry, thereby rendering the derivatives commercially non-viable in the domestic market, as compared to the cheap imports.
- b. The proposed duty would lead to a surge in the import of ethoxylates & derivatives and drive the value addition out of India. The same would lead to loss of employment and loss of revenue to the Government of India.
- c. The investment plans of INR 200cr in the plants in India to increase the production capacity would be reviewed as the proposed duty would make investment redundant. The future investments in India would be most probably shifted to other Solvay entities in South Asia.
- d. The contention of the lawyers of VVF during the course of the public hearing that there is no capacity for ethoxylation in South Asia is completely wrong inasmuch as there is a huge capacity for the same in Singapore by Shell and Solvay, which is expected to come on stream by March, 2015.

E.7 Written Submission by M/s. Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd. vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. Inverted duty structure for our industry will kill our competitive edge for both domestic and international market, as the imports of goods we manufacture will become more attractive for end users.
- b. VVF & Godrej never focused on Indian market. It was impossible to do business with VVF as their prices were high and their focus was always exports and domestic players were neglected by them.
- c. Employment and investment at risk.
- d. The data represented by VVF is manipulated as they have been able to sell at lower prices on international market, whereas the domestic customers were always compromised with higher pricing policy from them, thus using the saturated fatty alcohol from them for domestic supplies of ethoxylates, sulfonates, etc. became unviable.
- e. There is very high capacity of Ethoxylates in South East Asia which shall start coming into India with implementation of Safeguard duty creating inverted duty structure on our industry.

E.8. Written Submission by M/s. Viswaat Chemicals Limited vide letter dated 2nd September, 2014 as follows:

- a. Imposition of safeguard duty creates an inverted duty structure which facilitates imports to take over domestic manufacturing and this action is contrary to our government's stated intent of promoting manufacturing as exiting investments are under threat.
- b. VVF & Godrej never focused on Indian market. Godrej stopped offering Fatty Alcohol 1214 in the local market long back. They offer CetoStearyl Alcohol 1618 only when they have excess stock. VVF offers LA 1214 and CetoStearyl Alcohol whenever there are no exports. Imposition of this duty creates unfair advantage to one player to use the 20% advantage to creep into markets of incumbent players.
- c. Employment and Investment at risk.
- d. Imposition of Safeguard Duty forced the downstream industry to become uncompetitive and it created trading environment at the expense of a manufacturing one which the government is promoting.
- e. Incorrect information made by the VVF Lawyer's presentation as already SLS, SLES & Ethoxilates exports started from S/E Asian countries into India.

E.9 Written Submission by M/s. Unidus vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

Unidus offers saturated Fatty Alcohols (SFA) and the finished products made out of SFA find end applications in diverse Industries. Most of these end products attract import duty of 0-10% while SFA was available at Zero duty rate under FTA.

- a. Notification No. 03/2014-Customs (SG) dated 28th Aug 2014 imposing 20% Safeguard duty will bring in a new inverted duty structure, promoting imports from SE Asia & Middle East of Ethoxylates, Sulfonates etc.
- b. Imposition of this Draconian Safeguard Duty will destroy many Efficient Tax Paying Domestic Industries in SME sectors at the cost of 2 EOU.
- c. It will also result in
 - (i) Shift of value added Specialty Chemicals manufacturing out of India
 - (ii) Loss of Employments for Highly Skilled Technical Manpower- Chemists & Engineers
 - (iii) Foreign Exchange loss as we will import Higher Value added products instead of Basic SFA
 - (iv) Inflationary impact on mass market FMCG i.e. Shampoo, Toothpaste, Face Wash etc.
 - (v) Significantly reduce future investment in Specialty Chemical domain in India.
- d. In effect, this duty to a large extent will undo the present government's stated policy "Make in India".

E.10 Written Submission by M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand, M/s. Wilamar Trading Pvt. Ltd., Singapore, M/s. KL-Kepong Oleomas SDN BHD and M/s Galaxy Surfactants vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. The Notice of Initiation intimated that the data for the period 2010-11 would be treated as Period of Investigation (POI). However, the preliminary finding, rests on the data for period December, 2013 onwards till April, 2014.
- b. The DGS has ignored the investigation period chosen for initiation and took a new period for examining 'critical circumstances', which is not correct.
- c. Neither Indian safeguard law nor AoS provides for consideration of separate data for making provisional determination, separate data for determining existence of critical circumstances and separate data for making final determination. The data and information has to be examined for the POI. A totally new figure cannot be adopted in the name of critical circumstances.
- d. The whole period selected for examination is abnormal since the import would be abnormally low in Dec 2013/mid Jan 2014 and then abnormally high thereafter.
- e. Critical circumstances insufficient to recommend provisional duty.
- f. Clear evidence is needed to show that increased imports have caused/threatened to cause serious injury. As per Article 6 of the AoS, there must be a determination of the conditions precedent for imposition of safeguard duty. However, in Para 17.3 of the Prelim Finding, DGS has merely examined whether there existed critical circumstances without proceeding to examining existence of serious injury. In the instant case, there was no preliminary determination as required in the law.
- g. Quarter to quarter analysis is incorrect. The price of the goods is directly linked to the prices of raw materials CPKO and any increase/decrease in the same would result in increase/decrease in prices of goods. It is therefore illogical to undertake quarter to quarter analysis.
- h. Preliminary finding is not a reasoned order as it fails to take note of Respondent's submission and fails to disclose reasoning leading to determination.
- i. DGS has not understood the correct meaning of unforeseen developments and effect of obligations and there is no finding regarding the developments, which led to increase in imports.

- j. Non-examination of 'increase in import due to reduction in Tariff as an obligation to WTO' under Art. XIX GATT 1994. India unilaterally reduced the tariff on the goods to 7.5% and the same was not due to its obligations under GATT. This was a policy requirement. If imports increase as a result of suo moto policy initiatives safeguard measures cannot be imposed.
- k. Standing and capacity of domestic industry to supply in DTA not examined.
- l. Applicant Domestic Producer cannot form part of 'domestic industry' as it is a 100% EOU.
- m. DGS has not noted the finding on the question as to whether the Applicant Domestic Producer could meet the demand by selling the goods in the DTA and earning NFE. The DTA entitlement of the petitioner is dependent upon value addition. If more quantities are sold in the domestic market, positive NFE will not be achieved.
- n. It has not been shown how serious injury to the Indian market has been caused inasmuch as the Applicant Producer being a 100% EOU, the raw materials are imported for re-export and not for sale in the DTA. The Applicant Producer is not competing in the Indian market.
- o. No Causal Link established. EU imposed anti-dumping duty on VVF as a result of which VVF suffered injury and loss.
- p. VVF is in-competitive due to EOU Status. VVF has a very limited capacity due to sales in DTA and it has to bear additional burden of non-excisable customs duty on sales in DTA. Since customs duty is not leviable, sale in the DTA is subject to additional cost.
- q. VVF has suffered exchange gain loss.
- r. As there is no feasible adjustment plan, duty cannot be imposed.
- s. Different carbon chain lengths of fatty alcohol are different products in themselves and should be examined separately. Where multiple product types are included in a single product type, it is necessary to consider the prices of each product type for correct analysis.
- t. VVF has claimed a higher capacity utilization and DGS in its findings has reduced the same by 1/4th.
- u. Imposition of safeguard duty would be detrimental to SLES/SLS producers as well as downstream user industry.
- v. VVF has claimed excess confidentiality, without justifying the same. In notification providing the relied upon information to other interested parties, natural justice is violated.

E.11 Written Submission by M/s. Hindustan Unilever Ltd. vide letter dated 5th September, 2014 as follows:

- a. Fatty acids and glycerin being co-products are intrinsically linked. The cost of procurement of fatty acids and transfer price of fatty acids should not be exaggerated to claim a higher cost and NIP. The allocation of costs and capital employed between domestic and export sales should be clearly delineated.
- b. Domestic production should be considered only after reducing deemed exports to avoid inflated and inaccurate figures (as they presently stand).
- c. Injury analysis has been done without analyzing the annual trends and is thus contrary to practice and arbitrary. The increase in imports as shown by the yearly data is neither sudden, nor critical so as to require an imposition of immediate duty.
- d. Lowering of tariffs had already been envisaged and could not be classified as an unforeseen circumstance. Increase in capacities in any country is not of effect of India's obligations under GATT and is irrelevant in terms of unforeseen developments for imports.
- e. VVF has claimed that there is no benefit to be derived in terms of cost of production in the adjustment plan. The only set-offs admitted relate to the Indonesian subsidiary, which go against the concept of positive adjustment. The adjustment plan is unsustainable so far as it is contingent upon export policy of a foreign jurisdiction (Indonesia).
- f. No benefit of duty reduction is derived by the consumers/end users of the Fatty Alcohols. For a consumer, purchasing from an EOU unit is costlier than purchasing from a DTA unit.

Particulars(INR)	EOU	DTA
Raw material	100	100
Conversion Cost	50	50
Profit	15	15
CVD/ Excise	10	10*
Price	175	175
Customs Duty	3.5%	NIL
Domestic Selling Price	181.12	175

* - Assumed to be based on Selling Price

- g. Imposition of anti-dumping duty by EU has impacted exports of VVF thus impacting the availability of the product in the domestic markets also. If sales realization of EOU and DTA markets remains at par, it cannot be denied that injury caused to VVF is primarily from DTA sales.
- h. The cost and price demonstrated by VVF has been inflated. The imposition of safeguard duty will lead to a drop in the downstream users' profits that in turn will increase prices and pass them on to consumers.
- i. If safeguard duty is imposed, it would not be viable to manufacture derivative products in India, as they can be imported in India without any customs duty.
- j. Alternatively, the specific safeguard remedy available under the ASEAN CECA to counter a surge in imports should be recommended.

E.12. Written Submission by M/s Majorhub Oleochemicals Pvt. Ltd. vide letter dated 4/9/2014 as follows:

- a. Majorhub has never advocated keeping Godrej out of the picture; in fact they requested the informer to question Godrej. How will it be verified that in a notice where Godrej industries was not considered as an importer what is the verification that the importation facts have not been altered. Either the officer issuing the notice has concealed Godrej or the intelligence team.
- b. Applicant has subdivided the import of Fatty alcohol into Saturated and Unsaturated alcohol, the reason behind this being the nature of the trade.
- c. Majorhub is a trader. There is no evidence either in law or in historical figures portraying that a trader is not at a disadvantage due to imposition of the safeguard duty, in fact the truth is that due to the disadvantage caused they have to find an alternative business. We have submitted the evidence the reduction in the number of factory workers to the Directorate General of Safeguards.
- d. The Finance Minister had in the budget given examples of such biased levy of safeguard duty. Where the levy on raw materials for soap and Olivo chemicals has been reduced to 0%, similarly if the levy for galaxy is increased, it will not be unfair (with respect to raw material in other industries also, bigger industries have been given preferential treatment over smaller ones).

E.13 Written Submission by M/s Aarti Industries Limited vide letter dated 2nd September 2014 as follows:

- a. The imposition of duty will give an unfair advantage to Godrej who are one of the two domestic manufacturers of fatty alcohol and stand to gain the most over other manufacturers of SLS and SLES.
- b. Aarti Industry's major sale is in domestic market and the survival of their will be at stake as it will be highly uneconomical to run their plant with large capacity based on small export market.
- c. There will be an adverse impact on investment and employment.

E.14 Written Submission by M/s Matangi Industries vide letter dated 2nd September 2014 as follows:

- a. Their products use fatty alcohols as raw material and these products are being imported duty free from South East Asian Countries due to various FTA's applicable. Due to inverted duty structure, they will have to pay huge duty for importing raw material and will not be able to compete.
- b. The domestic industries (VVF and Godrej) never focussed on the Indian market.
- c. Employment and Investment at risk.
- d. A very competitive Downstream Industry is now being forced to become uncompetitive. The Safeguard duty will give preference to import substitutes and at odds with the current government policy of encouraging local manufacturing

E.15 Written submissions filed by Domestic Industry (M/s VVF (India) Ltd.) vide their letter dated 5th September, 2014.

a. Pre-requisites for levy of duty met

Article 2 of the Agreement on Safeguards under, GATT 1994, the basic requirements for imposition of duty under Article 2 are as under:

- i. *Such product is being imported in increased quantities; absolute or relative to domestic production*
- ii. *Imports are under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry*
- iii. *Existence of domestic injury that produces like or directly competitive products,*

Under the Municipal Law, Section 8B (1) of the Act provides for imposition of safeguard duty on the basis of a determination that the product is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry. Thus, for applying a safeguard measure, there must be a determination that:

- Petitioner has standing as "Domestic Industry" of the "like article"
- Surge in imports
- Such increased imports have caused or threaten to cause serious injury to a domestic industry.

- Non-attribution of factors other than imports causing injury

The rules also provide that the petitioner should provide an adjustment plan, with the application for imposition of duties over a longer period. The petitioner submits that the aforesaid requirements are fully met in the present case and request that a determination be made for levy of definitive duties.

b. Domestic Industry- Standing of Petitioner as a “domestic Industry for the like article”

Like Article is defined under sub-rule (e) of Rule 2 of the Safeguard Rules as, “*an article which is identical or alike in all respects as the article under investigation*”. There is complete commercial and technical interchangeability between the imported and the indigenous product. The basic features of the imported products and the like article produced by “domestic industry” are as under:

- Saturated Fatty alcohols with a carbon chain length of C8, C10, C12, C14, C16 or C18 & blend thereof, i.e. they have common physical and chemical characteristics.
- Arising as a result of High Pressure & High Temperature Hydrogenation, i.e. similar manufacturing process and technology used.
- Used primarily for the manufacture of surfactants, for personal care, home care and textile auxiliary applications, i.e. common function & uses.
- Single saturated fatty alcohols or blends of the same/similar Carbon Chain lengths, i.e. have common Product specification.
- Sold to common users and dealers, i.e. have same market.
- Covered under the heading 2905.17 or 3823.70, i.e. common HSN Classification

Thus, the article produced by domestic industry is a “like articles” to the imported goods, in terms of the Rules. The petitioner is a producer of a major share (approximately 65%) of the total production of the “like article” in India. It is a settled position that a “major proportion” or a “major share” does not mean the majority, but merely a significant or important part. In this context, reliance is placed on the decision in the case of Lubrizol India (P) Ltd Vs. Designated Authority reported in 2005 (187) ELT 402. The petitioner’s share of domestic production is about 65% of total Indian production and therefore, qualifies as “domestic industry”.

c. Surge in Imports

c.i The imports of fatty alcohols are already very high, and are continuing to increase further. The details of the imports are as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616	79957
Trend	100	172	257	290	403

*Based on April- June’ 2014

c.ii The imports continue to increase at a phenomenal rate. There is a threefold increase in the quantum of imports, from 2010-11 (base year) to 2013-14. There has been an increase in imports in absolute terms as well as relative to demand, on a year on year basis, both in terms of rate and quantity. In addition to an absolute increase in imports, the imports relative to total production of the DI, have also increased significantly.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616	79957
VVF Production	68605	49585	67837	93297	60746
Imports as a % of production	29%	69%	75%	62%	132%
Trend	100	238	259	214	455

*Based on April-June’ 2014 data

Thus, it may be seen that the imports relative to the production of the DI have increased from 29% in 2010-11 to 62% in 2013-14. The data for 2014-15 shows a further increase in imports relative to production from 29% to 132%. An

analysis of Imports relative to domestic production, i.e. production less exports, shows a more alarming and realistic picture of the relative increase in imports.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Imports relative to domestic production**	60%	118%	226%	247%	610%
Trend	100	197	377	412	1020

*Based on April-June' 2014 data **(production less exports)

c.iii The WTO Panel in *US- Steel Safeguard* has held that the requirement under Article 2.1 of Agreement on Safeguards is of “increased imports” and not of “increasing imports”. Thus, there is no requirement for the imports to be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product “is being imported” at such increased quantities at the end of the period of investigation, so as to cause injury to the domestic industry, the requirements of Article 2.1 are met. The relevant para of the report is reproduced below:

“7.207 We find support for our view in Article 2.1, which provides “that such product is being imported ... in such increased quantities”. The Agreement uses the adjective “increased”, as opposed to “increasing”. The use of the word “increased” indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have “increased” in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product “is being imported” at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met.”

c. iv The WTO Panel had occasion to consider the term “increased imports” in its panel report relating to *US Wheat Gluten*. An extract of the said decision is given below:

“1.1 The USITC observed that the volume of imports increased by 38 per cent over the POI[3], and found that “virtually all” of the increase occurred in 1996 and 1997.[4] The USITC also referred to data pertaining to the ratio of imports to production that indicate a drop from 100.6 per cent in 1993 to 88.2 per cent in 1994 and then an increase to 89.7 per cent in 1995, 139 per cent in 1996 and 145.4 per cent in 1997.

1.2 While these data indicate a decrease in imports -- both absolute and relative to domestic production - early in the POI, they subsequently indicate a sharp and substantial rise through to the end of the POI. We view this increase in imports reflected in the data before the USITC - both absolute and relative to domestic production - as recent, sudden, sharp and significant.”

c.v It is important to note that a 38% increase in imports over a 5 year period has been considered as “increased imports”. In the present case the imports have increased by 403% in 2014-15. In the last three years, there has been a very substantial increase in the volume of imports. Even though the increase of imports relative to DI total production has marginally declined in 2013-14 as compared to 2012-13, but it still remained at a very high level. Further, the decline was not because of any decline in imports but because of improvement in production of the DI on account of an improvement in export sales.

d. SERIOUS INJURY CAUSED TO DOMESTIC INDUSTRY

For the determination of serious injury, the following aspects have been considered to be relevant:

d.i. Rate and amount of increase imports in absolute and relative terms:

The imports have been increasing consistently throughout the entire period. As mentioned above, they have increased by 291% as compared to base year. Imports relative to domestic production (less exports) have also been increasing consistently i.e., from 60% to 247% in 2013-14. In 2014-15, the imports relative to domestic production have further increased to 610% as compared to 2010-11. The rate and amount of increase in imports is significant, is absolute and relative terms.

d.ii. Share of imports in Domestic Market

The share of imports in the consumption or demand has increased from 44% in 2010-11 to 72% in 2013-14, which has further increased to 80% in 2014-15 (annualised). In the year 2010-11, the market was almost evenly distributed between the domestic industry and the imports, and the Indian industry commanded more than 50% of the market share. In 2011-12, there was a surge in imports, and the imports captured more than 60% of the market. As is evident from

graph above, the imports are continuously on a rise since 2011-12, and are now holding more than 80% of the market share. The comparison of imports and domestic industry sales, as against the total Demand is as under:

Financial Year	Total Imports	Sales of DI	Sales of Other Indian Producer	Total Demand	Market Share	
					DI	Imports
2010-11	19843	17080	8242	45165	38%	44%
2011-12	34142	15285	6677	56104	27%	61%
2012-13	51055	12891	7573	71519	18%	71%
2013-14	57616	14777	8728	81123	18%	71%
2014-15*	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*Based on April-June' 2014 data

The Market Share of the Domestic Industry, on the other hand, has drastically decreased from 38% in 2010-11 to 10% in 2014-15.

d.iii. Change in the levels of Sales

The trend of Domestic sales of the petitioner is as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Domestic sales of DI	17080	15285	12891	14777	10376
Trend	100	89	75	87	61

*Based on April-June' 2014 data

From 2010-11 to 2012-13, the domestic sales of DI have consistently decreased, both in absolute terms and relative to consumption. In 2013-14, there has been a marginal improvement in sales as compared to 2012-13 but it still remained significantly lower than 2010-11 level. The decline in sales, must be viewed having regard to the dramatic fall in market share, from 38% to 10%, while the share of imports has increased from 44% to 80%. The domestic sale of the DI has further hit an all-time low in 2014-15 (annualised basis).

On an analysis of last three quarters, the declining trend of domestic sales becomes evident:

	Q3'2013-14	Q4'2013-14	Q1'2014-15
Domestic Sales (MT)	3557	2965	2594
Trend	100	83	73

d. iv. Domestic Production

In a growing market, the bulk of the incremental demand has been met by the imports. The domestic industry has not gained from the growth in the domestic demand and its domestic production has fallen significantly.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Domestic Production (less exports)	33319	28974	22560	23303	13065
TREND	100	87	68	70	39

d. v. Productivity

There are no significant changes in the productivity.

d.vi. Capacity Utilization

- a. The capacity utilization for domestic production (production less exports) has also declined considerably.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Capacity Utilization %	28%	24%	19%	19%	11%
Trend	100	86	68	68	39

* Based on April- June' 2014 data

- b. The capacity utilization for domestic production has declined from 28% to 19% in 2013-14 and further decreased to 11% in 2014-15. Even though overall capacity utilization, having regard to the exports, improved marginally in 2013-14,

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Capacity Utilization %	57%	41%	56%	78%	51%
Trend	100	72	99	136	89

it is again on a declining trend in 2014-15.

* Based on April- June' 2014 data

- c. Further, an analysis of last three quarter also shows a decline in capacity utilisation.

	Q3' 2013-14	Q4' 2013-14	Q1' 2014-15
Capacity Utilisation (Domestic) (%)	19%	15%	11%
Trend	100	79	58
Capacity Utilisation (Total) (%)	84%	64%	51%
Trend	100	76	61

d.vii. Profit & Loss

The profitability of domestic industry has got fully eroded in 2011-12 and 2012-13. The profitability is reflected in the table below:

Years	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Profit/loss	100	-266	-2796	-2232

Since 2011-12, the domestic industry's position has been worsening rapidly, and it has not been able to recover its costs, in spite of an increase in market size. The production of the like article has become totally unviable, as the domestic industry continues to incur heavy losses.

d. viii Employment

The employment in the unit has increased from *** in 2010-11 to *** in 2014-15. This increase is largely on account of the expansions in the splitting plant, fatty acid fractionation plant, Glycerine plant and installation of captive power plant., the benefits of which have now started accruing.

e. Threat of injury is imminent

All the relevant parameters show a decline in the financial position of the domestic industry. In view of the above, unless duties are imposed forthwith, the domestic industry would not be able to survive. Serious injury has been caused, as is evident from the above analysis. Further worsening in the condition of domestic industry is imminent. The imports are

currently at high levels and increasing. In the WTO Panel Report of US Lamb, it has been held that imports at a very high level, for a long period of time, without further increases, would constitute a threat of serious injury. The fatty alcohols continue to be imported in large volumes, since 2011-12. The domestic industry has a declining market share, and faces huge losses. The very survival of the petitioner is at stake, as threat of further serious injury is imminent.

f. Causal link between the imports and the serious injury suffered by the domestic industry

f.i There is a direct nexus between the imports and serious injury caused to domestic industry. The imports were at their highest in 2012-13 and 2013-2014. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period when the imports were at high levels. The duties on imports of fatty alcohols from certain sources have been removed with effect from 01.01.2014. Anticipating this reduction, imports declined in the third Quarter. The petitioner was able to retain its customers during this period. In Q4, 2013-2014, after removal of duties of customs, the imports have increased drastically and the condition of domestic industry has further worsened. A comparison of Q3, Q4 of 2013 and Q1 of 2014-15 reveals the following:

	Q3'13-14	Q4' 13-14	Q1'14-15
Imports (MT)	13161	18176	19989
Trend	100	138	152
Imports Relative to VVF Production (%)	52%	94%	132%
Trend	100	181	254
Market Share of Imports	70%	76%	80%
Trend	100	109	114
Market Share of DI	19%	12%	10%
Trend	100	63	53

f.ii. From the above, it may be seen that the performance of domestic industry has significantly worsened in the last quarter as compared to the earlier period. The effect of any marginal improvements in Q3 has been totally wiped out in Q4' 2013-14 and Q1 of 2014-15. The imports have drastically increased in Jan- June' 2014-15.

f.iii. As a consequence, the domestic industry is facing severe price undercutting, price underselling and price suppression from the imports. Profits of domestic industry have also declined drastically in the last quarter. This clearly indicates that serious injury has been caused and threat of further injury is imminent. The causal link between the imports and injury is also established.

g. Absence of other factors causing injury

g.i There are no other factors causing injury to the domestic industry. The demand for fatty alcohols has been increasing consistently over the last three years. There is about 122% increase in demand, yet the domestic industry has not been able to increase its production, sales or profits commensurate to this growth in the market.

g.ii The petitioner is a 100% EOU, due to which it enjoys a competitive advantage over DTA Units. The customs duty on the raw materials (PKO), such as palm kernel oil, (which is in the range of 7.5% to 100% ad valorem) is far in excess of the duty applicable to finished goods. Since an EOU can import the raw material (PKO) without payment of duties, and clear its finished products on payment of duty @7.725% (which has now become 3.86% w.e.f 18th Feb 2014), the net duty applicable to EOU's is much less than that borne by DTA units manufacturing fatty alcohols from imported materials. The duty structure is advantageous for EOU units, since the duty on raw material is generally 100%. For instance, a DTA unit importing the raw material valued at Rs. 70, would have to pay duty of Rs. 70, whereas the EOU would be able to obtain the raw material without duties, under exemption. The like article, cleared from an EOU would be chargeable to duty at 7.725%, which would be in the range of Rs. 8 to Rs. 10. Thus the net duty incidence on the EOU is significantly lower than for DTA units.

g.iii. It is submitted that the DTA and EOU units in India are similarly placed. The PKO constitutes about 2/3 of the total cost of production. There are also no changes in the pattern of consumption, to suggest that injury is being caused by such factors. In the present case, there are no other circumstances or factors which are causing injury to the domestic industry at the same time and the requirements of causation are fully met.

h. Unforeseen circumstances**h.i Unforeseen increase in global capacities- far in excess of global demand**

Petitioner believes that since 2011, there has been 151% increase in the Global capacity for the subject goods. Out of the said increase in capacity, about 75% capacity increase has been done by the multinationals such as Wilmar, Ecogreen, KL-Kepong, Musi Mas etc, who are the participating exporters, opposing the levy of duty in the present investigations.

Estimated Global Capacity

Country	Pre 2011 (MT)	Post 2011(MT)
Indonesia	3,24,000	9,98,000
Malaysia	4,90,000	5,90,000
Phillippines	1,80,000	2,80,000
Global Capacity	22,70,000	34,27,000

h.ii.

EXPORTER	Estimated Current Capacity
Sasol / Wilmar JV China	60,000
Wilmar International Ltd. Indonesia	1,50,000
Wilmar Huntsmen JV Netherlands	1,50,000
Ecogreen Oleochemicals Pte Ltd.	4,04,000
Musi Mas Indonesia	2,80,000
KL Kepong Oleomas Sdn Bhd Malaysia	2,80,000
Thai Oleochemicals Co. Ltd Thailand	1,30,000
China Sanjiang Fine Chemicals China	1,30,000
Liaoyang Huaxing Shenyang China	2,20,000
Total	18,04,000

The setting up of such a huge capacity has led to the over supply of the subject goods in the market. In South East Asian region alone, about 60% of global capacity has been setup whereas it has less than 7% of global demand. This has caused glut in the market.

h.iii. The sharp and sudden increase in the global supply of fatty alcohols has resulted in a search for markets and price wars between existing suppliers to capture existing and future markets. The main target for the incremental capacities is the growing markets of China and India. The global demand in the developed world is largely saturated and there are already local players, who have strong presence in these markets. As against this, the economic development in China and India, as well as per capita consumption of products such as shampoos, detergent etc., is on the rise. This is coupled with an increasing population. In the case of China, the multinationals are in the process of setting up units in China to take advantage of various benefits offered by the local administrations. In respect of India, however, the principal strategy appears to be to export the products in huge quantities, so as to flood the Indian market with the imported products, and oust Indian producers, such as the petitioner from the Indian market.

h.vi. The demand scenario in the various markets is as under:

- **AMERICAS:** The American market does not have a growing demand and is already saturated. Natural alcohols are facing steep competition from synthetic alcohols which are comparatively cheaper due to availability of Shale gas at low prices.
- **EUROPE, AUSTRALIA & RUSSIA:** These are also saturated markets having negligible growth in demand. Local produces such as Shell, BASF, Wilmar etc., are already catering to the local demand. Moreover, EU has imposed Anti-dumping duties on the imports of fatty alcohols from the South East Asian Region.
- **AFRICA:** A very small market, mostly catered to by Sasol in South Africa
- **MIDDLE EAST:** Local producers having a capacity of 83,000 MT (Saudi Kayan), far in excess of local demand.

For the reasons above, India is the primary focus.

i. Public Interest

i. i. As stated above, because of the surplus capacities created in South East Asia, there is a global over-supply of the subject goods. In such a scenario, these exporters have adopted an aggressive strategy to capture the Indian market and wipe out the domestic industry. It is submitted that the Domestic Industry is already running in huge losses. Unless definitive duties are levied to redress the surge in imports, domestic producers will face closure. In the absence of competition from Indian producers, foreign exporters may restrict supplies and hike prices, which would be against the long term interests of Indian consumers.

i. ii In the short term also, levy of duties would have negligible impact on the consumer prices of end products such as toothpaste, shampoos detergents etc. A calculation of the Impact of duties on shampoos is reproduced below:

SHAMPOO (SACHET) 6 ML	
	RS.
PRICE	1
COST	0.6
15%* SLES USED BY WEIGHT @ \$1257/ MT	0.068
FATTY ALCOHOL CONTENT IN SLS 50%*	0.034
EFFECT OF 20% DUTY	0.0068
% OF PRICE	0.68%
Less than 1% of price or less than a paisa	

*Based on industry standard

**1 molecule of SLES consists of 1 Molecule Fatty Alcohol. The molecular weight of SLES is 384 (refer the SLES RHODIA) and the average molecular weight of C1214 is 190-197 (refer VVF C12-14 MSDS), since the ratio of the two molecular weights (i.e 194/384) is 0.5, the Fatty Alcohol content in SLES is around 50%.

i. iii. From the above, it may be seen that the impact of 20% duties on Fatty Alcohol would be negligible, less than 1%, on the price of the Shampoos even when it is sold in sachets.

j. Right of participation restricted

j.i. The petitioner requests that written submissions of only registered “Interested parties” may be taken on record. It may also be noted that, exporters and importers, who even though have registered, have not filed the prescribed questionnaire as required under Rule 6(4). Every exporter, importer and association, who wishes to participate must satisfy the Hon’ble DG regarding his status as an interested party of the subject goods. Rule 6(4) of the rules requires the exporter to furnish information in prescribed format within 30 days. In the instant case, most of the exporters have not filed a response to the Exporter’s questionnaire. The Questionnaire requires the Exporter to furnish information, to substantiate that they are “Exporter of the subject goods”. In the absence of any response, their claim as Exporter is not substantiated. If these parties are allowed to participate and their submissions are taken on record, the same would render Rule 6(4) a nullity. Similarly, the majority of the Importers have not filed any response to the Importer’s Questionnaire, and as such have not produced any evidence or information to show that they have imported subject goods, during the relevant period. Therefore, even their claim as Importers is not substantiated and they should also not be allowed to participate in the proceeding.

j.ii. “Interested Party” as defined in the Rules, includes “a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article”. To participate in the Safeguard proceedings, an association must show its eligibility i.e. must prove that the majority of its members are producers, exporter or importers of the subject goods, by way of documentary evidence. ISCMA has failed to show, that a majority of its members are dealing with the subject goods. In view of the fact, that some of the members of the Association, such as Godrej Industries Ltd are supporting the levy of duties, the views of the office bearers, cannot be considered to be the views of the Association. The Association can take an official position, only after conducting a GBM/polls, to ascertain the views of the majority of the Members of the Association.

k. Excessive confidentiality

a. The Appellate Body in *EC – Fasteners (China)*, has stated that:

“543. Article 6.5.1 contemplates that in “exceptional circumstances” confidential information may not be “susceptible of summary”. In such exceptional circumstances, a party may indicate that it is not able to furnish a non-confidential summary of the information submitted in confidence, but it is nevertheless required to provide a “statement of the reasons why summarization is not possible”. Article 6.5.1 relieves a party of its duty to provide a non-confidential summary of information submitted in confidence only if doing so “is not possible”. It is not enough for a party simply to claim that providing a summary would be burdensome or costly. Summarization of information will not be possible where no alternative method of presenting that information can be developed that would not, either necessarily disclose the sensitive information, or necessarily fail to provide a sufficient level of detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence”.

b. In the present case, neither any summary nor any statement of reasons as to why such summarization is not possible has been provided to the Petitioner. It may be seen that all the quantity related data of the Petitioner have been disclosed in the initiation notification as well as the provisional findings. Adopting a different standard of confidentiality for the Exporters/ Importers is not justified. The petitioner therefore, requests that the parties should be called upon to furnish a non confidential summary of the information, failing which submissions of such parties should be rejected.

E.16. M/s Godrej Industries Ltd. (Supporter)– Submissions dated 5th September, 2014

a. Godrej is concerned by the very sharp increase in the volume of imports and in a short span of 3 to 4 years, the imports have gone up from less than 20,000 MT in 2010-11 to 57600 MT in 2013-14.

b. While there is a consistent increase in the demand for the product in India, the share of imports has shot up from 44% in 2010-11 to more than 70% in 2013-14.

c. The flooding of the Indian market with imports, has adversely affected the profitability of Indian producers and therefore, imposition of definitive duties is required at the earliest.

F. Post-Public Hearing views of the Parties allowed to attend Public Hearing (other than Interested Parties) who gave their written submissions:**F.1. Written Submission by M/s. Hindustan Polyamides & Fibres Limited (HPFL) vide letter dated 5th September 2014 as follows:**

- a. The investigation has been initiated based on information made available by secondary source IBIS and the reasons for making this exception should be made known. The safeguard duties should not have been recommended on such a product, the import data and the tariff heading of which have been consciously kept outside the purview of the findings.
- b. The investigation is flawed as the scope of the PUC has been defined without proper analysis and appreciation of the facts. C8 Alcohol should be out of the purview of the investigations.
- c. There is a lack of technical substitutability. There is a difference of physical characteristics. C8 and C10 are in liquid state and the melting point of C8 is -16.5°C and that of C10 is 5-7°C. On the other hand, C18 is solid with melting point as 56-60°C.
- d. C8 is also not commercially substitutable. There is a significant difference in the prices between C8 and other pure chemicals and therefore the question of commercial substitutability is completely ruled out.
- e. The domestic industry is not producing C8 and C10 and do not have any intent to produce them either. Therefore, any injury to Domestic Industry cannot be attributed to C8 and C10.

F.2 Written Submission by Indian Specialty Chemical Manufacturer’s Association vide letter dated 5th September 2014 as follows:

- a. Imposition of Safeguard duty is against the grain of what the Government has been articulating. Safeguard duty creates in Inverted duty structure for the downstream Surfactant Industry and as a result, by policy imports are being encouraged instead of domestic manufacturing.
- b. By imposing this duty, we are dis-incentivising efficient producers who have toiled to build the competitiveness

F.3 Written Submission by M/s Croda India vide letter dated 3rd September 2014 as follows:

- a. The imposition of duty will move value manufacturing out of India, lead to loss of employment, have an inflationary impact on consumer goods, significantly reduce future investment in India and could lead to industry getting back to increased use of environmental harmful feed stocks like Alkyl Phenols in place of SFA.
- b. Many grades of SFA are as such not available when required. The two domestic industry producers never focussed on India and were always keen for exports and a major proportion was exported to countries where they

is no duty protection and where these manufacturers successfully compete and so it is expected to be easier for them to compete in India.

- c. The huge downstream industry needs cost effective options to serve the end consumer in India. Increased costs will eventually lead to increase in prices of many consumer products, fuelling inflation.
- d. Employment and investment opportunities are lost. Ethoxylates were manufactured with Alkyl Phenol (not environment friendly) but with conscious efforts substitute eco-friendly Ethoxylates based on SFA were developed to make industry environment friendly and this will be impacted sharply if the SFA cost increase of safeguard duty is maintained.

G. Rejoinder Submissions- Interested Parties -:

G.1. Government of Indonesia vide letter dated 12/9/2014 as follows:

- a. No evidence of increased import. The data of five most recent months shows no recent, sudden, sharp and significant increase at all. Also, the rate of increase was relatively low and it even dropped by 16% in April 2014. The POI used is too short which does not allow proper examination to be made.
- b. The authorities have failed to establish the link between import and unforeseen developments. There is no evidence of serious injury or significant overall impairment as there is no increased imports, also the Petitioner operates under EOU, so that its sales, capacity, capacity utilization, production, market share should be examined based on the Petitioner's export performance. No causal relationship between import and performance of the Petitioner has been established.
- c. There is no non attribution analysis of other factors made by the DG Safeguards in the preliminary determination as mandated by Article 4.2 (b) of the Agreement.
- d. Under EOU, the volume of domestic sales of the Petitioners is totally dependent on its export performance i.e. more export more domestic sales. The domestic sales are hence irrelevant.

G.2 M/s. PT Musim Mas vide letter dated 18th September 2014 as follows:

- a. Absolute and relative increase in imports not established. The rate of increase of imports of the subject goods exhibits a declining trend over the course of the POI, therefore no increase in imports has occurred and the increase in imports is not recent, sudden, sharp and significant to cause or threaten to cause serious injury.
- b. No serious injury or threat of serious injury has been established as having been caused to domestic industry.
- c. The key injury parameters in relation to employment, production, productivity and inventory show an upward trend over the course of the period of investigation.
- d. The petitioner has submitted in their written submission that the significant increase in employment is attributable to "expansions in splitting plant, fatty acid, fractional plant, glycerine plant and installation of captive power plant". It is unclear why such an expansion of the very manufacturing plants would be undertaken, when the petitioner is allegedly suffering injury.
- e. A causal link was not established between the increased imports and the alleged serious injury. Injury has been caused by factors other than imports such as export oriented focus of the domestic industry, the restrictions imposed on the domestic industry on sale of goods in the domestic market and bottlenecks in the domestic industry's production processes.
- f. Global increase in capacity cannot be said to be an unforeseen development, in the light of declining rate of increase in imports as against the increase in capacities of South East Asian exporters, and therefore, no linkage exists between the increase in imports and increase in the capacities of exporters in South East Asia.
- g. The submissions of the Petitioner that market in America, Europe, Australia and Russia, are saturated is incorrect. We have compiled the import volumes of the subject goods into the United States from South East Asia to establish whether there is a saturation of the markets in the United States as claimed by the Applicant. In particular, the data below provides the import volumes of Fatty Alcohols classified under HS Code 382370 for the period 2010 to 2013 from Indonesia, Malaysia and Singapore:

h.

Country	2010 (Kgs)	2011 (Kgs)	2012 (Kgs)	2013 (Kgs)
Indonesia	3,53,57,553	3,04,62,364	3,35,52,695	3,95,05,317
Malaysia	3,52,55,606	4,07,38,116	4,20,26,903	4,78,50,859
Singapore	2,64,580	2,76,712	2,95,032	24,05,731

- i. Export of subject goods from Singapore has increased by 715% in 2013 as compared to 2012. This clearly shows that the US market is not saturated. The claim made by the petitioner is baseless.
- j. Applicant has not provided details of the adjustment plan in its initial Application. And has failed to address any positive adjustments being taken or planned to be taken by the domestic industry, as required under Rule 5(2)(b) of the Indian Safeguard Rules.

G.3. M/s Kusa Chemicals Private Limited vide letter dated 2nd September 2014 as follows:

- a. The imposition of duty will create an inverted duty structure for the surfactants/lubricant additive industry.
- b. Domestic industry (VVF & Godrej) never focused on Indian market. Kusa was buying their RM's from Godrej until they decided to stop manufacturing and then from VVF who were unable to fulfil the monthly quantity requirement, hence forcing to find alternative import suppliers, which also now is being closed as an option.
- c. Employment and Investment at risk.
- d. A very competitive Downstream Industry is now being forced to become uncompetitive. The Safeguard duty will give preference to import of downstream products and our export will also get hurt. This is at odds with the current government policy of encouraging local manufacturing.

G.4. M/s Galaxy Surfactants Ltd., KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, M/s Thai Fatty Alcohols Co Ltd & M/s Wilmar Trading Pte Ltd vide letters dated 18th September 2014 as follows

- a. The pre-conditions for imposition of safeguard duty are not restricted to the three conditions listed by VVF but further include:
 - (i) It must be proved that the increase in import is due to an obligation incurred by India under GATT, 1995 [Article XIX.1 (a) of GATT]
 - (ii) It must be proved that the imports increased due to development which could not be foreseen at the time of the WTO Agreement [Article XIX.1 (a) of GATT]
 - (iii) The application of the Applicant Domestic Producers shall be supported by a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition (Rule 5 (2) (b))
 - (iv) The authority must satisfy about the existence of a plan which will facilitate positive adjustment to import competition [Rule 11(2)]
 - (v) It should be proved that the measure is in public interest.
- b. A positive adjustment plan must be provided even when one day duty is imposed, in terms of Rule 5 (2)(b) read with Rule 11(2).
- c. Being a 100% EOU, the Petitioner does not have the requisite standing as a "Domestic Industry" in the present investigation. It has been held by Supreme Court in *Hindustan Granites vs Union of India* [2007 (12) SCC (178)] that EOUs are formed with an objective to export their entire production while sales in Domestic Tariff Area (DTA) forms only an exception to the general rule.
- d. Godrej has supported the application filed by Petitioner but there is no concept of 'supporter' under safeguards provisions (DGS has held in its final finding in Hot Rolled Coils/sheets and strips). Furthermore, VVF is an EOU and it is ineligible to form part of domestic industry and its data cannot be used to ascertain injury in the domestic market.
- e. Use of Import data for 2014-15, which is merely based on 2 months data, is bound to skew the entire analysis. Period of investigation has been restricted by DGS.
- f. Petitioner has considered all the carbon chain lengths as homogenous and then combined them to show a surge in imports but examination of trend and effect of imports by clubbing all the types of Fatty Alcohols chains as a single product is incorrect.
- g. Major part of Import of Fatty Alcohol is not for use in Indian Domestic market but for the finished goods manufactured out of the same and exported out of the country. The demand as provided by the Petitioner is not correct.
- h. The DGS may inquire thoroughly to see if economic parameters which are showing injury the data relating to non-subject goods may have been included.
- i. Loss of domestic market, while gaining export market cannot be considered as an injury. Further, the drastic fall in profitability with increasing production and sales, does not appear to be proper.
- j. The causal link between the imports of subject goods and performance of Petitioner is missing. In fact, the Petitioner's performance is directly linked to following factors, which has not been forthcoming either in the petition nor the preliminary finding of DGS:
 - i. Anti-Dumping duty imposed by EU on VVF exports of subject goods:
Since 2011, when the anti-dumping duties took effect, the Petitioner also started suffering injury and went into loss for the first time.
 - ii. VVF not competitive due to its EOU status:
As Excise duty levied on clearances of an EOU to DTA, is equivalent to customs duty and Basic Customs duty is not cenvatable, as result, any EOU wishing to sell in DTA has to bear an additional cost.
 - iii. Effect of ASEAN-India FTA:
One of the biggest reason for rise in imports is due to Indian Government's own initiative to boost trade.
 - iv. Intrinsic factors:

From their financial statements, it appears petitioner has suffered injury on account of slowdown in consumption, slower growth of urban areas, increase in raw material cost, inflation, lower GDP growth, policy details, high interest rates and higher deficit.

- k. The injury can also be attributed to petitioner ability in managing its foreign exchange exposer, reading markets and competition and building competencies.
- l. Excess capacities in other jurisdiction is immaterial for determining unforeseen circumstances.
- m. The Imposition of safeguard duty will lead to inverted duty structure in respect of SLS/SLES.
- n. Petitioners have claimed excessive confidentiality. They have not even disclosed those data in their written submissions, which have already been disclosed in preliminary findings.

G.5. M/s Galaxy Surfactants Limited (separate submission) vide letters dated 18th September, 2014

Submission on the subject of Europe being a critical market for the domestic industry:

- a. The rebuttal of the Domestic Industry that Europe is not a major market is factually incorrect.
- b. At the time of imposition of ADD in Europe was the biggest Export market for the Domestic Industry. Since other players competing with the Domestic Industry in Europe also have lower ADD (e.g. Ecogreen having 0% ADD) it was not possible to pass on this duty to customers creating a disadvantage to domestic industry player.
- c. As a result, continuing to depend on Europe with such high shares in 2012-13 only added to the injury which is in line with their financial statements.
- d. Exports of fatty alcohol from India (mainly to Europe) were being subsidized at the expense of the Domestic Market which is why Imports also came in.
- e. The impact of the ADD is clear in the trend that the share of Europe in Domestic Industry business has fallen every year progressively.
- f. As per law, an Indian company cannot seek Safeguard duty for injury resulting from subsidizing exports or to mitigate the injury from ADD.

Submission on the subject of Import surge will not happen due to inability to transport water based products (Galaxy Surfactants Limited):

- a. The points presented by the Domestic Industry are incorrect and there is adequate capacity available in the proximity regions from where finished goods can come at Nil/Low duty and it has been confirmed by our own purchase.
- b. All Fatty Alcohol based products are not water based as Ethoxylates & Alcohol Sulfates are water free products further confirming the pattern of the Domestic Industry to present incorrect facts.
- c. If an Indian company has been exporting in large quantities to every corner of the world and the trend has been upward, there is no validity of the point that products made from Saturated Fatty Alcohol are water based and hence cannot be transported over large distances.
- d. Imports volumes, which are kept at the bay by the intensely competitive Downstream Surfactant Industry, started surging post the start of the investigation which the DG Safeguard needs to note. This is an alarming development considering the significantly higher employment, investment and economic footprint of the downstream Surfactant Industry.
- e. All the above only goes on to prove the fact sufficiently that Domestic Industry has been misleading the Authorities on the impact of the Invested Duty Structure and using wrong information to seek protection against an injury caused from subsidising exports.
- f. A globally competitive Indian Manufacturing Industry should not be used for an experiment to test a hypothesis presented by a company whose manufacturing has been accepted to be uncompetitive and whose data is faulty and responses erroneous.

G.6. M/s Viswaat Chemicals Limited vide letter dated 2nd September 2014 as follows:

- a. The basic raw material for the manufacturing of Fatty Alcohol is mainly produced in Malaysia and Indonesia. Hence Indian Manufacturers can never be competitive as they have to import the basic oil. Thus without the imports they will not be competitive and will have to close down their units.
- b. VVF claims that the increased import of Fatty Alcohol ruins the domestic manufacturers but one of the domestic manufacturer, Godrej Industries is doing very well and consistently in profits.
- c. VVF does not have the capacity to fulfil the requirement of some of the Fatty Alcohols such as C8 & C10 still they want to cover the same under Safeguard Duty.
- d. VVF claims that during 2012-14 due to high imports of Fatty Alcohols their profitability, Market share, return on investment was affected very badly. But the actual reason is, basic raw material covered by them was at very high price and sudden collapse of the price internationally affected their sale. In addition to that, currency fluctuation also affected their raw material cost.
- e. The Indonesian investment, as per the interview given by VVF in the Chemicals Weekly, is not a new but an old one but this was not clearly indicated in the petition or shown part of adjustment plan for the future. The fact that it is already 60% operational and already being exported to India means that it is not a new adjustment as

indicated in the petition. Indonesian Investment was not for tax saving then why does the Adjustment plan sheet show a tax saving due to this.

G.7. M/s Aarti Industries Limited vide letter dated 18th September 2014 as follows:

The imposition of this duty will discourage manufacturing of value added products in India as it will encourage duty free import of these products, discourage investment, lead to loss of employment, unfair advantage to one of the fatty alcohol manufacturer as they also happen to be manufacturer of downstream products and finally and inflationary impact on consumer goods.

G.8 M/s. PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia vide letter dated 19th September 2014 as follows:

- a. The preliminary determination was based on incomplete analysis of factors required to impose provisional safeguard measures. The examination made by the DG SG in the preliminary determination failed to present evidence of increased import, serious injury or threat thereof and causal link between import of FOH and the injury claimed. Also no unforeseen development was correctly and properly established and no adequate and reasoned non-attribution analysis was done
- b. There is no link between unforeseen development and imports. Based on the interview of the Petitioner by Chemical Weekly 9 September 2014, the Petitioner has admitted that it has invested in Indonesia, aiming to cater Indian and Chinese market. There are absolute inconsistencies between what the Petitioner claimed in its written submission and the facts revealed by the CEO of the Petitioner. The Petitioner failed to explain convincingly why the growth in capacity is unforeseen event. The expansion of capacity was planned and in stages so that it is clearly foreseen.
- c. The Petitioner tried to renew the data by adding the first quarter April-June 2014-15 (annualized) in its written submission, which is clearly designed to deliberately show it suffered serious injury. What the Petitioner states as its domestic production could be equated with its domestic sales but the situation is more confusing in the case of domestic capacity utilization. Such confusing analysis would not result in an objective outcome as it is intentionally designed to artificially create serious injury or threat of serious injury.
- d. The Petitioner tried to deny the fact that its overall performance is totally dependent on its export performance. The Petitioner claimed that its EOU status does not have any effect on its overall performance including the domestic sales. The Petitioner suffered decline of their export sales drastically (based on monthly and quarterly analysis). The domestic sales volume of the petitioner was insignificant as compared to export volume. The injury suffered is attributable to the extremely poor export performance. The Petitioner made no analysis to this critical fact but it only claimed narratively without any single analysis of data that its EOU status did not have any impact on its domestic performance, which is completely wrong. The CEO of the Petitioner in his interview confirmed that the Petitioner cannot even penetrate China market due to the higher import tariff. This is so since India has not yet concluded FTA with China, unlike South Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, and Thailand whereby they already have had FTA with China under the framework of ASEAN.

G.9. M/s HUL vide letter dated 19/09/2014

a. Pre-Requisites for Levy of Duty Met:

The essential requirements for a safeguard investigation cannot be limited to the language of Article 2 of the Agreement on Safeguards ("Safeguards Agreement"). Safeguards measures have their genesis in Article XIX of GATT 1994 under the WTO, which has an additional requirement apart from the factors enumerated by the Applicant, i.e. unforeseen developments. The Adjustment plan of the Applicant is reliant on policies of foreign jurisdictions and does not favour the Applicant but rather its subsidiary in Indonesia

b. Domestic Industry:

The "domestic production" supposedly calculated by the Applicant is also a misnomer since it is essentially the production quantity after excluding all export sales. Even if the Applicant has standing in the present investigation, the domestic industry scope for the purposes of injury still excludes one other major producer of the product under consideration i.e. Godrej.

c. Surge in Imports:

While there is an increase in imports, the EOU status of the Applicant clearly indicates where the priority of the Applicant is, i.e. Export sales. The period after the initiation of the investigation has been affected by the investigation itself, whereby this period should not be considered in the analysis of the surge in imports.

d. Serious Injury caused to the Domestic Industry:

The injury analysis presented by the Applicant relies haphazardly upon varying periods of consideration. All volume related parameters are inherently impacted by the EOU status of the Applicant and its continued focus on export sales. The price of exports made by India is lower compared to the price of imports into India which is allegedly causing it serious injury

e. Threat of Injury:

It is submitted that the Applicant has not provided any evidence to sustain its claims on threat of injury.

f. Causal Link between the imports and the serious injury suffered by the Domestic Industry:

There are certain factors which have clearly caused injury to the Applicant, which are EOU status of the Applicant, Dwindling Export performance of the Applicant

g. Unforeseen Circumstances

It is a fact that South East Asia is a global hub for oleo chemicals due to its abundant resources for palm kernel oil (the chief raw material).

h. Public Interest:

The Applicant's analysis on cost and price impact of duties continues to be flawed and inaccurate.

i. Right of Participation Restricted:

HUL has a right to participate in the hearing and all processes and the Hon'ble Director General (Safeguards) is obligated to take HUL's submissions on record.

j. Confidentiality

If the Hon'ble Director General (Safeguards) directs the exporters/importers to disclose volume data, it would be equitable to accordingly instruct the Applicants to disclose the relevant information as well.

k. Adjustment Plan

The adjustment plan proposed by the domestic industry is already in place - the Indonesian plant is already 60% operational and **all the exports are made only to India**. This is in clear contradiction to the claim made by VVF's representative at the public hearing to the effect that only 1.7% of the imports being from the Indonesian entity.

G.10 Domestic Industry (M/s VVF (India) Ltd.) vide their letter dated September 18, 2014**a. *Unforeseen Circumstances*****Unforeseen Circumstances not required to be examined under the law**

- i. The provisions under the Indian law do not require a determination as regards unforeseen circumstances. In the absence of Municipal Law requiring the imports to be a result of unforeseen circumstances, this requirement cannot be read into the law. It is a settled position that International law as enacted through various treaties can only be an aid to interpretation. There is hence no legal requirement that the increase in imports should be due to unforeseen circumstances. In this context, reliance is placed on the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Grahamophone Vs. Bahadur Pandey reported in 1984 (2) SCC 535 (SC) wherein it has been held as under:

“Comity of nations or no, municipal law must prevail in case of conflict. National courts cannot say yes if Parliament has said no to a principle of international law. National courts will endorse international law but not if it conflicts with national law. National courts being organs of the national State and not organs of international law must perforce apply national law if international law conflicts with it”

- ii. In most jurisdictions, a view is being taken that the Agreement on Safeguards (AOS) being the most recent legislation, incorporates and clarifies the scope of the obligations under the GATT Agreement.

Surge in Imports due to unforeseen circumstances

- i. Without prejudice to the fact that there is no requirement under Indian Legislation to make a determination as regards “unforeseen development”, it is submitted that the surge in imports is on account of following unforeseen circumstances.
- ii. The fact that the duties were being reduced progressively under the Free Trade Agreement was well within the knowledge of the Authorities, but the huge increase in capacities and the consequent surge in imports was not foreseen.
- iii. The levy of export duties by Indonesia and others, resulting in market distribution was not foreseen by India, at the time it entered into obligations under the Uruguay Round.
- iv. Huge production facilities will be set up in the countries covered under the FTA, without commensurate increase in global demand

Estimated Global Capacity

Country	Pre 2011 (MT)	Post 2011(MT)
Indonesia	3,24,000	9,98,000
Malaysia	4,90,000	5,90,000
Phillippines	1,80,000	2,80,000
Global Capacity	22,70,000	34,27,000

Source: Oleoline

From the above it may be seen that the global capacity has increased from 22,70,000 MT to 34,27,000 MT, since 2011.

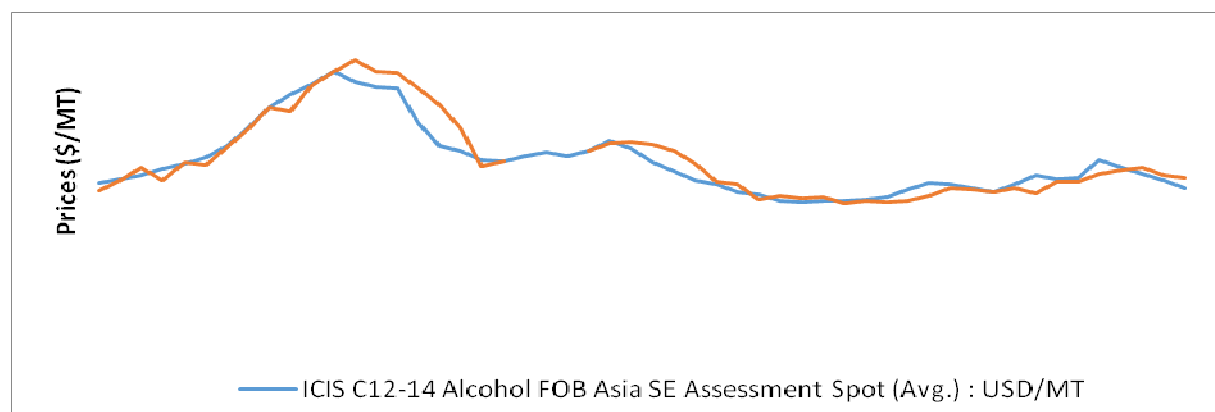
- v. Imposition of anti-dumping duty by European Union, which was the prime market for the subject goods.
- vi. Levy of high export tax on the principle raw material by the major exporting nations.

b. *There is no negative rate of increase of imports*

The conclusion that the rate of increase of Imports was relatively low and it even dropped by 16% in April 2014 is totally incorrect. In this context, it is submitted that the requirement under the Agreement on Safeguards as well as the Municipal laws is that the subject article should be imported in such “increased quantity” so as to cause serious injury to domestic industry. Reliance is placed on decision of the WTO Panel in US- Steel Safeguards and US Wheat Gluten.

c. *The injury is not caused on account of the export performance*

- i. On an annual basis, the exports have increased from 35286 MT in 2010-11 to 69994 MT in 2013-14. The exports have increased almost two fold during the injury period. The injury to the domestic industry is, therefore, not on account of a decline in export sales.
 - ii. A comparison has been sought to be made between the import prices and export prices of the domestic industry. In this context, it is submitted that only a comparison of the export prices and import prices at the same level i.e., at FOB level can give the correct picture.
- VVF's export prices largely follow market trends as can be seen from the following graph:



Graph 1

The above information clearly reflects that the injury is not on account of the exports.

- In any case, the injury determination has been done without consideration of the export volumes. The sales, domestic production, profitability etc., have been considered only for domestic sales and not for exports. This itself amounts to non-attribution of the effect of exports from the injury analysis.
- There are no other circumstances or factors which are causing injury to the domestic industry at the same time and the requirements of causation are fully met.

- While the domestic industry has interests in export markets, the injury submissions have been made on the basis of the information relating to the performance of the domestic industry, in the domestic market. The injury suffered is therefore not attributable to the export performance.

- It may be added, that the domestic industry was eligible to sell a much higher quantity in the local market during the injury period, having regard to the provisions of the EOU scheme.

d. Adverse impact on consumers of shampoos consequent to levy of duty

i. It has been contended by some of the parties that there will be a serious impact of the duties on the prices of shampoos and other consumer products. Calculations have been provided earlier to show that the effect of the duty would be only 0.68% of the price.

ii. Interestingly, even though duties on fatty alcohols have been falling progressively every year (from 15% to 0%), the consumers have not enjoyed any reduction in prices consequent to the Tariff changes. There has also been a variation in fatty alcohol prices, but with no reduction in prices for Indian consumers.

iii. Alternatively the quantity of the fatty alcohol, SLS/SLES can certainly be reduced by a minute fraction to retain the high levels of profitability.

e. No Adverse impact on ethoxylaters and producers of SLS, SLES

i. The contention that by the imposition of safeguard duty an inverted duty structure will be created for the SLS/SLES industry is not justified and even if it were to happen there are various remedies available under the law which can be availed by affected producers.

ii. The likelihood of a surge in imports of downstream products is highly unlikely, for the following reasons:

- No surplus capacity for manufacture of these downstream products in the FTA countries, due to less availability of ethylene oxide in the region, and the current capacities being contracted by multinational companies for their captive consumption.

- Historically there has been a duty differential of over 10% between Fatty alcohol and SLS/SLES, there have been negligible imports of SLS/SLES in the past due to high cost of transportation.

- SLES is in slurry form, and the water content in the solution is about 50% -70%, hence transport is very costly.

- The total import of SLS / SLES in the last financial year, 2013-14 was only 604 MT as against imports of more than 57000 MT of fatty alcohols in the same period.

- Anti dumping duties have been imposed by EU on imports of Fatty Alcohols from various sources. In spite of such duties, there has been no significant increase in the imports of SLS/SLES/ ethoxylates, to the EU as reflected by the import data for the EU for the downstream products.

Year	Top Countries	FTA Countries	Others	Total	% Top	% FTA
2010	95998	2193	12337	110528	87%	2%
2011	89380	1978	13252	104610	85%	2%
2012	97205	2632	14076	113913	85%	2%
2013	104740	1532	18612	124884	84%	1%

Source: EU Official Website

- More than 80% of the exports of SLS and SLES and ethoxylates to the EU are from Switzerland, Norway, USA, India, Japan, and Turkey (referred to as top countries), which do not enjoy nil duty under the FTA.
- We would also invite attention to our submissions on the issue made earlier.
- Fatty alcohols constitute about half of the raw material content of SLES
- SLS / SLES are used in the production of shampoos, toothpastes, etc.
- There are legal and advisory restrictions on the quantity of SLS / SLES, that can be used in personal care products
- Toothpastes typically have less than 2% of SLS, whereas Shampoos typically have less than 15%

Effect of duty on Cost / Price Toothpaste

Price of Toothpaste (150g)	Rs. 70
Cost of Toothpaste – excluding profit, dealer margin, wholesaler margin, advertising cost, etc.	Rs. 40
Max 2% SLS used in toothpaste by weight - 3g of SLS @ USD 2360 per MT as per HUL submission (Para 34)	Rs. 0.42
Fatty Alcohol content in SLS is 60% -	Rs. 0.25
Effect of 20% duty on Fatty Alcohol	Rs. 0.05

The net effect of a duty on toothpaste of Rs. 70 is only 5 paise – that is 0.07% that is not even 1%

f. Selection of period not inappropriate

- i. From a plain reading of Article 6 of the Agreement on Safeguards, it may be seen that the requirements of Articles 2 to 7 and 12, are required to be met for the purposes of definitive duties and not for provisional measures. Thus, for a provisional levy, only a preliminary determination that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury is required to be made.
- ii. It is noteworthy that the phrase “*preliminary determination*” has been used in Article 6 as against the term “*determination*” used in Article 2 and Article 4 of the AoS.
- iii. The aspect of criticality is to be examined having regard to the most recent period. The initiation notification considered 2013-14 as a part of the period of investigation. Since actual data was not available at that time, annualised figures were considered. In the provisional findings, the actual data has been considered for 2013-14, which reflects a surge in imports.
- iv. The claim that the data for the entire injury period has not been considered is factually incorrect, as is evident from paragraph 17.4 of the findings. Only for examining the aspect of criticality, the quarterly analysis has been undertaken.

g. No serious injury caused to the domestic industry

- i. For the determination of serious injury, the following aspects have been considered to be relevant.

- Rate and amount of increase imports in absolute and relative terms
- Share of Domestic market taken by imports
- Changes in level of sales,
- Production,
- Productivity,
- Capacity utilization
- Profit/losses
- Employment

- ii. All the relevant parameters have shown significant decline, which has further continued in 2014-15 (based on Quarter 1' 2014-15 data)

h. Threat of injury is imminent

All the relevant parameters show a decline in the financial position of the domestic industry. In view of the above, unless duties are imposed forthwith, the domestic industry would not be able to survive. Serious injury has been caused, as is evident from the above analysis. Further worsening in the condition of domestic industry is imminent.

i. Definition of product under consideration appropriate

- ii. It has been argued that Indian producers are neither manufacturing nor offering for sale unblended products i.e., C8, C10, C12, C14, C16 and C18. We submit that C8 is being manufactured and sold by Godrej Industries to many customers including HPFL. Copies of invoices are enclosed with the response filed by M/s Godrej Industries Ltd.
- iii. As regards the domestic industry, it has the capability to manufacture C8 and is willing to offer it to Indian customers, provided there is a demand for it.
- iv. It has also been argued that pure cuts are not being sold by VVF and that there is a huge price differential between the blended and the unblended products. This is not correct, for the reason that the prices of the blended and unblended products vary based on the demand and supply in the market.

v. Further, mixing of pure cut alcohols to produce a blended product can be done by a simple physical blending process known as Single Phase Blending.

j. Interested party wise comments:

(i) **Government of Indonesia** - Serious injury caused to domestic industry is evident from a sharp decline in the domestic sales, as compared to consumption in India. The domestic industry has a declining market share, and faces huge losses.

(ii) **PT Musim Mas** - The injury requirements cannot be understood as a checklist, as is being considered by this exporter. Not correct to say, that any decline in market share is on account of restrictions under the EOU scheme. As explained earlier, as long as a positive NFE is maintained, there is no restriction on the sale of goods into the DTA.

Adjustment plan proper

The petitioner has submitted a detailed Adjustment plant, showing year-wise projected savings. In terms of the Adjustment Plan, the domestic industry is in the process of setting up a plant in Indonesia. As per the plan, the petitioner will import a partially processed product, to avoid the heavy export tax imposed by the Indonesian and other governments and to enjoy certain logistic advantages, better negotiate prices with raw material suppliers and option to source PKO from smaller plantations. Consequent to the reduction in the raw material cost, there will be a decline in the overall cost of production of fatty alcohols in India. A detailed calculation sheet reflecting the manner in which the savings will be achieved has been provided as an Annexure F to the Petition.

(iii) **Kusa Chemicals Pvt. Ltd.** - the safeguard duty on fatty alcohols will not apply to imports made for use in export products. Therefore, the apprehension that the investment or employment will be adversely affected, is misplaced.

(iv) **Croda India Company Pvt. Ltd.** - It has been contended by Croda that the domestic industry does not sell certain grades. No grades have however, been specified in the letter. Croda, both in India and abroad, has placed orders on us for supply of the following grades, which have been duly supplied by us.

(v) **Sterling Auxillaries-** The contention that downstream industries engaged in manufacturing anti-oxidants will not survive is misplaced and only about 200 MT per year of fatty alcohols are sold for anti-oxidants and hence imposition of Safeguard Duty will have very insignificant impact on this industry.

(vi) **KL-Kepong OleomasSdnBhd / Wilmar / Thai fatty / Galaxy Surfactants** –An Export oriented Unit is a Domestic industry as has been held in the case of *Vikram Ispat Ltd.* and in various findings of the Designated Authority. The decision in the case of Hindustan Granites, further confirms the claim of the petitioner that there is no restriction on sales of goods in the DTA, even in 2004. The issue that the injury is on account of exchange control losses is totally unjustified. Even though the forex policy is in place, there will be forex exchange gain/loss due to the timing gap between the hedging and the actual receipt of the materials to the factory or sales of the materials from the factory.

The petitioner has a forex management policy in place. Even though the forex policy is in place, there will be forex exchange gain/loss due to the timing gap between the hedging and the actual receipt of the materials to the factory or sales of the materials from the factory. In the financial statement revenue is recognised on the date the commercial invoice is raised in the system and same way the raw material cost is on the date the goods receipt note is prepared in the system. The forex rate at which the revenue as well as the raw material cost is recognised may differ as compared to the hedging rate due to the timing gap between the hedging date vs. revenue /raw material cost recognition date. Basically the impact shown in the financial statement is part of the revenue and raw material cost but for reporting, the same is shown as part of the other expenses as per the accounting standard. It is only an entry which exists due to the manner of accounting. It is also important to consider that during the period 2011-12 and 2012-13 there was high exchange rate volatility and steep depreciation of the rupee which led to most corporate reporting high foreign exchange losses. The fluctuation, was the cumulative effect of several national and international factors, including the Eurozone crisis, for the devaluation of the Indian rupee, which hit a record low of 56.40 against the dollar. The petitioner's losses, are much lower than industry trends.

(vii) **Majorhub** - It is not clear what is the basis for seeking duty only on Galaxy Surfactants. The Safeguard duty is on the imports of the product under consideration, irrespective of the importer.

(viii) **CavinKare** - The effect of duties on shampoos would be negligible. Since the impact on the cost of Shampoos, is negligible, the profitability of CavinKare would not be significantly affected.

(ix) **Unidus-** There will be no significant impact on downstream producers. Furthermore, the end users should be buying from within India and not importing, if they want to endorse the 'Made in India' philosophy. As regards, setting up India as a global manufacturing hub – it is clarified that the duties would not apply to fatty alcohols used in export products.

(x) **Solvay** - South East Asia is a major hub for the manufacture of personal care and home care products. Much of the ethoxylate production is contracted to regional producers of shampoos and other products. In these circumstances, there is no surplus capacity available for export to India.

(xi) **Viswaat Chemicals** - there is little possibility of a huge surge in imports from South East Asia of the ethoxylates and other downstream products, as there is little surplus capacity in the region.

(xii) **Omni Impex Pvt. Ltd.** - The argument that huge imports of downstream products may come from Sabic is unjustified. As explained earlier, the high freight and technical reasons do not permit import of downstream products. Additionally, Sabic does not enjoy nil duty under FTA, and its imports would attract 10% duty.

(xiii) **PT Ecogreen** - Serious injury has been caused to domestic industry, with a sharp decline in the domestic sales, as compared to consumption in India. Profitability has also been adversely affected. There is a direct nexus between the imports and serious injury caused to the domestic industry.

(xiv) **HUL** - A doubt has been raised on the allocation of expenses for co-products, Glycerin and Fatty Acids. In this regard, it is clarified that Fatty alcohols are our main products, and Glycerin and Fatty Acids are incidental in the manufacture of Fatty alcohol. As regards adjustment plan, through its unit in Indonesia, the petitioner would be able to save on export tax and gain other logistics and price advantages.

(xv) **Hindustan Polyamides & Fibres Limited (HPFL)** - The Chapter Heading mentioned in the Petition is only indicative in nature, and is in no way binding on the scope of the product.

(xvi) **M/s VVF (India) Ltd. letter dated 29/9/2014**, has further clarified that the contention of some of the parties in their rejoinder submission that the US market is not stagnant, and imports from Singapore have increased by 715% is not correct. It was submitted that while imports from Singapore particularly have increased, but the total imports from all sources into US of fatty alcohol have not shown any dramatic increase. They enclosed year wise import data for subject goods, as made available by USITC on their official website.

G.11. M/s Godrej Industries Ltd. (Supporter) vide their letter dated 19th September, 2014

- a. P.T. Musim Mas in its submission at para 3.9.2 has stated that GIL's domestic sales have increased by 7% and 13% in 2013-14 and 2012-2013 as compared to the previous years, respectively. For a trend analysis, the sales quantity in 2012-13 and 2013-14 is required to be compared with the base year, 2010-11. There is a decline in sales in 2011-12, 2012-13 and 2013-14 as compared to base year. In 2011-12, margins have been maintained at the cost of sales, whereas in 2012-13, and 2013-14, in an effort to retain customers, margins have plunged.
- b. We deny the allegations made by M/s Viswaat Limited in para 2 of their submission that we have refused to supply the subject goods to them. We have been regularly supplying Ceto Stearyl Alcohol to Viswaat as and when it has been demanded.
- c. There is no unfair advantage to GIL as alleged in the written submissions of Viswaat and Aarti. The safeguard duty is required to protect the domestic industry and other producers from the injury caused by sudden increase of imports. The domestic industry and integrated player like GIL will be able to better utilise its fatty alcohol capacity, due to imposition of the safeguard duty which would create a level playing field.
- d. GIL does not have in house ethoxylation and ethoxylates are obtained under tolling arrangements. Hence the question of affecting domestic ethoxylators does not arise. GIL's sulphonation capacity is also limited (15% - 20% of industry capacity) and much lower than the market leader. The contention that GIL would adversely affect SLES/SLS industry is therefore not correct.
- e. The written submissions filed by HUL in para 58 have mentioned that GIL has 50% of its capacity registered as an EOU, which is not correct. The domestic capacity of GIL is around 70% of the total capacity. So, the requirements of domestic market can be easily met by GIL. Even otherwise, there is no restriction in the EOU Scheme on sales effected to a DTA unit by an EOU.
- f. It was stated by Croda during the public hearing, that Indian producers are not supplying C1618. In this context, we submit that we have regularly supplied to Croda and have submitted sample documents.
- g. We may also add that we have supplied C8 and C10 fatty alcohols in the domestic market during the period of investigation. We submit that C8 fatty alcohol has been sold by GIL to many customers including HPFL (sample invoices enclosed)
- h. Further, it has been argued that Indian producers are neither manufacturing nor offering for sale unblended products i.e., C8, C10, C12, C14, C16 and C18. It has been submitted that there is a huge price differential between the blended and the unblended products. This is not correct for the reason that the prices of the blended and unblended products vary based on the demand and supply in the market. If unblended grades are excluded, the importers will be able to circumvent the duty by importing the pure cuts and producing the blends with a process of physical blending. For example, if there is a safeguard duty applicable to C16 C18 blend, exporters will sell C16 and C18 in the proportion in which they get generated. The importers will be able to blend it in the same proportion. Currently, since C16 C18 is available, the demand for the C16 and C18 is lower and hence these items command high prices. But once the duties will apply on the blends, the demand for the unblended product would increase, resulting in a rationalization of prices of blends vs pure cuts. We further submit that the process of physical blending of pure cuts is routinely carried out in our factory as and when the need arises. It is not a complex process and can be easily carried out by the importers/customers.

- i. For any others aspects not covered herein above in this written submissions and relevant to the proceedings, GIL hereby adopts the written submissions made by the Domestic Industry, to the extent applicable.

H. Rejoinder by other parties

H.1 M/s. Hindustan Polyamides & Fibres Limited (HPFL) vide letter dated 19th September 2014 as follows:

- a. Requirements for levy of duty not met, having regard to adequacy and accuracy of evidence
- b. The DG has to follow the same principles as followed in the other investigations by the Directorate and if there is any deviation it has to provide full justification for such deviation from standard practices, especially with regard to standing of domestic industry, product under consideration, source of import data, and injury analysis
- c. The Applicant industry has not given any response to our claim that they are not producing C8 nor they intended to do so. The pure cuts are also not comparable to the blends
- d. No injury to the applicant industry can be caused by imports of C8 because applicant industry is not producing C8. Further, it is commercially not viable for them to produce C8 and C10 as there is no justification to recommend duties on such products.
- e. The imposition of safeguard duty is not only legally untenable but shall also prejudice the interests of the end users.
- f. All the issues relating to the rights and status of the non-registered interested parties go into oblivion once the DG has allowed the interested parties to make oral submissions and also to submit written submissions and rejoinder submissions like any other interested parties. The definition of interested parties is any inclusive definition. 'Interested parties' are not required to file response to any questionnaire prescribed by the Authority. The only legal requirement under Rule 6(6) is that the said oral information should be taken into consideration only when it is reproduced in writing.

I Examination in respect of pure C-8 grade

- a. During the examination of rejoinder submitted by M/s Godrej Industries Ltd. dated 19/9/2014 it has been noticed that they are manufacturing and selling C-8 single cut and in support, they have also submitted the relevant copy of invoices. It is noticed that this fact of actual production of pure C8 fatty alcohol was not placed on record earlier, and this issue has been raised by Interested party and also by another party. Therefore, in the interest of providing an opportunity to the Interested Parties to respond on this new evidence made available to the directorate, the Director General (Safeguards) ordered circulation of this evidence amongst all Interested Parties (including other parties) on 24/9/2014 with a direction to seek their responses latest by 29/9/2014. It was also circulated to the Domestic Industry and the Supporter, M/s Godrej Industries Ltd.
- b. It was found that both the Domestic Industry and the supporter, M/s Godrej Industries Ltd vide their letters dated 25/9/2014 expressed their views that they have no objection to the exclusion of pure C8 from the scope of investigations on account of small Indian market, for this grade. Since the DI and the Supporter have categorically admitted exclusion of pure C8 fatty alcohol from the scope of the PUC, the PUC stands revised/modified to this extent. Therefore, the response from different Interested Parties to the rejoinder submission of the Supporter dated 19-09-14, therefore, do not carry any relevance whatsoever, even then the responses received by different Interested Parties are being discussed below for academic purpose.

J. Views of the interested parties to the rejoinder submitted by M/s Godrej Industries Ltd. dated 19/9/2014:

J.1 M/s PT Musim Mas dated 29.09.2014.

- a. Analysis of Domestic sales in isolation is not sufficient to determine whether the imports have had any impact on the performance of GIL. The authority shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses and employment.
- b. The decline in domestic sales in 2013-14 as compared to the base year has been less than 2% only.
- c. GIL's claim that the increase in its sales has been at the cost of its profitability is false. In particular, GIL's Annual Reports indicate that the fatty alcohol division has consistently contributed the most to the turnover in its chemical division business.
- d. In addition, GIL states in paragraph 6 of its submissions that "there is no restriction in the EOU Scheme on sales effected to a DTA unit by an EOU" which is not correct. GIL may sell its goods in the DTA, only on fulfillment of a positive NFE and on payment of certain duties.

- e. As VVF (India) Limited is a 100% EOU and GIL also has a dedicated EOU, if there is a decrease in the value of export sales of both the companies, the impact on the availability of the subject goods for sale in the domestic market would be substantial. This decrease in Indian produced fatty alcohols would in turn lead to an increase in prices of the subject goods in India. Therefore, contrary to GIL's submission, there are restrictions imposed on an EOU's sales of the subject goods to the DTA and further this has an impact on the domestic user industry's access of the subject goods.

J.2. M/s HUL dated 29.09.2014.

- a. Submissions post hearing did not include any representations on behalf of Godrej, DG Safeguards cannot now accept a submission at such belated stage.
- b. DG Safeguards may clarify what "operating margins" (as used by Godrej in its submissions) means. It is also submitted that there is no source provided, nor any certification as to the credibility of this data.
- c. In response to paragraph 4 of HUL's submissions it is submitted that it is not merely Godrej's impact on the SLES/SLS industry that is of concern to the users of Fatty Alcohols. Rather, it is the imports of SLES/SLS that remain the primary threat to the downstream industry.
- d. As regards Godrej's averments at paragraph 6, it is submitted that even if Godrej's claim is accepted, an increase from 50% to 70% DTA capacity for Godrej only increases total DTA Capacity % (with total capacity as base) by 7.7%, which is negligible.
- e. Godrej's DTA production is higher than the wrongly calculated "domestic production" of VVF. Therefore, Godrej has a larger share in domestic production than VVF.
- f. At paragraph 2 and 7 of its averments Godrej has argued that it produces and has regularly supplied C1618 blend to Croda. However, since Godrej is not part of the domestic industry, it is not relevant to see Godrej's merchant market sales of the blends.
- g. At paragraph 9 of its submissions, it is submitted that unblended products of Fatty Alcohols have a notably higher price than blended products, with the difference being well in excess of 20% - which is the duty the importers might try to "circumvent" as per Godrej.

J.3 M/s PT Ecogreen dated 29.09.2014.

- a. GIL's domestic Sales annual data shows only a positive trend. This shows that the domestic sales of GIL was stable, proving no serious injury and equally there was no effect of the trend of import of FOH on its domestic performance as its sales decreased in 2011-2012 while the volume of import of FOH into India was lower than that of 2012-2013 and 2013-2014.
- b. It is a standard practice in safeguard investigation that the examination of industry indicators should instead refer to the trend of the entire period of the period of investigation instead of base year only. The DG Safeguards preliminary findings shows that the rate of GIL's domestic sales grew positively based on monthly and quarterly analysis.
- c. There are a number of critical factors of causal link such as the status of the Petitioner as EOU, the elimination of import tariff on FOH into India under Indian-ASEAN FTA, poor export performance of the Petitioner due to the imposition of anti-dumping duty on its import of FOH by the EU, inability to export to China due to higher tariff etc. which the GIL completely failed to address in its written submission.
- d. GIL made no single examination of factors related to unforeseen development, serious injury or threat of serious injury, causal link and non-attribution factors in its written submission, in the absence of which the GIL has failed to support the position of the Petitioner.

J.4 M/s Unidus dated 29.09.2014.

- a. It is not understood how GIL can raise new issues & submit copies of documents, at this stage. Same benefit should be given to other interested parties also.
- b. Rejoinder submitted by M/s VVF should also be circulated.
- c. As we can see imposition of the Provisional Duty, consumers are importing the Downstream Products & forcing both the applicants & other local players to lose the business to overseas Sulfonators & Ethoxylators in ASEAN countries as finished products are allowed to be imported at 0- 6% under FTA.

J.5 M/s Viswaat by email dated 29.09.2014 .

- a. In response to our submissions, Godrej has given the details of their supply of Ceto Stearyl Alcohol TA 1618 to us for the last 3 years. However, they have not mentioned anything on the supply of Fatty Alcohol 1214 to us. Here we would like to clarify that we had mentioned Fatty Alcohol 1214 which we are using in bulk compared to Ceto Stearyl Alcohol.
- b. New submissions should not be allowed to be made at rejoinder stage.

- c. Domestic industry in many cases does not revert to the customers with quotes, or gives unreasonable quotes and does not make deliveries as per customer's schedule.
- d. Godrej has given invoices of Ceto-Sterly Alcohol, whereas the predominant market is of C1214 alcohol, which they also import.
- e. Godrej competes with its customers. Despite not having ethoxylation plant, Godrej and VVF have easy access to tolling, which is evident from their Export statistics.

J.6 M/s Aarti Industries Limited by letter dated 29.09.2014

- a. Fresh submission as a part of rejoinder should not be accepted.
- b. Godrej has never reverted or approached for supply of Lauryl Alcohol
- c. Godrej will get unfair advantage in manufacture of downstream products, and would be able to make, break or distort market share of such products.

K. Views of the other parties in response to the rejoinder submitted by M/s Godrej Industries Ltd. dated 19/9/2014:

K.1 M/s HPFL dated 29.09.2014 .

- a. We have not been supplied written submissions of M/s Godrej Industries Ltd., pursuant to the public hearing held on 26.8.2014, which were sent by email only to certain interested parties.
- b. There are no grounds and circumstances explained by the said party to seek a special dispensation from the DG to file fresh evidence, which was not a part of the record earlier but appears to be taken cognizance of at such late stage of investigations.
- c. There is no indication that the Hon'ble DG has indeed allowed such late submission of the additional evidence at this late stage of investigations.
- d. It is not clear whether M/s Godrej Industries Ltd. is now proposed to be considered as a part of the Domestic Industry in terms of the safeguard laws particularly when the same was not a part of the Domestic Industry either in the initiation notification or in the Preliminary Findings. If the DG now proposes to consider M/s Godrej Industries Ltd. also as a part of the Domestic Industry, we would urge that an opportunity may be given to all the interested parties to address the legal validity of considering M/s Godrej Industries Ltd. as a part of the Domestic Industry particularly when the said party is an importer of the very same goods contributing towards the alleged increase in imports.
- e. As regards the statements made and evidence supplied in the rejoinder submissions by Godrej, we would like to bring the following to your kind attention:
 - (i) The copies of the invoices are hardly legible.
 - (ii) Most of the crucial information including the dates of the invoices have been kept confidential which is unfathomable.
 - (iii) On behalf of our clients HPFL, we would like to clarify that even Godrej has not supplied C8 after the year 2011. They have repeatedly expressed their lack of interest in the C8 business through their sales & marketing team. Further neither Godrej nor DI have responded to our offer to buy C8 from them, nor have they made any specific assurance to the DG that they will be supplying C8 to match with our requirements.
 - (iv) It is important to note that Godrej has kept even the production information relating to production of C8 and C10 confidential in their questionnaire response which should not be allowed.
 - (v) That the claim of Godrej that there is no difference between the prices of C8 and those of the blends, is completely false.

There is no consolidated information available on record for the two producers as a whole for our comments.

K.2 M/s Croda by letter dated 29.09.2014 .

- a. We would like to clarify that point 7 in the rejoinder has wrongly interpreted our comments during the public hearing held on 26th August 2014. What we highlighted in the meeting was that while one of the domestic producers VVF could not supply C18 product meeting our requirements of carbonyl value specifications during last 5 years, other domestic producer Godrej has also faced occasional difficulties in supplying required quantities meeting specifications as per our delivery dates more so during 2013-14.
- b. With respect to availability and supplies of C12-14 from Godrej - as highlighted by us as well as many other consumers of this product, right from period of mid-2011, Godrej representatives have told us verbally that they do not offer C12-14 alcohol for sale to external customers and it is being used for their in house consumption only. We had met them as recently as in April'14 and July-August'14 when this was reiterated by them. However, this was never confirmed in writing.

L. Examination & Findings of the Director General (Safeguards) :

1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, exporters and exporting nation. Submissions made by the various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for imposition of safeguard duty on the import of product under consideration has been examined under the municipal law as well as international law. The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at appropriate places below. The findings have been given accordingly. These findings are based on the examination of the application/submissions made by the DI, post- Initiation and Public hearing responses of the Interested Parties and other data so far available on record.

2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its Sub-section (1) of Section 8B provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article, if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions, so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in terms of law.

4. I find that one of the Interested party has raised the issue of jurisdiction of this office in processing the safeguard application in view of the ASEAN bilateral Free Trade Agreements and have held that since majority of the import is originating from ASEAN nations, the Deptt. of Commerce, who is the negotiator of these FTAs, to be the appropriate authority for providing them relief. This issue has been well addressed while issuing recommendations for levy of safeguard duty on provisional basis. However, once again I am explaining as to how the DG is competent to investigate the matter in this case.

5. In this regard, I have gone through the provisions of the said bilateral FTA. An extract from the treaty is given below:

ARTICLE 10***Safeguard Measures***

1. Each Party, which is a WTO Member, retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Safeguards) and Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Agriculture). Any action taken pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement (ASEAN-India DSM Agreement).

5.1 In view of the above provision, as against the contention of the Interested Parties that Safeguard Directorate is not an appropriate forum for relief in the instant case, it is found that merely the fact, that various Agreements provide for alternate mechanisms, to address trade imbalances, does not exclude the jurisdiction of DG Safeguards, acting under the aegis of the Customs Tariff Act, 1975. In fact, the ASEAN Free Trade Agreement, itself provides that notwithstanding the treaty, the WTO Members (including India) shall retain their rights and obligations under the Agreement on Safeguards.

5.2 Further, the general Safeguard measures are imposed on a non-discriminatory manner, against all imports of the product under consideration, irrespective of country of export, save and except the de-minimis provision, provided under the proviso to Section 8B(1) of CTA, 1975. Moreover, the applicant in the instant case resorted to relief under General Safeguard measures, which is fully justified under the existing legal provisions. Therefore, it is abundantly clear that this office has the jurisdiction and the authority to process safeguard application of the applicant in the instant case and accordingly therefore, I proceed to record the findings.

6. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification. Various issues raised by the interested parties have been addressed at appropriate places in these findings and herein below.

7. Reference has been made by several interested parties to an interview given by a senior official of the domestic industry, wherein it has been stated by him that the domestic industry has enjoyed significant growth in the last 10 years. The domestic industry has produced a letter dated 29/9/2014 requesting the Chemical Weekly to clarify the factual position. They have also produced a communication from the Chemical Weekly confirming that a clarification would be published in the next issue. As the findings are based on verified information of the domestic industry, no reliance is being placed on the interview.

8. **Scope of the product under investigation:** The product under consideration is “ Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) ” **excluding pure C8 hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under**

consideration). The 'PUC' is being imported under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 of the Customs Tariff Act 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. The 'PUC' are mainly used for the manufacture of surfactants, personal care products, home care products, pharmaceutical and agriculture related end application, processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastic and fabricated metal products, include mining, offshore operations, construction work and as solvent and for degreasing purposes. The product is not sold at retail level and is for industrial users.

9. Some of the Interested Parties have contended that the product scope has not been appropriately defined since different branched chain /blended fatty alcohols are different items. It is requirement of law that the injury must be caused to the "domestic industry" which produces the like or directly competitive products. The fatty alcohols produced by the petitioner are comparable to the imported goods, and are commercially and technically interchangeable with the imported article. Further the product covers grades/types which are same as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The products of all these headings find similar uses. Therefore, these products are like and directly competing products. Despite possible minor superficial differences, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses. These are sold via similar or identical marketing channels.

10. It has been submitted by the DI that the product under consideration includes grades/types derived out a single raw material and the entire set of carbon chains C8 to C18 needs to be looked at as a single category of product. The applications are broadly common, that is in the detergent and personal care industry. In fact, as stated by the DI, both C12 C14 and C16 C18 can be converted to ethoxylates and used as surfactants in detergent applications. C12 C18, which is a blend of C12 C14 and C16 C18, can also be used for similar applications. C14 must also be considered as it is a part of the blend C12 C14. It was also contended that blends can be obtained from pure cuts by a physical process. Moreover, it may be relevant to consider, that the fatty alcohols constitute less than 10% of the soaps, detergents, personal care products. The different blends have commercial and technical interchangeability. The essential character of end-use product, is not acquired from the fatty alcohol, but by use of other materials, which are predominant and/or are present in the end product in far greater proportions. These products compete mainly on price. It is on record that the petitioner is using the Lurgi process at its Talaja unit. By this process, a product commercially known as coconut alcohols which is a blend of C8 to C18 can be produced. By a process of fractional distillation, any of the fractions – C8 to C18 can be taken out. Therefore, since these items are interchangeable and originate out of identical raw material by an identical manufacturing process, the PUC in this case has been correctly defined.

11. It is the contention of one party (not a registered interested party) M/s Hindustan Polyamides & Fibres Limited (HPFL) that the DI has not manufactured C8 and C10 fatty alcohol during the injury period. It is also contended that since the DI has not manufactured C8 and C10, they should not have had included the same in their description of the PUC. In this regard, it is found that the DI has provided evidence to show that they have produced and sold C10 fatty alcohol on payment of excise duty. In so far as C8 is concerned, the DI has stated that they have the capability to manufacture C8, but as there is little demand for C8 in India, therefore they have not sold this grade. However, the capability of DI to produce C8 has not been disputed by any of the parties. The other Indian producer i.e., M/s Godrej Industries Ltd., who is supporting the instant safeguard application filed by the Domestic Industry, has produced invoices to show that it has produced and sold pure C8 during the injury period.

12. In this regard it is pertinent to note that C8 fatty alcohol was included in the PUC by the DI by virtue of their capability to manufacture the same, which has not been disputed by any interested party. However, it is also a fact that when the DI is not actually manufacturing the said product, there cannot be any comparison with the imported like or directly competing product, because even though pure C8 might be imported into India, there is no domestically produced pure C8 fatty alcohol by the DI for use, as pointed out by one party. Accordingly therefore, it is found that the domestic data of the DI does not contain any reference to pure C8; and also the import data taken does not include any entry of imported pure C8 fatty alcohol. As contended by the DI, the purpose of including pure C8 fatty alcohol alongwith blends, in PUC was with an intention to check probable circumvention by importing pure fatty alcohols instead of blends (including C8 and others) and mix them as per desired requirements for sale in market. I also note that neither the information initially furnished by DI includes the import information of C8 nor the tariff heading 29051690 relating to C8 has been included.

13. The information vide rejoinder letter dated 19.09.2014 submitted by M/s Godrej Industries Ltd. regarding production of pure C8 and their sales invoices, was circulated amongst all interested parties and other parties for comments. It is also noticed that both M/s VVF India Ltd. and M/s Godrej Industries Ltd. have vide their letters dated 25-09-14 have stated that considering very small quantity manufactured by the supporter industry, they have no objection to the exclusion of pure C8 fatty alcohol from the scope of investigations on account of small Indian market for this grade. The supporter industry has also provided details of production, sale etc. pertaining to pure C8 fatty alcohol as given below:

14. Detail of total production and sales after exclusion of Pure C8 Fatty Alcohol.:

MT	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 1 st Quarter
All India Production (MT)	118582	96344	112613	143232	28319
Production of supporter of Pure C8(excluded)	208	37	31	0	0
Actual All India Production	118374	96307	112582	143232	28319
Total sales of Indian producers	8242	6677	7573	8728	2485
Sales of supporter of Pure C8 (excluded)	33	26	31	15	0
Actual total sales of Indian producers	8209	6651	7542	8704	2485

I find from the above table that the supporter producer has produced and sold pure C8 fatty alcohol in meager quantities as compared to total production. On exclusion of the quantity of pure C8 manufactured and sold by the supporter producer from the total quantity of the PUC, I find that there is no impact on the merits with regard to data furnished by the DI with respect to increase in imports and measurement of serious injury. Therefore, in view of the above and also in view of the fact that the DI has no objection to the exclusion of pure C8 fatty alcohol, the same is excluded from the scope of the PUC.

15. In view of the above, I agree to exclude pure C8 fatty alcohol from the ambit of the PUC from the scope of the present investigation. For the reasons stated above, the scope of the product under consideration is modified/revised to this extent and the revised/modified PUC is “Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) excluding pure C8”, hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration).

16. **Domestic Industry:** Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:

“(b) “Domestic Industry” means the producers -

- as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;”

The application has been filed by M/S VVF (India) Limited, Mumbai, a 100% Export Oriented Unit, the applicant accounts for 65% of the total Indian production. As per records of the case, there is one other producer of this product, namely, Godrej Industries Limited (‘GIL’).

17. M/s Godrej Industries Limited, vide their letter dated January 22, 2014, has supported the application filed by M/s VVF (India) Ltd. and submitted details of their production, domestic sales and export information for the year 2010-11 to 2013-14. It is found that there is no concept of supporter in safeguard investigation. Hence, they are not treated as Domestic Industry in the subject investigation. However, being relevant to the issue at hand, the data submitted by them has been taken on record for injury analysis. The share of DI in the total production of the product in India varies from 51% to 65% during last four years as shown in the table below:

Period	Production DI (MT)	Production Others(MT)	Total Indian Production(MT)	Share of DI in Indian Production
2010-11	686 68605	49769	118 118374	58%
2011 2011-12	495 49585	46722	962 96307	51%

2012-13	2012-	678	67837	44745	112	112582	60%
2013-	2013-14	932	93297	49935	142	143232	65%

18. As the applicant has a major share in production of the like article in India, it is a validly constituted domestic industry.

19. It has been argued by some of the Interested Parties that the petitioner is ineligible to seek protection under the safeguard provisions, for the reason that it is a 100% EOU. In this context, reliance has been placed by them on the decision of Hon'ble Supreme Court in Hindustan Granites vs Union of India [2007 (12) SCC (178)] wherein it was held that EOUs are formed with an objective to export their entire production while sales in Domestic Tariff Area (DTA) are only an exception to the general rule. The issue before the Apex Court was not one relating to the interpretation of Section 8B of the Customs Tariff Act. Moreover, in the said decision, the Apex Court has held that there is no restriction on sales of goods in the DTA by an EOU. Even if sale to the DTA is an exception, I find that this exception is being made by the DI consistently during the period of investigation. The quantity of PUC being sold in the DTA is also significant portion of the total domestic demand. The DI therefore, has the right to seek protection from the DG.

20. The Interested parties have further relied on the decision of the Designated Authority in the case of Ceftriaxone Disodium Hemiheptahydrate-Sterile from China PR (Final findings dated July 2, 2008) on the point that EOUs cannot form part of domestic industry. In the facts of that case, I find that the EOU has been excluded from domestic industry, as it had made substantial imports, and injury appeared to be self-inflicted. Under Section 9A of the Act (relating to Anti-dumping investigations), producers who are importers or related to the importers or exporters, may be excluded from the scope of "domestic industry". There is no such exclusion under the safeguard provisions nor is it the case of the parties that the petitioner is an importer of subject goods. In this context, the DI has placed reliance on paragraph 34 of the findings of the Designated Authority (Anti Dumping) in the case of Vitamin A, in which Piramal Healthcare (100% EOU) was considered to be a domestic industry:

"With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as "domestic industry". In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic sales and not as imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules".

21. It has been further contended by the interested parties, that there are restrictions on the quantum of domestic sales that can be made by an EOU. I find from the Foreign Trade Policy, that there is no restriction on sales in the DTA by an EOU, provided positive NFE is maintained. I find merit in the contention that an export oriented unit is a producer of the like article in India.

22. In the case of Vikram Ispat Vs Commissioner Of Central Excise reported in 2000 (120) ELT 800 Tri Del.(LB), the Hon'ble Tribunal held that domestic sales made by an EOU are not treated as imports and are liable to be treated as clearances of manufactured goods subject to levy of central excise duty. In the case of Cosco Blossoms Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Customs reported at 2004 (164) ELT 423 (Tri Del), the Hon'ble Tribunal reiterated that goods cleared by an EOU domestically are treated as domestic goods.

23. In view of the above, I find that the petitioner is a producer in India, having a major share in the production of the like article, and it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975.

24. Source of Information:

The 'PUC' is being imported falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The import data for the 'PUC' has been obtained from IBIS, Mumbai, (Transaction wise) for the period from 2010-11 to 2013-14 and April – June 2014. The data on various economic parameters was submitted by the Domestic Industry in their application till December, 2013 and same has been verified by this Directorate on the basis of central excise records of the domestic industry to the extent possible and the verified data has been taken into consideration for injury analysis. The data from Jan, 14 to April, 14 in respect of various economic parameters, has been taken as furnished by the applicant, duly authenticated, and then verified by this office and relied upon at the time of issuance of Provisional Findings.

25. During the Public Hearing, information relating to the injury parameters for the period 2010-11 to 2013-14 and 1st quarter of 2014-15 has been submitted by the domestic industry, duly authenticated, which after verification (as per excise records, to the extent considered necessary) has been considered for injury analysis. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner, duly certified by independent Chartered Accountant.

26. **Period of Investigation (POI):**

Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define ‘period of investigation’ or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the “length of the period of investigation” and its “breakdown”:

“We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports.” (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)⁶

The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

“In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, “the determination of whether the requirement of imports “in such increased quantities” is met is not a merely mathematical or technical determination.” The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports “the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation”. The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination.” (Para 7.209)⁷

27. From the above it is clear that neither the Municipal law on Safeguard duty nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation. However, in the spirit of the references cited above, it appears that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past, but the investigation period should be the recent past.

28. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered on year to year basis, from financial year 2010-11 to 2013-14. In the Notice of Initiation, import data up to December, 2013 had been considered on annualized basis. In the Provisional Findings, import data was considered till April’14, along with the domestic data for the same period, which was examined on monthly and quarterly basis for determining existence of critical circumstances and serious injury, to consider imposition of provisional safeguard duty. The data has since been updated till June, 2014 by the DI during the Public Hearing. Therefore, considering these facts and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2010-11 to 2013-14 including first quarter of 2014-15 as the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI) for the purpose of the present investigation.

29. Some of the interested parties have raised the point that by adopting the data from January 2014 to April 2014, the DG has changed the period of investigation and recommended provisional safeguard duty without giving them opportunity of being heard. This submission is without any basis and without proper understanding of law. The “Period of Investigation” is not a defined legal expression as in the case of Anti-dumping law. In safeguard law, period of

⁶ WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

⁷ WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

investigation merely denotes a reference period selected by the DG in his discretion just for the sake of comparison of increase in imports and measurement of serious injury during such selected period. Though the Trade Notice provides for submission of data for minimum period of three years yet the period selected by the DG may be more than three years or less. Unfortunately, the interested parties have misunderstood the law on the selection of the period (though called period of investigation in common parlance). There could be situations where the period selected may be too short say three months, yet in my view the DG is fully competent under the law to select such period if the situation regarding increase in imports and injury warrants so. For example, in a situation of global recession, there could be sudden increase in imports at much faster pace and in such situation, the DG is obliged to entertain application for protection even when the injury has been caused during such short span of time. The objective of municipal safeguard law is to protect the domestic industry against the onslaughts of increased imports and extension of such protection cannot depend on length of the period. That is the reason perhaps the municipal law does not prescribe the length of the period and the same has been left to the discretion of the DG.

30. The period of investigation/reference period has been extended till end of June 2014 by the DG when relevant data was submitted by the DI at the time of public hearing and written submissions thereafter. Therefore, the data for the period from January 2014 till April 2014 adopted for analysis of injury due to increased imports in critical circumstances, is well within the investigation period and is not beyond the investigation period as contended by some of the interested parties. All the interested parties have been furnished the data till end of June 2014 and therefore have been given opportunity to respond and give their submissions.

31. It has also been submitted by some of the interested parties that they were not granted any hearing before adopting the period from January 2014 to April 2014, since this period was not part of the selected period in the Notice of Initiation and therefore, there is violation of principles of natural justice. I am of the view that this period has been examined solely from the point of view as to whether critical circumstances exist or not and also as to whether serious injury is caused or not during the period of criticality as claimed by the DI. This was necessary due to claim of the DI that imports are on the increase rapidly due to zero duty with effect from 01.01.2014 on the import of the PUC from ASEAN countries, under the FTA. The country cannot be allowed to be flooded with increased quantities of PUC merely because imports are allowed at zero rate under FTA. If the trend is not controlled, the domestic industry would vanish which would be fatal for the industrial base and economy of the country, since that would make the end user industry dependent on imports. If the situation warrants, the domestic industry must be extended protection on provisional basis to regulate the influx of such imports. In any case, the aspect of serious injury during the selected period i.e. 2010-11 to 2013-14 has been examined on annual basis while issuing the preliminary findings in the form of Notice of Initiation and it was *prima facie* determined that serious injury has been caused to the DI. This has been explained in para 17.3 of this Notice.

32. The core issue of existence of critical circumstances leading to irreparable damage to the position of the DI and suffering of serious injury or threat thereto by the DI, on preliminary basis, have been duly addressed by me. Further, no interested party has pointed out any specific provision of law which has been violated by the DG while issuing preliminary findings for imposition of provisional safeguard duty.

33. Further, the preliminary findings recommending the levy of duty on provisional basis are issued in terms of Rule 9. The municipal safeguard law does not contain any provision for granting hearing or any other opportunity to the interested parties before recommendations are made on preliminary basis. Similarly, no provision has been made in law to hear the interested parties before issuance of Notice of Initiation which are also preliminary findings. However, the municipal law specifically makes a provision for allowing opportunity in terms of Rule 6, to the interested parties to explain their case as part of the investigation process after the Notice of Initiation but before final findings are issued. It is not their case that they have not been given opportunity before final findings were issued. In my view, the statutory frame work on the subject does not provide for granting any hearing etc. before issuance of preliminary findings. Therefore, the requirements of principles of natural justice have been met wherever legally necessary.

34. It has also been submitted by some the interested parties that the data pertaining to the period from January, 2014 till April 2014, as submitted by the DI, has not been verified before recommending interim duty. In this regard, my view is that verification of data is not legal requirement. Further, none of the interested parties have stated that the data submitted by the DI is incorrect.

35. It has also been submitted that the DG, in his preliminary findings, has merely culled out existence of critical circumstances but there is no determination of serious injury or threat thereto due to increased imports during the period. I find that this submission is not correct. I have made analysis of all the relevant factors which are incorporated in para 20 to 33 of the Preliminary Findings and the conclusion regarding serious injury has been given in para 34. Further, causal link between increased imports and serious injury has been established as explained in para 35 of the Preliminary Findings.

36. Some of the interested parties had made similar submissions before the Board on Safeguards and the Central Govt after the issuance of Preliminary Findings recommending levy of provisional safeguard duty. However, the Board had concurred with the recommendations of the DG and the Central Govt. also accepted the findings of the DG and imposed provisional duty despite these submissions made by the interested parties.

37. Confidentiality of information submitted:

Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

38. The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application and during the course of investigations, which has been examined from time to time and granted where it appeared to be reasonable. Therefore, the request of confidentiality whenever claimed, to the extent considered necessary after its examination, has been accepted. Some of the interested parties have claimed that relied upon information was not provided to them and the DI has been allowed excessive confidentiality. This submission is without any basis. The information given by the DI has been examined with respect to their claim of confidentiality and allowed wherever their claim was found to be justified in my discretion. There is no dispute that non-confidential version has been given to all the interested parties.

39. Increased Imports:

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :”

40. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, -in absolute terms or in relation to domestic production.

41. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines ‘increased quantity’ as follows:

“(c) “increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.”

42. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC)⁸, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:

“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause

‘serious injury’.”

The Panel on US — Wheat Gluten⁹, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:

“8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1[of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”

⁸ Appellate Body Reports on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999

⁹ Panel Report on US — Wheat Gluten WT/DS166/R 31 July 2000

43. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned law and WTO jurisprudence.

44. Imports of product under consideration into India have shown sharp increase in absolute terms. The increase in imports in absolute terms is sudden and significant, causing severe injury to the domestic industry. The data relating to imports of product under consideration in absolute terms from 2010-11 to 2013-14 is as under:

a) Increased Import in absolute terms:

45. Fatty Alcohol is imported into India from a number of countries, and primarily from Indonesia, Thailand and Malaysia. The imports have shown an increasing trend in absolute terms, causing injury and serious threat of injury to the Domestic Industry. The quantum of imports of Fatty Alcohol, during 2010-11 to 2013-14 and in 2014-15 (annualised based on data of Quarter 1' 2014-15) are as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1'14-15	2014-15*
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616	19989	79957
Trend	100	172	257	290	101	403

*Based on April- June' 2014 (Annualized)

46. It is apparent from the data in the table above that there is a surge in import in absolute terms. The imports have increased from 19843 MT 2010-11 to 57616 MT in 2013-14, which shows an increase of 190%. There is a sudden surge in 2011-12 over 2010-11, by about 72%. The imports have continued to increase during the period of investigation. Analysis of data for 2014-15, shows a further increase of 303%, as compared to 2010-11.

b) Import in relation to Production:

47.. The imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to production of the Domestic Industry when compared with the base year. The import with respect to total Indian production increased from 17% in 2010-11 to 40% in 2013-14, which is a significant surge. Imports in relation to DI production has also increased significantly from 29% in 2010-11 to 62% in 2013-14.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1'14-15	2014-15*
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616	19989	79957
VVF Production	68605	49585	67837	93297	15187	60746
Total Indian Production	118374	96307	112582	143232	28319	113278
Imports as a % of DI production	29%	69%	75%	62%	132%	132%
Imports as a % to Indian Production	17%	35%	45%	40%	71%	71%
Trend	100	238	259	214		455
VVF Domestic Production**	33319	28974	22560	23303	3266	13065
Imports as a % to Domestic Production	60%	118%	226%	247%	612%	612%

Based on *April-June' 2014 data Annualized.

**VVF Production less exports

48. It is evident from the above that there is a surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to production and consumption. The increase in imports both absolute and relative, is significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Customs Tariff Act' 1975.

49. Serious Injury and Threat of Serious Injury:

Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act provides as follows:

"Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry; and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury."

50. Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

51. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of

Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

52. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which may show "serious injury" to the Domestic Industry, and therefore may justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "serious injury" to the Domestic Industry.

53. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

54. In Argentina — Footwear (EC), the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a):

"[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate 'significant overall impairment' of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'."

55. The Panel on US — Wheat Gluten, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

[We] do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."

56. Accordingly, in analysing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions which are relevant to the affected industry have been considered. All submissions made by the interested parties, domestic industry, supporting domestic producers and opposing interested parties, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry as discussed below:

a. Market Share: Market share of domestic producers has fallen significantly as compared to imports. Applicants had a market share of 38% in 2010-11 which fell to 27% during 2011-12. The market share of the applicants further declined to 18% in 2012-13 and 2013-14. An analysis of annualized data for 2014-15 (based on Quarter 1' 2014-15) shows a further decline in market share to 10%. On the other hand, the market share of imports increased from 44% in 2010-11 to 71% in 2013-14, and 80% in 2014-15 (Annualized).

Financial Year	Total Imports	Sales of DI	Sales of Other	Total Demand	Market Share	
					DI	Imports
2010-11	19843	17080	8209	45132	38%	44%
2011-12	34142	15285	6651	56078	27%	61%
2012-13	51055	12891	7542	71488	18%	71%
2013-14	57616	14777	8704	81097	18%	71%
Q1' 2014-15	19989	2594	2485	25068	10%	80%
*2014-15	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*Based on April-June' 2014 data (Annualized)

b. Production: The production of the Domestic Industry has increased over the period, mainly on account of the exports. This becomes evident from the trend of domestic production (i.e. Production less exports) shows a declining trend.

*based on April-June' 2014 data (Annualized)

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1' 2014-15	*2014-15
PRODUCTION						
Production (DI) MT	68605	49585	67837	93297	15187	60746
Trend	100	72	99	136		89
Production less exports	33319	28974	22560	23303	3266	13065
Trend	100	87	68	70		39

The domestic production has declined from 33319 in base year to 23303 in 2013-14, and 13065 in 2014-15

c. Capacity Utilisation:

The installed capacity of the domestic industry has remained 1,20,000 MT during the period. The overall capacity utilization has improved due to sales in export markets. If export sales are removed from consideration, the capacity utilisation reflects a decline from 28% in base years to 19% in 2013-14, and 11% in 2014-15 is again on a declining trend in 2014-15.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1' 2014-15	2014-15 (ann.)*
Capacity Utilization % (Production)	57%	41%	57%	78%	51%	51%
Trend	100	72	100	137	89	89
Capacity Utilization % (Production less e Exports)	28%	24%	19%	19%	11%	11%
Trend	100	86	68	68	39	39

d. Changes in the level of Sales:

The domestic sales of DI have consistently declined in 2010-11 to 2012-13, both in absolute terms and relative to consumption. In 2013-14, there has been a marginal improvement in sales as compared to 2012-13, sales remained significantly lower as compared to 2010-11. The decline in sales, has to be viewed in the context of the sharp decline in market share of domestic industry, from 38% to 10%, while the share of imports has gone up from 44% to 80%.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1' 2014-15	2014-15*
Domestic sales of DI	17080	15285	12891	14777	2594	10376
Trend	100	89	75	87	-	61

*based on April-June' 2014 annualised.

e. Employment:

It is seen from the table below that the level of employment has not undergone a significant change. In any case, employment levels are often inflexible in the short run.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Employment	100	109	119	124	122

*Based on April-June' 2014 data annualized.

f. Productivity:

The productivity levels have moved in line with capacity utilization.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Productivity per day	100	72	99	136	89

*Based on April-June' 2014 data

g. Profit & Loss:

The profitability of the Domestic Industry has fallen sharply since 2010-11. The domestic industry is unable to make profitable sales in the Indian market.

Years	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Profit/loss	100	-266	-2796	-2232

It has been contended by the domestic industry that in order to retain customers, the Domestic Industry was forced to lower its prices and make loss making sales. It is evident that the domestic industry is suffering severe financial losses on account of imports.

57. Other factors causing serious injury or threat thereof:

Para (2) of Annex to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 lays down that the determination referred to in subparagraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased import are causing "serious injury" to the Domestic Industry at the same time, such "serious injury" shall not be attributed to increased imports.

As such, the possible other factors that may be attributed to the serious injury to Domestic Industry have been examined. Followings are relevant in this regard :

a. Demand for the product:

When overall demand increases, it is expected that, in tandem therewith, sales of the domestic industry will show rising trend. However, in this case, market share of the DI has shown a steep decline whereas the market share of imports has risen. The incremental demand has been largely met by the imports.

b. Import in relation to Demand:

For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is determined as the imports of product into India from different countries, domestic sales of the Domestic Industry (DI) and domestic sales of the other domestic producer. Changes in demand/consumption so determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources and supplies by the Domestic Industry in order to determine whether imports of product under consideration in India have increased significantly in relation to consumption or demand for the product in the country. It is noticed in the table below that the import with respect to demand increased from 44% in 2010-11 to 72% in 2013-14, which is a very significant increase. It may be seen that the same trend continued in 2014-15, where the imports with respect to demand increased to 80%.

Financial Year	Total Imports	Sales of DI	Sales of Other	Total Demand	Market Share	
					DI	Imports
2010-11	19843	17080	8209	45132	38%	44%
2011-12	34142	15285	6651	56078	27%	61%
2012-13	51055	12891	7542	71488	18%	71%
2013-14	57616	14777	8704	81097	18%	71%
Q1' 2014-15	19989	2594	2485	25068	10%	80%
2014-15*	79957	10376	9940	100273	10%	80%

*Based on April-June' 2014 data annualized.

c. Inventory:

Given the nature of the product, domestic industry is not in a position to maintain significant inventories. The inventories reflected, are mainly on account of storage of the product during export. The level of inventories may therefore, not appropriately reflect the condition of the domestic industry.

d. Changes in the patterns of consumption:

It is claimed by the Domestic Industry that there is no evidence on record that the pattern of consumption with regard to the product under consideration has undergone any material change as far as the Indian market is concerned. None of the Interested Parties has also brought on record any evidence to dispute this claim of the Domestic Industry, and is, as such, accepted.

e. Trade restrictive practices of and competition between the domestic producers:

There is no evidence on record that trade restrictive practices or competition between the domestic producers could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

f. Export performance:

The exports of domestic industry have increased over the injury period. The exports in 2013-14, were significantly higher than in 2010-11, indicating that the injury is not on account of exports. In any case, for determination of serious injury, only information relating to the domestic market has been considered. It has been contended by many of the parties that the domestic industry has suffered due to its export performance. I do not find much merit in this contention. The exports of the domestic industry have increased in 2013-14 as compared to base year and preceding year, as can be seen from the table below. Moreover, the domestic industry had idle capacity to meet the requirements of Indian customers, had there been a demand for the indigenous product, of course subject to permission required for sale in the DTA.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Q1'14-15	2014-15 (Ann.)
Exports	35286	20611	45277	69994	11920	47680
Trend	100	58	128	198		135

g. Price undercutting, suppression/depression:

It is observed that the landed price of the imports of "PUC" is significantly lower than the (a) selling price of the domestic industry except in 2011-12 and (b) cost of sale. Due to imports, the domestic industry has been selling much below its cost of sales. In an attempt to compete with imports and retain customers, the domestic industry was unable to raise its prices, in 2012-13 even though its cost of sale had increased by 22% as compared to base year. The price undercutting is resulting in price suppression. The domestic industry is suffering financial losses during the entire period. The variation in cost of sales and selling price with respect to landed prices of imports are as under:-

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Landed price of imports	Rs/MT	103024	132784	114082	96610	114493
	Trend (indexed)	100	129	111	94	111
Cost of Sales	Rs/MT (Indexed)	100	141	122	104	
Selling Price	Rs/MT (Indexed)	100	138	101	94	116

h. Developments in technology:

The petitioner has claimed that the technology for production of the product has not undergone any change. This has not been refuted by any Interested Party. Developments in technology are therefore, not a factor causing injury, in this case.

58. There are hence no factors, other than the surge in imports that are also simultaneously causing serious injury to the Domestic Industry.

59. Conclusion Regarding Serious Injury:

a. The imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. As a result of the significant surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury. Performance of the Domestic Industry has moved inversely to the imports, with a significant deterioration in most of the parameters.

b. Market share, domestic production, domestic sales, capacity utilization, and profitability of domestic industry have declined during the injury period reflecting serious injury to the domestic industry. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows 'a significant overall impairment'. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration.

60. Threat of Serious Injury:

There is threat of serious injury to the Domestic Industry producing Fatty Alcohol in India due to the surge of imports and the current trend of import volumes entering India. The volume of imports continues to increase, despite already being at very high levels. The market share of imports has also substantially increased over the period. Considering the production capacities available with foreign producers, it is likely that the imports will continue to increase, resulting in further injury to the domestic industry. The likelihood of further imports leads to the conclusion that there is a threat of further serious injury to the domestic industry. In view of the fact, that the domestic industry is unable to make profitable sales in the Indian market, I am of the view that in the absence of levy of safeguard duty, the Domestic Industry faces serious injury and a threat of serious injury.

61. Causal Link between Increased Imports and Serious injury or Threat of Serious injury:

As per Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, the Director General (Safeguards) is obligated to "*determine serious injury or threat thereof of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to these rules*". Further, paragraph 2 of the Annex requires establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

"The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports."

62. Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports."

*To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."*¹⁰

63. A comprehensive evaluation of parameters as above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard:

- i) The increase in the Market share of imports was accompanied by a significant decline in the share of the domestic industry in consumption in India
- ii) The period of surge in imports coincides with decline in the profitability of domestic industry

¹⁰ [Panel Report on Korea — Dairy](#), paras. 7.89-7.90

- iii) While the demand has shown a rising trend during the period of investigation, the incremental demand was largely met by imports and the domestic industry was not able to benefit from the growth in demand.

64. From the above, it is clearly established that there is causal link between increased imports and serious injury or threat thereto.

65. Adjustment Plan:

Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

66. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

67. The domestic industry has submitted a detailed Adjustment plan, showing year-wise projected savings. In terms of the Adjustment Plan, the domestic industry is in the process of setting up a plant in Indonesia. I find that the said plant in Indonesia has already become operational in December 2013. The Domestic industry has submitted that their unit in Indonesia is under trial production and about 2% of their raw material requirement has been fulfilled by the said unit so far.

68. As per the plan, the petitioner will import a partially processed product (SPKO) manufactured by their own unit in Indonesia to avoid the heavy export tax imposed by the Indonesia. I find that this would reduce the cost of production of the PUC and thus would substantially benefit the DI. Some of the interested parties have claimed that the DI in their petition has stated that the import of fatty acids from their unit in Indonesia will not change their cost of production of fatty alcohols and therefore, the adjustment plan should be understood accordingly. In this regard, I find that the DI in their petition, they have given the Rehabilitation Plan which gives details of savings to be made on import and transportation of fatty acids from their Indonesia unit. Further, the DI, in their rejoinder dated 18.09.2014 in para 2.6 has clearly stated that consequent on reduction of raw material cost there will be a decline in the overall cost of production of fatty alcohols in India. Further, the DI has stated that the fixed cost incurred on idle splitting capacity in Talaja unit would be neutralized in phased manner by usage of this capacity for other businesses like splitting of local oils or other materials.

69. I find that their plan as given above is viable and is likely to make them competitive to meet the challenges in increased imports.

Capacity of the DI to Supply in the DTA;

70. Some of interested parties have contended that the DI is 100% EOU and therefore may not be able to supply the PUC due to their focus on exports to meet their export obligations. I agree with the interested parties that the DI will not be able to sell the PUC in the DTA unless they achieve positive NFE through exports. However, I find from that consistently, during the period under investigation, the DI, by exporting the PUC, has been earning their eligibility to clear substantial quantities of PUC into the DTA. The exports made by the DI in fact have increased substantially in the year 2013-14. No reason has been pointed out by the interested parties which can raise doubt on the capacity of the DI to sell a good quantity of the PUC in the DTA. The manufacturing capacity of the DI is not in doubt. I find that the above argument is not convincing, since the DI can sell any quantity into the DTA at concessional rate of duty subject to the NFE achieved by them in export of goods. I further find that there is no restriction on the DI to sell the PUC in the domestic market on full payment of duty. Therefore, once the domestic market responds to the DI with respect to the demand, the DI is in a position to manufacture and meet the entire demand in the DTA. I feel the market should respond to the DI once the imports are made costlier on imposition of safeguard duty. This should also enable the DI to put their entire capacity of manufacture into use. The DI presently is not a position to compete with the cheaper imports of PUC. Some of the interested parties have also submitted that they have supply problems with the DI, since their focus is mainly on exports. However, I find that this submission is not supported by any cogent evidence and therefore is not acceptable.

Period of Protection:

71..Regarding adjustment plan, I find that the most important part of the adjustment plan with respect to commencement of production of fatty acids in Indonesia has already been made operational in December, 2013 though the production of this plant would be increased in phased manner. Therefore, the DI does not require protection for three years as requested by them to become competitive and to adjust to the challenge of increased imports. In my view, the period for the purpose of adjustment has to be reduced.

Alternate Remedy:

72. Some of the interested parties have submitted that the DI should seek relief under the Free Trade Agreement, since increased imports have taken place from ASEAN countries only. In this regard, I find that it is the prerogative of the DI to seek protection either under the general safeguard law or safeguard law specific to the FTA. Since the

application has been made in terms of section 8B of the Customs Tariff Act, 75, I have to examine the issue accordingly. I do not have powers to direct the DI to avail the provisions of FTA and Rules made there under.

Unforeseen developments:

73. It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement in the municipal law or on the methodology that should be followed for analysing unforeseen developments. The WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the “unforeseen developments” which led to the serious injury to the Domestic Industry. The Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports. In this regard, I find that Article XIX of GATT, 1994 provides that serious injury has to be as a result of unforeseen developments.

Article XIX of GATT 1994 states as follows:

“1.(a)If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.”

74. The Appellate Body in Argentina — Footwear (EC) case held that the phrase “Unforeseen Developments” means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

75. The applicant has given a number of reasons for surge in imports, which in their understanding constitute the unforeseen circumstances in this case, which are summarized below:

a. Unforeseen increase in global capacities- far in excess of global demand

The global capacity currently is 151% of the Pre-2011 levels. The domestic industry has claimed that the global capacity for the subject goods has increased based on the details available in Oleoline, a publication, as under:

Estimated Global Capacity

Country	Pre 2011 (MT)	Post 2011(MT)
Indonesia	3,24,000	9,98,000
Malaysia	4,90,000	5,90,000
Phillippines	1,80,000	2,80,000
Global Capacity	22,70,000	34,27,000

It is contended that the setting up of a huge capacity has led to global oversupply of the subject goods. None of the participating exporters or Governments have challenged the correctness of the figure furnished by the DI in their rejoinder/counter submissions or thereafter. I find that there is merit in the submission of the DI.

b. Global Demand Supply Gap

The setting up of production facilities in South East Asia, has resulted in an alarming increase in imports. This coupled with the fact that these capacities are targeted for emerging markets, such as India, was clearly unforeseen.

c. Imposition of Anti-dumping duty by European Union

It is further seen that the European Union had conducted an Anti-dumping investigations against import of subject goods and had imposed definitive anti-dumping duties in 2011, against various sources of the material. These duties shifted the focus towards the Indian market which was unforeseen.

d. Export tax on the principal raw material

It has also been submitted that the imposition of export duty on Crude Palm Kernel Oil, the main raw material for the subject goods, was not foreseen at the time of Uruguay round.

76. Having regard to the information on record and submissions made by the interested parties, it is observed that the imports of the product under consideration have increased on account of surplus capacity, significant demand supply gap and imposition of anti-dumping duty on exports of Fatty Alcohol by the European Union. Producers in South East Asian Countries are on the look-out for emergency markets like India, with a large population and increasing per capita consumption of detergents, personal care products, etc.

77. Therefore, I hold the rise in import of Fatty Alcohol due to imposition of anti-dumping duty by European Union aided by huge demand supply gap for this product due to excessive capacities, to be an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

Public Interest:

78. Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”

79. It has been claimed by some of the interested parties that imposition of safeguard duty would adversely impact the user industry, forcing them to incur huge losses. The Domestic industry has provided its estimation, based on the best available information, that the imposition of duty will have negligible impact on the user industry i.e. Shampoos, tooth pastes and other home & personal care products. The domestic industry has tried to quantify the impact of 20% safeguard duty on eventual downstream products claiming that the 20% increase in price on account of safeguard duty, if fully passed onto the eventual end product (assuming that the Domestic Industry increases the prices by 20%) would have minimal impact on the eventual end products, as is seen from the table below:

SHAMPOO (SACHET) 6 ML	
	RS.
PRICE	1
COST	0.6
15%* SLES USED BY WEIGHT @ \$1257/ MT	0.068
FATTY ALCOHOL CONTENT IN SLS 50%*	0.034
EFFECT OF 20% DUTY	0.0068
% OF PRICE	0.68%
Less than 1% of price or less than a paisa	

*Based on industry standard

**1 molecule of SLES consists of 1 Molecule Fatty Alcohol. The molecular weight of SLES is 384 (refer the SLES RHODIA) and the average molecular weight of C1214 is 190-197 (refer VVF C12-14 MSDS), since the ratio of the two molecular weights (i.e 194/384) is 0.5, the Fatty Alcohol content in SLES is around 50%.

- None of the interested parties have brought on record, evidence to refute the claim made by the domestic industry. In such circumstances, the claim of the interested parties that the levy of duty would significantly affect the consumers remains unsubstantiated.
- Further, the claim of interested parties that the levy of duties will create an inverted duty structure for the SLS/SLES industry, resulting in increase in imports of SLS/SLES is also not substantiated by any data. It has been submitted by the domestic industry that the duties on SLS/SLES has historically been less than the duties on Fatty alcohol. However, these goods have never been imported in substantial quantities. It has also been submitted by the domestic industry that the imposition of anti-dumping duty by European Union has not led to increase in imports of downstream products in the EU. It has been contended that there is no surplus capacity of SLS/SLES in the major exporting nations, and therefore the apprehension that fear of imports of SLS/SLES will increase significantly, is unfounded. The importers have contended that imports of SLS /

SLES are likely since water based transportation of these items is possible. However, there is no material available on record, which indicates that the duties would result in an increase in the import of downstream products, such that the local producers would be unable to face the competition. In any case, I agree that the imposition of safeguard duty would lead to inverted duty structure for the downstream industry till the levy expires. But if the protective duty of safeguard is not levied, it may cause extinction of the DI which would be a much disastrous situation for the economy of the country. The protection of the DI is also part of the policy of the Govt. Therefore, this argument is not sufficient to deny protection to the DI.

80. Section 8B has been enacted in the public interest for the protection of domestic producers, suffering serious injury due to a surge in imports. The law envisages giving protection to such producers, so that they can adjust their business to deal effectively with the imports. This is a temporary measure for a limited period. Unless duties are imposed to safeguard the interests of the domestic industry, they would continue to face injury, and may be forced to stop production of the product altogether. In this scenario, the users would be left with no local supplier of the product. This would not be in the public interest or in the interests of ultimate consumers or producers of intermediate products.

81. The above claims of Domestic Industry have not been disputed by any Interested Party in these investigations. In view of the absence of any contrary submissions/rejoinders having been filed by any Interested Party in this case, the submissions made by the Domestic Industry are considered justified. As shown by the Domestic Industry, it appears that impact of the safeguard duty on different segments of the users of the subject product would be minimal. It is therefore, concluded that if the duties were imposed, the impact of the same on the eventual end product would not be significant.

82. In the light of the facts on record, it is concluded that imposition of safeguard duty would be in public interest and the interests of end users would not be very adversely impacted.

Developing Nations:

83. The percentages of imports from developing nations have also been examined. As the imports from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia, will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

Conclusion:

84. On the basis of above examination and analysis done, it is concluded that :-

- a. There has been a significant increase in imports of Fatty Alcohol, the Product Under Consideration (PUC) in absolute terms as well as in relation to domestic production over the entire Period of Investigation (POI). Thus, it can be concluded that there is a significant surge in imports of PUC so as to cause or threaten to cause serious injury. This surge in imports is also quite significant in relation to total demand as well.
- b. The investigation has shown that the domestic industry has suffered serious injury, considering overall performance, on the basis of listed economic parameters, i.e., market share, sales and profitability, which have steeply declined from the base year till 2013-14, as also in the first quarter of 2014-15. The Domestic Industry has been able to demonstrate serious injury caused in the form of mounting losses and by way of declining sales even when demand for the PUC rose in the country. This has caused significant overall impairment to the position of the domestic industry. Moreover, the market share of DI has declined in 2013-14 as compared to the base year. The market share of the DI in 2013-14 is at the same level when compared with the previous year despite the fact that there is considerable rise in the domestic demand during the period. It establishes the causal link between the rise in imports and serious injury caused to the Domestic Industry during the POI.
- c. The Domestic Industry has been able to demonstrate that the developments in the market for surge in imports of the Product under Consideration were unforeseen.
- d. The Domestic Industry has also been able to show that imposition of safeguard duty in this case would be in Public Interest because the probable impact of the safeguard duty on end users/consumers would be minimal. It is also found that no Interested Party has refuted or disputed this aspect with cogent evidence, during the course of investigation.

85. Recommendations:

In view of the above findings, I am making following recommendations:

- a. The increased imports of "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of, C8, C10, C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unbled (Not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14)", **excluding pure C8 hereinafter referred to as 'PUC'** into India, have caused serious injuries and are threatening to cause serious injuries to the domestic producers of "PUC" and it will be in

the public interest to impose safeguard duty on imports of "PUC" into India in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97, for a period of two years and six months. This period shall be computed from the date of levy of provisional safeguard duty vide notification no.3/2014-Cus (SG) dated 28.08.2014. Considering the average cost of sales of "PUC" by the domestic producer after allowing a reasonable return on capital employed, safeguard duty as indicated below, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry on PUC being imported falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. (HS code is only indicative in nature and the product description shall prevail in all circumstances) is recommended to be imposed:

period	Rate of Safeguard duty
1 st year	20% advelorem
2 nd year	18% advelorem
Subsequent six months	12% advelorem

- b. I hereby also confirm the provisional safeguard duty recommended by me earlier and imposed under Gazette of India Extraordinary vide G.S.R.357(E) dated 26th May, 2014 and imposed vide Min. of Finance Notification No. 03/2014-Cus (SG) dated 28th August, 201, in terms of this Final Findings. However, in terms of final determination regarding scope of the PUC, made above, the provisional safeguard duty recommended to be imposed on "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of pure C-8 in preliminary findings dated 26/5/2014 is recommended to be withdrawn and will be refunded in terms of law, if collected.
- c. As the imports from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia, will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No. D-22011/26/2013/pt.]

R.K.SINGLA, Director General